राष्ट्रीय संस्करण

15 वर्षीय शेफाली ने तेंदुलकर का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
>> 14

वर्ष 3 अंक 153

दैनिक जागरण

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, सोमवार, 11 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सौहार्द के साथ मंदिर निर्माण की दिशा में सरकार

फैसले के बाद ▸ एनएसए डोभाल ने हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं से की मुलाकात, अशांति फैलाने की कोशिश करने वाले तत्वों से किया सतर्क

धर्मगुरुओं ने फैसले का स्वागत किया, सुरक्षा पर सरकार के कदमों को सराहा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद मंदिर निर्माण के साथ-साथ देश में सौहार्द बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता में है। इस दिशा में रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने हिंदू एवं मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात कर शांति-सौहार्द की दिशा में सहयोग की अपील की। दूसरी ओर, मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन के विकल्पों पर भी सरकार काम कर रही है।

मुलाकात के दौरान डोभाल ने धर्मगुरुओं से कहा कि देश के भीतर और बाहर से कुछ तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। धर्मगुरुओं ने भी देश में शांति, कानून-व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में सरकार को सहयोग का भरोसा दिया। धर्मगुरुओं ने इस बात पर संतोष जताया कि शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दोनों समुदायों के करोड़ों लोगों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ संयम से स्वीकार किया। धर्मगुरुओं ने इस संबंध में सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से उठाए गए एहतियाती कदमों की भी सराहना की। बैठक में मौजूद मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना था कि इस देश का मुसलमान अमन पसंद है। वह देश के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहा है। बैठक में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद, शिया जमात-ए-इस्लामी के उपाध्यक्ष इंजीनियर मुहम्मद सलीम, जमीयत अहले हदीस के प्रमुख असगर इमाम सलफी, मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत के अध्यक्ष नवेद हामिद, दरगाह अजमेर शरीफ के इमाम जैनुल आबदीन, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अख्तरूल वासे और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अध्यक्ष सिराउद्दीन कुरैशी मौजूद थे।

बैठक में मौजूद रहे ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती ने ऐसे विमर्श आगे भी जारी रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम भले ही एक साथ ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं, लेकिन साथ-साथ देश के विकास और सुरक्षा के लिए काम तो कर सकते हैं। बैठक में योगगुरु रामदेव, स्वामी परमानंद और स्वामी असीमानंद भी मौजूद थे।

डोभाल ने कहा कि देश के सभी समुदायों का भविष्य यहीं सुरक्षित है और सभी को एकजुट होकर देश के विकास में सहयोग करना होगा। उन्होंने सावधान किया कि सीमा पार से और देश के भीतर भी कुछ लोग आपसी सौहार्द व भाईचारे को खत्म करने की कोशिश में जुटे हैं।

1989 में ही बन गया था नक्शा : विहिप ने 1989 में ही राममंदिर का नक्शा तैयार कर लिया था। नक्शे के अनुरूप पत्थरों को तराशने का 80 फीसद काम पूरा हो चुका है, जो फिलहाल रामजन्मभूमि न्यास के अधीन है। यदि विहिप के नक्शे और उसके द्वारा तराशे गए पत्थरों का उपयोग किया जाता है, तो मंदिर निर्माण अगले दो-ढाई साल में पूरा हो जाने की उम्मीद है।

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ बैठक की और देश में शांति व्यवस्था कायम रखने पर चर्चा की। प्रेट्र

1993 में बनाए गए कानून में ही है ट्रस्ट का प्रावधान

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द सरकार इस बाबत कदम बढ़ाएगी। फैसले के अनुसार सरकार सीधे तौर पर अधिसूचना जारी कर राममंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर सकती है। 1993 में नरसिम्हा राव सरकार ने अयोध्या जमीन अधिग्रहण कानून में ही ट्रस्ट का प्रावधान कर दिया था। चूंकि संसद से पारित कानून में पहले ही ट्रस्ट का प्रावधान है, इसीलिए इसके लिए नए सिरे से संसद में जाने की जरूरत नहीं है। एक बार ट्रस्ट का गठन होने के बाद रामलला की सारी विवादित जमीन और 1993 में अधिगृहीत जमीन ट्रस्ट को सौंप दी जाएगी। जल्द ही ट्रस्ट के गठन की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारी के अनुसार, ट्रस्ट के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद अयोध्या में विवादित और अधिगृहीत सभी जमीन का मालिकाना हक ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा। कानून में यह प्रावधान किया गया है कि ट्रस्ट ही इस जमीन के विकास और विभिन्न निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी संभालेगा। बाद में ट्रस्ट ही तय करेगा कि राममंदिर का निर्माण विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की ओर से तैयार पुराने नक्शे के अनुसार किया जाएगा या फिर नया नक्शा बनवाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीते 24 घंटों में सोशल मीडिया पर भड़काऊ व आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 40 और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। सांप्रदायिक व सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ रविवार को 22 मुकदमे दर्ज किए गए। दो दिनों में ऐसे प्रकरणों में 34 एफआइआर दर्ज कर 77 आरोपितों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं, गोरखपुर में तीन सिपाही जन्मदिन की पार्टी में जश्न मनाने में जुटे थे। पटाखा फोड़ रहे थे और जयकारे लगा रहे थे। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

अयोध्या पर विशेष पेज

सर्वसम्मत फैसला>> 4
अयोध्या लाइव >> 5
फैसले के बाद >> 6

सरोकार

कार्बेट में खोजा जा रहा मानव व वन्यप्राणी संघर्ष का समाधान

भोपाल : कार्बेट फाउंडेशन ने मप्र स्थित कान्हा–बांधवगढ़, बांधवगढ़–संजय दुबरी कॉरीडोर में ऐसे उपाय किए गये हैं, जो मानव–वन्यप्राणी संघर्ष की समस्या का समाधान प्रस्तुत करते दिखते हैं। वन्यप्राणियों की सुरक्षा व वनवासियों को संरक्षक के रूप में स्थापित करने का प्रयास इसमें शामिल है। (पेज–11)

जागरण विशेष

बीमारी दूर करना है तो कुछ मीठा हो जाए

कोलकाता : कहते हैं ज्यादा मिठाइयां मर्ज लेकर आती हैं, लेकिन कोलकाता के रवींद्र कुमार पाल ने मिठाइयों को ही दवाओं का रूप दे दिया है। उनकी मिठाइयां अल्सर, मिर्गी, किडनी व गॉल ब्लैडर में स्टोन, अत्यधिक रक्तस्राव और उच्च रक्तचाप में कारगर हैं। (पेज–11)

न्यूज गैलरी

सिटी न्यूज ▸ पृष्ठ 2

जनवरी में फिर लागू हो सकता है ऑड–इवेन

नई दिल्ली : ऑड–इवेन जनवरी में फिर लागू हो सकता है। हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी क्योंकि उस समय दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू होगी। सरकार का दावा है कि ऑड–इवेन से प्रदूषण घटा है और जाम से भी मुक्ति मिली है। तीसरी बार इसे लागू किया गया है।

राज–नीति ▸ पृष्ठ 3

स्विस बैंक में दर्जनभर भारतीय अकाउंट्स के दावेदार नहीं

नई दिल्ली : स्विस बैंक में करीब दर्जनभर भारतीय अकाउंट्स के दावेदार सामने नहीं आए हैं। अगर जल्द इन अकाउंट्स पर दावा नहीं किया गया, तो इनकी पूरी रकम स्विट्जरलैंड सरकार के खाते में चली जाएगी। स्विट्जरलैंड के अधिकारियों के मुताबिक निष्क्रिय अकाउंट्स में कम से कम 10 खाते भारतीयों के हैं।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 7

'बुलबुल' से बंगाल में भारी तबाही, 10 की मौत

कोलकाता : चक्रवाती तूफान 'बुलबुल' ने शनिवार रात बंगाल में दस्तक दी और रविवार तड़के तक नौ जिलों में जमकर तांडव मचाया। तेज हवाओं व भारी बारिश से तटीय जिलों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। 10 लोगों की मौत भी हुई है। बंगाल में तबाही मचाने के बाद बुलबुल बांग्लादेश की ओर रवाना हो चुका है।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 13

पाक में सिख अलगाववादियों की मौजूदगी ने बढ़ाई चिंता

नई दिल्ली : पाकिस्तान के करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब के लिए भारतीयों की आवाजाही शुरू हो गई है, लेकिन पाक में सिख अलगाववादियों की मौजूदगी ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। भारत को डर है कि दरबार साहिब से मत्था टेककर लौटने वाले श्रद्धालुओं में शामिल होकर सिख अलगाववादी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए भारत की सीमा में घुस सकते हैं।

महाराष्ट्र में भाजपा की ना के बाद सरकार बनाने के लिए शिवसेना को मिला न्योता

बदलती तस्वीर ▸ राज्यपाल ने आज शाम 7 .30 बजे तक मांगा जवाब

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पाटिल बोले, शिवसेना ने जनादेश का किया अपमान

राज्य ब्यूरो, मुंबई

महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सरकार बनाने के लिए अब शिवसेना को न्योता दिया है। भाजपा द्वारा सरकार बनाने से इन्कार करने के कुछ ही समय बाद राज्यपाल ने राज्य की दूसरी बड़ी पार्टी शिवसेना को यह न्योता दिया। राज्यपाल ने शिवसेना के विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे से सोमवार शाम 7.30 बजे तक अपनी पार्टी की इच्छा और सरकार बनाने की उसकी क्षमता यानी बहुमत के आंकड़े की जानकारी देने को कहा है। राजभवन की तरफ से जारी बयान में यह जानकारी दी गई है।

राज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते शनिवार को भाजपा को सरकार बनाने का न्योता दिया था। शिवसेना के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी भाजपा 105 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर दो बार हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। दूसरी बार हुई बैठक को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इन बैठकों के बाद भाजपा नेताओं ने राजभवन जाकर राज्यपाल को बता दिया कि बहुमत सिद्ध करने लायक संख्याबल नहीं होने के चलते पार्टी सरकार नहीं बनाएगी।

राज्यपाल से मुलाकात के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने शिवसेना पर जनादेश के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की जनता ने भाजपा-शिवसेना गठबंधन को सरकार बनाने का जनादेश दिया था। पाटिल ने शिवसेना को कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए शुभकामनाएं भी दी।

वहीं, राज्यपाल से न्योता मिलने के बाद शिवसेना में हलचल तेज हो गई। एक होटल में ठहरे पार्टी के विधायक शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के घर पहुंचे और बैठकों का दौर शुरू हुआ। इससे पहले, शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शिवसेना का ही बनेगा। उन्होंने 170 विधायकों के समर्थन का दावा भी किया था।

हालांकि, शिवसेना के लिए सरकार बना पाना आसान नहीं है। शिवसेना राकांपा और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। राकांपा के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि शिवसेना ने समर्थन के लिए उससे संपर्क नहीं साधा है। लेकिन अगर वो समर्थन चाहती है तो सबसे पहले उसे राज्य के साथ ही भाजपा के नेतृत्व वाले राजग गठबंधन से अलग होना होगा। वह एक साथ दो गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी रह सकती है। शिवसेना के कोटे से मोदी सरकार में अरविंद सावंत मंत्री है। पार्टी अगर राकांपा की शर्त मानती है तो सावंत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा।

बता दें कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के 105 और शिवसेना के 56 सदस्य हैं। जबकि, राकांपा के 54 और कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 44 है। बहुमत के लिए 145 सदस्यों की जरूरत है।

महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और अन्य नेताओं ने राजभवन में रविवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और अवगत कराया कि भाजपा राज्य में सरकार नहीं बनाएगी। प्रेट्र

शिवसेना के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शर्त

संजय राउत जिन दो पार्टियों के भरोसे सरकार बनाने का दावा करते आ रहे हैं, उसमें से एक राकांपा के प्रवक्ता नवाब मलिक ने साफ कर दिया है कि शिवसेना एक साथ दो गठबंधनों में नहीं रह सकती।

वह पहले केंद्र और राज्य हर जगह भाजपा से गठबंधन तोड़ने का फैसला करे, फिर हमसे समर्थन की उम्मीद करे। जबकि कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी महासचिव मल्लिकार्जुन खडगे ने कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिलने की बात कहते हुए किसी को समर्थन देने पर अंतिम निर्णय अपने आलाकमान पर छोड़ दिया है। वहीं, कांग्रेस के कई नेता शिवसेना से दूरी बनाकर रखने के लिए लगातार आगाह करते आ रहे हैं।

विधायकों ने सोनिया गांधी पर छोड़ा गठबंधन का निर्णय पेज>>3

अमेरिका में एच1बी वीजा धारक हजारों भारतीयों को बड़ी राहत

- ऐसे भारतीयों के पति या पत्नी को अमेरिका में काम करने की होगी अनुमति
- अदालत ने ओबामा सरकार के नियम को रद करने से किया इन्कार

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में एच-1बी वीजा पर काम करने वाले हजारों भारतीयों को तात्कालिक राहत मिली है। अमेरिका की अदालत ने ओबामा सरकार के उस नियम को रद करने से इन्कार कर दिया है, जिसके तहत एच-1बी वीजा धारक भारतीय पेशेवरों के पति या पत्नी को वहां काम करने की अनुमति मिली हुई है।

कोलंबिया सर्किट जिले की अपील अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को इस मामले को वापस निचली अदालत में भेज दिया और उससे पूरी तरह से सोच-विचार कर इस पर अंतिम फैसला लेने को कहा। एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियों को विशेष व्यवसाय के लिए विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने का अधिकार मिला है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पूर्ववर्ती बराक ओबामा सरकार के दौरान 2015 में बने एक नियम के तहत कुछ खास श्रेणी के एच-4 वीजा धारकों को अमेरिका में काम करने की अनुमति मिली है, खासतौर पर एच-1बी वीजा धारकों के पति या पत्नी को जो जिन्हें अभी ग्रीन कार्ड नहीं मिला हो। इस नियम का सबसे ज्यादा लाभ खासकर भारतीय महिलाओं को मिलता है, जिनके पति एच-1बी वीजा पर अमेरिका में नौकरी करते हैं। अमेरिका के कर्मचारी इस नियम को खत्म करने की मांग कर रहे हैं और ट्रंप प्रशासन भी उनके साथ है।

अगर यह नियम खत्म हो जाता है तो एच1बी वीजा पर अमेरिका में नौकरी करने वाले भारतीय की पत्नी या पति तब तक वहां नौकरी नहीं कर सकते हैं, जब तक उन्हें ग्रीन कार्ड नहीं मिल जाता।

प्रतीकात्मक फोटो

नीलामी में स्पेक्ट्रम कीमत कम रखने पर विचार

नई दिल्ली : दूरसंचार विभाग (डीओटी) चालू वित्त वर्ष में प्रस्तावित स्पेक्ट्रम नीलामी में बेस प्राइस कम रखने पर विचार कर रहा है ताकि टेलीकॉम कंपनियां नीलामी में हिस्सा ले सकें और उन्हें किफायती दाम में स्पेक्ट्रम मिल सके। सूत्रों का कहना है कि विभाग स्पेक्ट्रम के दाम में 35 प्रतिशत तक की कटौती के बारे में सोच रहा है। एक अधिकारी ने कहा, 'हम अगले वर्ष मार्च से पहले स्पेक्ट्रम नीलामी की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक की योजना के मुताबिक यह नीलामी इसी वित्त वर्ष में होनी है। (पेज–12)

चाहर के जलवे से भारतीय टीम ने जीती टी–20 सीरीज

नई दिल्ली : श्रेयस अय्यर (62) और केएल राहुल (52) की अनुभवी पारियों के बाद गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम ने रविवार को बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी–20 में 30 रनों से जीत दर्ज कर सीरीज 2–1 से जीत ली। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट पर 174 रन बनाए। जवाब में दीपक चाहर (छह) और शिवम दुबे (तीन) ने बांग्लादेश को 19 .2 ओवर में 144 रनों पर समेट दिया। (पेज–14)

बांग्लादेश पर चाहर का प्रहार

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

ऐतिहासिक प्रदर्शन

- तेज गेंदबाज दीपक ने ली हैट्रिक, सात रन पर छह विकेट लेकर टी–20 में किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
- तीसरे टी–20 में भारत ने बांग्लादेश को 30 रनों से हराकर 2–1 से जीती सीरीज

2018 में जब चेन्नई सुपरकिंग्स ने प्रतिबंध के बाद वापसी करते हुए आइपीएल का खिताब अपने नाम किया था, तो महेंद्र सिंह धौनी की सेना में उत्तर प्रदेश के आगरा के युवा तेज गेंदबाज दीपक चाहर (6/7) एक नए यौद्धा के तौर पर उभरे।

बांग्लादेश की टीम जब रविवार को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट संघ स्टेडियम में तीसरे टी-20 में भारतीय टीम के हाथों से जीत खींच रही थी, तब धौनी के इसी शागिर्द चाहर ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बनने के साथ ही इस प्रारूप का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके बांग्लादेश का बोरिया बिस्तर समेट दिया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट पर 174 रन बनाए थे। जवाब में दीपक की दमदार गेंदबाजी की बदौलत बांग्लादेश की टीम 19.2 ओवर में 144 रनों पर सिमट गई और 30 रनों से मुकाबला और सीरीज गंवा बैठी। दिल्ली में हुए पहले टी-20 मुकाबले में हार के बाद अगले दोनों मुकाबले जीतकर भारतीय टीम ने 2-1 से टी-20 सीरीज अपने नाम कर ली।

(विस्तृत खबर पेज–14 पर)

नागपुर में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में हैट्रिक के बाद साथियों के साथ जश्न मनाते दीपक चाहर। (एपी)

पहली हैट्रिक लेने वाले भारतीय

गेंदबाज	प्रारूप
हरभजन सिंह	टेस्ट
चेतन चौहान	वनडे
दीपक चाहर	टी–20

आइपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेलते हैं आगरा के तेज गेंदबाज चाहर

बहुरंगे दिन

सड़क, जल और वायु मार्गों से बेहतर ढंग से जुड़ेगी रामनगरी, एनएचएआइ, जलमार्ग तथा एयरपोर्ट अथारिटी के अलावा पीडब्लूडी की कई परियोजनाओं पर चल रहा है काम

17 हजार करोड़ की परियोजनाओं से बढ़ेगी अयोध्या की कनेक्टिविटी

संजय सिंह, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने भले ही राम मंदिर के निर्माण का रास्ता अब जाकर साफ किया हो, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने रामनगरी के लिए लोगों की पहुंच आसान बनाने का काम कई वर्ष पहले ही प्रारंभ कर दिया था।

अयोध्या को थल, जल और नभ तीनों मार्गों से जोड़ने के लिए दोनों सरकारें अब तक लगभग 17 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रारंभ कर चुकी हैं। एनएचएआइ, जलमार्ग प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथारिटी और रेलवे से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की अलग-अलग एजेंसियां इन परियोजनाओं को पूरा करने में जुटी हुई हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर देश-विदेश के श्रद्धालुओं के लिए राम नगरी की यात्रा अत्यंत सुगम होने की आशा है।

सड़क मार्ग से कनेक्टिविटी : अयोध्या की सड़क मार्ग से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में ही योजना बना ली थी। परिणामस्वरूप सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 2018 में अयोध्या में 5300 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। इनके तहत अयोध्या के चारों तरफ 250 किमी लंबे चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग के 91 किमी खंड को चार लेन में बदलने की शुरुआत की गई थी। इसके लिए उन्होंने 900 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की थी। इसके अलावा अयोध्या से चित्रकूट तक के राम वन गमन मार्ग को नेपाल में सीता जी के जन्मस्थान जनकपुर से जोड़ने के लिए संपर्क मार्ग के निर्माण का भी आगाज हुआ था।

रेल मार्ग से कनेक्टिविटी : अयोध्या की रेलमार्ग से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इनमें दोहरीकरण, विद्युतीकरण तथा स्टेशन विकास की परियोजनाएं शामिल हैं। फरवरी 2018 में तत्कालीन रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने 1100 करोड़ रुपये लागत वाली इन परियोजनाओं की शुरुआत की थी। इनमें फैजाबाद-बाराबंकी लाइन का दोहरीकरण भी शामिल है। तब उन्होंने कहा था कि अयोध्या स्टेशन के विकास पर 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इसे राम मंदिर की तर्ज पर डिजाइन किया जाएगा। फिलहाल अयोध्या और फैजाबाद दोनों स्टेशनों में सुविधाओं के विकास और विस्तार के अतिरिक्त सुंदरीकरण के कार्य चल रहे हैं।

जलमार्ग से कनेक्टिविटी : 2018 में ही गडकरी ने वाराणसी में 7195 करोड़ की जलमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया था। उस वक्त उन्होंने अयोध्या की सरयू नदी को गंगा से जोड़ने का एलान करते हुए कहा था कि सरयू में वाटरपोर्ट का विकास कर गंगा की स्टीमर सेवाओं का विस्तार सरयू नदी तक किया जाएगा, ताकि प्राचीन काल की भांति अयोध्या, वाराणसी और गंगासागर के बीच जल मार्ग के जरिये भी कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके।

तैयार हो रहा है श्रीराम एयरपोर्ट

अयोध्या को वायु सेवाओं से जोड़ने के लिए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर काम कर रही हैं। केंद्र की सलाह पर उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद में पूर्ण एयरपोर्ट के विकास के लिए एयरपोर्ट अथारिटी को एयरस्ट्रिप समेत 100 एकड़ जमीन देने की मंजूरी प्रदान की है। विकसित होने पर इस एयरपोर्ट को श्रीराम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 1000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। फिलहाल अयोध्या तक हवाई पहुंच बढ़ाने में लखनऊ और गोरखपुर एयरपोर्ट की अहम भूमिका है। भविष्य में अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए देश–विदेश के श्रद्धालुओं की रुचि बढ़ेगी। इसे देखते हुए सरकार ने अडानी समूह को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास, विस्तार, आधुनिकीकरण, संचालन एवं प्रबंधन का जिम्मा दिया है। समूह आने वाले पांच वर्षों में इस एयरपोर्ट पर लगभग 3000 करोड़ रुपये खर्च करेगा। अयोध्या को हिंडन एयरपोर्ट से भी कनेक्ट किया जा रहा है जिसके तहत शीघ्र ही गाजियाबाद से फैजाबाद के लिए उड़ानें शुरू करने का प्रस्ताव है।

पूर्व सीईसी टीएन शेषन का निधन

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। 86 वर्षीय शेषन ने रविवार रात करीब 9.30 बजे चेन्नई स्थित घर में अंतिम सांस ली। पिछले कुछ वर्षों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। शेषन को देश में चुनाव व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाने के लिए जाना जाता है।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कुरैशी ने कहा, 'दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि टीएन शेषन का कुछ देर पहले निधन हो गया है। वह एक सच्चे योद्धा थे और अपने बाद के चुनाव आयुक्तों के लिए प्रेरणास्रोत रहे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।' कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी ट्वीट कर शेषन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, 'यह जानकर दुख हुआ कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का चेन्नई में निधन हो गया है। वह पलक्कड़ के विक्टोरिया कॉलेज में मेरे पिता के सहपाठी थे।' तिरुनेल्लई नारायण अय्यर शेषन यानी टीएन शेषन का जन्म 15 दिसंबर, 1932 को केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था।

टीएन शेषन फाइल फोटो

चेन्नई स्थित घर में रविवार रात करीब 9.30 बजे ली अंतिम सांस

1955 बैच के तमिलनाडु कैडर के आइएएस अधिकारी रहे शेषन 12 दिसंबर, 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहे। सरकारी सेवाओं के लिए उन्हें 1996 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभालने से पहले 1989 में वह देश के 18वें कैबिनेट सचिव के पद पर थे। लेकिन तत्कालीन पीएम वीपी सिंह से उनकी नहीं बनीं। सिंह ने उन्हें कैबिनेट सचिव के पद से हटाकर योजना आयोग में भेज दिया था। वीपी सिंह के बाद प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर ने उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था। चंद्रशेखर तब कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहे थे। कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर उन्होंने शेषन को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था।

गुरुपर्व आज, निकाला जाएगा नगर कीर्तन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव पर दिल्ली के विभिन्न गुरुद्वारों में तैयारी पूरी कर ली गई है। रविवार की शाम को बंगला साहिब गुरुद्वारा लाइटों की रोशनी से जगमग दिखा। वहीं, रकाबगंज व शीशगंज गुरुद्वारों को भी विशेष रूप से सजाया जा रहा है। आज शीशगंज गुरुद्वारे से नगर कीर्तन भी निकाला जाएगा जो कि नानक प्याऊ तक जाएगा। इसके अलावा बंगला साहिब गुरुद्वारे में इन दिनों गुरु नानक देव जी पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन चल रहा है। इसमें उनके सिद्धांत व जीवन के बारे में यहां आने वाली संगत को जानकारी दी जा रही है। इसमें करीब 250 पेंटिंग्स को शामिल किया गया है।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) के प्रवक्ता सुदीप सिंह ने कहा कि दिल्ली कमेटी की ओर से सोमवार को साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 550वें पर्व को समर्पित होकर शहाना नगर कीर्तन निकाला जाएगा। इस बार नगर कीर्तन के रूट में थोड़ा बदलाव हुआ है। यह सुबह 10 बजे गुरुद्वारा शीश गंज साहिब से शुरू होकर फव्वारा चौक, कोड़िया पुल, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाएं मुड़कर खारी बावली, सदर बाजार, आजाद मार्केट, रोशन आरा रोड, सब्जी मंडी, घंटाघर होता हुआ शाम को गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहिब में समाप्त होगा।

बंगला साहिब के हेड प्रिस्ट सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह ने कहा कि प्रकाशोत्सव पर दो दिनों तक दीवान सजेगा। इन दो दिनों में लाखों की संख्या में संगत आती है। ऐसे में लोगों की भीड़ को भी व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए गुरुद्वारे में करीब 500 की संख्या में सेवादार मौजूद रहेंगे। 11 व 12 नवंबर को विशेष रूप से लंगर का भी इंतजाम रहेगा। साथ ही यहां पूरा दिन विभिन्न संगत कीर्तन कर नानक जी का स्मरण करेंगी। वहीं, रकाबगंज गुरुद्वारे के मुख्य प्रशासक राम सिंह ने बताया कि प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारे में तैयारियां चल रही हैं। इसमें विशेष लंगर के साथ कीर्तन प्रमुख है।

कई सड़कों पर परिवर्तित रहेगा यातायात

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : गुरु नानक देव जी के 550वें गुरुपर्व के अवसर पर सोमवार को राजधानी में नगर कीर्तन निकाला जाएगा। इस दौरान नगर कीर्तन कई मार्गों से होकर गुजरेगा। इसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। इसके मद्देनजर नगर कीर्तन वाले मार्ग पर कई स्थान पर यातायात परिवर्तित रहेगा। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को सोमवार को नगर कीर्तन वाले मार्ग पर जाने से बचने की सलाह दी है। यातायात पुलिस का कहना है कि यात्री शुरू करने से पहले मार्ग के बारे में पता कर लें।

दूसरी ओर गुरु नानक देव के 550 वें प्रकाशोत्सव और गंगा स्नान के अवसर पर 12 नवंबर को भारत के बड़े बाजारों में से एक सदर बाजार बंद रहेगा। इस बारे में कुतुब रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश यादव और फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र शर्मा ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 11 नवंबर को नगर कीर्तन के स्वागत में बाजार में जगह-जगह पर मंच लगाकर भंडारे का आयोजन किया जाएगा।

गुरुनानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में लाइटों से जगमगाता बंगला साहिब गुरुद्वारा। पारस कुमार

आरएमएल अस्पताल मोती बाग में बनाएगा कैंसर ब्लॉक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्र के अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान व राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल के मोती बाग में प्रस्तावित दूसरे परिसर में कैंसर ब्लॉक का निर्माण होगा। यहां 300 बेड के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के निर्माण की योजना है। एनडीएमसी ने इसके लिए आरएमएल अस्पताल को जमीन देने पर सहमति जताई है। हालांकि एनडीएमसी व आरएमएल अस्पताल प्रशासन के बीच अभी समझौता होना बाकी है, लेकिन अस्पताल प्रशासन मन बना चुका है कि मोती बाग में जमीन मिलने पर इसमें कैंसर के इलाज की सुविधा विकसित की जाएगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी मोती बाग में आरएमएल अस्पताल का दूसरा परिसर (कैंपस) विकसित करने की घोषणा कर चुका है। इसलिए वहां आरएमएल अस्पताल को जगह मिलना तय है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पताल परिसर में 550 बेड के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के निर्माण की आधारशीला रखी है। इसमें यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, न्यूरोलॉजी व न्यूरो सर्जरी से संबंधित बीमारियों के इलाज की सुविधा होगी। इसमें कैंसर की सर्जरी की भी सुविधा होगी।

न्यूज गैलरी

आज होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा स्थगित

नई दिल्ली : देश के कुछ हिस्सों में स्कूल और कॉलेजों के बंद रहने से सोमवार को होने वाली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। सोमवार को इंटरमीडिएट/इंटरमीडिएट (आइपीसी) के पांचवें पेपर एडवांस एकाउंटिंग की परीक्षा होनी थी। हालांकि 13 नवंबर की परीक्षा यथावत होगी। सभी परीक्षार्थी डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉट-आइसीएआइडॉटओआरजी से ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। (जेएनएन)

कंडक्टर बसों में महिलाओं को नहीं दे रहे पिंक टिकट

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई बसों में मुफ्त सफर के तहत महिलाओं को पिंक टिकट नहीं मिल रहे हैं। इस कारण कई बार महिलाओं को जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है। कुछ महिलाओं ने इसे लेकर दिल्ली परिवहन निगम को शिकायत की है। उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली परिवहन निगम ने कंडक्टरों को निर्देश जारी किया है कि सभी महिलाओं को पिंक टिकट उपलब्ध कराएं। यदि कोई कंडक्टर पिंक टिकट देने से मना करना है तो उस पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पिंक टिकट नहीं होने पर महिलाओं को 200 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। (जासं)

सोने की तस्करी में विदेशी महिला व भारतीय गिरफ्तार

नई दिल्ली : आइजीआइ एयरपोर्ट पर कस्टम ने सोने की तस्करी में तजाकिस्तान की महिला व दिल्ली निवासी तस्कर को गिरफ्तार किया है। आइजीआइ एयरपोर्ट कस्टम विभाग के उपायुक्त कलरव मिश्रा ने बताया कि आठ नवंबर को इंडिगो की उड़ान इस्तांबुल से आई थी। इससे उतरी तजाकिस्तानी महिला के बैग की जांच की गई तो उससे 650 ग्राम सोने के गहने बरामद हुए। दूसरा मामला नौ नवंबर का है। थाई एयरवेज की फ्लाइट से ऑकलैंड से बैंकॉक होते हुए आइजीआइ एयरपोर्ट पर भारतीय शख्स उतरा था। उसके सामान की जांच में सोने की चेन, ब्रेसलेट, सोने की अंगूठी, हीरा जड़ित दो सोने की अंगूठी सहित सोने के 12 बिस्कुट बरामद हुए। गहने उसने पहन रखे थे, जबकि सोने के बिस्कुट हैंड बैग में छुपा रखे थे। उससे बरामद 627 .7 ग्राम सोने की कीमत करीब 27 लाख रुपये है। (जासं)

सर्वश्रेष्ठ जूनियर लाइब्रेरी में द श्रीराम स्कूल ने मारी बाजी

नई दिल्ली : 40 मैक्स मूलर मार्ग स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में बंदना सेन लाइब्रेरी पुरस्कार (बीएसएलए) वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ जूनियर लाइब्रेरी के लिए दिल्ली के बसंत विहार स्थित द श्रीराम स्कूल को जबकि सीनियर श्रेणी में मुंबई के द कैथेड्रल व जॉन केनन स्कूल को विजेता घोषित किया गया। (जासं)

धीमी हुई हवा तो बढ़ गया वायु प्रदूषण

चिंताजनक ▶ दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 38 अंक बढ़कर 321 दर्ज किया गया

नोएडा, ग्रेनो और गाजियाबाद में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली में अनुमान से कम चल रही हवा की रफ्तार से राजधानी में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ना शुरू हो गया है। मंगलवार को प्रदूषण का स्तर फिर से बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच सकता है। रविवार को हवा की अधिकतम गति आठ किलोमीटर प्रति घंटा ही रही। पहले 20-25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की उम्मीद जताई गई थी। इसकी वजह से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 38 अंक ऊपर दर्ज किया गया। शनिवार को एक्यूआइ 283 दर्ज किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड (सीपीसीबी) के प्रदूषण मॉनीटरिंग स्टेशन में रविवार को दिल्ली का एक्यूआइ 321 के स्तर पर दर्ज किया गया। यह बहुत ही खराब श्रेणी में आता है।

दिल्ली के साथ एनसीआर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। हवा की गति धीमी होने से स्थिति और खराब होने की आशंका है। प्रदूषण निगरानी एजेंसियों का अनुमान है कि मंगलवार को गंभीर स्थिति में जा सकता है। सोमवार को उत्तर-पश्चिम से हवा चलने और गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। वहीं मंगलवार को यह गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा चलने की वजह से पराली से आने वाला धुआं इंडेक्स बढ़ा देगा। एजेंसियों के अनुसार पंजाब व हरियाणा में 1882 पराली जलाने की घटनाओं का पता चला है।

गहलोत बोले, पड़ोसी राज्य पराली जलाना तुरंत बंद करें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

पर्यावरण मंत्री कैलाश गहलोत ने पड़ोसी राज्यों से पराली जलाने पर तत्काल रोक लगाने का अनुरोध किया है। साथ ही कहा कि पराली के प्रबंधन के लिए राज्य सरकारें किसानों को मशीनें वितरित करने में तेजी लाएं। उन्होंने ये बातें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर के समक्ष समीक्षा बैठक के दौरान कहीं।

केंद्रीय मंत्री द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें गहलोत ने कहा कि पड़ोसी राज्यों को पराली जलाने पर तुरंत रोक लगानी चाहिए, ताकि दिल्ली के लोगों को सर्दी में प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण को भी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों पर धूल कण वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के निर्देश देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने छह नवंबर को अपने आदेश में पराली जलाने से किसानों को दूर रखने के लिए केंद्र को राज्यों के साथ मिलकर तीन महीने के भीतर एक व्यापक योजना तैयार करने का निर्देश दिया था।

कैलाश गहलोत। (फाइल)

जनवरी में फिर लागू हो सकता है ऑड-इवेन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : ऑड-इवेन जनवरी में फिर लागू हो सकता है। हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी क्योंकि उस समय दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू होगी। सरकार का दावा है कि ऑड-इवेन से प्रदूषण घटा है और जाम से भी मुक्ति मिली है। तीसरी बार इसे लागू किया गया है। रविवार को यह योजना लागू नहीं थी और सोमवार व मंगलवार को भी लागू नहीं रहेगी।

दिल्ली में एक बड़ा बदलाव भी जनता देख रही है। लोगों को जाम की समस्या से जूझना नहीं पड़ रहा है। इस बार चालान बहुत कम काटे गए हैं। इस बारे में यातायात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि लोग वाहनों के कागजात पूरे लेकर चल रहे हैं और इस योजना के नियम का उल्लंघन करने के मामले भी कम आ रहे हैं। सबसे पहले इसे 2016 में एक जनवरी से 15 जनवरी तक लागू किया गया था।

दिल्ली सरकार लोगों को यह समझाने में कामयाब रही थी कि यह योजना उन्हीं के लिए लागू की जा रही है। इसके बाद इसी साल 16 से 30 अप्रैल तक लागू किया गया था। हालांकि दूसरी बार पहली बार जितनी सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि इस वक्त स्कूल खुले थे। गर्मी और शादियों के चलते भी कुछ समस्या आई थी।

गिरफ्तारी पर बिगड़ी बात, बेनतीजा रही वकीलों और पुलिस की बैठक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

तीस हजारी मामले में हाई कोर्ट के निर्देश पर पुलिस और वकीलों के बीच समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल ने की, लेकिन यह बैठक बेनतीजा ही समाप्त हो गई। दरअसल, पुलिस और वकील दोनों ही आरोपितों पर कार्रवाई के लिए अड़े हुए थे। ऐसे में अब न्यायिक जांच के आधार पर ही दोषियों पर कार्रवाई तय होगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर रविवार की शाम पुलिस और वकीलों के बीच बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता उपराज्यपाल ने की। बैठक में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही वकीलों के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों से बनी समिति के लोग मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में वकीलों ने दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। वहीं, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की न्यायिक जांच हो रही है। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसे लेकर दोनों पक्षों के आपस में अड़े रहने की वजह से बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल सका। हालांकि, उपराज्यपाल ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद उन्होंने दोनों पक्षों से कहा कि मुद्दे के सुलझाने के प्रयास जारी रखें और मिल बैठकर यदि इस मामले का हल निकल आता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है।

वकील को गोली कैसे लगी, सुबूत तलाशने पहुंची सीएफएसएल की टीम : तीस हजारी कोर्ट परिसर में गत दिनों वकील और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प मामले में पुलिस की स्पेशल इनवेस्टीगेशन टीम (एसआइटी) की जांच जारी है। इसी क्रम में रविवार को सीएफएसएल की टीम तीस हजारी कोर्ट पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने इस बात की जांच की कि वकील को पुलिस की चलाई गोली कैसे लगी। गोली लॉकअप के अंदर चलने के बाद ग्रिल से टकराकर वकील को लगी अथवा उन्हें सीधे मारी गई थी। दरअसल, गोली लगने की घटना का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज में भी ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाई है। लिहाजा जांच के बाद सीएफएसएल की टीम गोली वकील को कैसे लगी इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास कर रही है। उधर, पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को भी तीस हजारी कोर्ट में सुरक्षा कारणों से अंडर ट्रायल कैदी पेश नही होंगे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट जेलों में जाकर कैदियों की सुनवाई करेंगे।

यह है पूरा मामला

दो नवंबर को तीस हजारी कोर्ट परिसर में वकील और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस दौरान गोली लगने से दो वकील घायल हो गए थे। इसके बाद बेकाबू हुए वकीलों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की थी। वहीं, पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज कर दिया था। इस घटना में 20 पुलिसकर्मी और आठ वकीलों को चोट आई थी। इसकी जांच क्राइम ब्रांच की एसआइटी कर रही है। वहीं हाई कोर्ट ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। यह जांच रिपोर्ट छह सप्ताह में कोर्ट को सौंपी जाएंगी।

रैन बसेरों में बेड पर लेटेंगे बेघर, मिलेगा गद्दा व तकिया

वीके शुक्ला, नई दिल्ली

15 नवंबर से सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम हो जाएगा शुरू

रैन बसेरों में रहने वाले बेघरों के लिए दिल्ली सरकार इस बार खास तैयारी कर रही है। बेघरों को बंकर बेड मिलेंगे और उन्हें कंबल के साथ ही गद्दा व तकिया भी उपलब्ध कराया जाएगा। 15 नवंबर से इनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम शुरू हो जाएगा।

दिल्ली सरकार के तहत दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) बेघरों के लिए रैन बसेरा चलाता है। दिल्ली में 193 रैन बसेरे स्थायी रूप से बने हैं, जिनकी क्षमता 17 हजार है। इस समय सात हजार बेघर इनमें रह रहे हैं। पिछले 15 दिनों से करीब दो सौ बेघर और बढ़ गए हैं। रात में ठंड बढ़ने के साथ ही इन लोगों का रैन बसेरों में पहुंचना शुरू हो गया है। इसे देखते हुए टेंटों में 70 रैन बसेरे बनाए जाने का फैसला लिया गया है।

इस बार डूसिब की सभी बेघरों को गद्दे व तकिया उपलब्ध कराने की योजना है। इसके लिए अभी से ही तैयारी शुरू की गई है। इसके अलावा बेघरों को रात्रि विश्राम के लिए इस बार बंकर बेड उपलब्ध कराए जाएंगे। ये बेड डबल होते हैं। एक बेड के बराबर स्थान में ऊपर नीचे दो लोग सो सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्थानों पर फोल्डिंग चारपाई व तख्त भी उपलब्ध कराए जाएंगे। डूसिब ने बेघरों को मदद पहुंचाने के लिए पिछले साल एप लांच किया था, जो चल रहा है। एप को गूगल प्ले स्टोर से डूसिब रैन बसेरा के नाम से डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप पर बेघरों के बारे में कोई भी सूचना दे सकता है। इसके लिए बेघर की फोटो के साथ स्थान के बारे में जानकारी देनी होगी। सूचना मिलते ही बचाव दल वहां पहुंचकर उसे सड़क से उठाकर रैन बसेरे में पहुंचाएगा।

डूसिब ने इस बार 16 बचाव दल बनाए हैं। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछली बार जनवरी में इस एप की शुरुआत की गई थी, जो काफी सफल रहा है। इसके अलावा ठंड बढ़ने पर सप्ताह में दो बार डाक्टर रैन बसेरे में दौरा करेंगे।

हमने मिलकर जीत ली डेंगू से लड़ाई : केजरीवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

डेंगू के खिलाफ दस हफ्ते-दस बजे-दस मिनट अभियान आखिरी रविवार को समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस अभियान की सफलता पर दिल्ली की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दुनिया के सौ देशों में डेंगू का प्रकोप है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ऐसे में दिल्ली ने इस अभियान के जरिये पूरी दुनिया को राह दिखाई है। इस साल अभी तक दिल्ली में डेंगू के सिर्फ 1100 मामले ही सामने आए हैं।

उन्होंने कहा कि आज से दस हफ्ते पहले हम लोगों ने डेंगू के खिलाफ जंग का एलान किया था। आज दसवां हफ्ता है, जब हमने अपने घर की जांच की है। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों ने मिलकर डेंगू पर लड़ाई जीत ली है। 2015 में 15 हजार से ज्यादा केस थे और 60 लोगों की मौत हुई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर यह आंदोलन न बनता तो दिल्ली के लोगों ने हिस्सा न लिया होता। इसमें बहुत सी सेलेब्रिटी और आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, समर्थन किया, आशीर्वाद दिया। दिल्ली के बाहर रह रहे लोगों ने शुभकामनाएं दीं। मैं दिल्ली के लोगों की ओर से उन्हें शुक्रिया अदा करता हूं।

उन्होंने कहा कि देश के अन्य हिस्सों में डेंगू फैला हुआ है। वहां के लोगों ने कहा कि काश हमारे यहां भी इस तरह का अभियान होता। दिल्ली ने रास्ता दिखाया है। अब देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में दिल्ली के दिखाए रास्ते के आधार पर डेंगू के खिलाफ अभियान चलेगा।

क्या किया अभियान के दौरान

- लोगों को जागरूक किया कि घर में जमा साफ पानी को हर सप्ताह बदलें।
- लोगों से कहा गया कि अपने पड़ोसियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें।
- डेंगू का मच्छर साफ पानी में ही पनपता है। इस कारण गमले, कूलर, एसी, टायर आदि में जमा पानी को हर सप्ताह लोगों ने बदला।
- सरकार की अपील पर अपने घर की जांच के बाद दस दोस्तों को फोन कर प्रेरित किया। सभी के सहयोग से ही डेंगू को जड़ से खत्म किया जा सका।

अपने निवास पर रखें पौधे का पानी बदलते अरविंद केजरीवाल। सौजन्य : दिल्ली सरकार

योजना

दिल्ली पर शासन करने वाले अंतिम हिंदू सम्राट के तौर पर भी जाने जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, एएसआइ उनसे संबंधित दस्तावेज और पुरावशेषों को जुटा रहा है

दिल्ली में बनेगा पृथ्वीराज चौहान का संग्रहालय

वीके शुक्ला, नई दिल्ली

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) किला राय पिथौरा में सम्राट पृथ्वीराज चौहान से संबंधित संग्रहालय बनाएगा। संग्रहालय बनाने के लिए इस किले में बनी इमारत का विस्तार किया जाएगा। इस संग्रहालय में रखने के लिए एएसआइ पृथ्वीराज चौहान से संबंधित दस्तावेजों और पुरावशेषों को जुटा रहा है।

राय पिथौरा किले का कायाकल्प 1998 में वाजपेयी सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे जगमोहन मल्होत्रा ने करवाया था। पहले इसके आसपास गंदगी रहती थी। जगमोहन ने अपने प्रयासों से दिल्ली विकास प्राधिकरण को सक्रिय करके विकास योजनाएं बनवाकर इसका संरक्षण और विकास करवाया। उसी समय यहां संरक्षण केंद्र भवन बनाया गया। इसके ऊपर पृथ्वीराज चौहान की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई। मगर संरक्षण केंद्र भवन को अब विस्तार दिया जा रहा है। इस संरक्षण केंद्र के चारों ओर सुंदर हरा भरा पार्क विकसित किया गया है। डीडीए ने 2002 में इस पार्क को विकसित कर के एएसआइ को सौंप दिया था।

लाल कोट किला राय पिथौरा दिल्ली के तौर पर बसा पहला शहर था। जागरण

इसके संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री जगमोहन अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान राजा बने तो उन्होंने लाल कोट का विस्तार करते हुए एक विशाल किला बनवाया। वास्तविकता में लाल कोट किला राय पिथौरा दिल्ली के तौर पर बसा पहला शहर था। तोमर और चौहान वंश के शासकों ने लाल कोट के भीतर अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था जिन्हें मुस्लिम आक्रांताओं ने गिरा दिया और पत्थरों का कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद में इस्तेमाल किया गया। अमीर खुसरो ने भी अनंगपाल के महल का वर्णन किया है। बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन तथा इल्तुतमिश ने राय पिथौरा के किले को ही अपना आवास बनाया था। किला राय पिथौरा को दिल्ली के सात शहरों में प्रथम होने का गौरव हासिल है, जिसका निर्माण 1180-1186 के बीच में हुआ।

पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर शासन करने वाले अंतिम हिंदू सम्राट के तौर पर भी जाने जाते हैं। वे मुस्लिम लुटेरे और हमलावरों के विरुद्ध प्रतिरोध की कहानियों के लोकप्रिय नायक हैं। लाल कोट का विस्तार उन्होंने आसपास पत्थरों की विशाल प्रचीर और द्वार बनाकर करवाया था जिसे राय पिथौरा किले के नाम से जाना गया इसके बारह दरवाजे थे। प्रेस एंक्लेव रोड पर राय पिथौरा किले के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं।

अस्पतालों के नर्सिंग कर्मियों ने दी हड़ताल की चेतावनी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : नर्सिंग कर्मचारियों की पदोन्नति व अन्य मांगों को लेकर दिल्ली नर्सेज फेडरेशन ने आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सोमवार से नर्सिंग कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। फेडरेशन ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो 15 नवंबर के बाद अस्पतालों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों की हड़ताल होने पर मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

फेडरेशन के महासचिव लीलाधर रामचंदानी ने कहा कि पांच सालों में न तो किसी नर्सिंग कर्मचारी को पदोन्नति दी गई है, न ही अस्पतालों में उनके नए पद सृजित किए गए हैं। कई अस्पतालों में नए विभाग व वार्ड खुले हैं, जिससे नर्सिंग कर्मियों पर काम व मरीजों की देखभाल का बोझ बढ़ा है। लंबे समय से वे पदोन्नति व नए पद सृजित करने की मांग कर रहे हैं।

अवैध शराब बिक्री मामले में 52 पुलिस अफसरों पर आंच

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली

पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी में शराब माफिया के साथ मिलकर अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ जनहित याचिका का दिल्ली हाई कोर्ट ने निपटारा कर दिया। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि दिल्ली पुलिस मामले में 52 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच कर रही है। इनमें 37 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है और 15 मामलों में जांच जारी है।

मुख्य पीठ ने निर्देश दिया कि जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए व नंद नगरी इलाके में अवैध शराब की बिक्री रोकी जाए। पीठ ने कहा कि दिल्ली पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है तो अब इसमें आगे निगरानी की जरूरत नहीं है। इससे पहले हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि नंद नगरी इलाके में अवैध शराब बिक्री मामले में कितने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत मिली है और कितने मामले में विभागीय जांच शुरू की गई है? किस तरह के आरोप लगे हैं, क्या कार्रवाई की गई है और कब तक कार्रवाई पूरी हो जाएगी? पीठ ने यह भी पूछा था कि क्या किसी मामले में अफसरों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर विभागीय कार्रवाई की गई? इन सवालों के जवाब में हलफनामा दायर कर दिल्ली पुलिस ने मुख्य पीठ को बताया कि अवैध शराब बिक्री, ड्रग तस्करी और जुआ खेलने के मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कुल 480 शिकायतें मिली हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान 43 पुलिस अधिकारियों को निलंबित रखा गया और 52 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई। अब तक कुल 37 अधिकारियों के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और 15 मामले की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद 13 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी गई।

सोनिया पर छोड़ा गठबंधन का निर्णय

महाराष्ट्र का घमासान ▶ विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार भी आलाकमान को सौंपा

कांग्रेस की राजनीति का सियासी केंद्र बना जयपुर

नरेंद्र शर्मा, जयपुर

महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बीच कांग्रेस की राजनीति का सियासी केंद्र जयपुर हो गया है। जयपुर-दिल्ली हाईवे पर स्थित एक रिसोर्ट में रविवार दोपहर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दिया है। इस संबंध में एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया। ऐसे में अब सोनिया गांधी ही इस पर निर्णय करेंगी।

कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया था। सूत्रों के अनुसार, खड़गे की मौजूदगी में हुई बैठक में विधायक दल के नेता के लिए अशोक चव्हाण का नाम रेस में आगे है। रविवार शाम पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे जयपुर पहुंचे। उन्होंने यहां खड़गे, पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट एवं अशोक चव्हाण के साथ बंद कमरे में बात की और फिर सभी विधायकों से साथ चर्चा की।

शिवसेना को समर्थन देने के पक्ष में कुछ लोग : खड़गे ने 'दैनिक जागरण' से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने हमें विपक्ष के बैठने के लिए जनादेश दिया है। हम जनादेश का सम्मान करते हैं। खड़गे ने कहा कि कुछ लोग शिवसेना को समर्थन देने के पक्ष में है तो कुछ खिलाफ। लेकिन इस बारे में अब अंतिम निर्णय सोनिया गांधी ही करेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी को विपक्ष में

मल्लिकार्जुन खड़गे। फाइल

बैठने का जनादेश मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों को धमका रही थी, लालच दिया जा रहा था। ऐसे में विधायकों को जयपुर लाया गया है।

सियासी संकट के चलते जयपुर भेजे गए सांसद : महाराष्ट्र में सियासी संकट के चलते कांग्रेस के विधायक शुक्रवार देर शाम जयपुर पहुंचे थे। उन्हें जयपुर से 25 किलोमीटर दूर दिल्ली रोड पर ब्यूना विस्ता रिसोर्ट में ठहराया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद प्रतिदिन शाम को रिसोर्ट पहुंचकर विधायकों से मुलाकात करते हैं।

केंद्र के इशारे पर काम कर रहे राज्यपाल : रिसोर्ट के बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के कामकाज पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बिना मौका दिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायकों से मिलेंगे छग के सीएम भूपेश बघेल

नईदुनिया, रायपुर

महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर जारी उठापटक के बीच कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक कौशल की लाभ लेने की सोची है। उन्हें तत्काल जयपुर जाने के लिए कहा गया है, जहां महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक ठहराए गए हैं।

तेजी से बदले सियासी हालात में शिवसेना और एनसीपी के बीच गठबंधन की संभावना बढ़ गई है। अटकले हैं कि कांग्रेस बाहर से समर्थन दे सकती है। हाईकमान के कहने पर

भूपेश बघेल। फाइल

बघेल रविवार रात दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने पार्टी के आला-नेताओं से मुलाकात की। सोमवार दोपहर तीन बजे वह जयपुर जाएंगे। वहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायकों से मिलेंगे।

मातोश्री के बाहर उद्धव को सीएम बनाए जाने का पोस्टर लगाया

मुंबई, एएनआइ : महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को राज्य का मुख्यमंत्री बनाए जाने का आह्वान करने वाला एक पोस्टर मातोश्री के बाहर लगाया गया है। मातोश्री उद्धव ठाकरे का निवास स्थान है। यह पहला मौका नहीं है जब शिवसेना प्रमुख को राज्य का सीएम बनाए जाने का आह्वान करते हुए पोस्टर सामने आया है।

शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा रविवार को लगाए गए पोस्टर में लिखा है कि महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे की जरूरत है। राज्य के शिवसैनिकों की इच्छा है कि शिवसेना का कोई मुख्यमंत्री हो। पांच नवंबर को शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे की तस्वीर के साथ मातोश्री के बाहर भी एक पोस्टर लगाया गया था, जिसमें माई एमएलए, माई मुख्यमंत्री लिखा गया था। बता दें कि शनिवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया था। हालांकि रविवार को राज्यपाल के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने भाजपा द्वारा अकेले सरकार बनाने में सक्षम होने में असमर्थता जता दी।

मोदी सरकार ने चार मेडिकल डिवाइस पार्क को दी मंजूरी

- देश में संभव हो सकेगा मेडिकल उपकरणों का निर्माण
- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में लगेंगे ये पार्क

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने देश में चार मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला मेक इन इंडिया को ध्यान में रखकर लिया गया है। इन पार्क की स्थापना से देश में विश्वस्तरीय मेडिकल उपकरणों का उत्पादन किया जा सकेगा। इन्हें घरेलू बाजार में उचित कीमत पर मुहैया कराया जाएगा। अनुमति हासिल करने वाले पार्कों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में स्थापित होने वाला पार्क शामिल है। हालांकि उत्तराखंड और गुजरात ने भी पार्क स्थापित करने के लिए सरकार से संपर्क किया था।

इन पार्क में मेडिकल उपकरणों के उत्पादन हेतु जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे आयात बिल में कटौती संभव हो सकेगी, साथ ही उच्च गुणवत्ता वाली टेस्टिंग सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। लागत में कमी आएगी। हाल ही में आंध्र के मेडटेक जोन में सुपरकंडक्टिंग मैग्नेटिक कॉयल टेस्टिंग के लिए सीएफसी की स्थापना को मंजूरी दी जा चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक इस समय देश के रिटेल मार्केट में मेडिकल डिवाइस का कारोबार तकरीबन 70 हजार करोड़ रुपये का है। इन उपकरणों के मामले में भारत एशिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। इसके बावजूद भारतीय मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री आकार में बहुत छोटी है। भारत अपनी चिकित्सकीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। देश के विभिन्न राज्यों में मेडिकल डिवाइस पार्क बनने के बाद इस स्थिति को बदलने में मदद मिलेगी।

घर और बाहर महिलाओं की असुरक्षा शर्म की बात : भागवत

नागपुर, आइएएनएस : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने महिलाओं की सुरक्षा में कमी की निंदा करते हुए कहा है कि यह शर्म का विषय है। उन्होंने जीवन के क्षेत्र में महिलाओं के लिए बराबरी और समान अवसर का आह्वान किया।

भागवत ने कहा,'लक्ष्मण को सीता के आभूषणों की पहचान के लिए कहा गया था। जवाब में लक्ष्मण ने कहा था कि वह सिर्फ सीता के पैर के आभूषण को पहचान सकते हैं क्योंकि उन्होंने कभी उनके चेहरे की ओर नहीं देखा था। ऐसी परंपरा होने के बाद भी शर्म की बात है कि हमारी महिलाएं न तो घर में और न ही बाहर सुरक्षित हैं। कैसे हमारी अनगिनत महिलाएं असुरक्षित हैं?'

उन्होंने कहा, परिवार चलाने के साथ ही देश चलाने की भूमिका में महिलाओं के साथ बराबरी के व्यवहार की जरूरत है। संघ प्रमुख ने टिप्पणी की, 'सिर्फ मौका, आजादी और थोड़ी सी मदद कीजिए, वह सब करके दिखाएंगी।'संघ के समर्थन से महिलाओं पर कराया गया अध्ययन नई दिल्ली में 24 सितंबर को जारी किया जा चुका है। संघ से संबद्ध दृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र (डीएसएपीके) द्वारा किए गए अध्ययन को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भागवत ने जारी किया।

जन्मशती पर ठेंगड़ी की सराहना की

नागपुर, प्रेट्र : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी को विनम्र व्यक्ति के रूप में याद किया। भागवत ने कहा कि दिवंगत मजदूर नेता ने अपने सिद्धांतों से समझौता किए बगैर हमेशा दूसरों की परवाह की।

भागवत ने संघ से संबद्ध बीएमएस के संस्थापक की जन्मशती पर एक साल तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत करने वाले कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने कहा, 'दत्तोपंत एक विनम्र व्यक्ति थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता किए बगैर लोगों से संपर्क किया। उन्होंने जो उपदेश दिया उसका पालन किया और लोगों का विश्वास जीता।' संघ प्रमुख ने कहा, ठेंगड़ी एक सजग व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को सही राह दिखाई और हमेशा उनका ध्यान रखा। वर्धा जिले के

नागपुर में दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्मशती समारोह को संबोधित करते मोहन भागवत। प्रेट्र

निवासी ठेंगड़ी स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ के संस्थापक थे।

भगवान राम के बारे में भागवत ने कहा कि कुछ लोग 8000 साल बाद भी उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग राम के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। यह सवाल इसलिए पैदा होता है क्योंकि भगवान राम को देखा नहीं जा सकता।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मंजूर हुई मनोहर कैबिनेट की सूची

बिजेंद्र बंसल, नई दिल्ली

- पांच दिन बाद हो पाई मनोहर लाल की शाह से मुलाकात
- दो घंटे तक चली मुलाकात में नए मंत्रियों के नाम पर लगी मुहर

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। फाइल

हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की सूची पर रविवार दोपहर भाजपा हाईकमान की मुहर लग ही गई। महाराष्ट्र के सियासी संकट और अयोध्या फैसले के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से पांच दिन के इंतजार के बाद मुलाकात हुई। शाह के निवास पर इस बैठक में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा,पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ.अनिज जैन, प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला सहित प्रदेश संगठन मंत्री सुरेश भट्ट भी मौजूद थे। दो घंटे चली यह बैठक दोपहर 1.30 खत्म हुई।

इस दौरान शाह ने मुख्यमंत्री द्वारा पार्टी के प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (संघ) की प्रांतीय टीम से चर्चा करके बनाई मंत्रिमंडल की सूची में शामिल एक-एक विधायक की कार्यक्षमता के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने शाह को गठबंधन सरकार के सहयोगी दल के मुखिया दुष्यंत चौटाला द्वारा उपलब्ध कराई गई मंत्रियों की सूची में शामिल विधायकों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई। सूत्र बताते हैं कि शाह ने मनोहर लाल को पहले ही सरकार में युवा चेहरों और महिलाओं को तरजीह देने का भी आदेश दिया था।

नए मंत्रियों के नाम पर शाह की मुहर लगने के बाद माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री 12 नवंबर को मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं क्योंकि सोमवार वे पंजाब के पठानकोट जाएंगे। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के यहां भी सोमवार को हिसार में कार्यक्रम हैं। राज्यपाल भी चंडीगढ़ में ही हैं। राज्यपाल अपने घर में मांगलिक कार्य में हिस्सा लेने के लिए 16 व 17 नवंबर को बिहार जाएंगे।

संघ की प्रांतीय टीम को भी दी जाएगी नई कैबिनेट की जानकारी : राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के निर्देश पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रांतीय टीम को भी अपनी नई टीम की जानकारी देंगे। जानकारी के अनुसार प्रांत संघ चालक और एक राष्ट्रीय पदाधिकारी के साथ मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही चर्चा करेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री अपने तय कार्यक्रम के तहत रविवार सायं रोहतक से वापस नई दिल्ली स्थित हरियाणा निवास भी पहुंच गए थे। हरियाणा निवास में ही मुख्यमंत्री ने संघ पदाधिकारियों को टिकट वितरण से पहले भाजपा प्रत्याशियों की अंतिम सूची दिखाई थी। जिन विधायकों को मंत्री बनाया जाना है,उनके नाम अभी गोपनीय रखे जा रहे हैं। इन विधायकों को भी मंत्रिमंडल विस्तार से एक दिन पहले ही सूचित किया जाएगा।

झारखंड में रघुवर समेत 30 विधायकों को मिला टिकट, 10 का पत्ता साफ

राज्य ब्यूरो, रांची

- भाजपा ने जारी की 52 उम्मीदवारों की पहली सूची
- लोस चुनाव हारने वाले प्रदेश अध्यक्ष गिलुवा को एक और मौका
- अन्य दलों से आए छह में पांच विधायकों को बनाया उम्मीदवार

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 52 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत 30 विधायकों पर दोबारा भरोसा जताया गया है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव हार चुके प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा को एक और मौका दिया है। वह चक्रधरपुर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि 10 सीटिंग विधायकों के टिकट कट गए हैं। अपने मंत्रियों पर भी भाजपा का भरोसा कायम रहा है। सीपी सिंह, राज पालिवार, नीरा यादव, रणधीर सिंह, लुइस मरांडी, रामचंद्र चंद्रवंशी को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा ने मंत्री सरयू राय, नीलकंठ सिंह मुंडा

रघुवर दास। फाइल

व अमर बाउरी की सीट को फिलहाल होल्ड पर रखा है।

रविवार शाम पांच बजे भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने प्रत्याशियों की घोषणा की। दूसरे दलों को छोड़कर आए विधायकों को पार्टी ने टिकट का तोहफा देकर नवाजा है। इनमें बरही से मनोज यादव, मांडू से जेपी पटेल, भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही, बहरागोड़ा से कुणाल षाडंगी व लातेहार से प्रकाश राम शामिल हैं। आजसू और भाजपा में गठबंधन के पेंच को देखते हुए लोहरदगा सीट को होल्ड पर रखा गया है। झामुमो छोड़कर पार्टी में शामिल हुए शशिभूषण मेहता को पांकी से उम्मीदवार बनाया है।

गठबंधन को लेकर भाजपा व आजसू झुकीं

राज्य ब्यूरो, रांची

- अमित शाह के बुलावे पर दोबारा दिल्ली गए सुदेश महतो
- लोहरदगा, चंदनकियारी आजसू के खाते में ही जाने की संभावना

विधानसभा चुनाव के तहत गठबंधन को लेकर रविवार को भाजपा और आजसू दोनों दल अब थोड़े-थोड़े झुकते नजर आ रहे हैं। शनिवार को अपने दावे की 19 सीटों की लिस्ट दिल्ली में भाजपा को सौंपकर आजसू प्रमुख सुदेश महतो लौटे तो दूसरे दिन उनका भाजपा नेतृत्व की ओर से फिर दिल्ली से बुलावा आ गया। इसके बाद सुदेश दिल्ली रवाना हो गए आजसू पार्टी सोमवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी।

लोहरदगा और चंदनकियारी सीटों के सवाल पर सुदेश ने स्पष्ट रूप से कहा कि सौंपी गई 19 सीटों में ये दोनों सीटें भी शामिल हैं। इन दोनों सीटों समेत कई सीटों पर हमारी प्रबल दावेदारी है। उधर भाजपा द्वारा लोहरदगा और चंदनकियारी सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं होने से संभावना जताई जा रही है कि दोनों सीटें आजसू के खाते में जा सकती हैं। इधर, संसदीय बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, आजसू 14 नवंबर को अपना घोषणापत्र जारी करेगी।

भाजपा से बात नहीं बनी तो झारखंड में अकेले ही लड़ेगी लोजपा : चिराग

राज्य ब्यूरो, पटना

लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में लोजपा की बात भाजपा के साथ नहीं बनती है तो 37 सीटों पर लोजपा अपने बूते ही चुनाव लड़ेगी। पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद चिराग रविवार को पटना पहुंचे। हवाई अड्डा परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोजपा की इच्छा है कि वह एनडीए गठबंधन के तहत झारखंड में भी चुनाव लड़े। आरंभ में लोजपा ने छह सीटों के लिए अपना प्रस्ताव झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को दिया था पर बात नहीं बन पाई। इसके बाद मामला तीन सीटों तक आ गया

चिराग पासवान। फाइल

लेकिन इस पर भी बात अभी तक नहीं बन पाई है। अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिराग ने कहा कि देश ने इस फैसले को सकारात्मक तरीके से स्वीकार किया है।

स्विस बैंक में दर्जनभर भारतीय अकाउंट्स के दावेदार नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्विस बैंक में करीब दर्जनभर भारतीय अकाउंट्स के दावेदार सामने नहीं आए हैं। अगर जल्द इन अकाउंट्स पर दावा नहीं किया गया, तो इनकी पूरी रकम स्विट्जरलैंड सरकार के खाते में चली जाएगी। स्विट्जरलैंड के अधिकारियों के मुताबिक निष्क्रिय अकाउंट्स में कम से कम 10 खाते भारतीयों के हैं।

स्विट्जरलैंड सरकार ने वर्ष 2015 से निष्क्रिय अकाउंट्स की डिटेल सार्वजनिक करनी शुरू की थी। इसका मकसद यह था कि अकाउंट्स के दावेदार उचित दस्तावेज पेश कर इनमें पड़ी राशि का इस्तेमाल करें। अधिकारियों ने कहा कि उस वर्ष करीब 2,600 ऐसे अकाउंट्स सामने आए, जिनमें पड़ी कुल रकम लगभग 300 करोड़ रुपये थी। उस समय उनकी तलाश भी शुरू की गई थी, जिनके करीब 80 लॉकर्स का कोई दावेदार नहीं था।

इन निष्क्रिय अकाउंट्स में से कई ब्रिटेन के शासन काल वाले भारतीयों से संबंधित हैं। लेकिन पिछले छह वर्षों में एक भी भारतीय ने निष्क्रिय अकाउंट पर दावा पेश नहीं किया है। अधिकारियों के मुताबिक कुछ अकाउंट्स में दावा अवधि अगले महीने समाप्त हो जाएगी। शेष की दावा अवधि अगले वर्ष के अंत में समाप्त होने वाली है। दिलचस्प यह है कि इसी अवधि के दौरान पाकिस्तान से संबंधित कुछ अकाउंट्स के दावेदार सामने आए हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के भी कई निष्क्रिय अकाउंट्स के दावेदारों ने दावा पेश कर दिया है।

वर्ष 2015 के बाद से हर वर्ष निष्क्रिय अकाउंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। इन अकाउंट्स की संख्या अब करीब 3,500 पर पहुंच गई है।

आचार संहिता उल्लंघन मामले में आरपीएन सिंह को शो-कॉज

जागरण संवाददाता, रांची : आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमसीएमसी कोषांग के नोडल पदाधिकारी ने यूपीए के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। नोटिस के माध्यम से उन्होंने 48 घंटे के अंदर उनसे जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। एमसीएमसी कोषांग के नोडल पदाधिकारी लोकेश मिश्र ने नोटिस जारी कर यूपीए के झारखंड प्रभारी से पूछा है कि आठ नवंबर को प्रेस क्लब रांची में बिना अनुमति उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस किया था, जो प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अंदर अपना पक्ष स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की जाए।

गौरतलब है कि इससे पहले आरजेडी लोकतांत्रिक पार्टी के खिलाफ भी एफआइआर दर्ज की गई थी। दरअसल, पार्टी के अध्यक्ष की उपस्थिति में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के लिए जिला प्रशासन से इजाजत भी नहीं ली गई थी।

विवादों में घिरी कांग्रेस, अयोध्या के फैसले के बारे में लेख पर नेशनल हेराल्ड ने मांगी माफी

नई दिल्ली, एजेंसियां: शनिवार को अयोध्या मामले में आए फैसले का स्वागत करने वाली कांग्रेस की परेशानी रविवार को पार्टी के ही मुखपत्र नेशनल हेराल्ड ने बढ़ा दी। इसमें एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें फैसले के लिए सर्वोच्च न्यायालय की तुलना पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से की गई। हालांकि जब भाजपा ने इस लेख पर ऐतराज जताते हुए कांग्रेस को घेरा तो अखबार ने माफी मांगने के साथ ही वेबसाइट से यह विवादित लेख हटा लिया।

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन में लेख का हवाला देते हुए कहा, इसमें कहा गया है कि कोर्ट ने वही निर्णय दिया -जैसा शुरुआत से विहिप और भाजपा

- पार्टी के मुख्यपत्र में अयोध्या फैसले के लिए शीर्ष अदालत की तुलना पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से की गई थी

वाले चाहते थे जबकि कोर्ट यह बात मान रहा है गैरकानूनी तरीके से न सिर्फ मस्जिद गिराई गई, बल्कि विवादित स्थल के नीचे मूर्तियां रखी गईं। अयोध्या विवाद पर आया फैसला पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की याद दिलाता है जिसने कथित तौर पर पाक के तत्कालीन गवर्नर जनरल गुलाम मुहम्मद को अवैध कार्य करने की अनुमति दे दी थी। पात्रा ने कहा, यह दुखद है कि इस तरह का लेख अखबार में लिखा गया। भारत की तरह किसी अन्य देश का न्याय तंत्र पारदर्शी नहीं है। इस लेख ने कांग्रेस के दोहरे चरित्र को उजागर किया है।

सोशल मीडिया से लेख का वीडियो लिंक हटाया : अखबार ने एक माफीनामा ट्वीट किया है, जिसमें कहा गया, 'अगर लेख से हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुईं हैं तो हम माफी मांगते हैं। लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं और नेशनल हेराल्ड इनसे सहमत नहीं है।' बाद में लेख से संबंधित लिंक को भी सोशल मीडिया से हटा लिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व द्वारा नाराजगी जताए जाने के बाद यह माफीनामा प्रधान संपादक (एडिटर इन चीफ) द्वारा जारी किया गया है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

राहत की सांस इतनी भी न लीजिए कि राजनीति करना ही मुश्किल हो जाए!

बोले नायडू

संस्कृत भारती विश्व सम्मेलन में उपराष्ट्रपति ने कहा-मैंने स्वयं इसे पढ़ा नहीं है, लेकिन समझता बहुत बेहतर तरीके से हूं, क्योंकि तेलगु और संस्कृत एक-दूसरे के बेहद नजदीक हैं

संस्कृत को बनाएं आम बोलचाल की भाषा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि संस्कृत देश को जोड़ने वाली भाषा है, इसे आम बोलचाल की भाषा बनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने स्वयं इसे पढ़ा नहीं है, लेकिन समझते बहुत बेहतर तरीके से हैं, क्योंकि तेलगु और संस्कृत एक-दूसरे के बेहद नजदीक हैं।

यहां छतरपुर मंदिर परिसर में चल रहे संस्कृत भारती विश्व सम्मेलन के दूसरे दिन रविवार को उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू बतौर मुख्य वक्ता पहुंचे थे। अपने संबोधन में उप राष्ट्रपति ने देशवासियों से संस्कृत भारती के संभाषण आंदोलन में सहयोग करने का आह्वान किया। कहा कि ऋषि-मुनियों ने इस भाषा में अपना ज्ञान समाज को दिया है। सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी समस्याओं का हल मौजूद है। उन्होंने कहा, पांच चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। मां, जन्मभूमि, मातृभाषा, मातृभूमि और गुरु। 10वीं कक्षा तक बच्चों को मातृ भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। नायडू ने कहा कि कुछ लोगों में भ्रम है कि कॉन्वेंट में पढ़े बिना उच्च पद पर

नई दिल्ली के छतरपुर मंदिर परिसर में आयोजित संस्कृतभारती विश्व सम्मेलन में बोलते उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। विपिन शर्मा

नहीं पहुंचा जा सकता है। ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि देश के वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति में से कोई कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा है, यहां तक कि मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी ने तो कॉन्वेंट स्कूल देखा भी नहीं है। फिर भी वह उच्च पद पर पहुंचे हैं। इसलिए संस्कृत को पढ़ने और अपनाने में किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए। वहीं सरकार को भी इसके प्रचार-प्रसार के लिए और कदम उठाने चाहिए। इससे पूर्व उन्होंने विश्व में संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार पर आधारित प्रदर्शनी को देखा और उसे अद्भुत बताया।

जूना पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने कहा कि संस्कृत में कालगणना, सुनने का बोध, शास्त्र, परमपुरुष का ज्ञान और सर्वव्यापी सत्ता इत्यादि सभी का ज्ञान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह सुरेश सोनी, केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, संस्कृत भारती के अध्यक्ष गोपबंधु मिश्र, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, संस्थाओं के अध्यक्ष और अन्य नागरिक उपस्थित थे।

हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सम्मानित : समारोह में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सम्मानित किया गया। जयराम ने कहा कि उपराष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होना उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन है। संस्कृत भारत की ही नहीं, बल्कि विश्व की भाषा बन सकती है। हिमाचल प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जाएगा।

सर्वसम्मत फैसला

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 'भारत में राम मंदिर', 'रामलला', 'अयोध्या फैसला', 'बाबरी मस्जिद' और 'सुप्रीम कोर्ट' शब्द गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए गए। भारत के बाद फैसले को लेकर सबसे ज्यादा सर्च नेपाल में हुए। यहां के जनकपुर में माता सीता की जन्मस्थली है।

मुगल सल्तनत से आजादी के बाद तक अनसुलझा रहा था अयोध्या मसला

नई दिल्ली, प्रेट्र : मुगल सल्तनत, ब्रितानी हुकूमत और फिर स्वतंत्रता के बाद भी दशकों तक अनसुलझा रहा अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद आखिरकार नौ नवंबर, 2019 को उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद समाप्त हो गया। उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को कहा कि भारतीय इतिहास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इस फैसले के साथ ही करीब 130 साल से चले आ रहे इस संवेदनशील मामले पर परदा गिर गया।

अतीत के विवादों का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को गिराकर किया गया है। अदालत ने मुसलमानों की इस दलील को खारिज कर दिया

- उच्चतम न्यायालय के शनिवार के फैसले के साथ विवाद खत्म

कि खाली जमीन पर मस्जिद बनाई गई थी। देश का सामाजिक ताना बाना इस विवाद के चलते बिखरा हुआ था। मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में कराया था। यह पाया गया कि यह स्थल दशकों से निरंतर संघर्ष का एक केंद्र रहा और 1856-57 में, मस्जिद के आसपास के इलाकों में हिंदू और मुसलमानों के बीच कई बार दंगे भड़क उठे।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दो धार्मिक समुदायों के बीच कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए, ब्रिटिश सरकार ने परिसर को भीतरी और बाहरी बरामदे में विभाजित करते हुए छह से सात फुट ऊंची ग्रिल-ईंट की दीवार खड़ी की। भीतरी बरामदे का इस्तेमाल मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए और बाहरी बरामदे का इस्तेमाल हिंदू पूजा के लिए करने लगे।

नेहरू ने दिया था रामलला की प्रतिमा हटाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर अपने फैसले में 1934 के संघर्ष और 1949 के विवाद का भी जिक्र किया है। 1934 में जहां बैरागियों ने मस्जिद के दो गुंबद तोड़ दिए, वहीं 1949 में राम लला की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। बात आगे बढ़ी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रतिमा हटाने का निर्देश दिया, लेकिन अदालत ने इस पर रोक लगा दी।

अदालत ने कहा कि 27 मार्च 1934 को ईद-उल जुहा के दिन अयोध्या के निकट शाहजहांपुर में गोहत्या की घटना से नाराज हनुमान गढ़ी के बैरागी मस्जिद पर चढ़ गए और दो गुंबदों को तोड़ दिया। इतने में पुलिस पहुंच गई और बैरागियों को आगे तोड़फोड़ करने से रोक दिया। लेकिन, दोनों समुदायों के बीच तेजी से तनाव फैल गया। ब्रितानी हुकूमत ने एक मुस्लिम ठेकेदार से गुंबदों का फिर से निर्माण करा दिया। 1934 तक मुसलमान मस्जिद में नियमित नमाज पढ़ते थे। इसके बाद 22 दिसंबर, 1949 तक उन्होंने सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ी।

अदालत ने 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात की उस घटना का भी जिक्र किया, जब लगभग 50-60 हिंदू मस्जिद में घुस गए और वहां राम लला की प्रतिमा स्थापित कर दी। इस घटना ने विवाद को और हवा दी। राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिरीक्षक ने प्रतिमा हटाने का आदेश दिया। लेकिन, इससे तनाव बढ़ने की आशंका से फैजाबाद के जिलाधिकारी ने मस्जिद में ताला लगाकर इमाम को चले जाने को कहा। हिंदुओं को राम लला के दर्शन की इजाजत मिली। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रतिमा को हटाने का निर्देश दिया। लेकिन अदालत ने इस पर रोक लगा दी।

1856-57 के दंगों के पहले साथ-साथ कायम थी हिंदू-मुस्लिम आस्था

अयोध्या मामले के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1856-57 के दंगों से पहले वहां हिंदू और मुस्लिम आस्था साथ-साथ कायम रही। विवादित ढांचा परिसर में दोनों समुदायों के बीच दंगा भड़क गया था। शनिवार को संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से सुनाए गए अपने फैसले में अयोध्या के विवादित स्थल के ऐतिहासिक पहलुओं को भी सामने रखा है।

शीर्ष कोर्ट ने कहा है भारत की अवधारणा जितनी पुरानी है यह उतने ही पुराने विवाद के समाधान की जिम्मेदारी थी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि विवाद से जुड़ी घटनाएं मुगल शासनकाल, ब्रिटिश उपनिवेश शासनकाल और वर्तमान संसदीय काल में फैली हुई हैं। पांच सदस्यीय पीठ ने कहा, 'खास तौर से 1856 से पहले दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते हुए साथ-साथ रह रहे थे। प्रतिरोध ही रक्तपात का कारण बना। अभी स्थल का अलगाव वाला स्वरूप हिंदू और इस्लामिक परंपराओं में अलगाव का मूर्त रूप ले चुका है और जो अपनी पहचान बनाने की ओर अग्रसर है।'

सम्मिलित ढांचे से जुड़ा वास्तविक महत्व दोनों पक्षों के लंबे समय तक इस्तेमाल और प्रकृति का सुबूत है। विवादित स्थल हिंदू और मुस्लिम परंपराओं, विश्वास और रिवाजों के सह-अस्तित्व और आस्था के सम्मिलन का गवाह है।

फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट ने देखे ढेरों साक्ष्य

नई दिल्ली, प्रेट्र : उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने से पहले विवाद से संबंधित ढेर सारे साक्ष्यों का अवलोकन किया। ये साक्ष्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड में लाए गये थे। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 533 दस्तावेज का अवलोकन किया। इनमें धार्मिक ग्रंथ, यात्रा वृत्तांत, पुरातात्विक खोदाई की रिपोर्ट, मस्जिद गिराए जाने से पहले के इस स्थान की तस्वीरों और विवादित स्थल पर मिली कलाकृतियों का अध्ययन शामिल है।

इसके अलावा, संविधान पीठ के सदस्य न्यायाधीशों ने वहां मिले स्तंभों पर उकेरी हुई लिपि के अनुवाद और राजपत्र में शामिल दस्तावेज का भी अध्ययन किया। पीठ ने इस मामले में इतिहासकारों, धार्मिक मामलों के विशेषज्ञों और पुरातत्व विशेषज्ञों सहित 88 से अधिक गवाहों के मौखिक साक्ष्य का भी अवलोकन किया। शीर्ष अदालत ने विवादित स्थल के मालिकाना हक और वहां पूजा-अर्चना की अनुमति के लिए मुकदमा दायर करने वाले चार पक्षकारों के बयानों की भी विवेचना की।

तारीखों में कानूनी विवाद

- इस विवाद में पहला मुकदमा 'राम लला' के भक्त गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी, 1950 को दायर किया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारियों द्वारा उन्हें गर्भगृह में जाने और पूजा करने से रोका जा रहा है।
- 5 दिसंबर, 1950 को परमहंस रामचंद्र दास ने भी पूजा-अर्चना जारी रखने और विवादित ढांचे के मध्य गुंबद के नीचे ही मूर्तियां रखी रहने के लिए मुकदमा दायर किया था, लेकिन उन्होंने 18 सितंबर, 1990 को यह मुकदमा वापस ले लिया।
- निर्मोही अखाड़े ने 1959 में 2.77 एकड़ विवादित स्थल के प्रबंधन के लिए मुकदमा दायर किया।
- 18 दिसंबर, 1961 को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और नौ स्थानीय मुस्लिम अदालत पहुंचे और उसने मस्जिद की विवादित संपत्ति पर मालिकाना हक होने का दावा करते हुए इसे बोर्ड को सौंपने और वहां रखी मूर्तियां हटाने का अनुरोध किया।
- 1 जुलाई, 1989 को 'राम लला विराजमान' की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश देवकीनंदन अग्रवाल और जन्म भूमि ने मुकदमा दायर कर समूची संपत्ति पर अपना दावा किया।
- अयोध्या में 6 दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने की घटना और इसे लेकर देश में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद सारे मुकदमे इलाहाबाद उच्च न्यायालय को निर्णय के लिए सौंप दिए गए थे।

विदेश में रहने वाले भारतीयों ने भी फैसले को सराहा

- शांति और सौहार्द कायम करने के लिए पीएम समेत नेताओं के प्रयासों और बयानों की भी हुई तारीफ
- हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इसे हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों की जीत बताया

वाशिंगटन, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने विवादित ढांचे को गिराने को गैरकानूनी बताते हुए मुस्लिमों को भी मस्जिद के लिए अयोध्या में ही पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस संतुलित फैसले का देश में ही नहीं विदेश में भी सराहना की जा रही है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने इसे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के लिए जीत बताया है।

अमेरिका की भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर थी। फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य दलों के नेताओं के बयानों को भी उसने गंभीरता से सुना। अमेरिका के विदेश विभाग ने प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं के बयानों की सराहना की, जिसमें सभी वर्गों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई थी। वहीं, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (एचएएफ) ने एक बयान में फैसले को हिंदुओं के साथ ही मुस्लिमों की भी जीत बताया। फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डाइएस्पर स्टडीज (एफआइआइडीएस) ने फैसले को संतुलित बताया। संगठन ने कहा कि यह फैसला आगे के अन्य विवादों के लिए न सिर्फ एक नजीर पेश करता है, बल्कि भारतीय न्यायिक प्रणाली की परिपक्वता को भी दर्शाता है। संगठन ने राम मंदिर जैसे संवेदनशील मसले पर संतुलित और ऐतिहासिक फैसला देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार भी जताया है।

एफआइआइडीएस ने देश में शांति और सौहार्द बनाए रखने में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सामाजिक-राजनीतिक संगठनों के साथ ही विभिन्न समुदाय के नेताओं के प्रयासों की भी सराहना की। विश्व हिंदू परिषद के विचारों से प्रभावित अमेरिकी संगठन वर्ल्ड हिंदू काउंसिल फॉर अमेरिका (वीएचपीए) ने भी फैसले की सराहना की है। संगठन ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए वर्षों की दासता, क्रूरता और त्रासदी के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक था।

अयोध्या पर सर्वसम्मति से आने वाला पहला फैसला

पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुनाया सर्वसम्मत फैसला, इससे पहले के तीन फैसलों में न्यायाधीशों के बीच रही थी असहमति

माला दीक्षित • नई दिल्ली

अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने शनिवार को पूरी विवादित जमीन मंदिर बनाने के लिए दिए जाने और मुसलमानों को दूसरी जगह पांच एकड़ जमीन मस्जिद के लिए देने का फैसला सुनाया है। इस फैसले के वैसे तो कानूनी, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर गहरे मायने निकलते हैं, लेकिन इस फैसले की एक सबसे बड़ी खासियत सभी पाचों न्यायाधीशों का एकमत होना भी है। यह पहला मौका है जबकि अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद से जुड़े मामले में फैसला देते समय पीठ के सभी न्यायाधीश एकमत रहे हैं। इससे पहले अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक से तीन फैसले आए, लेकिन हर फैसले में पीठ के न्यायाधीशों के बीच असहमति भी थी।

वैसे तो कानून की तय व्यवस्था में फैसला हमेशा बहुमत का लागू होता है। लेकिन न्यायिक परंपरा और लोकतंत्र में असहमति का भी स्थान है। अयोध्या मामले में सर्वसम्मति का कितना महत्व है यह बात शनिवार को फैसला पढ़ने से पहले मुख्य न्यायाधीश द्वारा कहे गए वाक्य, उनके चेहरे के भावों और फैसले में उसे लिखने वाले किसी एक न्यायाधीश का नाम ऊपर नहीं लिखे जाने से समझी जा सकती है। फैसला पढ़ना शुरू करने से पहले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि फैसला एक है। सर्वसम्मति का है। फैसला देश में शांति और सौहार्द कायम करने वाला है।

शनिवार से पहले अयोध्या विवाद पर तीन और फैसले आ चुके हैं, लेकिन हर फैसले में पीठ के कुछ न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश से असहमत रहे थे। अयोध्या विवाद के मुकदमे का पहला महत्वपूर्ण आयाम अयोध्या में 1993 में केंद्र सरकार का कानून बनाकर 67 एकड़ जमीन अधिगृहीत करना था, जिसे इस्माइल फारुकी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उसी समय तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट को रिफरेंस भेज कर राय मांगी थी कि क्या राम जन्मभूमि के अंदर और बाहरी अहाते में मस्जिद बनने से पहले कोई हिन्दू मंदिर वहां था? ये दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सुने। संविधान पीठ ने राष्ट्रपति के रिफरेंस को गैर जरूरी बताते हुए बिना जवाब दिए वापस कर दिया था। लेकिन जमीन अधिग्रहण की वैधानिकता के मुद्दे पर पांच जजों ने 1994 में तीन-दो के बहुमत से अधिग्रहण को वैध ठहराया था। हालांकि, अधिग्रहण कानून में उन धाराओं को रद कर दिया गया था, जिसमें राम जन्मभूमि के लंबित मुकदमे को समाप्त करने की घोषणा थी। उसके बाद अयोध्या विवाद का लंबित मुकदमा दोबारा चलना शुरू हो गया था। बहुमत का यह फैसला जस्टिस एमएन वेंकेटचलैया, जेएस वर्मा और जीएन रे का था, जबकि जस्टिस एसपी भरूचा और एएम अहमदी ने तीनों जजों की राय से असहमति जताते हुए अलग फैसला दिया था। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण को अवैध ठहराया था। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद में दूसरा महत्वपूर्ण फैसला 30 सितंबर 2010 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का था, जिसमें तीन न्यायाधीशों की पीठ ने दो-एक के बहुमत से फैसले में राम जन्मभूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। इसमें से एक हिस्सा रामलला विराजमान को दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा मुसलमानों को दिए जाने का आदेश था। बहुमत से फैसला देने वाले जस्टिस सुधीर अग्रवाल और एसयू खान ने रामलला का मुकदमा आंशिक रूप से स्वीकार किया था, जबकि निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड का मुकदमा खारिज कर दिया था। दोनों का मुकदमा खारिज करने के बावजूद निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष को जमीन का हिस्सा दिया गया था। पीठ के तीसरे न्यायाधीश जस्टिस धर्मवीर शर्मा ने बहुमत के फैसले से असहमति जताते हुए पूरी राम जन्मभूमि रामलला को दे दी थी। जस्टिस शर्मा ने रामलला का मुकदमा पूरी तरह स्वीकार किया था और बाकी के सभी मुकदमे पूरी तरह खारिज कर दिए थे।

अयोध्या पर सर्वसम्मति से एतिहासिक फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच में शामिल बाएं से जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर • प्रेट्र

अयोध्या के मुकदमे में तीसरा महत्वपूर्ण फैसला 27 सितंबर, 2018 को आया, जिसमें तीन न्यायाधीशों की पीठ ने दो-एक के बहुमत से फैसला दिया था। इस फैसले में दो न्यायाधीशों दीपक मिश्रा और अशोक भूषण ने इस्माइल फारुकी मामले में दिए गए फैसले के एक अंश को बड़ी पीठ को भेजने की मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज कर दी थी। तीसरे न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर ने बहुमत से असहमति जताते हुए इसे बड़ी पीठ को भेजने का आदेश दिया था। इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी कि इस्माइल फारुकी फैसले में दिए गए उस अंश को बड़ी पीठ को भेजा जाए जिसमें कोर्ट ने कहा है कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है।

मुस्लिम पक्ष का कहना था कि उस फैसले में की गई इस टिप्पणी से उनका मुकदमा कमजोर हो जाएगा। हालांकि दो न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया था कि इस्माइल फारुकी फैसले में की गई टिप्पणी जमीन अधिग्रहण के बारे में है। उसका मुख्य मुकदमे और सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपीलों से कोई लेना-देना नहीं है। इस फैसले के बाद ही लंबित 14 अपीलों की मेरिट पर सुनवाई शुरू हुई थी, जिन पर शनिवार को फैसला आया है।

अब किसी पूजा स्थल पर विवाद के लिए तैयार नहीं है देश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अयोध्या फैसले में एक तरफ जहां कोर्ट के अंदर सर्वसम्मति थी वहीं सरकार, न्यायपालिका और आरएसएस की सोच भी एक ही लाइन पर दिखी। अलग-अलग शब्दों में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और और सरसंघचालक मोहन भागवत ने साफ-साफ जताया कि विवादों को पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ने का वक्त है। जाहिर तौर पर यह संकेत सीधे-सीधे मथुरा और काशी से जुड़ता दिखता है। यह मानकर चला जा सकता है कि भविष्य में धार्मिक स्थलों के विवाद की गुंजाइश बहुत कम है।

शनिवार को फैसला पढ़ते वक्त जस्टिस गोगोई ने 1991 के पूजा स्थल कानून का भी उल्लेख किया और यह बताया कि संसद का यह कानून 15 अगस्त, 1947 के दिन जिस भी पूजा स्थल की जो स्थिति है, उसमें किसी धार्मिक बदलाव की इजाजत नहीं देता है। इतना ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े कानूनी मुकदमे भी खत्म माने जाएंगे। केवल राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद को इससे छूट थी। यानी उनकी ओर से सचेत कर दिया गया है कि कोर्ट अब ऐसे किसी मुद्दे को सुनने के लिए तैयार नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

अमन

- प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और सरसंघचालक का छिपा संदेश
- विवादों को पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ने का वक्त

सरसंघचालक मोहन भागवत

दोपहर में सरसंघचालक मोहन भागवत ने अपने बयान में साफ किया कि संघ आंदोलन नहीं करता है, राम मंदिर आंदोलन में जुड़ना एक अपवाद था। जाहिर है कि संघ किसी और आंदोलन की नहीं सोच रहा है। शाम को देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने बहुत बारीकी से यह संदेश दे दिया कि अब देश में कटुता के लिए स्थान नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अब नए भारत के निर्माण में सबको जुटना है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और करतारपुर कॉरिडोर का उल्लेख करते हुए कहा कि आज के दिन का संदेश जोड़ने का है। जुड़ने का है और मिलकर जीने का है। सभी कटुता को तिलांजलि देने का वक्त है। नए भारत में भय, कटुता और नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होगा।

राम मंदिर के रूप में सबसे बड़े धार्मिक विवाद के निपटने के बाद कोई भी अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता है। देश का मुस्लिम वर्ग भी मंदिर निर्माण के फैसले को अपना चुका है। साधु संत समाज की ओर से भले ही मथुरा और काशी जैसे मुद्दे उठाए जा सकते हैं, लेकिन उसे भाजपा या संघ से खुला समर्थन मिले इसकी गुंजाइश नहीं है। भाजपा के घोषणापत्र में राम मंदिर 1991 से शामिल रहा है, लेकिन कभी भी मथुरा और काशी का जिक्र नहीं हुआ है।

फैसला देने वाले पांच न्यायाधीशों की सुरक्षा बढ़ाई गई

नई दिल्ली, प्रेट्र: अति संवेदनशील राम जन्मभूमि विवाद मामले में फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है, लेकिन अब न्यायाधीशों की सुरक्षा में एस्कार्ट टीमों को भी लगाया गया है। साथ ही उनके आवास पर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए हैं। यह जानकारी अधिकारियों ने रविवार को दी।

शनिवार को फैसला सुनाए जाने के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, नामित मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि माननीय न्यायाधीशों को किसी प्रकार का कोई खास खतरा नहीं है, लेकिन एहतियातन सुरक्षा को बढ़ाया गया है।

बदला रुख

अयोध्या पर अब 'थर्ड अंपायर' की भूमिका छोड़ रहे विपक्षी दल

दलों के समक्ष अपना रुख बदलने की चुनौती, कांग्रेस समेत अधिकांश विपक्षी दल दे रहे नैरेटिव बदलने का संकेत

संजय मिश्र • नई दिल्ली

आयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विपक्षी पार्टियां भले ही ध्रुवीकरण की सियासत थमने के लिहाज से निर्णायक मान रही हैं, लेकिन इन दलों के लिए राह बहुत आसान नहीं है। इस मामले में अब तक 'थर्ड अंपायर' की भूमिका निभाते रहे विपक्षी दलों के लिए तीन दशक के लबादे से बाहर आना बड़ी चुनौती होगी। संभवतः इसीलिए फैसले के तुरंत बाद से कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अपने अनुरूप राजनीतिक विमर्श की दशा-दिशा में जरूरी बदलाव का संकेत देने लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) इसका अपवाद जरूर है जिसने पश्चिम बंगाल की अपनी सियासी चुनौतियों के मद्देनजर फैसले पर अब तक चुप्पी साध रखी है।

विपक्षी पार्टियों को इस बात का बखूबी अहसास है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर किसी तरह के किंतु-परंतु को संघ-भाजपा बड़ा सियासी हथियार बना सकते हैं। इसीलिए अधिकांश दलों ने फैसले का सम्मान करते हुए इसे स्वीकार करने की अपील करने में देर नहीं लगाई। प्रतिक्रिया देने में कांग्रेस के अलावा हिंदी पट्टी की पार्टियों मसलन समाजवादी पार्टी, राजद और बसपा की तेजी से जाहिर है कि नई परिस्थितियों के हिसाब से विपक्षी दल इस मुद्दे पर अपने राजनीतिक विमर्श को नए सिरे से गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

वैसे भी चाहे कांग्रेस हो या सपा-बसपा या राजद इन पार्टियों के राजनीतिक उत्थान और ढलान में अयोध्या मुद्दे की बड़ी भूमिका रही है। भाजपा-संघ के अलावा अयोध्या विवाद से सबसे ज्यादा यही पार्टियां जुड़ी भी रही थीं। अयोध्या में 1986 में मंदिर का ताला खुलवाने से लेकर 1989 में शिला-पूजन का

अखिलेश यादव

तेजस्वी यादव

काम कांग्रेस की सरकार में हुआ तो 1992 में विवादित ढांचे का विध्वंस भी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के वक्त हुआ। इस विध्वंस के बाद राव सरकार ने दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा भी की थी। हालांकि यह अलग बात है कि न ही राव और न ही यूपीए की दोनों सरकारों में ऐसी कोई कोशिश की गई।

छिन गई थी कांग्रेस की राजनीतिक जमीन : मंदिर आंदोलन के दो सबसे प्रमुख केंद्र रहे उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस की राजनीतिक जमीन ध्वस्त होने की सबसे बड़ी वजह यही मुद्दा था। ऐसे में अदालत के फैसले से विमर्श बदलने का मौका मिलते ही 1992 में दोबारा मस्जिद की बात करने वाली पार्टी ने राममंदिर निर्माण की हिमायत कर दी। बीते पांच साल से नरम हिंदुत्व के संकेत दे रही कांग्रेस की राजनीतिक विमर्श को बदलने की बेचैनी इसी से समझी जा सकती है कि जहां बाकी विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की अपील की है। वहीं कांग्रेस ने इससे आगे जाकर यह कहने से गुरेज नहीं किया कि अब अदालत के फैसले के बाद भगवान श्रीराम का मंदिर बनना चाहिए।

सपा, बसपा और राजद भी बदल रहे रुख : हिंदी पट्टी के राज्यों में अयोध्या मसले की संवेदनशीलता का तकाजा ही है कि इस पर संघ-भाजपा के खिलाफ सीधा मोर्चा लेने वाले मुलायम सिंह यादव की पार्टी सपा हो या बिहार में लालू प्रसाद की राजद दोनों दलों ने फैसले का सम्मान करने की घोषणा में देर नहीं लगाई। दिलचस्प यह है कि मुलायम और लालू की जगह इन दोनों के सियासी उत्तराधिकारी पुत्रों ने खुद इसका एलान किया। अखिलेश यादव ने फैसले को सबके लिए बाध्यकारी बताते हुए उम्मीद जताई कि इसे देश में कानून का शासन और प्रजातंत्र सुदृढ़ होगा। सपा का यह रुख उसके सियासी नैरेटिव से बिल्कुल जुदा है। तेजस्वी यादव ने फैसले के सम्मान की अपील के साथ उम्मीद जताई कि अब सभी दल जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देंगे। आडवाणी को मंदिर आंदोलन में गिरफ्तार करने वाले लालू प्रसाद की पार्टी का यह रुख भी विमर्श में बदलाव के संकेत दे रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने संविधान का हवाला देते हुए फैसले का सम्मान करने की बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में उम्मीदों का सूरज निकला। लंबे समय से मंदिर का सपना संजोए श्रद्धालुओं के चेहरों पर खुशी देखते बन रही थी। उत्साह मानो किसी उत्सव जैसा था। अपने आराध्य भगवान श्रीराम के भव्य-दिव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद अयोध्या में जैसे रौनक ही आ गई...

अयोध्या लाइव

आज हमारे राम सीखचों से आजाद हो गए। जो कार्य वर्षों पहले हो जाना चाहिए था, वह अब हुआ। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। अब हमारे राम आजाद हैं। इंतजार सिर्फ मंदिर के निर्माण का है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जितना स्वागत किया जाए, कम है। मंदिर जल्द बने यही कामना है।

– **लता मराठी**, रायगढ़पाली, महाराष्ट्र

अच्छा फैसला आया है, यह फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था। वर्षों से राम को कैद कर रखा गया था। हम लोग जब भी अयोध्या आते थे, भगवान को कैद में देख मन दुखी हो उठता था। कोर्ट के फैसले ने हम सभी की इच्छा पूरी कर दी। इस प्रयास के लिए कोर्ट का जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है।

– **चिमनभाई पटेल, खेड़ा**, गुजरात

अयोध्या बैकुंठ से उतर कर आई है, इसके साथ कोई अनहोनी नहीं हो सकती है। स्वर्ग नगरी जिनकी है, आज हम उन्हीं के दर्शन करने आए हैं। इस फैसले के हम सभी गवाह बने हैं। इसी उम्मीद से जा रहे हैं कि अगली बार जब दर्शन को आए तो यहां भगवान राम का भव्य मंदिर हो।

– **विद्या शर्मा, वसंत गांव**, दिल्ली

घर वाले डांट रहे थे कि अयोध्या मत जाओ। लड़ झगड़ कर हम सभी यहां पहुंचे हैं। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद हम यहां से बहुत बड़ी खुशी लेकर जा रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब हमारे राम भव्य मंदिर में बैठेंगे। हमारे लिए यह ऐतिहासिक दिन है, फैसले की जितनी प्रशंसा की जाए कम है।

– **वैष्णो देवी, गजनसूमड़ बॉर्डर**, जम्मू

अतिसय रगड़ करय जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। लाख-लाख धन्यवाद, कोई आशा भी नहीं कर सकता था कि इतना बड़ा फैसला आएगा। पूरे नेपाल का हिंदू खुशियां मना रहा है। बहुत लंबे समय बाद इस फैसले से इतनी खुशी मिली है कि उसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है।

– **सुकई यादव, रूपन देही लुंबनी**, नेपाल

खुशी का दिन है। सपना साकार होने को है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला और तारीख हमारे जीवन के लिए यादगार रहेगी। आज अयोध्या में अपने प्रभु के दर्शन कर हम धन्य हो गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है।

–**अनीता देवी, समस्ती पुर**, बिहार

साक्षात्कार

फैसले के बाद सभी आनंद में हैं : नृत्यगोपाल दास

महंत नृत्यगोपाल दास उन चुनिंदा लोगों में हैं, जिनका राम मंदिर से सरोकार शीर्ष धर्माचार्य के रूप में ही नहीं, बल्कि मंदिर आंदोलन के नायक की भी भूमिका में रहा है। वह उस पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं, जिसने साढ़े तीन दशक पूर्व मंदिर आंदोलन का आगाज किया और समय-समय पर आंदोलन की अगुआई की। आंदोलन के साथ महंत नृत्यगोपाल दास भी अनेक मोड़ से गुजरे। कई बार आंदोलन की सफलता को लेकर संशय भी पैदा हुआ, पर महंत नृत्यगोपाल दास अपने मिजाज के अनुरूप पूरी दृढ़ता से रामजन्मभूमि की मुक्ति के साथ मंदिर निर्माण का स्वप्न साकार करने में लगे रहे। आज जब यह आंदोलन अंजाम तक पहुंच गया है, वह आनंद से विभोर हैं। **महंत नृत्यगोपाल दास** से दैनिक जागरण के **रमाशरण अवस्थी** ने विस्तार से बात की। प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश :

● सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कैसा लग रहा है?

-हम रामलला पर भरोसा करने वाले लोग हैं और हमारा विश्वास कभी विचलित नहीं हुआ। कोर्ट का फैसला आने के बाद धर्म और सत्य की जीत का विश्वास पुख्ता हुआ है।

● रामलला के भव्य मंदिर की राह प्रशस्त हुई है। यह कब तक फलीभूत होगी?

-ऐसा प्रतीत होता है कि माह-दो माह में आवश्यक औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी और इसी के साथ मंदिर निर्माण की शुरुआत होगी। फिर बनते अधिक देर नहीं लगेगी। यह मंदिर करोड़ों रामभक्तों की आस्था का केंद्र है और उनका हरसंभव सहयोग तमाम प्रकार के संसाधनों की कोई कमी नहीं रहने देगा।

● मंदिर निर्माण के लिए रामजन्मभूमि न्यास तीन दशक से तैयारी कर रहा है, आज यह किस दौर में है?

-हमारी तैयारी पूरी है। प्रस्तावित मंदिर के लिए दो तिहाई पत्थरों की तराशी कर ली गई है। प्रथम तल का काम पूरा हो चुका है। औपचारिकता पूरी होते ही हम रामजन्मभूमि पर मंदिर निर्माण शुरू करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए वहां पत्थरों को मात्र ले जाने का काम बाकी है।

● सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण के लिए शासकीय न्यास के गठन का आदेश दिया है। ऐसे में रामजन्मभूमि न्यास की क्या भूमिका होगी?

-संभावित शासकीय न्यास और रामजन्मभूमि न्यास को अलग-अलग कर देखे जाने की जरूरत नहीं है और न्यास ने मंदिर निर्माण की जो तैयारी कर रखी है, उसे पूर्णता मिलेगी।

● रामजन्मभूमि मुक्ति का प्रयास 491 वर्ष पूर्व वहां बना मंदिर तोड़े जाने के साथ ही शुरू हो गया था। आज जब यह चिर प्रयास फलीभूत हुआ है, तो श्रेय किसे देंगे?

-न्यायालय ने जो किया, वह अभूतपूर्व है। 30 वर्ष पूर्व राममंदिर के लिए आंदोलन की शुरुआत करने वाला विहिप नेतृत्व भी कम अहम नहीं है पर निर्णायक प्रयास करने वाली अदालत के अलावा संतों का आशीर्वाद वह ताकत बना, जिसके बूते मंदिर का आग्रह समाधान तक तब्दील होने में कामयाब हुआ।

● आंदोलन के कई शिल्पी आज नहीं हैं, आंदोलन की सफलता के अवसर पर उन्हें किस रूप में याद करेंगे?

-आज सभी आनंद में हैं, उनकी आत्मा भी जहां होगी, आनंदित होगी।

● इस अहम अवसर पर देश के बारे में आपका क्या संदेश है?

-सर्वे भवंतु सुखिनः/ सर्वे संतु निरामयाः/ सर्वे भद्राणि पश्यंतु/ मा कश्चित दुख भाग्भवेत। (सभी सुखी हों, सभी रोगमुक्त हों, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी न बने)।

छंटता दिखा संशय का कुहासा

अयोध्या में जारी रहा आस्था का अविरल प्रवाह आशंकाओं पर भारी उत्साह

राजीव दीक्षित ●

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संयम बरत कर यूं तो रामनगरी शनिवार को हुई अग्निपरीक्षा में खरी साबित हो चुकी थी लेकिन रविवार को जब सरयू तट पर भोर हुई तो अयोध्या पर छाया संशय, संदेह और आशंकाओं का रहा-सहा कुहासा भी छंट गया। पौ फटने के साथ सरयू तट की ओर बढ़ते स्नानार्थियों के कदम आस्था और उत्साह के अविरल आवेग की अनुभूति करा रहे हैं। सूर्योदय की दस्तक देती पूरब दिशा में आकाश पर छायी मद्धिम लालिमा मानो अयोध्या में नये सवेरे का संदेश दे रही हो।

'आरती लिहिन सूरज भगवान जी
कथी के दियरा कथिया के बाती
सोने के दियरा कपूरा के बाती
गाय के घियवा चुवाय के हो
बरबा सारी राती।'

अरुणोदय की इस मोहक छटा के बीच वातावरण में गुंजित हो रहे स्वर बरबस ध्यान खींचते हैं। बिहार के आरा जिले से आयीं मुन्नी देवी, धनभारत देवी, बिजला कुंवर और कमला देवी सरयू में स्नान के बाद जलते हुए दीये को हवा में गोल-गोल घुमाकर पूरब के क्षितिज पर उगते सूर्य की आरती कर रही हैं। चंद कदमों की दूरी पर सरयू की आरती के लिए पुरोहित राजा महाराज नदी के जल में दीपदान मांज रहे हैं। प्रशासन की सख्ती से भले ही श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई हो लेकिन सरयू में आस्थाजनित जिजीविषा का प्रवाह भी दिखा। सरयू स्नान कर एक व्यक्ति स्नान कर बैसाखियों के सहारे नदी से बाहर आ रहा है। यह बेगूसराय के मुकेश सिंह हैं जिनका बायां पैर पोलियोग्रस्त है। वे फैसले से काफी खुश थे। बीते 14 वर्षों से अनवरत विभिन्न पर्वों पर अयोध्या आ रहे मुकेश से सवाल हुआ कौन देता है आपको यह हौसला? जवाब मिला, 'राम जी और सरयू मैया मुझे हिम्मत देती हैं।'

अयोध्या की नई सुबह : क्षितिज पर लालिमा छाई तो सरयू सुनहरे रंग में नहाई नजर आई। उदित होते भुवन भास्कर की रश्मियों के स्पर्श से सरयू भी मुदित है। अंजुलियों से गिरते जल के साथ सरयू भी मानो उम्मीदों के सूरज का आभार जता रही है ● हृदेश चंदेल

ठाकुर जी हैं तो क्या चिंता है

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से श्रद्धालुओं के मन में उपजी आशंकाएं भी मानो सरयू के प्रवाह में बह गई हों। गोरखपुर से आयीं कालिंदी देवी नहाने से पहले पुरोहित राजेंद्र प्रसाद पांडेय की चौकी के बगल में अपना झोला रखते हुए साथ आयीं पड़ोसन राम गति देवी से कहती हैं, 'घर पर सब घबरा गईल बाटे।' फिर पुरोहित से पूछती हैं 'पंडित जी सब ठीक रही ना।' पुरोहित उन्हें आश्वस्त करते हैं 'अब कुछ नहीं होगा, भगवान राम ने सब ठीक कर दिया है।' स्नान करके लौट रहीं पूनम सिन्हा के कान में ये शब्द गूंजते हैं तो वह ठिठक जाती हैं और कालिंदी देवी से मुखातिब होकर कहती हैं 'ठाकुर जी हैं तो क्या चिंता है?' फिर बोलीं, 'सबहिं नचावत राम गोसाईं।' बताया कि बिहार के गया जिले से अकेले आयी हैं। फिर जैसे भूल सुधार करते हुए कहा 'हम नहीं आते हैं, ठाकुर जी बुलाते हैं।'

राम जी की प्यारी राजधानी लागे...

संत तुलसी दास घाट से राम की पैड़ी होकर राम घाट पहुंचते ही कानों में भजन की मधुर स्वर लहरियां गूंजती हैं-

'राम जी की प्यारी राजधानी लागे
मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे'

घाट की सीढ़ियों पर हारमोनियम, तबला और मंजीरा बजाते युवकों की भजन मंडली को घेरकर बैठे स्नानार्थी तालियां बजाकर झूमते हुए भावविभोर हैं। स्नान के बाद लुटिया में सरयू का जल भरकर नागेश्वरनाथ के जलाभिषेक के लिए जाते श्रद्धालु आस्था से अनुप्राणित वातावरण में आराधना के रंग भर रहे हैं।

नई सुबह का स्वागत, फिर सजी प्रवचन की चौपाल

रघुवरशरण ●

रविवार सुबह के नौ बजे हैं। यही वह समय होता है जब संत-श्रद्धालु अभी सरयू स्नान से लौट रहे होते हैं। तब तक रामनगरी के प्राचीन तुलसीबारी मुहल्ले के विश्व शांति आश्रम में प्रवचन की चौपाल सज गई।

अंतरराष्ट्रीय ख्याति के कथाव्यास आचार्य लक्ष्मणदास भगवान राम और अयोध्या की महत्ता का राग छेड़ चुके हैं। वह रामकथा के प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस के इस सूत्र का विवेचन कर रहे होते हैं, 'अवध प्रभाव जान तब प्राणी/ जब उर बसहिं राम धनु पानी।' यानी अयोध्या का प्रभाव अनुपम है, पर उसे ऐसे भक्त की दृष्टि से समझा जा सकता है, जिसके हृदय में धनुर्धारी राम बसते हों। यही आध्यात्मिक आभा युवा मयंक शर्मा को हरियाणा के सिरसा से रामनगरी तक खींच लाई है। वह कहते हैं कि रामलला का भव्य मंदिर हमें उन जड़ों से जोड़ेगा, जिससे हम युगों से सांस्कृतिक मूल्यों का संस्कार पाते रहे हैं।

जड़ों और मूल्यों से सरोकार की यही ललक गुजरात के साबरकांठा की बुजुर्ग ललिता बेन को रामलला के दर्शन मार्ग पर आगे बढ़ा रही होती है। वह कहती हैं, मैं पूर्व में दो बार रामलला के दर्शन कर चुकी हूं। आगे महंत रामशरणदास से भेंट होती है। उनका आश्रम रंगमहल रामलला के दर्शन मार्ग पर ही है। वह रामलला के दर्शनार्थियों के इस सवाल से प्रायः मुखातिब होते रहे हैं कि रामलला का मंदिर कब बनेगा और स्वयं मंदिर आंदोलन से प्रभावी जुड़ाव के बावजूद इस सवाल का जवाब देने में असमर्थ होते रहे हैं। रविवार को वह पूरे विश्वास में थे, पर उनसे यह सवाल पूछने वाला कोई नहीं था। यानी रामलला के प्रतिदिन औसतन दस हजार और साल भर में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का विश्वास पुख्ता हो चला है।

रामशरणदास कहते हैं, मंदिर निर्माण का मार्ग इतनी शांति और सौहार्द से प्रशस्त होगा, यह तो सपने में भी नहीं सोचा था और अब तो यह स्वप्न साकार भी हो चुका है। रामलला की चौखट से लौटते हुए पूजन के बर्तन की दुकान संचालित करने वाले किंचित मायूस राघवेंद्र तिवारी से भेंट होती है। वे मंगलवार को पड़ रहे कार्तिक पूर्णिमा मेला फीका होने की आशंका से ग्रस्त होते हैं, पर अगले पल इस परिकल्पना से चमत्कृत होते हैं कि जल्दी ही रामलला की ओर श्रद्धालुओं का ऐसा प्रवाह उमड़ेगा, जिनके लिए स्थानीय बाजार ही नहीं, पूरी रामनगरी अयोध्या को अपना आंचल बहुत बड़ा करना होगा।

रामजन्मभूमि की ओर जाते दर्जनों मार्ग अब भी बैरियर और पुलिस की चेकिंग से बाधित हैं, पर उनके लिए वर्तमान के अवरोधों से अनंत गुना बड़ी वह उम्मीद है, जिसके सूत्र रामनगरी को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर चमकाने के साथ स्थानीय लोगों का चमकदार भविष्य बनाने से जुड़ते हैं। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा।

यूं तो मैं पहली बार आया हूं। रामलला की मुक्ति के लिए अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा है, यह भी सुनता रहा पर अदालत के निर्णय के बाद रामलला का दर्शन कर जीवन में अपूर्व धन्यता आई है।

–**प्रेमकुमार**, हैदराबाद

रामलला के बारे में खूब सुनती आई थी। आज ऐतिहासिक अवसर पर उनका दर्शन हमारे लिए किसी महान धरोहर से कम नहीं।

– **विजयलक्ष्मी**, हैदराबाद

बहुत अच्छा लग रहा है। रामलला लंबे समय से अस्थायी मंदिर में थे और अब वह भव्य मंदिर में विराजमान होंगे।

– **राधा**, हैदराबाद

मैं गाइड हूं। मेरा काम लोगों को पर्यटन कराना है पर आज रामलला के दर्शन के साथ-साथ स्वयं के भी पर्यटक होने का एहसास हुआ। –**मुन्ना भाई**, हैदराबाद

मैं रामलला का आभारी हूं। जिनकी प्रेरणा से उस दिन अयोध्या आने का अवसर मिला, जब रामलला स्वयं सदियों बाद मुक्त हुए हैं। फैसले के बाद आना सुखद अनुभव रहा।

–**वेंकटरत्न**, हैदराबाद

मेरे लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि हजारों किलोमीटर का सफर तय कर मैं उस दिन अयोध्या पहुंची, जो रामलला के लिए नई सुबह है।

– **आदिलक्ष्मी**, हैदराबाद

रामलला का भव्य मंदिर बनना ही चाहिए और अब यह संभावना प्रशस्त हुई है। इस दिन रामलला के दर्शन का संयोग अपूर्व है।

– **विकास चतुर्वेदी**, रायबरेली, उत्तर प्रदेश

खाकी वर्दीधारी भी डुबकी लगाने को दिखे लालायित

रामनगरी में चप्पे-चप्पे पर मौजूद खाकी वर्दीधारी भी अयोध्या के पांव पखारती पुण्यदायिनी सरयू में डुबकी लगाने को लालायित दिखे। सरयू तट पर साथी राम नरेश तिवारी और आरएन पांडेय के साथ स्नान के लिए आये उप्र प्रदेश पुलिस के सिपाही चक्रधर पांडेय कहते हैं 'कार्तिक माह में अयोध्या में ड्यूटी करने आये हैं तो सरयू स्नान का पुण्य क्यों न कमाएं।'

सद्भाव की बंदगी

आस्था कभी रुकती नहीं, न ही बंधनों में सिमटती है। यह जब सारे बंधनों को तोड़ उमड़ती है तो नई मिसाल बनती है। ऐसा ही नजारा अयोध्या में था। रविवार को मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला में रखी शिलाओं पर माथा टेक कर भाव विभोर होने वालों में हर धर्म-वर्ग के लोग शामिल थे। सद्भाव की बंदगी का यह नजारा देश में बदलते माहौल का पैगाम ही तो है... ● प्रेट्र

रामलला के दर्शन कर... धन्य-धन्य भाग्य हमारे

रविप्रकाश श्रीवास्तव ●

रामलला के दर्शन मार्ग पर चहल-पहल थोड़ा कम है, लेकिन गलियां सूनी नहीं हैं। दुकानें खुली हैं और रामधुन वातावरण में घुली है। दर्शन मार्ग कड़े पहरे में है। सुबह के करीब साढ़े सात बजे हैं। श्रद्धालुओं की आवाजाही शनिवार की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा है। हनुमानगढ़ी से होते हुए रामलला के दर्शनार्थियों का जत्था भजन गाते चला जा रहा है।

दर्शन अवधि शुरू हुए आधा घंटा बीत चुका है। सुरक्षाकर्मी सतर्क हैं कि कहीं से प्रतिबंधित वस्तुएं क्षेत्र में न पहुंचे। मीडिया कर्मियों के कैमरे भी इस क्षेत्र में मना हैं। अमावा मंदिर के बाद दर्शन के लिए कतार लग जाती है। कुछ श्रद्धालु दर्शन कर बाहर निकलते नजर आते हैं। पूछने पर पता चला कि ये पहली पांत के श्रद्धालु हैं, जो रामलला क दर्शन करके वापस आ रहे हैं। श्रद्धालुओं को झुंड बनाकर खड़ा होने से सुरक्षाकर्मी मना करते हैं। आगे बढ़ते रहिए...। महिला कहती है कि बेटी को आने दो, फिर चले जाएंगे...। यह महिला थीं गुजरात के अहमदाबाद की यशोधरा बेन। वह अपने पति, दो पुत्रियों और बेटे के साथ अयोध्या दर्शन के लिए पहुंची थीं। रामलला का दर्शन कर खुश यशोधरा कहती हैं कि कतार में आगे स्थान मिला। रामलला का दर्शन कर हम सभी का भाग्य धन्य हुआ। उनके पति शरद कुमार कहते हैं कि इस ऐतिहासिक घड़ी पर रामलला का दर्शन करना सौभाग्य की बात है। थोड़ी देर में उनकी बेटी शालिनी पहुंच जाती हैं और बजरंगबली के दर्शन को कहकर आगे बढ़ जाती हैं।

अयोध्या में सुरक्षा पाबंदियों का असर रामलला के दर्शनार्थियों पर पड़ रहा है भाई साहब...। यह कहते हुए एक सुरक्षाकर्मी आने वाले श्रद्धालुओं को आगे जाने का निर्देश देता है। गोरखपुर के शत्रुघ्न प्रसाद पांडेय रामलला का दर्शन कर भावुक हैं। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब सरकार जल्दी से मंदिर बनवा दे...। प्रसाद खरीद रहे पंकज मिश्र भी शत्रुघ्न प्रसाद की बात से सहमत नजर आते हैं। दिन चढ़ने पर श्रद्धालुओं की आमद में थोड़ा इजाफा दिखने लगता है। पूर्वाह्न के पौने 11 बजे खबर मिलती है कि एसएसपी आशीष तिवारी परिसर पहुंच गए हैं।

बदलेगी दर्शन अवधि

परिसर की सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों की माने तो कार्तिक पूर्णिमा को लेकर दो दिनों के लिए दर्शन अवधि में बदलाव किया जा रहा है। 11 और 12 नवंबर को श्रद्धालु पहली पाली में सुबह सात से दोपहर 11:30 बजे और दूसरी पाली में दोपहर 12:30 बजे से शाम पांच बजे तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे।

चुनौती बनी पांच एकड़ जमीन

आनंदमोहन ●

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन तलाशना चुनौती बना हुआ है। सबसे बड़ा पेच जमीन की उपलब्धता का है। फैसले के बाद सदर तहसील के कई राजस्व ग्रामों से प्रस्ताव आए हैं।

सदर, मिल्कीपुर, बीकापुर एवं सोहावल तहसील के लेखपालों से फैसला आने के तत्काल बाद पांच एकड़ जमीन के लिए प्रस्ताव मांगा गया था। सूत्रों के अनुसार, रामनगरी तो दूर अयोध्या नगर निगम क्षेत्र का एक भी राजस्व गांव नहीं है जिसमें जमीन उपलब्ध हो। तहसीलदार सदर प्रमेश कुमार का कहना है कि कोर्ट ने तीन महीने का समय दिया है, तब तक जमीन तलाश ली जाएगी। पांच एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन के लिए सदर तहसील के जिन राजस्व ग्रामों से प्रस्ताव आए हैं उनमें राजेपुर, भदौली बुजुर्ग, चांदपुर हरवंशपुर, मलिकपुर एवं डाभासेमर समेत कई गांव बताए गए हैं। चांदपुर हरवंश, मलिकपुर एवं डाभासेमर की सरकारी जमीन माध्यमिक शिक्षा विभाग की है। एक महीना पहले कमिश्नर मनोज मिश्र व जिलाधिकारी अनुज कुमार झा भी इसे देख चुके हैं। उस वक्त मकसद औद्योगिक बताया गया था। सोहावल तहसील से रौनाही के कृषि प्रक्षेत्र, बीकापुर में नंदरौली राजस्व ग्राम से सरकारी जमीन का प्रस्ताव आया है। यह जमीन हाईवे पर है। मिल्कीपुर तहसील का प्रस्ताव अभी आना है। मस्जिद के लिए अब सबसे उचित चांदपुर हरवंश की जमीन को अयोध्या-प्रयागराज हाईवे पर होने के नाते बताया जा रहा है, पर दिक्कत नगर निगम क्षेत्र से बाहर होने की है। अकेले चांदपुर हरवंश राजस्व ग्राम नगर निगम क्षेत्र के विस्तार में प्रस्तावित है। उस प्रस्ताव में पांच एकड़ जमीन से ज्यादा वाले राजेपुर, भदौली बुजुर्ग, मलिकपुर समेत अन्य राजस्व ग्राम शामिल नहीं हैं। नगर निगम सूत्रों का कहना है कि लगभग दो महीने पहले सीमा विस्तार संबंधी मांगे गए एक आरटीआइ के जवाब में प्रस्तावित राजस्व गांवों की शासन को भेजी गई सूची में चांदपुर हरवंश शामिल है। सदर तहसील के अलावा सोहावल तहसील के भी पांच राजस्व ग्राम सीमा विस्तार में शामिल हैं। रौनाही व नंदरौली उसमें शामिल नहीं है।

नया नजरिया

चिंता न रार, पक्षकार अब चाहते हैं रामनगरी का विकास

मुस्लिम पक्षकारों के घरों से गूंजता रहा सौहार्द का संदेश, कोर्ट के फैसले के साथ दिखे इकबाल अंसारी और हाजी महबूब

रविप्रकाश श्रीवास्तव

सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको शिरोधार्य है, यह काफी हद तक साफ शनिवार को ही हो गया था। बची-खुची चंद आशंकाएं थीं, वे रविवार को 'रवि' के उदय के साथ ही विलीन हो गईं। रामनगरी में चिंता दिखी न रार...। विवाद के मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी हों या हाजी महबूब, उनके घर की दरो-दीवार से सौहार्द का संदेश ही फूटता रहा। दोनों ही न्यायपालिका के साथ खड़े दिखे। साथ ही दोनों में दिखी एक ही ख्वाहिश, बहुत हुआ...। वर्षों तक विवाद से अवरुद्ध रहे विकास की रवानी सरयू की लहरों के माफिक रामनगरी में बहनी चाहिए। बेहतर शिक्षा के इंतजाम होने चाहिए, युवाओं को काम मिलना चाहिए ताकि उन्हें दूसरे शहरों के सामने हाथ न फैलाना पड़े। पेश है, उनके घर से लाइव रिपोर्ट...।

चिंता से मुक्त परिवार के संग मगन दिखे इकबाल : सुबह के 11 बज रहे हैं। अयोध्या का कोटिया मोहल्ला, जो कल तक 'पीपली लाइव' बना था, वहां बिल्कुल शांति पसरी है। हां, इकबाल के घर की सुरक्षा कड़ी है। बाहर ही चार कुर्सियां पड़ी हैं, जिन पर इकबाल अपने भतीजे आसिफ और कुछ अन्य लोगों के साथ गुफ्तगू में मशगूल दिखे। तभी उनका मासूम पौत्र शहाबुद्दीन, जो अभी चलना सीख रहा है, गुब्बारा लेकर उनकी तरफ भागता है। गिर न पड़े इसलिए इकबाल लपक कर उसे गोद में उठा लेते हैं। कुछ देर शहाबुद्दीन के साथ बिताने के बाद इकबाल की नजर अखबार पर पड़ती है। उसे उठाकर खबरें पढ़ने लगते हैं। खबरनवीस को देख सलाम कर बैठने के लिए कहते हैं। भतीजे आसिफ को चाय लाने के लिए बोल कर इकबाल मुखातिब होते हैं। कहते हैं कि हमारे वालिद मरहूम हाशिम अंसारी ने तो 2010 में ही कहा था कि अब विवाद न बढ़ाया जाए। निर्मोही अखाड़ा और विहिप ही पहले न्यायालय गए। इनकी याचिका के बाद हमारे पिता ने याचिका दाखिल की। चाय लेकर पहुंचे इकबाल के भतीजे आसिफ कहते हैं परिवार ही नहीं, बल्कि समाज का हर वर्ग फैसले का स्वागत कर रहा है। चाय की चुस्की के साथ इकबाल आगे कहते हैं कि 20 जुलाई 2016 में पिता हाशिम अंसारी का इंतकाल होने के बाद पक्षकार के रूप में वह कायम हुए। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गया है। हर कोई इसका सम्मान करे। अयोध्या के विकास के बारे में सोचे।

आवाम को बंदिशों में देख हाजी परेशान : रविवार दोपहर के 1.30 बज रहे हैं। टेढ़ी बाजार से हाजी महबूब के घर जाने वाले रास्ते पर कड़ा पहरा है। हाजी के घर का दरवाजा बंद है। खटखटाने पर एक पुलिसकर्मी दरवाजा खोलता है। सवाल करता है कि किससे मिलना है। हाजी साहब से...। यह सुनकर पुलिसकर्मी एक रजिस्टर लाता है, जिसमें आगंतुक का नाम पता दर्ज करने के बाद उनके कमरे में प्रवेश मिलता है। कमरे में कुछ मुस्लिम धर्मगुरु चर्चा में मशगूल हैं, जो कुछ देर बाद बाहर चले जाते हैं। हाजी अपने सोफे पर बैठे रहते हैं। उनका पहला सवाल होता है कि आप लोग बताइए...अयोध्या कैसी है? फैसले को लेकर पाबंदियों से जूझ रही आम जनता का कष्ट हाजी की बातों में साफ झलका। कहते हैं कि पाबंदियां बहुत बढ़ गई हैं, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। खैर छोड़िए, अब तो विवाद का पटाक्षेप हो चुका है। लोग संयम का परिचय दें। रामनगरी के विकास के बारे में सोचें। हाजी फिर सुप्रीम फैसले की ओर लौटते हैं। कहते हैं, देखिए सरकार तीन महीने में क्या करती है...? जो फैसला आया ठीक है... हम लोग भी उसका अध्ययन करेंगे। मस्जिद के लिए कहां जमीन देते हैं, इस पर भी गौर किया जाएगा। हाजी आशंका जाहिर करते हैं कि विवाद पर जो लोग राजनीति की रोटियां सेंकते आए हैं, ट्रस्ट में भी उन्हीं के आदमी ही होंगे। करीब आधे घंटे की वार्ता में हाजी ने बार-बार अयोध्या के सौहार्द को सहेजने की अपील की।

अपने आवास पर दैनिक जागरण पढ़ते इकबाल अंसारी ● जागरण

फैसले के बाद

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर अपने फैसले में राम शब्द का उल्लेख 1789 बार किया, जबकि कोर्ट शब्द का 1785 बार। मॉस्क शब्द का 1144, मस्जिद का 348, हिंदू 1062, टेंपल 814, मुस्लिम 549, अयोध्या 527, सुबूत का 562 बार जिक्र किया।

राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त होने के बाद अयोध्या में चहल-पहल बढ़ गई है। रविवार को श्रीराम जन्म भूमि न्यास की कार्यशाला से लौटते श्रद्धालु। प्रेट्र

अब धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनेगी रामनगरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

प्रभु राम का 'टेंट-वास' खत्म होते ही उनकी अयोध्या के भी दिन बहुरने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद इस धर्मनगरी के 'उद्धार' की ओर कदम तो बढ़ाए गए, लेकिन विवाद के चलते उसकी रफ्तार काफी धीमी रही। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में आने के बाद अयोध्या का विकास सरकार की प्राथमिकता में होगा। यह भी तय है कि ज्यों-ज्यों राम मंदिर स्वरूप में आएगा, वैसे-वैसे रामनगरी धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित होती जाएगी। अगाध आस्था के बावजूद विवाद और सुरक्षा पहरे में अयोध्या अब तक घुटती रही है। राजधानी लखनऊ से महज 130 किलोमीटर फासला होने के बावजूद विकास के लिहाज से यह पुण्य धरती पिछड़ी ही रही। राम-भरोसे चली राजनीति भी इसका कभी कल्याण नहीं कर सकी। मगर, केंद्र के बाद प्रदेश में भी भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो विवाद पर फैसला आने के पहले ही अयोध्या की दशा सुधारने को खाका खींचा जाना शुरू हो गया था। अब न्यायालय ने राम मंदिर निर्माण का फैसला सुना दिया है। तीन माह में सरकार को ट्रस्ट बनाना है। पर्यटन विभाग भी इस फैसले से उत्साहित है।

पर्यटकों की राह नहीं रोकेंगी पावंदियां : पर्यटन विभाग का मानना है कि अब पाबंदियां पर्यटकों की राह नहीं रोकेंगी। श्रद्धालु अयोध्या आना भी चाहते हैं। दो वर्ष से दीपोत्सव में ही लगभग दो करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं। वैसे औसतन प्रतिदिन पचास हजार श्रद्धालु-पर्यटक अयोध्या पहुंचते हैं। अब राम मंदिर निर्माण शुरू होगा तो उसे बनते देखने की ललक भी लोगों में होगी। विभाग का आकलन है कि मंदिर निर्माण शुरू होते ही प्रतिदिन का आंकड़ा एक लाख को छू सकता है।

राम मूर्ति और संग्रहालय बढ़ाएंगे शोभा

अब राम मंदिर निर्माण शुरू होगा। पुरातात्विक महत्व के अन्य तमाम मंदिर पहले से हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा वहां 151 मीटर की भव्य मूर्ति सरयू के किनारे स्थापित कराई जा रही है। साथ ही डिजिटल म्यूजियम भी बनाया जाना है। इसके साथ ही अयोध्या में विकास की तमाम योजनाएं हैं, जो यहां की शोभा बढ़ाएंगी।

शुरू होगा अयोध्या तक हवाई सफर

अयोध्या में अभी रेलवे स्टेशन और बस अड्डा है। इनके जरिए पर्यटक पहुंच सकते हैं। हवाई सफर के लिए फिलहाल सबसे निकट लखनऊ का चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा ही विकल्प है। यहां से अयोध्या की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है। मगर, सरकार ने अयोध्या से महज आठ किलोमीटर दूर स्थित हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी घोषणा कर चुके हैं।

कामेश्वर चौपाल ने कहा, मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन

भरत कुमार झा, सुपौल : 9 नवंबर, 1989 को अयोध्या में राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले बिहार के सुपौल निवासी कामेश्वर चौपाल

शनिवार को राम मंदिर पर सुप्रीम फैसला सुनते ही आह्लादित हो उठे। कहा, यह उनके जीवन का यह सबसे महत्वपूर्ण और खुशी का दिन है। उन्होंने जो संकल्प लिया था, आज वह पूरा हो गया। हिंदू समाज की जो भावना थी, उसका सम्मान हुआ। महात्मा गांधी सहित अन्य महापुरुष रामराज्य की बात करते थे। सबके प्रति न्याय ही तो रामराज्य की सही परिभाषा है जो आज परिलक्षित हुआ। चौपाल ने बताया कि जब राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था, तब वह विश्व हिंदू परिषद के सह संगठन मंत्री थे। बिहार प्रदेश के सुदूर ग्रामीण इलाके से आने के बावजूद विहिप के अधिकारियों ने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें सौंपी तो वह गौरवान्वित हो उठे। उनकी मां उन्हें एक गीत सुनाया करती थीं-पहुना मिथिले में रहियो। उन्होंने इस गीत पर अपनी मां से सवाल किया था कि श्रीराम तो भगवान हैं, फिर पहुना (अतिथि) क्यों? मां का उत्तर था कि दुनिया के लिए भले ही भगवान हैं, लेकिन मिथिला के तो पाहुन (अतिथि) ही हैं श्रीराम। चौपाल ने कहा कि पुरखों ने बचपन में जो संस्कार भरा था, वही समर्पण के रूप में सदैव उनके साथ रहा है। ऐसे तो इष्टदेव और उधर मिथिला से संबंध, यानी हमारा तो दोनों संबंध साकार हुआ है। कहा, संयोग देखिए जब शिलान्यास किया गया था तो वह तारीख भी 9 नवंबर थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी 9 नवंबर को आया। जब उन्होंने शिलान्यास किया था तो उस समय सुबह के 10:30 बज रहे थे और जब फैसला सुनाया गया तो वह भी 10:30 बजे ही। चौपाल ने अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए कहा कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, तब उन्होंने पहली ईंट रखी थी और जब फैसला सुनाया गया, उस समय भी वे मौजूद थे। अपने राजनीतिक जीवन में चौपाल भाजपा कोटे से 2002 से 2014 तक विधान पार्षद रह चुके हैं। 1991 में रोसड़ा लोकसभा से उन्होंने रामविलास पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वह पराजित हो गए। 2014 का लोकसभा चुनाव उन्होंने अपने गृहक्षेत्र सुपौल से लड़ा, वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

देश की एकता और अखंडता के लिए अहम फैसला : यतींद्रानंद

जागरण संवाददाता, रुड़की : श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं अखिल भारतीय साधु परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता

स्वामी यतींद्रानंद गिरि ने श्रीराम जन्म भूमि मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे देश की एकता और अखंडता मजबूत होगी। जनमानस इस निर्णय की सराहना कर रहा है। यहां जारी बयान में स्वामी यतींद्रानंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसी के पक्ष एवं विपक्ष में होने की बात कहना न्याय संगत नहीं है। देश का संपूर्ण साधु समाज इस निर्णय का स्वागत करता हैं। इसके साथ ही, पूरे देश से इसे हृदय से स्वीकार करने की अपेक्षा रखता है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस निर्णय के विपरीत बात कर रहे हैं वह देश की संस्कृति, एकता और अखंड़ता और राष्ट्रीयता के प्रति अनादर का भाव उत्पन्न कर रहे हैं। वरिष्ठ महामंडलेश्वर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय दिया है। इससे बेहतर दूसरा कोई निर्णय नहीं हो सकता है। एक असंभव सी दिखने वाली समस्या का सुप्रीम कोर्ट ने समाधान किया है। पूरा देश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का आभार जता रहा है।

दिग्विजय का सवाल, क्या विवादित ढांचा तोड़ने वालों को मिलेगी सजा

नईदुनिया, भोपाल : कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 27 साल हो गए हैं। क्या अयोध्या में विवादित ढांचा तोड़ने के दोषियों को सजा मिल पाएगी। दिग्विजय ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस ने हमेशा कहा कि हर विवाद का हल संविधान द्वारा स्थापित कानून व नियमों के दायरे में ही खोजना चाहिए। विध्वंस और हिंसा का रास्ता किसी के हित में नहीं है। दिग्विजय ने राम जन्मभूमि मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अदालत ने माना है कि विवादित ढांचा तोड़ने वाले लोगों का कृत्य गैरकानूनी है। उन्होंने राम जन्मभूमि के फैसले का सभी पक्षों द्वारा सम्मान किए जाने पर आभार जताया।

गिरिराज किशोर ने लिया था दाढ़ी-बाल न कटाने का संकल्प

जासं, प्रयागराज : राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा माने जाने वाले आचार्य गिरिराज किशोर ने मंदिर निर्माण के लिए बड़ा संकल्प प्रयागराज में लिया था। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े दिग्गजों के सामने उन्होंने मंदिर बनने तक दाढ़ी-बाल न कटवाने की घोषणा की थी। 2014 में उनका देहावसान हो गया, मगर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। 1995 में श्रीराम जन्मभूमि न्यास के गठन के बाद प्रयागराज में हुई मार्गदर्शक मंडल की बैठक में अशोक सिंहल, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, विनय कटियार, देवकी नंदन अग्रवाल, डॉ. बीएल अग्रवाल, बैकुंठ नाथ भार्गव भी मौजूद थे। विहिप कार्यालय प्रभारी सुनील कुमार और विहिप नेता राजीव मिश्रा ने बताया कि बैठक में मंदिर के लिए वक्ता अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। जब आचार्य गिरिराज बोलने को खड़े हुए तो उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक भगवान राम भव्य मंदिर में विराजमान नहीं हो जाएंगे, तब तक वह दाढ़ी-बाल नहीं कटवाएंगे। विहिप की मासिक पत्रिका हिंदू विश्व में इसका उल्लेख भी हुआ था, जिसकी प्रतियां रामलला के सेवकों को वितरित की गई थीं। बैठक में शिरकत करने के लिए आचार्य विदेश से आए थे। देश के बाहर संगठन को खड़ा करने में उनकी अहम भूमिका थी, इसीलिए वह अक्सर विदेश जाते रहते थे। प्रयागराज में आयोजित सभी धर्म संसद और हिंदू सम्मेलनों में उन्होंने शिरकत की थी। अशोक सिंहल के आवास महावीर भवन में ही उनका रुकना होता था।

अधिगृहीत जमीन के लिए सरकार को अब किसी इजाजत की जरूरत नहीं

रास्ता साफ ▶ सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सरकार को अधिगृहीत जमीन भी ट्रस्ट को देने की मिली है छूट

गैर विवादित अधिगृहीत भूमि लौटाने की इजाजत मांगने वाली केंद्र सरकार की लंबित अर्जी हुई बेकार

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या मामले में फैसले के बाद केंद्र सरकार को अधिगृहीत जमीन के बारे में अब सुप्रीम कोर्ट से कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं रह गई है। अधिगृहीत जमीन का गैर विवादित हिस्सा भूमि मालिकों को वापस करने की इजाजत मांगने वाली केंद्र सरकार की शीर्ष कोर्ट में लंबित अर्जी अब महत्वहीन हो गई है।

शनिवार के फैसले में कोर्ट ने सरकार को अधिगृहीत जमीन भी ट्रस्ट को देने की छूट दी है, जो उस जमीन का प्रबंधन या विकास कर सकता है। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार की 29 जनवरी 2019 को दाखिल की गई अर्जी अब महत्वहीन हो गई है। इस अर्जी में सरकार ने अयोध्या में अधिगृहीत 67.703 एकड़ जमीन में से 0.313 एकड़ विवादित भूमि छोड़कर बाकी की जमीन रामजन्मभूमि न्यास व अन्य भू-मालिकों को वापस करने की इजाजत मांगी थी। अर्जी में सरकार ने कोर्ट से मामले में यथास्थिति कायम रखने का 31 मार्च 2003 का आदेश रद करने या बदलने की भी गुहार लगाई थी। ऐसा होने से सरकार अयोध्या भूमि अधिग्रहण को सही ठहराने वाले संविधान पीठ के इस्माइल फारुकी फैसले के मुताबिक अपने दायित्व का निर्वाह करने में सक्षम हो सकेगी। सरकार की ओर से यह अर्जी 16 साल पुराने मुहम्मद असलम भूरे मामले में दाखिल की गई थी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2003 को विवादित जमीन के साथ ही पूरी अधिगृहीत जमीन पर यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए थे। यह मामला अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में लंबित मुख्य अपीलों से अलग है। अब इस अर्जी पर सुनवाई की जरूरत नहीं रह गई है।

क्या थी सरकार की अर्जी? : अर्जी में सरकार ने कहा था कि 1993 में अयोध्या में विवादित स्थल सहित कुल 67.703 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ था। अधिग्रहण को ढाई दशक बीत चुके हैं। जो लोग अधिगृहीत जमीन के मूल मालिक हैं और जिनकी जमीन पर कोई विवाद नहीं है, उन्हें अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस्माइल फारुकी मामले में संविधान पीठ के फैसले के मुताबिक कार्रवाई करते हुए उनकी जमीन वापस कर दे। अधिगृहीत अतिरिक्त जमीन को लगातार केंद्र सरकार के पास बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। सरकार विवादित जमीन का मुकदमा जीतने वाले पक्ष के रास्ते के लिए जरूरी भूमि नापकर अपने पास रख लेगी। सरकार का कहना था कि इस अतिरिक्त जमीन का विवादित जमीन से कोई लेना-देना नहीं है इसलिए इसे लौटाने की इजाजत दे दी जाए। केंद्र सरकार ने कोर्ट से न्याय हित में इजाजत देने की मांग की थी। सरकार का कहना था कि 31 मार्च 2003 का यथास्थिति कायम रखने का आदेश उस समय के हालात देखते हुए दिया गया था।

1996 में रामजन्मभूमि न्यास ने मांगी की अपनी जमीन : अधिगृहीत जमीन में 42 एकड़ जमीन रामजन्मभूमि न्यास की है। इस्माइल फारुकी फैसले के बाद छह जून 1996 को रामजन्मभूमि न्यास ने केंद्र सरकार के पास अर्जी देकर अपनी जमीन वापस मांगी। सरकार ने 14 अगस्त 1996 को न्यास की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि इस मांग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित मुकदमे पर फैसला आने के बाद ही विचार हो सकता है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलील का सही मानते हुए न्यास की याचिका खारिज कर दी।

2002 में सामने आई असलम भूरे की याचिका

मुहम्मद असलम भूरे ने 2002 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर अयोध्या में भूमि पूजन रोकने की मांग की। 31 मार्च 2003 को असलम भूरे की याचिका संविधान पीठ ने निपटा दी। उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित मुकदमे का फैसला होने तक जमीन पर यथास्थिति कायम रहेगी। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम जन्मभूमि मामले पर फैसला देते हुए विवादित जमीन को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 14 अपीलें लंबित थीं जिन पर कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया है।

फैसले का अध्ययन करके आगे की रणनीति तय करेगा निर्मोही अखाड़ा

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष करने वाला और रामलला की सेवादारी (शैबियत अधिकार) का दावा करने वाला निर्मोही अखाड़ा मंदिर बनने की राह साफ होने से खुश है। इसके अलावा मंदिर निर्माण और प्रबंधन के लिए बनने वाले ट्रस्ट में शामिल किए जाने के कोर्ट के आदेश का भी आभारी है। लेकिन मुकदमा खारिज होने और सेवादारी का दावा ठुकराए जाने के पहलू का अध्ययन करने के बाद वह आगे की रणनीति तय करेगा।

निर्मोही अखाड़ा राम जन्मभूमि विवाद में एक प्रमुख पक्षकार था। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार के फैसले में अखाड़ा का मुकदमा कानून में तय समय के भीतर दाखिल न किए जाने के आधार पर खारिज कर दिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा की सेवादारी (शैबियत अधिकार) का दावा भी ठुकरा दिया था। हालांकि विवादित स्थल पर निर्मोही अखाड़ा की ऐतिहासिक मौजूदगी और उसकी भूमिका को देखते हुए कोर्ट संविधान में प्राप्त विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार को गठित किए जाने वाले ट्रस्ट में उसे उचित स्थान देने का निर्देश दिया है।

बता दें कि अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को न्याय के हित में कोई भी आदेश जारी करने का अधिकार और शक्ति प्रदान करता है। इसी के तहत निर्मोही अखाड़ा को ट्रस्ट में शामिल करने का आदेश दिया है।

निर्मोही अखाड़ा के सरपंच राजा रामचंद्र आचार्य का कहना है कि अपने हितों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए वह सभी जरूरी कदम उठाने पर विचार करेंगे लेकिन उसके पहले फैसले का बारीकी से अध्ययन करना जरूरी है। उनका कहना है कि जन्मभूमि पर उनका दावा अंदर के अहाते पर था बाहर के चबूतरे और अहाते पर निर्मोही अखाड़ा के अधिकार को तो हाई कोर्ट और जिला अदालत ने भी माना था। इसके अलावा मुस्लिम पक्षकारों ने भी चबूतरे पर उनका कब्जा और शैबियत का अधिकार माना है। वह कहते हैं कि शैबियत अधिकार की व्याख्या सात जजों की संविधान पीठ ने पहले जो की है, उसे उनकी ओर से इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने रखा भी गया था। अब देखना होगा कि कोर्ट ने किस आधार पर उनके दावे को समझे बगैर खारिज किया है। वह कहते हैं कि यह सिर्फ अयोध्या की बात नहीं है। जिस तरह से अखाड़ों ने भारतीय संस्कृति की रक्षा की है, उसके आधार पर ही वह यह कहने का हक रखते हैं। मंदिर निर्माण के लिए वे लोग 1885 से मुकदमा लड़ते चले आए हैं ऐसे में मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने से वह खुश हैं।

निर्मोही अखाड़ा के प्रवक्ता कार्तिक चोपड़ा कहते हैं कि इस मुकदमे की रोजाना सुनवाई कर फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। उनका कहना है कि अखाड़ा को ट्रस्ट में शामिल करने के कोर्ट के फैसले के भी आभारी हैं लेकिन उन्हें अभी इस बात का पता नहीं है कि केंद्र ट्रस्ट में उसे क्या भूमिका देगा।

चोपड़ा का कहना है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1961 में मुकदमा दाखिल किया था और कोर्ट ने उसका मुकदमा तय समय के भीतर माना है जबकि निर्मोही अखाड़ा ने 1959 में मुकदमा दाखिल किया था तब भी उसका मुकदमा तय समय के बाद दाखिल मानकर खारिज किया गया है। फैसला बहुत बड़ा है उसे पढ़ने और समझने में वक्त लगेगा। निर्मोही अखाड़ा फैसले का अध्ययन कर रहा है।

> अपने हितों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने पर विचार करेंगे, लेकिन उसके पहले फैसले का बारीकी से अध्ययन करना जरूरी है।
>
> राजा रामचंद्र आचार्य, निर्मोही अखाड़ा के सरपंच

'मोदी के नेतृत्व में अयोध्या विवाद, अनुच्छेद 370 का समाधान हुआ'

नई दिल्ली, प्रेट्र : अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के एक दिन बाद भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को कहा कि मोदी सरकार के तहत लंबे समय से लंबित कई मामले अपने तार्किक परिणाम तक पहुंचे हैं। अनुच्छेद 370, जीएसटी, एक साथ तीन तलाक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तार्किक समाधान हुआ है। उन्होंने कहा कि अयोध्या फैसले का समाज के हर तबके ने स्वागत किया है। समाज के हर तबके में उम्मीद जगी है।

- भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा-अयोध्या फैसले का समाज के हर तबके ने किया है स्वागत
- बोले-हर तबके में जगी उम्मीद

उल्लेखनीय है कि अयोध्या भूमि विवाद, अनुच्छेद 370 समाप्त किया जाना और एक साथ तीन तलाक का समाधान भाजपा और उसके हिंदुत्व संबद्धों के रुख के अनुकूल निकाला गया। कोर्ट के फैसले ने हिंदू संगठनों के पक्ष में अयोध्या मुद्दे का समाधान किया है। विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने के लिए हिंदू संगठनों ने दावा किया था। भाजपा 1989 से इस मांग का समर्थन कर रही थी।

मोदी सरकार ने लोकसभा में अपने बहुमत का इस्तेमाल अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने के लिए किया और मुस्लिम पुरुषों द्वारा एक साथ तीन तलाक कहे जाने के रिवाज को आपराधिक बनाया। अनुच्छेद 370 और एक साथ तीन तलाक भाजपा के मुख्य मुद्दों में शामिल थे। अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। भाजपा की अगुआई वाली राजग सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया था।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा। फाइल

विवादित ढांचे के विध्वंस पर भी जल्द आएगा फैसला

आलोक मिश्र, लखनऊ

- दर्ज कराए गए थे 49 मुकदमे, 347 लोगों की हुई है गवाही
- भाजपा के पूर्व अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सहित कई हैं आरोपित

राम मंदिर पर फैसला आने के बाद अब यह संभावना है कि विवादित ढांचे के विध्वंस के आरोपियों के मामले में भी जल्द ही निर्णय आ जाएगा। इस मामले में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता आरोपित हैं। इनमें बाला साहब ठाकरे और अशोक सिंहल समेत कई दिग्गज अब इस दुनिया में नहीं हैं। अयोध्या के थाना रामजन्म भूमि में छह दिसंबर, 1992 की शाम करीब 5.15 बजे विवादित ढांचा विध्वंस का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। लाखों अज्ञात कारसेवकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई। डकैती, धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाने, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने समेत आठ धाराओं में रिपोर्ट लिखी गई। ठीक दस मिनट बाद इसी थाने में तत्कालीन चौकी प्रभारी गंगा प्रसाद तिवारी ने दूसरा मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें अशोक सिंघल, मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेता गिरिराज किशोर, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी व मुरली मनोहर जोशी, विहिप के नेता विष्णु हरि डालमिया, भाजपा सांसद विनय कटियार, उमा भारती व साध्वी ऋतंधरा को नामजद किया गया था। यह एफआइआर धार्मिक उन्माद भड़काने, जनहानि के आशय से अफवाह फैलाने समेत अन्य धारा में दर्ज हुई थी। इसी थाने में मीडिया कर्मियों की ओर से भी अलग-अलग तारीखों में 47 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। थाना रामजन्म भूमि में दर्ज इन कुल 49 मुकदमों की सीबीआइ जांच हुई थी और आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए जा चुके हैं।

बिना जमानत के छूटे थे आरोपित : अधिवक्ता अभिषेक रंजन बताते हैं कि 5 अक्टूबर 1993 को दाखिल की गई चार्जशीट का संज्ञान लेकर कोर्ट ने समन जारी कर आरोपितों को तलब किया था। 7 दिसंबर 1993 को लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, साध्वी ऋतंभरा, पवन कुमार पांडेय समेत कई अन्य आरोपित कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने उन्हें पर्सनल बांड पर रिलीज करने का आर्डर किया था, लेकिन आरोपितों ने जमानत लेने से इन्कार कर दिया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर 1993 की तय की, लेकिन इस तारीख पर आरोपितों को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका था। तब कोर्ट ने बिना जमानत के सभी को छोड़ने का आदेश दिया था।

ये हैं आरोपित : बाला साहब ठाकरे, लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, अशोक सिंहल, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, पवन कुमार पांडेय, बृज भूषण शरण सिंह, उमा भारती, साध्वी ऋतंधरा, गिरिराज किशोर, अयोध्या के तत्कालीन डीएम और एसएसपी, राम विलास वेदांती, धर्म दास, महंत नृत्य गोपाल दास, महामंडलेश्वर जगदीश मुनि महाराज, बैकुंठलाल शर्मा, परमहंस रामचंद्र दास, विजय राजे सिंधिया और सतीश कुमार।

लिब्रहान आयोग ने भी की थी जांच

विवादित ढांचा विध्वंस के बाद सरकार ने प्रकरण की जांच के लिए लिब्रहान आयोग का भी गठन किया था। रिटायर जस्टिस एमएस लिब्रहान की अगुआई में आयोग ने पूरे प्रकरण की जांच की थी और अपनी जांच रिपोर्ट करीब 17 साल बाद 2009 को सौंपी थी। आयोग की जांच अवधि कई बार बढ़ाई गई थी।

बदला रुख

अयोध्या पर अब 'थर्ड अंपायर' की भूमिका छोड़ रहे विपक्षी दल

दलों के समक्ष अपना रुख बदलने की चुनौती, कांग्रेस समेत अधिकांश विपक्षी दल दे रहे नैरेटिव बदलने का संकेत

संजय मिश्र, नई दिल्ली

आयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विपक्षी पार्टियां भले ही ध्रुवीकरण की सियासत थमने के लिहाज से निर्णायक मान रही हैं, लेकिन इन दलों के लिए राह बहुत आसान नहीं है। इस मामले में अब तक 'थर्ड अंपायर' की भूमिका निभाते रहे विपक्षी दलों के लिए तीन दशक के लबादे से बाहर आना बड़ी चुनौती होगी। संभवतः इसीलिए फैसले के तुरंत बाद से कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अपने अनुरूप राजनीतिक विमर्श की दशा-दिशा में जरूरी बदलाव का संकेत देने लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) इसका अपवाद जरूर है जिसने पश्चिम बंगाल की अपनी सियासी चुनौतियों के मद्देनजर फैसले पर अब तक चुप्पी साध रखी है।

विपक्षी पार्टियों को इस बात का बखूबी अहसास है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर किसी तरह के किंतु-परंतु को संघ-भाजपा बड़ा सियासी हथियार बना सकते हैं। इसीलिए अधिकांश दलों ने फैसले का सम्मान करते हुए इसे स्वीकार करने की अपील करने में देर नहीं लगाई। प्रतिक्रिया देने में कांग्रेस के अलावा हिंदी पट्टी की पार्टियों मसलन समाजवादी पार्टी, राजद और बसपा की तेजी से जाहिर है कि नई परिस्थितियों के हिसाब से विपक्षी दल इस मुद्दे पर अपने राजनीतिक विमर्श को नए सिरे से गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

वैसे भी चाहे कांग्रेस हो या सपा-बसपा या राजद इन पार्टियों के राजनीतिक उत्थान और ढलान में अयोध्या मुद्दे की बड़ी भूमिका रही है। भाजपा-संघ के अलावा अयोध्या विवाद से सबसे ज्यादा यही पार्टियां जुड़ी भी रही थीं। अयोध्या में 1986 में मंदिर का ताला खुलवाने से लेकर 1989 में शिला-पूजन का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ तो 1992 में विवादित ढांचे का विध्वंस भी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के वक्त हुआ।

अखिलेश यादव

तेजस्वी यादव

छिन गई थी कांग्रेस की राजनीतिक जमीन : मंदिर आंदोलन के दो सबसे प्रमुख केंद्र रहे उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस की राजनीतिक जमीन ध्वस्त होने की सबसे बड़ी वजह यही मुद्दा था। ऐसे में अदालत के फैसले से विमर्श बदलने का मौका मिलते ही 1992 में दोबारा मस्जिद की बात करने वाली पार्टी ने राममंदिर निर्माण की हिमायत कर दी। बीते पांच साल से नरम हिंदुत्व के संकेत दे रही कांग्रेस की राजनीतिक विमर्श को बदलने की बेचैनी इसी से समझी जा सकती है कि जहां बाकी विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की अपील की है। वहीं कांग्रेस ने इससे आगे जाकर यह कहने से गुरेज नहीं किया कि अब अदालत के फैसले के बाद भगवान श्रीराम का मंदिर बनना चाहिए।

सपा, बसपा और राजद भी बदल रहे रुख : हिंदी पट्टी के राज्यों में अयोध्या मसले की संवेदनशीलता का तकाजा ही है कि इस पर संघ-भाजपा के खिलाफ सीधा मोर्चा लेने वाले मुलायम सिंह यादव की पार्टी सपा हो या बिहार में लालू प्रसाद की राजद दोनों दलों ने फैसले का सम्मान करने की घोषणा में देर नहीं लगाई। दिलचस्प यह है कि मुलायम और लालू की जगह इन दोनों के सियासी उत्तराधिकारी पुत्रों ने खुद इसका एलान किया। अखिलेश यादव ने फैसले को सबके लिए बाध्यकारी बताते हुए उम्मीद जताई कि इसे देश में कानून का शासन और प्रजातंत्र सुदृढ़ होगा। सपा का यह रुख उसके सियासी नैरेटिव से बिल्कुल जुदा है। तेजस्वी यादव ने फैसले के सम्मान की अपील के साथ उम्मीद जताई कि अब सभी दल जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देंगे। आडवाणी को मंदिर आंदोलन में गिरफ्तार करने वाले लालू प्रसाद की पार्टी का यह रुख भी विमर्श में बदलाव के संकेत दे रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने संविधान का हवाला देते हुए फैसले का सम्मान करने की बात कही है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस संसद में संख्या बल के हिसाब से विपक्ष की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। मगर अभी तक ममता बनर्जी या टीएमसी की ओर से फैसले पर कोई बयान नहीं आया है।

292 बार पाकिस्तान ने सितंबर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है जम्मू-कश्मीर में। इसमें 61 बार मोर्टार का इस्तेमाल किया गया। अगस्त में उसने 307 और जुलाई में 296 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है।

सीमा पर मेले जैसा माहौल... साक्षात दर्शन का इंतजार

महिंदर सिंह अर्लीभन्न, डेरा बाबा नानक

भारत-पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर खुलने के दूसरे दिन रविवार को हजारों की संख्या में संगत कॉरिडोर, टर्मिनल देखने और सीमा से श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने उमड़ पड़ी। संगत के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। कई राज्यों से पहुंचे लोगों में कॉरिडोर देखने की भी ललक थी। बगैर पासपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के पहुंचे लोगों को उस पार जाने की इजाजत नहीं मिली। उन्होंने गुरुद्वारा साहिब का दूर से ही दीदार किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। कड़े सुरक्षा प्रबंधों के कारण लोग टर्मिनल और दर्शनी स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन रविवार को संगत सीमा पर उमड़ पड़ी। मोहाली से आए अमर सिंह कहते हैं कि आज का दिन उनके जीवन का सबसे खुशी वाला है। उन्होंने सीमा पर आकर पहली बार अपने पूर्वजों की जन्मभूमि को इतने करीब से देखा है। प्रोफेसर मनजीत सिंह कहते हैं कि कॉरिडोर भारत-पाक के बीच सिख कौम का ब्रिज है। 72 साल बाद लोग फिर पाकिस्तान की भूमि पर पैर रख पाएंगे।

भार-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बनी दर्शनस्थली से गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जी के दर्शन करने के लिए हजारों संगत डेरा बाबा नानक पहुंची। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं के पास पासपोर्ट नहीं होने के कारण उनको उस पार नहीं जाने दिया गया। उन्होंने गुरुद्वारा साहिब के दूर से ही दीदार किए। जागरण

सिर्फ आधार कार्ड लेकर पहुंचे : श्री करतारपुर साहिब जाने के लिए क्या प्रक्रिया है लोग अब भी उससे अनजान हैं। रविवार को ऐसे श्रद्धालु भी कॉरिडोर पर पहुंचे जो अपने साथ आधार कार्ड लेकर आए थे और गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने पाकिस्तान जाना चाहते थे। मानसा से आए सुरजीत सिंह हरीके को सुरक्षा कर्मियों ने जाने से रोक दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने श्री करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए पासपोर्ट और फीस माफ करने की बात कही है। उन्होंने किसी भी पहचान के आधार संगत दर्शन करने जा सकती है। मानसा जिले से करीब 200 श्रद्धालु अपने आधार कार्ड लेकर आए हैं लेकिन टर्मिनल के पास सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें जाने से मना कर दिया गया। अब उन्हें दर्शनी स्थल से ही करतारपुर साहिब के दर्शन करने होंगे।

बिना पासपोर्ट और फीस के आए थे दर्शन करने : जत्थेदार अनंद सिंह भर्थ भी बिना पासपोर्ट के सिर्फ पहचान पत्र लेकर पहुंचे थे। सरकार ने टर्मिनल पर मुकम्मल प्रबंध नहीं किए हैं जिस कारण फीस माफ होने के बावजूद गरीब संगत करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए नहीं जा पा रही है। कॉरिडोर के उद्घाटन के दूसरे दिन रविवार को 229 श्रद्धालु गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए पाकिस्तान गए। इससे पहले शनिवार को 562 श्रद्धालु गए थे।

पाकिस्तान से नक्काशी किया चकला-बेलन लेकर आए : श्री करतारपुर साहिब के दर्शन कर लौटे गुरजिंदरपाल सिंह, ऊधम सिंह और राजपाल कौर ने बताया कि उनके जीवन की लालसा आज पूरी हुई है। पाकिस्तान से यादगार के तौर पर वे नक्काशी किया हुआ चकला और बेलन खरीदकर आए हैं। इसकी लकड़ी पर तांबे की तारों से नक्काशी की गई है।

बस में खत्म हो गईं कैप्टन अमरिंदर और इमरान खान के बीच दूरियां

इन्द्रप्रीत सिंह, करतारपुर साहिब

भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर क्या खुला, दिलों में बनी दूरियां भी खत्म होती नजर आ रही हैं। कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले डेरा बाबा नानक में आयोजित जनसभा में इमरान खान को चेतावनी देने वाले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तीन घंटे बाद जब पाकिस्तान में कदम रखा तो इमरान उन्हें रिसीव करने आए। कॉरिडोर से श्री करतारपुर साहिब जाते हुए बस में कैप्टन ने इमरान को बताया कि गुरुद्वारे के साथ उनके दादा का खास रिश्ता है। जब रावी दरिया ने अपना रुख बदला तो बाढ़ में यह ढह गया था तो उनके दादा महाराजा भूपेंदर सिंह ने बनवाया था। आठ मिनट के सफर में कैप्टन ने यह बात उन्हें दो बार बोली।

दोनों नेताओं के बीच इस बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें कैप्टन गुरुद्वारा साहिब के इतिहास के बारे में बताते नजर आ रहे हैं। ऐसा वह उस समय कह रहे हैं, जब बस गुरुद्वारा साहिब के पास पहुंच गई और इमरान खान उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह गुरुद्वारा साहिब का इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत कम समय में बनाया गया है।

थोड़ी से दूरी और इतना बड़ा फासला : बस में ही कैप्टन को पाकिस्तान पंजाब के सीएम उस्मान बजदर से मिलवाया गया। इसमें कहते सुन जा रहा है कि इतनी थोड़ी से दूरी और इतना बड़ा फासला। इस पर इमरान बोले कि ताल्लुकात अच्छे होते तो दोनों सीएम मिल लेते।

सिद्धू ने इमरान से कहा- आप पंजाब आएं, लोग फूल बरसाएंगे : बस में मौजूद नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान से कहा कि आप पंजाब आएं तो सही, लोग फूल बरसाएंगे। बस में जब सिद्धू इमरान से बात करते तो कैप्टन इधर-उधर देखने लगते और जब कैप्टन इमरान से बात करते तो सिद्धू ज्यादा ध्यान नहीं देते। मात्र एक दो बातों में ही सिद्धू ने कैप्टन और इमरान की बात में हस्तक्षेप किया। गुरदासपुर के सांसद सनी देयोल भी इसी बस में थे। उन्हें भी इमरान से मिलवाया गया। सिद्धू ने कहा, 'एह ने साडे सनी भाजी।' इमरान ने कहा, 'गुड टू सी यू।'

सोनभद्र के वनवासी समागम में शामिल होंगे राष्ट्रपति

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : उत्तर प्रदेश के बभनी के सेवा कुंज आश्रम में वनवासी गौरव के रूप में होने जा रहे बिरसा मुंडा जयंती समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिरकत करेंगे। सेवा समर्पण संस्थान का भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम एक से 30 नवंबर तक पूरे देश में वनवासी गौरव के तहत विभिन्न कार्यक्रम कराएगा। इसी क्रम में राष्ट्रपति 29 नवंबर को वनवासी समागम कार्यक्रम में पहुंचेंगे।

अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के जिला कार्यसमिति सदस्य आलोक चतुर्वेदी ने बताया कि 29 नवंबर के कार्यक्रम में देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी उपस्थिति के लिए सहमति जताई है। उनके निजी सचिव विक्रम सिंह ने पत्र प्रेषित कर दिया है। राष्ट्रपति के आगमन को देखते आश्रम के सभी सदस्य कार्यक्रम की सफलता को लेकर पूरे जोश से लग गए हैं। सेवा समर्पण संस्थान के सह संगठन मंत्री आनंद उपाध्याय ने बताया कि राष्ट्रपति आश्रम में बने कुछ भवनों का उद्घाटन कर सकते हैं। बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रारंभ से ही प्रकल्प से जुड़े रहे हैं, और उनकी रुचि भी आदिवासी वन-वनवासियों के उत्थान में शुरू से रही है।

तबाही मचाने के बाद 'बुलबुल' ने किया बांग्लादेश का रुख

आपदा ▶ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से की बात, मदद का दिया भरोसा

शनिवार रात बंगाल में दी थी दस्तक, चक्रवात के चलते 10 की मौत, नौ जिले प्रभावित

जागरण संवाददाता, कोलकाता

चक्रवात 'बुलबुल' ने शनिवार रात बंगाल में दस्तक दी और रविवार तड़के तक नौ जिलों में जमकर तांडव मचाया। चक्रवात के चलते राज्यभर में 10 लोगों की मौत हुई। वहीं तबाही मचाने के बाद बुलबुल बांग्लादेश की तरफ मुड़ चुका है। जिससे राज्य में प्रभावित इलाकों में मौसम धीरे-धीरे साफ हो रहा है। इससे पहले तेज हवाओं और भारी बारिश तटीय जिलों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया।

चक्रवात का सबसे ज्यादा प्रभाव बकखाली, फ्रेजरगंज, संदेशखाली, झड़खाली, नंदीग्राम, नयाचर और खेजूरी इलाकों में पड़ा। चक्रवात के चलते नौ जिलों में करीब तीन लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों पेड़ और मकानों को क्षति पहुंची है। रविवार को ड्रोन की मदद से क्षतिग्रस्त इलाकों का मुआयना किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फोन कर बुलबुल से हुई तबाही की जानकारी ली और राज्य की हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, 'चक्रवात की स्थिति और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश के मद्देनजर उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की।' चक्रवात से हुई तबाही को लेकर केंद्र सरकार भी चिंतित है। रविवार को राज्य सरकार ने केंद्र को बताया कि बुलबुल चक्रवात के चलते बंगाल के नौ जिलों में कुल तीन लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने नौ जिलों के जिलाधिकारियों ने बुलबुल चक्रवात से मची तबाही की पूरी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए पीएमओ से बात की और हालात की जानकारी दी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सुंदरवन धानची वन के करीब पहुंचने से पहले बेहद गंभीर चक्रवात थोड़ा कमजोर होकर तूफान में तब्दील हो गया।

चक्रवाती तूफान 'बुलबुल' ने रविवार को पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई। साउथ 24 परगना जिले के फ्रेसरगंज में मछुआरों की पूरी बस्ती उजड़ गई। प्रेट्र

ममता बोलीं-बंगाल की खाड़ी से बचाए गए 75 यात्री : चक्रवात 'बुलबुल' की आपदा से अनभिज्ञ बंगाल की खाड़ी में एक क्रूज शिप पर परिभ्रमण पर गए 75 यात्रियों को बंगाल पुलिस की ओर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार रात सचिवालय नवान्न स्थित कंट्रोल रूम में पत्रकारों से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि दक्षिण 24 परगना जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बचाव अभियान शुरू किया गया। बाद में सभी यात्रियों को नामखाना के पास स्थित मौसुनी द्वीप में स्थित सामान्य होने तक ठहरने की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि पहले ही राज्य प्रशासन ने तटीय जिलों में निचले इलाकों से 1,64,315 लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का काम किया।

बांग्लादेश में छह लोगों की गई जान, कई लापता

ढाका, रायटर : तटीय इलाकों में इस सप्ताहांत बुलबुल तूफान के पहुंचने के बाद बांग्लादेश में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। त्वरित सतर्कता बरतने से कई की जान बचा ली गई है। अधिकारियों ने रविवार को इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि तूफान अब कमजोर हो गया है।

छह में पांच की पेड़ गिरने से मौत हुई। संरक्षण स्थल में रात गुजराने के बाद रविवार को घर पहुंची 52 वर्षीया महिला की पेड़ गिरने से मौत हो गई। 60 वर्षीय मछुआरे ने अपना घर खाली करने से मना कर दिया था जिससे उसकी मौत हुई। अधिकारियों ने कहा कि करीब 30 लोग घायल हो गए हैं और करीब 600 घर आंशिक या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दो मछली पकड़ने वाली नौका अभी तक नहीं लौटी है और उसपर सवार 36 लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश के शिविर में कोई बड़ा नुकसान होने की खबर नहीं है। इसी शिविर में म्यामांर के हजारों शरणार्थी रह रहे हैं।

हरियाणा में ई-सिगरेट और हुक्का बार पर लगेगी पाबंदी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- डीजीपी ने पुलिस आयुक्तों व एसपी को दिए निर्देश
- एक लाख का जुर्माना और एक साल की सजा संभव

हरियाणा में युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए न तो ई-सिगरेट की बिक्री हो सकेगी और न ही ई-हुक्का बार चल सकेंगे। केंद्र सरकार ने ई-सिगरेट के उत्पादन, आयात, निर्यात, बिक्री और विज्ञापन पर पूरी तरह रोक लगाने का अध्यादेश जारी किया है। हरियाणा इस कानून को अपने राज्य में पूरी सख्ती से लागू करेगा।

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव के अनुसार ई-सिगरेट समेत सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन की उपलब्धता और उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए राज्य भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। सोमवार से शुरू होकर यह अभियान पूरे एक माह यानी 10 दिसंबर तक जारी रहेगा।

पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस आयुक्त और जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अध्यादेश के प्रावधानों को सख्ती से लागू कराएं। स्कूल, कॉलेज और शिक्षा संस्थानों में इस तरह के प्रतिबंधित उत्पादों के उपयोग को रोकने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। जिलों में जन जागरण अभियान चलाए जाएं तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाए।

पुलिस महानिदेशक के अनुसार अध्यादेश में ई-सिगरेट, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन और ई-हुक्का को प्रतिबंधित कर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इनकी तलाशी, जब्ती व जांच के लिए कम से कम पुलिस सब-इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को अधिकृत किया गया है। अध्यादेश के अनुसार व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ई-सिगरेट का होना अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं है।

मनोज यादव ने बताया कि पहली बार अपराध के मामले में एक वर्ष तक का कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। अगले अपराध के लिए तीन साल तक कैद और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ई-सिगरेट के भंडारण के लिए छह माह तक कैद अथवा 50 हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं।

भविष्य निधि घोटाले में शामिल चार और ब्रोकर फर्मों के पते निकले फर्जी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

खुल रहे राज

- पूछताछ के बाद जेल में दाखिल कराए गए एपी मिश्र
- ईओडब्ल्यू ने डीएचएफएल के यूपी हेड को किया तलब

बिजली कर्मियों की भविष्य निधि की रकम लूटने में शामिल रहीं चार और ब्रोकर फर्मों के पते फर्जी पाए गए हैं। ईओडब्ल्यू की जांच के कदम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं, पूरे प्रकरण में घोटाले के पीछे रची गई गहरी साजिश की कड़ियां भी एक-एक कर खुलने लगी हैं। जिन 14 ब्रोकर फर्मों के जरिये निजी कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) में निवेश किया गया था, उनमें पांच फर्मों के पते अब तक फर्जी निकले हैं। जिन पांच फर्मों के पते फर्जी पाए गए हैं, वे गाजियाबाद, मेरठ व दिल्ली के पतों पर रजिस्टर्ड थीं। अन्य नौ फर्मों की भी जांच कराई जा रही है।

ईओडब्ल्यू ने पावर कारपोरेशन के पूर्व एमडी एपी मिश्र की पुलिस कस्टडी रिमांड अवधि पूरी होने पर उन्हें रविवार सुबह करीब 10 बजे लखनऊ जेल में दाखिल करा दिया। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर एपी मिश्र को फिर पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की कार्रवाई की जाएगी।

डीजी ईओडब्ल्यू डॉ. आरपी सिंह का कहना है कि आरोपित पावर कारपोरेशन के पूर्व निदेशक एपी मिश्र, पूर्व निदेशक (वित्त) सुधांशु द्विवेदी व तत्कालीन सचिव ट्रस्ट पीके गुप्ता से पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की छानबीन कराई जा रही है। कुछ अहम तथ्य सामने आए हैं, जिन्हें तस्दीक भी कराया जा रहा है। बताया गया कि जांच एजेंसी ने सोमवार को डीएचएफएल के यूपी हेड को पूछताछ के लिए बुलाया है।

उल्लेखनीय है कि ईओडब्ल्यू डीएचएफएल के एक पूर्व कर्मचारी से भी पूछताछ कर चुकी है। कंपनी में निवेश कराने के दौरान किन-किन लोगों की अहम भूमिका थी और किनके जरिये ब्रोकर कंपनियों से संपर्क साधा गया था। ईओडब्ल्यू ऐसे कई बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। 14 फर्मों में 12 फर्में तो ऐसी हैं, जिन्होंने सिर्फ यूपीपीसीएल के लिए काम किया है। इन फर्मों से जुड़े सभी लोगों के बारे में ब्योरा जुटाया गया है। ध्यान रहे, 4122.70 करोड़ के भविष्य निधि घोटाले के मामले में हजरतगंज कोतवाली में एफआइआर दर्ज कराई गई है। शासन के निर्देश पर इस मुकदमे की विवेचना ईओडब्ल्यू कर रही है। ईओडब्ल्यू ने मामले में अब तक गिरफ्तार तीनों आरोपित अधिकारियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। माना जा रहा है कि अब ईओडब्ल्यू पावर कारपोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष से भी जल्द पूछताछ करेगी।

अरविंद कुमार ने संभाला पदभार : प्रमुख सचिव ऊर्जा व अध्यक्ष पावर कारपोरेशन के पद पर अरविंद कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उल्लेखनीय है कि पीएफ घोटाले के चलते राज्य सरकार पिछले दिनों पावर कारपोरेशन की एमडी अपर्णा यू और कारपोरेशन के अध्यक्ष आलोक कुमार को पद से हटा चुकी है। एम देवराज पहले ही एमडी का कार्यभार संभाल चुके हैं। परिवहन से ऊर्जा विभाग में पहुंचे अरविंद कुमार प्रमुख सचिव गृह भी रह चुके हैं।

उत्तराखंड के सीएम के मोबाइल पर हरकी पैड़ी को उड़ाने की धमकी

जागरण संवाददाता, हरिद्वार

पहले भी मिलती रही हैं धमकियां

हरिद्वार : हरकी पैड़ी को बम धमाके से उड़ाने की धमकी पहले भी मिल चुकी है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पिछले आठ सालों में धमकी भरे छह पत्र मिले हैं। यह पत्र आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के नाम से मिलते रहे हैं। शुरुआत के पांच पत्र तत्कालीन स्टेशन अधीक्षक समरेंद्र गोस्वामी के नाम पर आए हैं। समरेंद्र गोस्वामी के रिटायर्ड होने के बाद भी उनके नाम पर धमकी भरे दो पत्र हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर मिले हैं।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मोबाइल पर एक शख्स ने कॉल कर हरकी पैड़ी को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। इससे राजधानी देहरादून से लेकर हरिद्वार तक शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल अधिकारी आनंद रावत की तहरीर पर हरिद्वार की शहर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मोबाइल नंबर की जांच शुरू करते हुए कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की है। वहीं एहतियातन हरकी पैड़ी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

पुलिस के मुताबिक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का मोबाइल रविवार को उनके प्रोटोकॉल अधिकारी आनंद रावत के पास था। उसी दौरान अंजान नंबर से मुख्यमंत्री के मोबाइल पर कॉल आई। कॉल करने वाले शख्स ने हरिद्वार में हरकी पैड़ी को बम ब्लास्ट कर उड़ाने की धमकी दी। इसके बाद कॉल खत्म कर दी। प्रोटोकॉल अधिकारी आनंद रावत ने तुरंत यह जानकारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को दी। मामले की गंभीरता को देखते मुख्यमंत्री ने तत्काल आवश्यक निर्देश जारी किए। इसके बाद मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल अधिकारी आनंद रावत ने एसएसपी हरिद्वार को तहरीर भेजी। एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस के निर्देश पर रविवार देर शाम हरिद्वार शहर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस व सीआइयू की टीम मोबाइल नंबर की छानबीन करने में जुट गई। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है।

उपलब्धि

विदेशी वैज्ञानिकों ने एमओयू के लिए एचएयू के प्रतिनिधियों को बुलाया पोलैंड, एक साथ एक प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर तैयार करेंगे किस्में

सूखे से निपटने वाला गेहूं तैयार करेगा हकृवि

वैभव शर्मा, हिसार

- पोलैंड की द प्लांट ब्रीडिंग एंड एक्लामाइजेशन नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट से मिला है न्योता
- पोलैंड में भी पीला रतुआ जैसी बीमारी सूखे के दौरान गेहूं में आ रही है

भारत में जलवायु परिवर्तन फसलों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सूखे के कारण हर साल किसानों की हजारों एकड़ गेहूं की फसल बर्बाद हो जाती है। अब ऐसे ही हालात पोलैंड में भी बनने लगे हैं। इस मसले पर पोलैंड की द प्लांट ब्रीडिंग एंड एक्लामाइजेशन नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी आइएचएआर में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. हैब एडवर्ड अरसेनिक ने चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के गेहूं अनुभाग में वैज्ञानिकों संग समीक्षा की। इन हालातों से निपटने के लिए दोनों ही संस्थानों ने एक साथ आने का फैसला लिया है। इसके लिए दोनों संस्थानों के वैज्ञानिक एक एमओयू साइन कर रिसर्च करेंगे। इस एमओयू का उद्देश्य गेहूं की ऐसी किस्में तैयार करना है, जो सूखे से निपटने में सक्षम हो।

भारत और पोलैंड एक ही प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं। पोलैंड में भी पीला रतुआ जैसी बीमारी सूखे के दौरान गेहूं में आ रही है। ऐसे में दोनों संस्थानों का एक साथ आना जरूरी बन गया है। डॉ. हैब एडवर्ड ने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत करते हुए बताया कि हमने आगामी कांफ्रेंस के लिए कुलपति प्रो. केपी सिंह को पोलैंड आने का आमंत्रण दिया है। इसके साथ ही हमने उनसे इस काम से जुड़ी समिति में बतौर चेयरमैन शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया है।

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। फाइल

तीन दिन की कांफ्रेंस पोलैंड में होगी आयोजित : वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. हैब एडवर्ड अरसेनिक ने बताया कि जल्द ही वह पोलैंड में एक कांफ्रेंस आयोजित करेंगे, जिसमें एचएयू के वैज्ञानिकों को भी बुलाया गया है। एचएयू की तरफ से एमओयू के दौरान वैज्ञानिक डॉ. ओपी बिश्नोई की भी मुख्य रूप से भागीदारी रहेगी। इस कांफ्रेंस के माध्यम से दोनों ही संस्थानों के वैज्ञानिक व शोधार्थी अपनी-अपनी रिसर्च के अनुसार मत रख सकेंगे, ताकि गेहूं को लोगों के लिए उपयुक्त व अधिक पैदावार वाली फसल बनाया जा सके।

गेहूं में यह रोग हैं : रतुआ रोग- यह पत्तियों में होता है। पीला रतुआ व भूरा रतुआ ट्रिटी में ज्यादा आता था, मगर वर्ष 2000 के बाद भारत में गेहूं में भी इसकी शुरुआत हो गई। यह समस्या पहले पोलैंड में थी ही नहीं मगर अब क्लाइमेंट चेंज होने से वहां भी दिक्कत हो रही है।

सेप्टोरिया बीमारी : भारत में सेप्टोरिया बीमारी अभी कम है। मगर वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले समय में यह भारत में भी बढ़ेगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है।

जीवनरक्षक टीकों के 30 सैंपल की गुणवत्ता सही नहीं पाई गई

मनमोहन वशिष्ठ, सोलन

हिमाचल प्रदेश के कसौली में स्थित देश की एकमात्र सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी (सीडीएल) ने इस साल 31 अक्टूबर तक विभिन्न कंपनियों के पांच जीवनरक्षक टीकों के 30 सैंपल की गुणवत्ता सही नहीं पाई है। सीडीएल ने वेबसाइट पर फेल सैंपल की सूची जारी कर ब्रिकी पर रोक लगा दी है।

सीडीएल की ओर से देशभर की सरकारी व निजी कंपनियों में निर्मित और विदेशों से आयात व निर्यात होने वाले जीवनरक्षक टीकों की गुणवत्ता को जांचने व परखने के बाद ही बाजार में उतारा जा सकता है। वैक्सीन के बाजार में जाने के बाद भी सीडीएल वैक्सीन पर निगरानी रखती है।

इन वैक्सीन के सैंपल हुए फेल : इस वर्ष फेल हुए 30 सैंपल में बाईवालेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के 25, टीटी वैक्सीन (टिटनेस टॉक्साइड) का एक, मेनिंगोकोकल वैक्सीन (मस्तिष्क व रीढ़ को कवर करने वाली झिल्लियों में सूजन को कम करती है) के दो, टाइफाइड वैक्सीन का एक व रैबीज वैक्सीन का एक सैंपल शमिल है।

2013 से अब तक 71 सैंपल फेल : सीडीएल कसौली ने वेबसाइट पर 2013 से अब तक विभिन्न वैक्सीन के 71 सैंपल को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड घोषित किया है। इनमें टीटी वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, एंटी स्नेक वेनम सीरम, पैंटावेलेंट वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, टाइफाइड वैक्सीन, डिप्थीरिया एंटी टॉक्सिन वैक्सीन व रैबीज वैक्सीन समेत कई अन्य वैक्सीन के सैंपल शामिल रहे हैं।

> सीडीएल में आने वाली वैक्सीन की गुणवत्ता को गहनता से जांचा व परखा जाता है। इसके बाद उसके बैच रिलीज किए जाते हैं। गुणवत्ता व अन्य कमियों पर सैंपल को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड घोषित किया जाता है। इसकी जानकारी वेबसाइट पर जारी की है।
>
> **-डॉ. अरुण भारद्वाज, निदेशक, सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी, कसौली**

बोकारो के विधायक विरंची नारायण का वीडियो वायरल

राज्य ब्यूरो, रांची : भाजपा के बोकारो विधायक बिरंची नारायण का एक वीडियो वायरल हुआ है। निजी पलों के इस वीडियो में विधायक अकेले दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनके मोबाइल से यह वीडियो निकाल लिया हो या फिर विधायक ने किसी को भेजा हो और वहां से लीक हुआ हो। जो भी हो, विधायक ने वीडियो को फर्जी करार दिया है और डीसी व एसपी से इसकी जांच करने की मांग भी की है। अभी इसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है।

हनी ट्रैप का मामला तो नहीं : चर्चा यह भी है कि आधा दर्जन से अधिक विधायकों के वीडियो, ऑडियो और सेक्स चैट वायरल हो रहे हैं। पूरे मामले को हनी ट्रैप से जोड़कर देखा जा रहा है। बिरंची नारायण के वीडियो के बारे में सूत्रों के अनुसार चर्चा है कि यह वीडियो उत्तराखंड के किसी होटल का है।

दैनिक जागरण

समस्या कितनी भी विकराल क्यों न हो उसका समाधान अवश्य होता है

अयोध्या और राजनीति

यह देखना सुखद है कि अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय के बहुप्रतीक्षित फैसले को देश ने धैर्य के साथ स्वीकार किया और कहीं पर भी कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई जो चिंता का कारण बने। पूरे देश को प्रभावित करने वाले एक बड़े फैसले पर आम जनता का ऐसा संयमित आचरण उसकी परिपक्वता को ही रेखांकित करता है। इस परिपक्व आचरण की सराहना की जानी चाहिए-इसलिए और भी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के फैसले को उन्होंने भी स्वीकार किया जो अयोध्या में मस्जिद निर्माण के पक्ष में पैरवी कर रहे थे। निःसंदेह यह देखना भी सुखद है कि अयोध्या मसले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को करीब-करीब सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने भी स्वीकार किया। इनमें वे दल भी हैं जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग का न केवल विरोध किया करते थे, बल्कि ऐसी मांग के समर्थकों के तिरस्कार का कोई मौका भी नहीं छोड़ते थे। अब अगर ऐसे दलों के स्वर बदले हुए हैं तो इसका अर्थ यही है कि उन्हें यह आभास हो गया कि अयोध्या में राम जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हो, यह आकांक्षा केवल कुछ धार्मिक, सांस्कृतिक संगठनों की ही नहीं, बल्कि व्यापक हिंदू समाज की थी। दुर्भाग्य से इस आकांक्षा की न केवल अनदेखी की गई, बल्कि उसका उपहास भी उड़ाया गया। इतना ही नहीं, राम मंदिर निर्माण की मांग को खारिज करने को एक तरह का सेक्युलर दायित्व बना दिया गया। इसी के साथ मस्जिद के स्थान पर प्राचीन राम मंदिर होने का उल्लेख करने वालों को भी निंदित किया जाने लगा। सबसे दुर्भाग्य की बात यह रही कि इस काम में खुद को इतिहासकार कहने वाले लोग भी शामिल हो गए। इन इतिहासकारों की ओर से अयोध्या में राम मंदिर होने के अलावा अन्य सब कुछ होने के विचित्र और हास्यास्पद दावे किए जाने लगे। ऐसे ही दौर में जब भाजपा ने खुद को अयोध्या आंदोलन से जोड़ा तो स्वयं को सेक्युलर-लिबरल कहने वाले नेताओं और विचारकों ने उसे लांछित करना शुरू कर दिया। उनकी ओर से ऐसा प्रचारित किया जाने लगा मानो समाज के एक बड़े वर्ग की भावनाओं से जुड़े किसी मसले को उठाना कोई संगीन राजनीतिक अपराध हो। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की खुलकर पैरवी करने के कारण भाजपा को राजनीतिक रूप से अछूत तो बनाया ही गया, उस पर यह आरोप भी मढ़ा गया कि वह अयोध्या पर राजनीति कर रही है। यह आरोप उछालने वालों ने इसकी अनदेखी करने में ही अपनी भलाई समझी कि अयोध्या के विवादित स्थल पर मस्जिद निर्माण की उनकी पैरवी वोट बैंक की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं थी। यही कथित सेक्युलर राजनीति अयोध्या मसले को आपसी बातचीत से हल करने में बाधक बनी। इसी राजनीति ने एक ऐसा माहौल बनाया कि न्यायपालिका को अयोध्या विवाद को हल करने को प्राथमिकता देने से बचना चाहिए। ऐसा तब था जब भाजपा की ओर से यही कहा जा रहा था कि न्यायपालिका सदियों पुराने इस विवाद को जल्द सुलझाए। भाजपा इसके लिए भी सक्रिय रही कि आपसी बातचीत से इस विवाद का समाधान हो जाए। इसमें किन दलों की ओर से कैसे अड़ंगे लगाए गए, यह किसी से छिपा नहीं।

आज यदि लगभग सभी विपक्षी दल अयोध्या फैसले का समर्थन कर रहे हैं तो इससे उनकी पुरानी भूल ही रेखांकित हो रही है

इससे इन्कार नहीं कि 1992 में विवादित ढांचे का ध्वंस एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। हैरत नहीं कि उच्चतम न्यायालय ने इस घटना को आपराधिक कृत्य कहा। उसने विवादित परिसर में मूर्तियां रखने को भी गलत ठहराया, लेकिन इन कृत्यों से यह तथ्य ओझल नहीं होता था कि मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया। आखिरकार यही साबित हुआ कि ये तथ्य सही थे। इसमें दोराय नहीं कि विवादित ढांचे के ध्वंस ने देश पर गहरा असर डाला, लेकिन उन राजनीतिक दलों के रवैये में कोई खास फर्क नहीं आया जो भाजपा को सांप्रदायिक घोषित कर सेक्युलर राजनीति करने का दम भरते थे। विवादित ढांचे के ध्वंस के बाद भाजपा अपने चुनाव घोषणा पत्रों में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग का समर्थन करने तक सीमित रह गई। इसके अतिरिक्त उसके नेताओं की ओर से जब-तब यह यह कह दिया जाता था कि अयोध्या उनके एजेंडे में है। जब ऐसे बयान आते तो विपक्षी दल उस पर सांप्रदायिकता फैलाने की तोहमत मढ़ते और जब भाजपा किन्हीं खास मौकों पर राम मंदिर निर्माण की मांग का जोर-शोर से समर्थन करती नहीं दिखती तो उस पर ऐसे कटाक्ष किए जाते कि राम मंदिर निर्माण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता दिखावटी है। ऐसे कटाक्ष यही प्रतीति कराते थे कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात कोई दल कर सकता है तो केवल भाजपा ही। साफ है कि यदि अयोध्या पर राजनीति की गई तो भाजपा से अधिक उसके विरोधी राजनीतिक दलों की ओर से की गई। आज यदि लगभग सभी विपक्षी दल अयोध्या पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का समर्थन कर रहे हैं तो इससे उनकी पुरानी भूल ही रेखांकित हो रही है। बेहतर हो कि इस भूल को स्वीकार कर यह समझा जाए कि राजनीतिक परिपक्वता के प्रदर्शन में ही सबका हित है।

राम नाम की महिमा

हृदयनारायण दीक्षित

श्रीराम का आख्यान भारत के गांव गली तक व्याप्त है। देश का वातायन राममय है। इसीलिए अदालती कार्यवाही पर भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की नजर लगी हुई थी

आस्था भावविह्वल होती है। उस पर चोट बहुत सालती है। मन आशा और निराशा के बीच डोलता है। परिस्थितियां भले ही निराशाजनक हों, लेकिन आस्तिकता से आशा बनी रहती है। श्रीराम भारत की आस्था हैं। इतिहास के महानायक हैं। वह भारत का मन अंतरंग हैं। राष्ट्र के पौरुष पराक्रम के प्रतीक हैं। भारत का रोम-रोम 'राम-राम' में रमा हुआ है। मिले तो जय राम, अलग हुए तो राम-राम। संसार छोड़ें तो 'राम नाम सत्य'। भारत की श्रुति, स्मृति और काव्य का अंतस् हैं श्रीराम। देश के लगभग 70 प्रतिशत नागरिकों के नाम राम या रामकथा से जुड़े हुए हैं। वाल्मीकि और तुलसी की कविता में राम नाम श्रेष्ठ है, वाणी का क्षीर सागर है। मन संकल्प हैं, ध्यान और विज्ञान भी हैं। वह भारत के धैर्य गुण राम का प्रसाद हैं। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का ध्वंस बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने 1528 में किया था। तबसे 491 साल हो गए। यह आस्था पर हमला था। फिर अंग्रेजीराज से मुकदमों का दौर चला। कोई 161 साल हो गए। आशा और धीरज जवाब दे रहे थे। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय की प्रतीक्षा थी।

निर्णय की अधीरता के कारण सुस्पष्ट हैं। भारतीय श्रद्धा ने राम को अपने हृदय में बैठाया है, लेकिन वह इतिहास में हैं, भूगोल में भी हैं। डॉ. सत्यकेतु ने 'प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग' में लिखा है कि भारतीय ज्ञात इतिहास में मनु पहले राजा थे। इक्ष्वाकु उनके पुत्र थे। मनु और इक्ष्वाकु का उल्लेख ऋग्वेद में भी है। इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा थे। इनकी 19 पीढ़ी बाद राजा मांधाता हैं। उनके पुत्र पुरुकुत्स भी अयोध्या के राजा थे। इनके 11 पीढ़ी बाद हरिश्चंद्र। 41वीं पीढ़ी में सगर, 45वीं में भगीरथ। 60वीं में दिलीप और फिर दिलीप के पौत्र रघु। रघु के कारण ही श्रीराम रघुवंशी कहे गए। रघु के पुत्र अज और अज के पुत्र दशरथ। फिर श्रीराम। आदिकवि वाल्मीकि ने 'रामायण' में इन्हीं श्रीराम के इतिहास को महाकाव्य बनाया। वाल्मीकि के राम मनुष्य हैं, मर्यादा में सर्वोत्तम हैं। आस्था में ब्रह्म हैं। तुलसी के श्रीराम ब्रह्म हैं। वह अवतार लेते हैं। लीला करते हैं। श्रीराम का आख्यान भारत के गांव गली तक व्याप्त है। वह भारत के कण-कण में हैं। भारत का वातायन राममय है। इसीलिए अदालती कार्यवाही पर भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की नजर टिकी हुई थी।

श्रीराम का चरित्र और व्यक्तित्व विश्वव्यापी है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम राम की व्यापकता है। संस्कृत और प्राकृत सहित दुनिया की अनेक भाषाओं में श्रीराम कथाएं हैं। चीन के लियो ताउत्स चिंग का कथानक वाल्मीकि रामायण से संबंधित है। चीन के उपन्यासकार ऊचेंग की 'दि मंकी हसी ऊचि' राम के समकालीन हनुमान की कथा है। इंडोनेशिया में रामकथा पर 'ककविन रामायण' है। थाइलैंड में 'रामकियेन' है। लाओस में 'फालाम' एवं 'पोमचाक' हैं। मलेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, फिलीपींस तक राम चरित्र की व्यापकता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तमिल में 'तिरुमगन रामायण' लिखी थी। अनुवाद उनकी पुत्री एवं गांधी जी की बहू लक्ष्मी ने किया था। राजाजी ने भूमिका में लिखा, 'सीताराम, हनुमान और भारत को छोड़कर हमारी कोई गति नहीं। रामकथा पूर्वजों की धरोहर है। हम आज इसी के आधार पर जीवित हैं।' यहां रामकथा ही राष्ट्रजीवन का प्राण है। डॉ. राममनोहर लोहिया ने लिखा, 'राम की पूर्णता मर्यादित व्यक्तित्व में है। उन जैसा व्यक्तित्व कहीं नहीं। न इतिहास में और न कल्पना में। राम समन्वय के प्रतीक हैं। न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक। राम आनंद सागर हैं-हिलोरें लेने वाला सागर नहीं। विश्रांत निष्पंद।' ऐसे में श्रीराम जन्मभूमि मुकदमे के फैसले को सुनने की चरम राष्ट्रीय जिज्ञासा स्वाभाविक ही थी।

न्यायिक इतिहास में निर्णय की ऐसी प्रतीक्षा का दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। उदारमना हिंदू मानस ने लगातार प्रतीक्षा की। सभी लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक उपाय अपनाए। हाईकोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा की। मसला सर्वोच्च न्यायालय गया। यह उत्सुकता और जिज्ञासा की पराकाष्ठा थी। बाबरी निर्माण का मकसद उपासना स्थल बनाना नहीं था। मध्यकालीन सत्ता ने आस्था को कुचलने के ढेर सारे काम किए थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निकट 'कूवतुल इस्लाम' नाम की मस्जिद मंदिर सामग्री से बनी थी। इसका अर्थ इस्लाम की ताकत है। अजमेर में 'अढ़ाई दिन का झोपड़ा' एवं धार में भोजशाला मस्जिद के साथ औरंगजेब ने भी राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के लिए ऐसे ही अपकृत्य किए थे। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार अर्नोल्ड टायनबी ने दिल्ली में कहा था, 'पोलैंड के वारसा पर रूसी अधिकार के समय कैथेड्रल बनाया गया था। यह कार्य रूसियों ने पोलिसों को यह अहसास दिलाने के लिए किया था कि अब उनके भाग्यविधाता रूसी हैं। 1918 में पोलैंड ने स्वतंत्र होते ही कैथेड्रल गिरा दिया। रूसियों का प्रयोजन राजनीतिक था। औरंगजेब का उद्देश्य भी यही था।' बाबर का मकसद भी यही था।

गांधी जी ने स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व किया। रामराज्य का आदर्श रखा। रामराज्य की कल्पना में सभी अभिलाषाएं हैं। वाल्मीकि के अनुसार श्रीराम ने वनवास में मिलने गए भरत को अर्थविज्ञान का उपदेश दिया। राज्य व्यवस्था के तमाम सूत्र बताए। उन्होंने कहा, 'तब समय पर वर्षा होती है और सब तरफ समृद्धि-काले वर्षति पर्जन्यः सुभिक्षं विमला दिशः। न रोग, न पीड़ा, न अकाल मृत्यु।' तुलसी रामराज्य में समता का आदर्श रखते हैं-'राम प्रताप विषमता खोई।' रामराज्य में कोई दुखी नहीं। सब समृद्धि का हिस्सा पाते हैं। श्रीराम मंगल भवन हैं और अमंगलहारी हैं। कालिदास ने रघुवंश में राम के समय के इतिहासबोध की चर्चा की है कि विश्वामित्र ने श्रीराम को पुरावृत्त सुनाया था। भवभूति कालिदास और राजशेखर ने रामायण को इतिहास बताया है। बौद्ध जातकों में भी अयोध्या के इक्ष्वाकुवंशी मांधाता दशरथ एवं श्रीराम के उल्लेख हैं।

श्रीराम भारत के गौरवशाली इतिहास में हैं। सरयू का उल्लेख ऋग्वेद में है। अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद एवं तैत्तिरीय आरण्यक में है। यहां मनुष्य को नौ द्वारों वाली देवनगरी अयोध्या कहा गया है। अयोध्या का भाव अर्थ है अपराजेय। पुरातत्वविद् सांकालिया ने अयोध्या के आसपास के तमाम विवरण दिए हैं। अयोध्या और श्रीराम भारतीय इतिहास के सभी चरणों में हैं। राम की लौकिकता असंदिग्ध है और पारलौकिकता लोक आस्था की स्वीकृति। आस्था का जन्म और विकास प्रवाह 50-60 वर्ष में नहीं होता। श्रीराम के जन्म के सहस्त्रों वर्ष बीत गए। वाद हुए, प्रतिवाद हुए। खंडन-मंडन भी हुए। श्रीराम की कीर्ति विश्वव्यापी होती रही। तुलसीदास के विवरण में श्रीराम का नाम श्रीराम से भी बहुत व्यापक बीजमंत्र बना। ऐसे श्रीराम की जन्मभूमि का आहतकारी विवाद सैकड़ों वर्ष चला। इस दफा सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार 40 दिन सुनवाई की। परिणाम की प्रतीक्षा में भारत अधीर था। सारी दुनिया के हृदय स्पंदित थे। परिणाम आ गया है। अब लोकजीवन में उल्लास है।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

इतिहास से सबक लेने का समय

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले से सदियों पुराने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को सुलझा कर देश में सांप्रदायिक सौहार्द की एक मजबूत नींव रख दी है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट स्थापित करने और मस्जिद के लिए वैकल्पिक भूमि आवंटित करने का आदेश दिया है। देखा जाए तो यह विवाद हमारे समय के सबसे तल्ख मुद्दों में से एक था जिसका अब अंत हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुस्लिम समुदाय इससे सबक लेगा और सामाजिक सद्भाव कायम करने में आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभाएगा। दरअसल 1947 में धर्म के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन तमाम गहरे जख्म छोड़ गया था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदू और मुस्लिम, दो ऐसे समुदाय थे जो एक-दूसरे के बहुत करीब थे और कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, लेकिन विभाजन के बाद प्रेम, सद्भाव और भाईचारे जैसी भावनाएं नाराजगी, अविश्वास और संदेह में बदल गई थीं। विभाजन के लगभग चार दशक बाद राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद ने तो जैसे दोनों समाजों के बीच विभाजन की खाई को और चौड़ा कर दिया। हालांकि मुस्लिम नेता इसे सद्भाव बहाल करने के लिए दूसरे ऐतिहासिक अवसर के रूप में ले सकते थे। मगर ऐसा नहीं हुआ। बेहतर होता कि उन्हें शुरू में ही मंदिर निर्माण के प्रस्ताव को पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर मस्जिद को स्वयं स्थानांतरित करने का सुझाव देना चाहिए था, लेकिन ऐसा सोच पाना जैसे उनकी बुद्धिमता के परे था।

इस्लामिक देशों में ऐसे पर्याप्त उदाहरण हैं जहां मस्जिदों को स्थानांतरित कर दिया गया है। मुस्लिम देश इस फॉर्मूले को पहले ही अपना चुके थे जो अपनी अर्थव्यवस्था की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने यहां स्थित मस्जिदों को स्थानांतरित कर रहे थे। धर्म एक ऐसा अनुशासन है जो अपने अनुयायियों को समाज का एक शांतिपूर्ण सदस्य बनने का संदेश देता है, लेकिन इसके विपरीत धर्म को हमेशा एक विभाजनकारी शक्ति के रूप में देखा गया। मैने यह बात कुछ वर्ष पहले भी कही थी कि भारतीय मुस्लिम नेतृत्व समूचे अयोध्या प्रकरण में मुस्लिम समुदाय के विचारों को एक सकारात्मक ढांचा नहीं दे पाया। समुदाय के नेताओं को अतीत से बाहर आकर देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी। इसके बजाय वे नकारात्मक भावनाओं में जकड़े रहे और अपने दिलों में नाराजगी को

रामिश सिद्दीकी

अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर उससे सही सीख लेकर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जरूर बेहतर बनाया जा सकता है

रखते हुए अपनी संपूर्ण शक्ति को नकारात्मक दिशा में लगाते रहे। एक राष्ट्र अपनी संस्कृति, समाज, आस्था और इतिहास का एक सम्मिश्रण होता है। संस्कृति और इतिहास का संरक्षण और किसी धर्म या आस्था में विश्वास किसी भी समाज के अस्तित्व के दो अलग-अलग पहलू हैं।

उदाहरण के लिए अरब देशों ने अपने इतिहास को पुनर्स्थापित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से भारी निवेश करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने अपना धर्म त्याग दिया है। मैं एक बार संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में एक बहु-सांस्कृतिक कार्यक्रम में गया था जहां मैंने मिस्र के हॉल का दौरा किया था। मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ था कि एक मुस्लिम देश होने के बावजूद मिस्र अपनी इस्लाम से पूर्व की संस्कृति को विश्व के सामने लाने में बिल्कुल पीछे नहीं था, बल्कि वह इस्लाम पूर्व की संस्कृति को अपना अभिन्न अंग मानता है। यह हमारे लिए भी एक सीख थी। मिस्र का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। 'मुस्लिम ब्रदरहुड' जैसा कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन मिस्र की जमीन पर ही पनपा है, लेकिन ऐसा हिंसक संगठन भी मिस्र को अपने इतिहास एवं संस्कृति का सम्मान करने से नहीं रोक पाया। भारतीय मुसलमानों के लिए भी यह जरूरी है कि वे इस देश का नागरिक होने के कारण यहां के विकास और भारत की प्राचीन संस्कृति के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाएं। भारत हमेशा से आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान का जन्मस्थान रहा है। एक भारतीय के रूप में हमारे लिए आवश्यक है कि हम स्वयं को बेहतर बनाते हुए एक-दूसरे की आस्थाओं का सम्मान भी करें।

मुस्लिम समुदाय के चंद नेताओं ने न सिर्फ सामाजिक ताने-बाने को, बल्कि इस भावनात्मक मुद्दे पर आम आदमी की भावनाओं को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। वर्तमान समय में भारत के मुस्लिम युवाओं के लिए अब बहुत आवश्यक हो गया है कि वे समुदाय के इन नेताओं का अंधानुकरण बिल्कुल न करें। उनके लिए जरूरी है कि वे अपनी सोच और ताकत को देश निर्माण के सकारात्मक कार्यों में लगाएं। मध्यकालीन यूरोप में जब धार्मिक व्यक्तियों द्वारा बौद्धिक उत्पीड़न अपने चरम पर था और इतिहास को धीरे-धीरे मिटाया जा रहा था तब वहां चंद लोगों ने एक शांतिपूर्ण आंदोलन छेड़ा जिसे विश्व 'पुनर्जागरण' के नाम से जानता है। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने न सिर्फ उनके जीवन को, बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा दी।

पुनर्जागरण ने मानवता को आधुनिक सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ाया। उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं, जो केवल एक समाज या एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि समस्त मानवजाति तक पहुंचा है। पुनर्जागरण ने यूरोपीय लोगों की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। जो लोग स्वयं अंधकार के दलदल में धंस चुके थे, उन्होंने अपनी इच्छाशक्ति से पूरी दुनिया की खोज कर डाली। भारतीय मुस्लिम समुदाय को आज एक ऐसे ही बौद्धिक पुनर्जागरण की जरूरत है, ताकि वे दशकों से फंसे पूर्वाग्रहों की गहराइयों से बाहर निकल सकें, लेकिन इस तरह के आंदोलन की शुरुआत तब होती है जब हम जानते और मानते हैं कि अतीत में हमसे क्या गलतियां हुई हैं। कोई भी व्यक्ति या समाज इतिहास में वापस जाकर उसे दोबारा नहीं लिख सकता है, लेकिन एक कार्य हम सब निश्चित रूप से कर सकते हैं। और वह है कि हम इतिहास से सबक लें, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने में कामयाब हो सकें। एक राष्ट्र का सबसे बड़ा संसाधन उसके लोग होते हैं। यह स्वाभाविक है कि किसी भी राष्ट्र को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए वहां के नागरिक अपने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें।

(लेखक इस्लामिक विषयों के जानकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

संगति

सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य को किसी न किसी के साथ की आवश्यकता जरूर होती है और यही संगति उसके व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करती है। संगति का प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति से जहां व्यक्ति यश एवं कीर्ति कमाता है, वहीं बुरी संगति उसके पतन का कारण बनती है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता उसकी संगति से ही चल जाता है। कहते भी हैं कि किसी व्यक्ति का आचरण-व्यवहार जानना हो तो उसके मित्रों का आचरण जान लो। यानी जिस व्यक्ति के मित्र अच्छे आचरण वाले होंगे, वह वैसे ही आचरण को आत्मसात करेगा। कोई भी इंसान अपनी संगति से ही जाना-पहचाना जाता है। यदि हम समाज के अच्छे लोगों के साथ उठेंगे-बैठेंगे तो हमारी तुलना उनके साथ ही की जाएगी और यदि हम दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का साथ लेंगे तो हम उनकी तरह बन जाएंगे। व्यक्ति पर संगति का असर जाने-अनजाने में पड़ ही जाता है। कोई लाख कोशिश कर ले, वह इससे बच ही नहीं सकता। काजल की कोठरी में जाने के बाद कालिख लग ही जाती है। ऐसे में प्रत्येक मनुष्य को विवेक प्राप्त करने के लिए अच्छी संगति को अपनाना चाहिए।

असल में मूलरूप से मनुष्य के विचार और कर्म को उसके संस्कार एवं परिवेश ही दिशा देते हैं। यदि उसे अच्छे संस्कार और स्वच्छ परिवेश मिलते हैं तो वह कल्याण के मार्ग पर चलता है। यदि वह दूषित परिवेश में रहता है तो उसके कार्य भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में सर्वप्रथम व्यक्ति को अपनी इच्छा-कामना को नियंत्रण में रखने के लिए अपनी संगति सुधारनी चाहिए। यदि मनुष्य अपनी संगति सुधार ले तो उसका पूरा जीवन सुधर जाएगा। संगति व्यक्ति को स्वाभिमानी और उसे कठिन परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। संगति का असर इस तरह होता है कि सज्जनों की संगति से दुर्जन भी सज्जन बन जाता है। यानी व्यक्ति योगी के साथ योगी और भोगी के साथ भोगी बन जाता है।

आचार्य अनिल वत्स

मेल-मिलाप बढ़ाने वाला फैसला

सुशील कुमार सिंह

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देश में धार्मिक मेल-मिलाप बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा

जब न्याय समाजशास्त्र और धर्मशास्त्र के समुचित समिश्रण के साथ एकजुटता के मार्ग से गुजरता है तो इतिहास बनना स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या मामले में आया सुप्रीम फैसला हिंदू-मुस्लिम रिश्तों की तुरपाई करते हुए लोगों के बीच जिस सद्भावना के साथ उतारा गया उसे देखते हुए कह सकते हैं कि देश को अपेक्षा भी कुछ ऐसी ही थी। न्यायालय का यह फैसला देश को एकजुट करने का काम करेगा। गौरतलब है कि 9 नवंबर, 2019 की तारीख, इतिहास में दर्ज एक ऐसा साक्ष्य है जो सदियों तक नहीं भुलाया जा सकेगा। सैकड़ों वर्ष पुराने मामले और दशकों से चल रहे विवाद को शीर्ष अदालत ने जड़ से समाप्त कर दिया। जाहिर है अब मंदिर निर्माण का न केवल रास्ता साफ हो गया है, बल्कि मस्जिद निर्माण के लिए अलग से जमीन आवंटित करने का निर्णय धार्मिक मेलमिलाप का बड़ा उदाहरण भी है।

राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस के इतिहास पर एक नजर डालें तो पड़ताल बताती है कि जिस स्थान पर 1528 में मस्जिद का निर्माण हुआ था। हिंदू मान्यता के अनुसार इसी जगह पर भगवान राम का जन्म हुआ था। 1853 में हिंदुओं का आरोप था कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है, जिसे लेकर विवाद गहराया और दोनों पक्षों के बीच संघर्ष हुआ। साल 1859 में ब्रिटिश सरकार ने तारों की एक बड़ी बाड़ खड़ी करके अंदर और बाहर के परिसर में हिंदू और मुस्लिम पक्ष को अलग-अलग प्रार्थना करने की इजाजत दी। दशक बीतते गए और मामला 1885 में पहली बार तब अदालत पहुंचा जब महंत रघुवर दास ने फैजाबाद कोर्ट से बाबरी मस्जिद के पास ही राम मंदिर निर्माण की इजाजत मांगी, तब देश औपनिवेशिक सत्ता के अधीन था। आजादी के बाद 23 दिसंबर, 1949 में लगभग 50 हिंदुओं ने मस्जिद के केंद्रीय स्थल पर जैसे कि कहा जाता है, भगवान राम की मूर्ति रख दी। इसके बाद उस स्थान पर हिंदू समुदाय के लोग नियमित पूजा करने लगे और इसी के साथ मुसलमानों ने यहां नमाज पढ़ना बंद कर दिया। सिलसिलेवार तरीके से मामला आगे बढ़ता रहा, मंदिर निर्माण को लेकर जब-तब कई प्रयास भी हुए। इसी दौरान बाबरी मस्जिद 1992 में गिरा दी गई। जुलाई 2009 में लिब्राहन आयोग ने 17 साल बाद रिपोर्ट सौंपी। 30 सितंबर, 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया और विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बांट दिया गया। जिसमें एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड, जबकि तीसरा निर्मोही अखड़ा को देने का निर्णय दिया। अब शीर्ष अदालत ने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय दिया है जो अंतिम और अटल सत्य है, जिसका इंतजार देश की जनता कर रही थी। खास बात यह है कि इस निर्णय को लेकर देश भी एकजुटता दिखा रहा है। सियासी तौर पर भी सभी दल इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। यह भारत की विभिन्नता में एकता का ऐसा प्रतीक है, जिसे आज दुनिया एक बार फिर से समझने के लिए मजबूर हो रही होगी।

(लेखक वाईएस रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के निदेशक हैं)

मेलबाक्स

दूर हुआ विवाद

नया इतिहास लिखने वाला फैसला शीर्षक से लिखे अपने आलेख में संजय गुप्त ने जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले का समग्र विश्लेषण करते हुए देश के लिए आगे की राह सुझाई है। उल्लेखनीय है कि त्रेता युग के राम को केवल चौदह वर्षों तक वनवास में रहना पड़ा था, लेकिन कलियुग में तो उन्हें लगभग पांच सौ वर्षों का वनवास भोगना पड़ा, परंतु जैसा कि कहा गया है 'हारो न हिम्मत, बिसारो न राम को' तो राम भक्तों ने भी अपने आराध्य के लिए संघर्ष कभी छोड़ा नहीं। तब भी नहीं जब देश में मुगल अथवा ब्रिटिश आक्रांताओं का शासन था और तब भी नहीं जब आजाद भारत में वामपंथी इतिहासकारों द्वारा ऐतिहासिक सच्चाई को झुठलाने की तमाम कोशिशें की गईं। अंततः सदियों के उनके संघर्ष तथा ऐतिहासिक साक्ष्यों के आलोक में उन्हें राम जन्मभूमि के अंदर और बाहर का अहाता यानी पूरी जमीन मंदिर निर्माण के लिए मिल गई। माननीय न्यायालय का यह निर्णय एकतरफा नहीं है। उसने इस मामले का सौहार्दपूर्ण पटाक्षेप करते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी पांच एकड़ भूमि देने का आदेश सरकार को दिया है, ताकि वह वहां पर मुस्लिम समाज के लिए मस्जिद का निर्माण कर सके। फैसले को सुनकर कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी की याद आ गई। माननीय न्यायाधीशों ने इस अभूतपूर्व फैसले से 1528 और फिर 1992 में दो अलग-अलग पक्ष के द्वारा की गई गलतियों को एक साथ दुरुस्त कर दिया है। निःसंदेह उन्होंने न्याय सुनिश्चित करने के अपने दायित्व का पूरे मनोयोग से निर्वहन किया है। सभी जीत गए, कोई न हारा। यहां गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित वह पंक्ति बरबस ही याद आ रही है, 'प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जनम हमार सुफल भा आजू।'

चंदन कुमार, देवघर

अब सिर्फ सौहार्द की जरूरत

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला दो समुदायों के बीच सौहार्द स्थापित करने की दिशा में अच्छा कदम रहा। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी फैसले का सम्मान करने की बात की। विकास के मुद्दे को लेकर देश को आगे बढ़ाने की बात पर सहमति बनती नजर आई। इस बीच ओवैसी का बयान थोड़ा दुखदायी था। ऐसे वक्त में सभी को एकता की बात करनी चाहिए। यह भारत देश के प्रजातंत्र एवं न्याय प्रणाली की महानता है। हमारी न्याय व्यवस्था में देर है अंधेर नहीं है। आज भारत वर्ष को सौहार्द का एक नया अध्याय शुरू करने की जरूरत है न की आने वाली नस्लों को आधे अधूरे तथ्य बताकर भड़काने की।

udai.srivastava@rediffmail.com

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय

अयोध्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वह ऐतिहासिक था। यह फैसला ना तो हिंदूवादी नजर से देखा जाना चाहिए और ना ही मुस्लिमवादी नजरिए से, यह किसी धर्म विशेष के लिए फैसला नहीं है, बल्कि यह तो भारत का फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाते हुए सभी पक्षों का ध्यान रखा है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विवादित स्थल पर रामलला मौजूद थे, वहीं मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए वैकल्पिक जमीन देने की बात कही, भारत में विभिन्न धर्मों का जन्म एवं विभिन्न संस्कृतियों का जन्म हुआ है और सभी धर्म एक साथ आगे बढ़े सुप्रीम कोर्ट ने इस पक्ष का भी पूरी तरह से ध्यान रखा। श्री रामचंद्र जी सिर्फ आस्था के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं और अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनना भारतीय संस्कृति की जीत मानी जाएगी। मुस्लिम समाज की संतुष्टि के लिए भी एक मस्जिद बनाने की बात कही गई है वैसे भी विवादित स्थल पर मस्जिद बनना उचित नहीं होता, क्योंकि विवादित स्थल पर नमाज अदा नहीं की जाती है। हमें तारीफ करनी होगी भारतीय जनमानस की भी, क्योंकि इस फैसले को सभी पक्षों ने आपसी सौहार्द पूर्ण से स्वीकार किया। इसके साथ ही आपसी भाईचारा का संदेश देते हुए भारत की धर्मनिरपेक्षता की जड़ों को और अधिक मजबूत किया। अयोध्या में राम मंदिर बनना उन लोगों के लिए भी कड़ा संदेश जाएगा जो इसको सांप्रदायिक नजर से देख रहे हैं।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

उमेश चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार

आजकल

अयोध्या से आगे बढ़ने का वक्त

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की राह प्रशस्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसका पूरे देश में स्वागत किया जा रहा है। हालांकि प्रगतिवादी सोच और राजनीति ने राम मंदिर आंदोलन को कुछ सैद्धांतिक आधार पर झूठा साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीय समाज अपनी आस्था पर मजबूती के साथ डटा रहा। राम मंदिर के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया है, उसमें परोक्ष रूप से कहीं न कहीं इस चट्टानी आस्था ने भी भूमिका निभाई है

प्रतीकात्मक

बेशक सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला राम मंदिर पर ही दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में बाकी ऐतिहासिक और मिथकीय महत्व वाली विवादित जगहों के लिए भी उदाहरण के तौर पर पेश किया जाएगा। कम से कम वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ही बतौर नजीर पेश किया जाएगा। वैसे भी विश्व हिंदू परिषद ने जब राम मंदिर का आंदोलन छेड़ा था, तब उसके एजेंडे में अयोध्या की राम जन्मभूमि के साथ ही वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि को भी अतिक्रमण से मुक्त कराना था। हालांकि राम मंदिर पर सुप्रीम फैसला आने के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दी है, उससे इन मामलों को तत्काल उठाने पर संशय है। संघ प्रमुख ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि राम मंदिर के फैसले को जय या पराजय के नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए।

सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही नहीं, दूसरे संगठनों की प्रतिक्रियाओं से भी जाहिर है कि अब वे भी मानने लगे हैं कि मौजूदा हालात में देश की सबसे बड़ी जरूरत आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर आगे बढ़ना है। दुनिया के किसी भी समाज को देखिए, वह अपने सांस्कृतिक गौरव की ओर तब और ज्यादा शिद्दत से बढ़ता है, जब वह आर्थिक और सामाजिक रूप से ज्यादा मजबूत होता है। हालांकि प्रगतिवादी मान्यता रही है कि आर्थिक और सामाजिक मंच पर पूरी ताकत से स्थापित हो चुके राष्ट्र और समाज सांस्कृतिक गौरव बोध को भुला देते हैं। लेकिन यह पूरा सच नहीं है। प्रगतिवादी सोच मानती रही है कि जैसे-जैसे भारतीय समाज आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक रूप से आगे बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे वह अपने सांस्कृतिक गौरव से बेपरवाह होता जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खोदाई में मिले साक्ष्यों को ही आधार मानते हुए फैसला दिया है कि मीर बकी ने खाली जगह पर मस्जिद नहीं बनाई थी। विश्व हिंदू परिषद ही नहीं, व्यापक हिंदू समाज का भी तो यही आरोप है कि जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है, उसी मुगलिया सल्तनत काल में सनातन समाज पर राजकीय हमले हुए, उसकी आस्थाओं के केंद्रों को निशाना बनाया गया। उनके मंदिर तोड़े गए और वहां मस्जिदें बनाई गईं। इसके बाद इसी दौर में भक्तिकालीन कवियों- सूरदास, तुलसीदास आदि ने हिंदू समाज को जागृत किया।

कालांतर में आए तमाम बदलावों के बाद वर्ष 1986 के बाद आई नई शिक्षा नीति के बाद से अनेक मान्यताओं को किनारे किया गया। इसी दौर में राम मंदिर आंदोलन परवान चढ़ता है। सनातन समाज यह समझ नहीं पाया कि गंगा-जमुनी संस्कृति के नाम उसके साथ अतीत में हुए दुर्व्यवहार और उससे जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को क्यों नकारा जा रहा है। निश्चित ही तब की सत्ताधारी ताकतों ने अपने राजनीतिक हित के लिए इस तरह के विचार को पोषित किया। दरअसल तत्कालीन सत्ताधारी ताकतें अल्पसंख्यक मानस की एक विशेषता का दोहन करती रहीं। अल्पसंख्यक मानस हमेशा बहुसंख्यक के मुकाबले खुद को एक रखता है। लेकिन यह भी तब होता है, जब उसे यह ध्यान दिलाया जाए कि बहुसंख्यक समाज से उसे खतरा है। डरी हुई अल्पसंख्यक एकता का मानस राजनीतिक महापर्व में थोक के भाव से एकतरफा मत के रूप में समर्थन देता रहा है।

भारतीय राजनीति जिस मोड़ पर इन दिनों खड़ी है, उसमें तत्काल अभी किसी और बड़े आंदोलन की संभावना नहीं है। देश के सामने अगले कुछ वर्षों में पांच खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बनने का लक्ष्य है। अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर भारत को मजबूती से खड़ा करने के उद्देश्य को साकार तभी किया जा सकता है, जब ऐसे आंदोलनों से कम से कम इस प्रक्रिया के पूरी होने तक दूरी बनाई जाए। तब राम मंदिर की तरह के दूसरे लक्ष्यों को भी हासिल करना आसान होगा। वैसे भी नरेंद्र मोदी- अमित शाह की जोड़ी ने दिखा दिया है कि उनकी इच्छा शक्ति कितनी मजूबत है। उसे जब राजनीतिक आधार मिला तो उसने अनुच्छेद 370 के विवादित प्रावधानों को खत्म करने के साथ ही तीन तलाक के जरिये मुसलमान समुदाय की महिलाओं को न्याय दिलाने के असंभव समझे जाने वाले कामों को जमीन पर उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख राजनीतिक मुद्दा राम मंदिर का निर्माण, समान नागरिक संहिता और जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाना रहे हैं। अतीत में भाजपा राजनीतिक मजबूरियों की वजह से इन लक्ष्यों को कुछ वक्त के लिए मुल्तवी भी करती रही है। लेकिन अब परिदृश्य बदला हुआ है। अनुच्छेद 370 के विवादित अंश बीती हुई बात हो चुके हैं, राम मंदिर के लिए सर्वोच्च अदालत ने रास्ता बना दिया। इसलिए भाजपा का समर्थक वर्ग उम्मीद कर सकता है कि जल्द ही वह बाकी लक्ष्यों को हासिल कर सकती है। भाजपा के प्रति उसके समर्थक आधार वर्ग का यह भरोसा बाकी विवादित मुद्दों से कम से कम कुछ हद तक दूर रखने के दबाव वर्ग के रूप में कार्य करेगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना भी हो रही है। प्रगतिशील ताकतों ने एक तरह से अल्पसंख्यक वर्ग को उकसाते हुए सुप्रीम कोर्ट के लिए कहना शुरू कर दिया है कि उसने मान लिया है कि अल्पसंख्यक दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। अगर सबसे अच्छी प्रतिक्रिया किसी की मानी जा सकती है तो वह है इकबाल अंसारी की। उन्होंने कहा है कि यह मसला बहुत अहम था, जो अब खत्म हो गया। मैं खुश हूं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं। राम मंदिर आंदोलन में बतौर मुस्लिम पक्षकार लड़ते रहे इकबाल की प्रक्रिया इसका संदेश है कि देश को अगर आगे बढ़ना है तो इसी फैसले के साथ आगे बढ़ना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष के मस्जिद के दावे को भी स्वीकार किया है और उसे अलग पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है। बाबा रामदेव ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक भूमि आवंटित करने का निर्णय स्वागत योग्य है। रामदेव ने कहा कि उनका मानना है कि हिंदू भाइयों को मस्जिद के निर्माण में भी मदद करनी चाहिए। इन बयानों के साथ जिस तरह देश ने इस फैसले पर समझदारी दिखाई है, वह भी यह जाहिर करने के लिए काफी है कि देश बदल रहा है।

राम को न्याय मिला राम के देश में

आर के सिन्हा
सांसद, राज्यसभा

आखिर राम के देश भारत में उसी जगह भव्य राम मंदिर बनेगा जहां उनका जन्म हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के आधार पर माना कि बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि पर निर्मित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए बेहद खास रहा, क्योंकि पांच सदस्यीय पीठ का यह फैसला सर्वानुमति से आया है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के भी न्यायाधीश बैठे थे। सभी न्यायाधीशों ने साक्ष्यों और सुबूतों के आधार पर यह माना कि श्रीराम का जन्मस्थान यही है। वे इस नतीजे पर पहुंचे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व में किए गए शोधपूर्ण खोदाई के आधार पर। एएसआइ ने अपनी संबंधित शोध में पाया था कि जिस स्थान पर बाबर के सेनापति मीर बकी ने मस्जिद बनाई थी, वहीं पर पहले राम मंदिर था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का काम बहुत आसान हो गया, अपने फैसले को सुनाने में।

न्यायाधीशों ने यह तो माना कि बाबरी ढांचे को वहीं खड़ा किया गया था, जहां खोदाई में 12वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर के विध्वंस मिले हैं। लेकिन यह भी माना कि मंदिर को तोड़ा गया इसके सुबूत नहीं मिले। जाहिर सी बात है कि वर्ष 2019 में 1528 के प्रमाण ढूंढ निकालना आसान काम नहीं था।

इस विवाद से भारत में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की बार बार कोशिशें भी हुईं, दंगे हुए और सैकड़ों मासूमों की जानें भी गईं। राम के भारत में राम का घोर अपमान भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के एक बड़े कदम के रूप में भी देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि मुद्दे पर फैसला देते हुए यह भी साबित कर गया कि उसके लिए देश में भाईचारे को बनाए रखना भी बहुत अहम है। पर अफसोस की बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के साथ न्याय नहीं किया। हालांकि अब तक वे बार-बार यही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के दावे को भी नहीं माना है। पर सरकार को यह निर्देश दिया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बनेगा उसमें उसे भी शामिल किया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। उसने तो जिसके दावे को पूरी तरह से खारिज किया, उसे भी कुछ दिया है। मुस्लिम पक्ष के दावों को नहीं माना गया, पर उन्हें पांच एकड़ भूमि दी जा रही है, जहां वे मस्जिद बना सकेंगे। पहले का विवादित ढांचा तो मात्र 2.77 एकड़ ही था। सुप्रीम कोर्ट के इस बेहतरीन फैसले को कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम नेता खारिज कर रहे हैं। इस कुत्सित सोच की देश व्यापी निंदा होनी चाहिए।

हालांकि यह मानना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के निष्पक्ष और सर्वग्राह्य फैसले के बाद सारे देश में अमन और शांति का वातावरण बना रहा। देशवासी अपना सामान्य कामकाज करते रहे। यह भी लग रहा है कि वर्ष 1992 और 2019 के बीच का भारत बहुत बदल चुका है। आज देश की नई पीढ़ी में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ चुका है। आज का भारत बहुत परिपक्व हो चुका है। वह बड़े से बड़े फैसलों को सुनने के लिए तैयार है। उसे जिलानी या ओवैसी जैसे नेता गलत रास्ते पर नहीं लेकर जा सकते।

राम जन्मभूमि विवाद पर आए फैसले के बाद आयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना चाहिए और यह भी प्रयास होना चाहिए कि वहां हर वर्ष पूरी दुनिया से लोग आकर दर्शन करें। वह एक विश्व का महान पर्यटक स्थल बने। हजारों नवयुवकों को इससे रोजगार मिलेगा। सैकड़ों छोटे-बड़े होटल खुल सकते हैं। मंदिर परिसर के आसपास रोज रामलीला का मंचन भी हो तो सोने पे सुहागा होगा। थाइलैंड की राजधानी बैंकाक में और इंडोनेशिया के अनेक शहरों में प्रतिदिन रामलीला का बड़े से सभागारों में मंचन होता है। इन देशों में रामलीला देखने के लिए हजारों पर्यटक विश्व भर से प्रतिदिन आते रहते हैं। क्या इस तरह की रामलीला का मंचन हमारे राम की जन्मभूमि अयोध्या में नहीं होना चाहिए?

खरी-खरी

पोस्टर बॉय चंपू भिया की पीड़ा

सौरभ जैन

चंपू भिया आज सुबह से ही उदास बैठे थे। उन्होंने फेसबुक पर अपने फोटो के साथ विवेकानंद जी का कोटेशन चस्पा नहीं किया। न ही भाटसेप पर किसी और के अमृत वचन पर खुद का नाम चिपकाते हुए सारे ग्रुपों में फॉरवर्ड किया। आज अपने दर्जन भर राजनीतिक दायित्वों का उल्लेख करते हुए फेबु पर ज्ञान तक नहीं बांटा। चंपू भिया मित्रमंडली में तो खलबली मच गई- 'अरे! भिया कल रात को तो तंबाकू रगड़ते हुए रजवाड़ा खरीदने की बात कर रहे थे, फिर अलसट्टे में ये क्या हो गया!' इत्ते में एक एक समर्थक बोला कि कल रात को तो नोटबंदी-2 की घोषणा भी नहीं हुई, जो भिया का बीपी बढ़े। अनुमानों के सभी गधे संभावनाओं की जमीं पर दौड़ रहे थे।

रंजीत के किरदार में रहने वाले चंपू भिया आलोकनाथ का रूप धारण करते हुए बोले- 'यार छोटे, राजधानी से फरमान आया है कि बिना अनुमति के कहीं किसी भी नेता का फोटू-पोस्टर दिखे तो तत्काल हटा दिया जाए।' यह सुन समर्थक तो चंपू भिया से भी ज्यादा हताश हो गए। क्योंकि ये तो राजनीति में 'विशाल बैनर पे फोटुक छपने' की अपार संभावनाओं के चलते ही आए थे। चौराहे के किसी बैनर में 50-60 छुटभैयों के बीच अपना छोटा सा फोटो दिख जाने पर इन्हें वोई खुशी मिलती जो किसी पढ़ाकू को मेरिट में आने पे अखबार में फोटो छपने पर होती होगी।

राजनीति में दो टाइप के नेता होते है, पहले काम वाले, दूसरे नाम वाले। काम करके नाम बनाने वाले नेता अब बहुत कम बचे। दूसरे हैं नाम का ढिंढोरा पीटने वाले, किंतु काम नहीं करने वाले। भारत की राजनीति की ऊष्ट-कटिबंधीय जलवायु इन्हीं दूसरे टाइप के टट्टूओं के अनुकूल है। इसीलिए ये गली-मोहल्ले, चौराहे, और तो और रोड संकेतकों तक पर अपने 'युवा हिरदै सम्राट' होने का गोबर लीप देते हैं। रोड संकेतकों पर शहर का नाम तो नजर आता है, लेकिन किलोमीटर के स्थान पर छुटभैयों की ही मुंडी ज्यादा दिखती है।

अब डर पसर चुका था कि चंपू भिया का कहीं कोई 'बेनर-होल्डिंग' नहीं होगा तो कौन पहचानेगा कि वो 'अंडसंड कर्मठ, गजब योग्य और ईमानदारी के अंतिम पोस्टर हैं!' खुद को सबका बाप समझने वाले चंपू भिया के लिए पोस्टरबंदी उस नसबंदी की तरह है, जिसमें उनके पिता बनने की संभावनाओं का अंत हो चुका है।

ट्वीट-ट्वीट

यह केवल भारत में ही संभव है जहां जस्टिस अब्दुल नजीर सर्वसम्मति से लिए फैसले में शामिल हों और केके मुहम्मद ने ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध कराए हों। भारतीयता का विचार किसी भी विचारधारा से बड़ा है। उम्मीद है कि यह निर्णय सभी को खुश रखेगा। इसके साथ ही मैं शांति, प्रेम और सौहार्द की कामना करता हूं।

मोहम्मद कैफ@MohammadKaif

राम मंदिर पर आए फैसले के बाद एक सवाल जेहन में आता है कि क्या वामपंथी इतिहासकारों को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए जो इतने लंबे अर्से तक हमें गुमराह किए हुए थे।

आर जगन्नाथन@TheJaggi

शनिवार का दिन वाकई में ऐतिहासिक रहा। एक ही दिन में करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत और अयोध्या पर निर्णायक फैसला। इन दोनों में भी एकसमान धागा है। इनसे भारत-पाकिस्तान और हिंदू-मुसलमान के बीच मित्रता की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

सुधींद्र कुलकर्णी@SudheenKulkarni

सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की चुनौती

रिजवान अंसारी
अध्येता, जामिया मिलिया इस्लामिया विवि, नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या मसले पर अपना फैसला सुना कर सभी विवादों पर विराम लगा दिया है। न्यायालय के मुताबिक विवादित जमीन राम मंदिर पक्ष को और सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही पांच एकड़ की वैकल्पिक जमीन दी जाएगी। वहीं, निर्मोही अखाड़ा के दावे को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। देश का हर मुस्लिम भी न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखता है, लिहाजा फैसले की मिठास और कड़वाहट से परे हट कर इसके स्वागत करने का माकूल वक्त आ गया है। इसी के साथ इस बात की भी जरूरत है कि मंदिर-मस्जिद के तमाम सांप्रदायिक मुद्दों पर पूर्ण विराम लगाया जाए।

इसमें कोई दो राय नहीं कि संविधान ने सभी धर्मों को समान नजरों से देखा है और हमारा भी फर्ज है कि हम सभी धर्मों की आस्था और उनके विश्वास की कद्र करें। यही कारण है कि मुस्लिम समुदाय भगवान राम को इमाम-ए-हिंद का दर्जा देता है और कोर्ट में भी मुस्लिम पक्ष ने इस बात से कभी इन्कार नहीं किया कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है।

दशकों पहले जब यह विवाद शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक यह विवाद मुस्लिमों के वजूद और उनकी भावनाओं से जुड़ा रहा है। और यही वह भावना है जिसकी वजह से मुस्लिम पक्ष ने कभी अपना दावा नहीं छोड़ा। अमूमन किसी भी मुल्क में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच एक लकीर होती है और इतिहास गवाह है कि बहुसंख्यक ने हमेशा ही अल्पसंख्यक को दबाने की कोशिश की है। यही कारण है कि दुनिया भर के देशों में अल्पसंख्यकों को खास तवज्जो दी जाती है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्राविधान इसी का एक पहलू है। संविधान निर्माताओं को भी डर था कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर कोई अंकुश ना लगा सके, इसलिए मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यकों को विशेष जगह दी गई।

प्रतीकात्मक

जिस प्रकार हिंदू धर्म में भगवान राम को लेकर कई मान्यताएं हैं, उसी तरह मस्जिदों को लेकर इस्लाम के अंदर भी कई तरह की आस्थाएं हैं। इनमें से एक यह है कि जिस जमीं पर मस्जिद बन जाती है, वह जमीं ही नहीं, आसमान तक अल्लाह का हो जाता है। एक यह भी आस्था है कि कयामत के दिन अल्लाह सभी मस्जिदों को ज्यों का त्यों आसमान पर उठा लेगा, दुनिया की हर मस्जिद अल्लाह का घर है। ये ही वो आस्थाएं हैं जिस कारण हर मुस्लिम अयोध्या से लेकर दुनिया की तमाम मस्जिदों को एक ही निगाह से देखता है।

यह सच है कि मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन दी गई है। लेकिन विवादित जमीन पर हक न मिलने से मुस्लिम समाज में न केवल एक प्रकार का डर है, बल्कि अपने वजूद को लेकर भी कई सवाल हैं। और वह सवाल यह है कि क्या मस्जिदों को लेकर बढ़ने वाले विवाद अब एक रवायत बन जाएंगे? क्या अयोध्या का यह फैसला देश के दूसरे हिस्से में भी मंदिर- मस्जिद विवाद को जन्म देगा? यह सवाल इसलिए है, क्योंकि देश में मस्जिद-मंदिर को लेकर छोट-मोटे विवाद अमूमन सुनने को मिलते रहते हैं। और जिस प्रकार विवादित ढांचे को गिराने के बाद कोर्ट का फैसला मंदिर के पक्ष में गया है उससे इस बात का डर है कि यह फैसला कहीं धर्मस्थलों का विरोध करने वालों के लिए हौसला अफजाई करने वाला साबित न हो।

डर इस बात का हो चला है कि कोर्ट का यह फैसला अब कई नए विवादों को भी जन्म दे सकता है। इससे न केवल एक प्रकार के असंतुलन पैदा होने की आशंका है, बल्कि देश के किसी भी हिस्से में मस्जिद के निर्माण के लिए बेवजह की दुश्वारियां खड़ी होने का भी डर है। जाहिर है, मुस्लिमों के लिए एक डर का माहौल पैदा हो जाएगा। यह सच है कि सदियों से इस देश में हिंदू-मुस्लिम एक साथ रहते रहे हैं। लेकिन साथ रहने वालों के बीच ही सांप्रदायिक दंगे भी देखने को मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर है, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव का डर भी मुस्लिम समुदाय को सता रहा है। हालांकि, नमाज के लिए मस्जिद किसी भी जगह पर बनाई जा सकती है और मुस्लिमों की आस्था बाबर, अकबर जैसी किसी इंसान में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह में है। लेकिन दशकों तक मुस्लिम पक्षकार द्वारा विवादित भूमि पर दावा नहीं छोड़ा गया, क्योंकि मुस्लिमों को इस बात का अंदेशा था कि कहीं यह एक रवायत न बन जाए और देश के दूसरे हिस्से में मस्जिदों के लिए एक प्रकार का खतरा पैदा न हो जाए। इसलिए, इस बात की जरूरत है कि इस प्रकार की किसी भी आशंका को खत्म करने के उपाय सरकार ढूंढ़े। कोर्ट का यह फैसला तभी सार्थक सिद्ध होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए नजीर बनेगा, जब यह फैसला देशवासियों के लिए कोई दुश्वारियां न लाकर सामाजिक सद्भावना स्थापित करे। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना केवल मुस्लिम समाज, बल्कि हिंदू समाज के लिए भी एक परीक्षा वाला फैसला है। दुनिया भर की नजरें भारत और भारतीयों पर हैं। लिहाजा प्रेम और सौहार्द को बनाए रखने की जरूरत है।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश में सामाजिक तानाबाना मजबूत होगा?

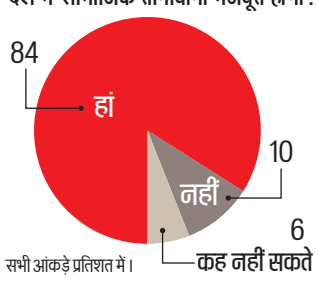

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा वापस लेने का केंद्र सरकार का फैसला सही है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

ओवैसी जी देखिए आप हैदराबाद,
यहां 'अयोध्या' बन चुका, कब का फैजाबाद!
कब का फैजाबाद यहां न कोई लड़ाई,
ज्यों शक्कर संग दूध मिल चुके मुस्लिम भाई।
जिनकी-जिनकी आंज गई पानी में भैंसी,
वही रुदन में लीन दिखें जिस तरह ओवैसी।

– ओमप्रकाश तिवारी

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस

शिक्षा से ही समग्र विकास संभव

रमेश पोखरियाल निशंक
मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार

शिक्षा से ही देश के समग्र विकास की राह खुलती है। नई शिक्षा नीति में परिवर्तन के माध्यम से हमें इसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास करना चाहिए

वर्ष 2014 में एनडीए की सरकार ने देश की कमान संभाली तो स्पष्ट किया था कि वैश्विक परिवेश की नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमें एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है। प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉ. के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति का गठन वर्ष 2017 में हुआ और उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा की आवश्यकतानुसार शिक्षा नीति सुझाएं।

31 मई 2019 को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट स्वीकार कर जब हमने नई शिक्षा नीति को पब्लिक डोमेन में डाला और समस्त हितधारकों से जुड़ने की कोशिश की तो यह विश्व में मुक्त नवाचार का अपनी किस्म का सबसे बड़ा प्रयोग था। नई शिक्षा नीति के लिए हमारे पास अब तक सवा दो लाख सुझाव प्राप्त हुए जिनका विश्लेषण जारी है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि हम अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मुकाबला अमेरिका, जर्मनी, जापान की नकल कर के नहीं कर सकते, हमें भारत बनकर ही वैश्विक चुनौतियों से निपटना होगा। हम विश्व गुरु रहे हैं। हमने पूरे विश्व को नेतृत्व दिया है, मार्गदर्शन दिया है, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे केंद्रों ने संपूर्ण विश्व को नई दिशा दिखाई। यह सब इसलिए हुआ कि हमारी शिक्षा नीति मूल्यों और संस्कारों पर आधारित थी। चाहे हमारे गुरुकुल रहे हों, चाहे विश्वविद्यालय रहे हों, सर्वत्र मानवीय मूल्यों की शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

किसी भी राष्ट्र की प्रगति और विकास का आकलन वहां पर संसाधन जुटा देने मात्र से नहीं होता। केवल अवस्थापना या उपकरण जुटाना पर्याप्त नहीं है, अपितु वहां के लोगों के द्वारा अपनाने वाली पद्धतियों, संस्कारों, मूल्यों, कार्य-शैलियों से राष्ट्र निर्माण होता है। हम अपने डिजिटल रिसोर्स से शहर के चप्पे-चप्पे की निगरानी तो कर सकते हैं, लेकिन सन्मार्ग पर चलते हुए हमें अपनी कार्य संस्कृति, संस्कारों, मूल्यों और कार्यशैली को भी उसी के अनुरूप ढालना होगा, तभी शक्तिशाली भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा।

हमारी अजर अमर भारतीय संस्कृति हमें उन मानवीय मूल्यों के दर्शन कराती है जो सर्वोत्कृष्ट समाज और राष्ट्र के निर्माण का आधार स्तंभ है। इस संस्कृति में हमें एकात्म मानववाद से प्रेरित भावनात्मक एकता के दर्शन होते हैं। यही एकता हमारी शक्ति है, यही कारण है कि हजारों वर्षों के विदेशी आक्रमणों के बावजूद हमने अपनी पहचान नहीं खोई है। इसीलिए मशहूर शायर इकबाल ने कहा है- कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।

अगर देखा जाए तो भारत आदिकाल से ही अनेकता में एकता की अनूठी मिसाल प्रस्तुत करता रहा है। हमने विविधता में एकता से न केवल भारत को जोड़ने की बात कही है, अपितु वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देकर पूरे विश्व को अपना परिवार माना है। विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाला भारत दुनिया को अन्य देशों की तरह एक बाजार के रूप में नहीं देखता, बल्कि अपने परिवार का ही एक हिस्सा मानता है। आज भारत को युवा राष्ट्र की संज्ञा दी जा रही है, विश्व मनीषा को भारत के नवयुवकों में विशिष्ट ऊर्जा दिखाई दे रही है। विकास और प्रगतिशीलता की इस आंधी में विश्व बिरादरी को भारत के बाजार अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आर्थिक रूप से सशक्त देश भारत में ही अपना निवेश करना चाहते हैं। विश्व के युवा राष्ट्र के रूप में हमारे पास युवाओं की असीम शक्ति है। शक्ति का सदुपयोग इस बात पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार हम इन्हें संस्कारित कर राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करें।

संपूर्ण मानवता की 18 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत का वैश्विक शक्ति के रूप में अभ्युदय इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे समूचे युवा अपनी अपनी क्षमता अनुसार देश के लिए समर्पित भाव से कार्य करें। एक ऐसे सशक्त, समृद्ध और वैभवशाली भारत का निर्माण जो संपूर्ण विश्व को नेतृत्व प्रदान कर सके। इस चुनौतीपूर्ण युग में केवल भारत ही वह देश है जो पूरे विश्व में एक देदीप्यमान सितारे की तरह सबका पथ आलोकित करने की क्षमता रखता है। विश्व के युवा राष्ट्र के रूप में हम सृजनात्मकता, उद्यमिता, नवाचार, शोध एवं अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकते हैं। कई बार मैंने विभिन्न मंचों पर यह कहा है कि युवा विद्यार्थियों के रूप में हमारे पास एक बड़ी शक्ति है। अमेरिकी जनसंख्या से अधिक हमारे विद्यार्थियों की संख्या है। हम इसे सकारात्मक दिशा में ले जाने में सक्षम हुए तो हम नए युग का सूत्रपात कर सकते हैं। एक भाव, जो मैं अपनी ओर से आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं, और उसमें मेरा यह दृढ़विश्वास भी है, कि भारत की अविरल गरिमामयी परंपरा और संस्कृति को संजोने में राष्ट्रवाद की धारणा और भावना अत्यंत उपयोगी होती है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रवाद किसी भी समृद्ध और सार्वभौम देश के लिए रीढ़ का काम करती है।

प्रतीकात्मक

इसलिए विद्यालयों, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में राष्ट्रवाद से प्रेरित शिक्षण होना कहीं अधिक लाभकारी होगा। मेरा तो यह भी मानना है कि हमारे विश्वविद्यालयों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का शिक्षण भी राष्ट्रहित और विकास के उद्देश्य से किया जाता है। इसलिए जो लोग राष्ट्रवाद और आधुनिक उच्चशिक्षा व्यवस्था में विरोधाभास देखते हैं, वो कहीं न कहीं बड़ी भूल कर रहे हैं।

आधुनिक विश्व में जिस प्रकार ऊहापोह मचा हुआ है, उसमें भारत जैसे प्राचीन और संस्कृति संपदा से धनी देश की भूमिका बलवती होती जा रही है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जिस दृढ़शक्ति और कुशलता से भारत की गरिमा को विश्व में पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है, उसकी चहुंओर प्रशंसा हो रही है। प्रधानमंत्री के 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के संकल्प को पूर्ण करने में हमारे शिक्षण संस्थान अद्वितीय योगदान कर सकते हैं, हमारी प्राचीन धरोहर को पुनर्प्राणित कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मूल्यों पर आधारित नई शिक्षा नीति भारत को वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में सफल होगी।

5 साल की सजा होगी हिमाचल प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर। इस संबंध में विधि विभाग के प्रधान सचिव यशवंत चोगल ने अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही धर्म की स्वतंत्रता विधेयक लागू हो गया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 11 नवंबर 2019

छत्तीसगढ़ में उन्हीं भवनों को अब बिजली कनेक्शन, जहां होगी रेन वाटर हार्वेस्टिंग

सख्त रुख ▶ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेडियो वार्ता लोकवाणी में गिरते जलस्तर पर जताई चिंता

बोले-लंबे अरसे से सही सोच और सही योजना के बिना निर्माण कार्य कराए गए

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेडियो वार्ता लोकवाणी की चौथी कड़ी में प्रदेश में गिरते भूजल स्तर पर चिंता जताई। उन्होंने रेडियो वार्ता के माध्यम से यह नियम लागू होने की जानकारी दी कि राज्य में अब उन्हीं नए भवनों को बिजली का कनेक्शन मिलेगा, जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग की यूनिट लगी होगी। सरकार ने सभी तरह के आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक परिसरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने सैकड़ों एजेंसियों और स्व-सहायता समूहों को आगे किया है, जो एक माह के भीतर सभी जगहों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करेंगे। मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में 'नगरीय निकास का नया दौर' विषय पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए पानी पर ज्यादा फोकस किया। उन्होंने कहा कि तालाब,नदी, नाले और जलप्रपातों का प्रदेश कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में लंबे अरसे से सही सोच और सही योजना के बिना निर्माण कराए गए हैं। गिरते भूजल स्तर का सबसे बड़ा कारण सीमेंट और कंक्रीट के जंगल की तरह शहरों का विकास किया जाना है। मौजूदा सरकार ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए छह प्रकार की कर दर निर्धारित की है। अब नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी योजना से शहर को भी जोड़ा जा रहा है। रायपुर में 212 करोड़ रुपये की जल आवर्धन योजना पर काम हो रहा है। बघेल ने मिनीमाता अमृतधारा जल, राजीव गांधी सर्वजल, मुख्यमंत्री चलित संयंत्र पेयजल, समूह पेयजल, सुपेबेड़ा जल योजना और सीवरेज मास्टर प्लांट के बारे में बताया। सीएम बोले- बरसों से लंबित खारून सफाई योजना को मंजूरी दी है। बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी के संरक्षण के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया। बिलासपुर में अरपा नदी की सफाई का बड़ा अभियान जनभागीदारी के साथ चलाया गया है।

भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा

- पार्षद अपना मुखिया चुनेंगे, तो नगरीय विकास निर्बाध रूप से होगा। युवा महापौर बन सकेंगे।
- नगरीय निकायों के तालाब मछुआरा समितियों को दिए जाएंगे।
- जमीन की गाइडलाइन दर 30 फीसद कम और छोटे भूखंडों के क्रय-विक्रय से रोक हटने पर एक लाख सौदे हुए।
- आधुनिक बाजार व्यवस्था में छत्तीसगढ़ की बाजार व्यवस्था टूट रही थी, पौनी-पसारी योजना उसे फिर जोड़ेगी।
- मोर जमीन-मोर मकान योजना के तहत 11 माह में 40 हजार मकान बने हैं।
- मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य केंद्र और मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालयों से बीमार, कुपोषित और जरूरमंदों तक पहुंची सरकार।
- राज्योत्सव में पहली बार छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों का सम्मान बढ़ा।

थर्ड जेंडर को उद्योग लगाने को सरकार देगी 40 फीसद सब्सिडी

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में तृतीय लिंग (थर्ड जेंडर) को उद्योग लगाने के लिए 40 फीसद सब्सिडी देगी। राज्य में इसी महीने लागू हुई नई उद्योग नीति में इसका प्रावधान किया गया है। सरकार के इस फैसले से थर्ड जेंडर के लोगों को अपने नए स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता मिल सकेगी। नए स्टार्टअप के लिए पट्टे पर जमीन भी प्रदान की जाएगी। अन्य तकनीकी मदद भी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी।

हिमाचल प्रदेश में बेलचा नहीं अब बंदूक थामेंगे बेलदार

प्रकाश भारद्वाज, शिमला

हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के बेलदारों के पास करने के काम नहीं है। हालत यह है कि महकमे में बेलदारों की संख्या बीस हजार से अधिक है, इनके वेतन पर हर माह लाखों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। बेलदारों को काम पर लगाने के लिए सरकार ने एक उपाय सुझाया है कि इन्हें पुलिस महकमे में समायोजित किया जाए। दो हजार बेलदारों को पुलिस विभाग में बतौर विशेष पुलिस अधिकारी (स्पेशल पुलिस अधिकारी) नियुक्त किया जाए। इसके लिए सचिवालय से पत्र पुलिस मुख्यालय पहुंच गया है जिसमें पुलिस विभाग से मंजूरी मांगी गई है। यह प्रस्ताव सिरे चढ़ा तो बेलदार बेलचा छोड़कर बंदूक थामे हुए नजर आएंगे। पुलिस विभाग से मंजूरी मिलने के बाद दो हजार नियमित बेलदारों को सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा का अति महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा जा सकता है। बेलदार मिलने के बाद पुलिस महकमे में चल रही स्टाफ की कमी भी दूर होगी।

सचिवालय से पत्र पहुंचा : सचिवालय से एक पत्र पुलिस मुख्यालय में पहुंचा है। इसमें दो हजार बेलदारों को पुलिस महकमे में दिए जाने बारे लिखा गया है। इस मामले पर पुलिस विभाग से विचार मांगे गए हैं ताकि उसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा सके। वर्तमान में विशेष पुलिस अधिकारी चंबा जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ-साथ लाहुल-स्पीति के क्षेत्र में भी सेवाएं दे रहे हैं। विशेष पुलिस अधिकारियों की संख्या करीब पांच सौ है। सरकार की ओर से प्रत्येक विशेष पुलिस अधिकारी को मासिक छह हजार रुपये मानदेय प्राप्त होता है। वर्ष 1999 में सतरूंडी आतंकी हमले के बाद सरकार ने राज्य की सीमाओं पर एसपीओ तैनात किए थे। इनका काम पुलिस के साथ गश्त करना, क्षेत्र की नाकेबंदी में सहयोग करना और समीओं पर नजर रखते हुए आला पुलिस अधिकारियों तक सूचना पहुंचाना है।

बेलदार का वेतन 30 हजार

लोक निर्माण विभाग में सेवारत बेलदार का वेतन करीब 30 हजार रुपये मासिक है। नियमित बेलदारों को 25 हजार से तीस हजार वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त दैनिक भोगी बेलदारों को करीब सात हजार मासिक मानदेय प्राप्त होता है।

ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक सरकार को नहीं भेजा है। हां, सरकार की ओर से बेलदारों को पुलिस विभाग में रखने को लेकर पूछा गया था। इस मामले में विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है।

- सीताराम मरडी, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश

लुवास में देशभर से जुटेंगे 450 पशु वैज्ञानिक, सर्जरी पर प्रस्तुत करेंगे रिसर्च

जासं, हिसार : इंडियन सोसायटी फॉर वेटरनरी सर्जरी संस्था इस बार हरियाणा के लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय (लुवास) में सर्जरी पर वार्षिक कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। 14 से 16 नवंबर तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में देशभर से 450 से अधिक पशु वैज्ञानिक, पशु विज्ञान के शिक्षक, सरकारी पशु चिकित्सक, छात्र व प्राइवेट वेटरनरी प्रैक्टिशनर अपने अब तक के बेहतरीन काम प्रस्तुत करेंगे।

लुवास में सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉ. अशोक बताते हैं कि इस कांफ्रेंस का उद्देश्य है कि देशभर के वेटरनरी सर्जन आपस में तकनीक और जानकारियां साझा करें, ताकि भविष्य में पशुओं के उपचार में आयाम स्थापित किए जा सके। इसमें पशुओं की आंख, नाक, पेट आदि की सर्जरी के विषय में सर्जन अपनी रिसर्च भी प्रस्तुत करेंगे। इसमें लुवास के वैज्ञानिक भी अपनी प्रजेंटेशन देंगे। इससे वे एक-दूसरे के कार्यों को भी जान सकेंगे। इस कांफ्रेंस में छात्रों को जोड़ने का उद्देश्य है कि छात्र पशुपालन और इससे जुड़ी विज्ञान को जानें, जिससे पशु चिकित्सा व शिक्षा के प्रोफेशन में तेजी लाई जा सके।

चिन्मयानंद प्रकरण : आज जारी हो सकता है भाजपा नेताओं को समन

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर

- पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने का है आरोप
- एसआइटी ने चार्जशीट में दो नेताओं का नाम किया शामिल

पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने का आरोपित बनाए जाने के बाद भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री व जिला सहकारी बैंक (डीसीबी) चेयरमैन डीपीएस राठौर ने भगवान की शरण ले ली है। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद वह परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर निकल गए थे। एसआइटी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर उन्हें व भाजयुमो के पूर्व जिला महामंत्री अजीत सिंह को कोर्ट से सोमवार को समन जारी हो सकता है, जिसके बाद वे जमानत करा सकते हैं।

चिन्मयानंद प्रकरण में विशेष जांच दल (एसआइटी) ने पांच नवंबर को अपनी जांच पूरी करते हुए चार्जशीट में भाजपा नेता डीपीएस राठौर और भाजयुमो नेता अजीत सिंह नाम भी शामिल किया था। एसआइटी के अनुसार, भाजपा नेताओं ने चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करते हुए सवा करोड़ रुपये मांगे थे। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के बाद अजीत सिंह शहर में ही थे, लेकिन डीपीएस राठौर की लोकेशन नहीं मिल रही थी। बताया जा रहा है कि वह परिवार के साथ वृंदावन और विभिन्न धार्मिक स्थल घूमने गए थे। मध्य प्रदेश के दतिया में पीतांबरा देवी के दरबार में भी पहुंचे। रविवार को डीपीएस राठौर परिवार के साथ वापस घर पहुंचे। जहां उनसे मिलने कुछ समर्थक भी पहुंचे। बता दें कि डीपीएस राठौर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष जेपीएस राठौर के छोटे भाई हैं।

वकीलों को चाहिए चार्जशीट की कॉपी

उधर, छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपित चिन्मयानंद के वकीलों को चार्जशीट की कॉपी का इंतजार है। इसी तरह चिन्मयानंद ब्लैकमेल करने के मामले में छात्रा, उसके तीन दोस्तों संजय, सचिन और विक्रम के वकीलों को भी कॉपी का इंतजार है। एसआइटी की ओर से सोमवार को कोर्ट के माध्यम से कॉपी उपलब्ध कराई जा सकती है। जिसके बाद दोनों मुकदमों में आरोपितों के वकील आगे की पैरवी को लेकर अपनी तैयारी करेंगे।

झालको का जलमीनार बना रहे बंगाल के तीन राजमिस्त्रियों के साथ मारपीट

जागरण संवाददाता, चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम)

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र की पट्टाजैंत पंचायत के सेलायसाई में झारखंड हिल एरिया लिफ्ट एरिगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (झालको) जलमीनार का निर्माण कर रही है। इस जलमीनार के निर्माण कार्य में लगे बंगाल के तीन राजमिस्त्रियों के साथ दो अज्ञात युवकों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं, भुक्तभोगी राजमिस्त्रियों ने दोनों पर जिंदा जलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। घटना शनिवार शाम करीब 6:30 बजे की है।

जगन्नाथपुर थाने की पुलिस ने जानकारी मिलते ही सेलायसाई पहुंच कर इस घटना में जख्मी जाकिर हुसैन को चाईबासा सदर अस्पताल भिजवाया। जख्मी जाकिर ने पुलिस को लिखित बयान में बताया कि वह बंगाल के बीरभूम जिले के मोराराई थाना क्षेत्र स्थित हरीशपुर गांव का रहने वाला है। शनिवार की शाम को सेलायसाई जलमीनार के समीप बैठ कर मोबाइल से अपने घर वालों के साथ बात कर रहा था कि अचानक गांव के ही दो युवक आए और उसे पकड़ कर मारपीट करने लगे। उसके साथ काम करने वाले अन्य दो राजमिस्त्री बानी शेख और अजहर शेख घर में खाना बना रहे थे। हो-हल्ला सुनकर दोनों घर से बाहर निकले, तो दोनों युवकों ने उनलोगों के साथ भी मारपीट की। इस दौरान दोनों युवकों ने उन्हें जलमीनार के अंदर ढकेल दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। जाकिर ने कहा कि तीनों को बंद करने के बाद दोनों युवक पेट्रोल लाकर जिंदा जला देने की धमकी देने लगे। यह सुनकर तीनों डर गए और उन्होंने भी अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा ली।

इधर, जानकारी मिलते ही पुलिस दलबल के साथ वहां पहुंची और बंद कमरे से तीनों राजमिस्त्रियों को निकाला। पुलिस ने जख्मी जाकिर हुसैन को इलाज के लिए तुरंत सीएचसी जगन्नाथपुर लाने के बाद प्राथमिक इलाज के बाद सदर अस्पताल भेजा।

इस संबंध में थाना प्रभारी मधुसूदन मोदक ने बताया कि जख्मी जाकिर हुसैन को जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर प्राथमिक उपचार कराया गया। यहां से चिकित्सक ने उन्हें सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया। वहां उसका इलाज चल रहा है। कहा कि जख्मी राजमिस्त्री व अन्य मिस्त्री दोनों युवकों को नहीं पहचानते हैं। इस मामले में दो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रहे है।

चिरेका स्टील फाउंड्री की छत से गिरकर उप्र के श्रमिक की मौत

जासं, मिहिजाम (जामताड़ा) : चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना (चिरेका) की स्टील फाउंड्री शॉप में रविवार को दिन में करीब तीन बजे छत से गिरकर उत्तर प्रदेश के निवासी एक बाइस वर्षीय ठेका श्रमिक की मौत हो गई। रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) के मुताबिक ठेका श्रमिक राजन ओझा, पिता जयप्रकाश ओझा, ग्राम पकियार विशुनपुर, घुघली महाराजगंज (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक दोपहर में स्टील फाउंड्री की छत पर सोलर सिस्टम के पैनल लगाने का काम चल रहा था। राजन ओझा पैनल की जांच करने के लिए ऊपर चढ़ा था।

उत्तराखंड में होमगार्ड्स को जल्द 600 रुपये मानदेय

विकास गुसाईं, देहरादून

- उप्र में दिए जा रहे 672 रुपये, 600 मानदेय और 72 रुपये डीए

उत्तराखंड में तैनात होमगार्ड्स को प्रदेश में अब 600 रुपये मानदेय देने की तैयारी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के क्रम में यह कदम उठाया जा रहा है। हालांकि, अभी यह निर्णय नहीं लिया गया है कि इन्हें उत्तर प्रदेश की भांति अलग से डीए दिया जाएगा या नहीं। मुख्यमंत्री द्वारा पीआरडी और उपनल कर्मियों का मानदेय बढ़ाने संबंधी घोषणा के बाद अब होमगार्ड्स के मानदेय को लेकर कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इस मसले को जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुपालन किया जा सके।

प्रदेश में अभी विभिन्न विभागों में साढ़े छह हजार से अधिक होमगार्ड्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन विभागों में पुलिस, परिवहन, सचिवालय व संचार आदि शामिल हैं। इन होमगार्ड्स से सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के साथ ही विभागों में सुरक्षा एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कार्य लिया जा रहा है। अभी इन्हें साढ़े चार सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। होमगार्ड्स के लिए बने नियमों के अनुसार पुलिस के सहायक के रूप में सेवा देने पर इन्हें पुलिस के समान ही अधिकार व सुविधाएं दिए जाने का जिक्र है।

तकरीबन तीन वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में होमगार्ड्स को पुलिस के समान वेतन दिए जाने का निर्णय सुनाया था। कुछ राज्यों ने इसका अनुपालन किया और कुछ ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। इस पर होमगार्ड्स ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पक्ष बने उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों को आठ सप्ताह के भीतर निर्णय का अनुपालन करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा कि बढ़ा हुआ मानदेय 25 अप्रैल 2017 से दिया जाए। इस पर शासन ने कुछ समय पहले कवायद शुरू की थी। इस संबंध में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड के होमगार्ड्स को उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स के भांति ही मानदेय दिए जाने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स को 600 रुपये मानदेय और 72 रुपये डीए दिया जाता है। इस बैठक के बाद वित्त ने होमगार्ड्स को 600 रुपये दिए जाने पर सहमति दी है। इस संबंध में पत्रावली तैयार की जा रही है, जिसे 13 नवंबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है।

हरिद्वार के आबादी वाले इलाकों में हाथियों के आतंक से उड़ी सरकार की नींद

केदार दत्त, देहरादून

- धर्मनगरी हरिद्वार में 2021 में होने वाले महाकुंभ के आयोजन के मद्देनजर बढ़ी चिंता
- शासन ने बुलाई वन महकमे के अफसरों व डब्ल्यूआइआइ के वैज्ञानिकों की बैठक

2021 में हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के बीच हाथी, गुलदार समेत दूसरे वन्यजीवों की शहर में धमक ने शासन से लेकर सरकार तक की नींद उड़ा दी है। राजाजी टाइगर रिजर्व से लगे हरिद्वार में जंगली जानवरों विशेषकर हाथियों की धमक रोकने को रणनीति बनाने के मसले पर अब शासन सक्रिय हो गया है। इस कड़ी में वन विभाग के अफसरों व भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआइआइ) के वैज्ञानिकों की सोमवार को अहम बैठक बुलाई गई है। इसमें यह तय किया जाएगा कि हरिद्वार में हाथियों को कैसे आबादी वाले क्षेत्रों में आने से रोका जाए।

राजाजी रिजर्व से लगे हरिद्वार में हाथी, गुलदार समेत दूसरे वन्यजीवों की आबादी वाले इलाकों में निरंतर धमक से रिजर्व प्रशासन के साथ ही वन महकमे के माथे पर बल पड़े हैं। हाल में हरिद्वार के पिंजनहेड़ी क्षेत्र में आबादी में आ धमके हाथी ने दो लोगों को मार डाला था। इससे पहले भी बीएचईएल क्षेत्र में हाथी के हमले में दो लोगों की जान गई थी। लगातार गहराती इस समस्या को देखते हुए महकमे ने पूर्व में मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल से जांच पड़ताल कराई। जांच रिपोर्ट में साफ किया गया था कि हरिद्वार में हाथी-मानव संघर्ष की स्थिति बेहद चिंताजनक है। इसे थामने को वन सीमा पर मजबूत सोलर फेंसिंग समेत अन्य कई अहम सुझाव भी दिए गए थे।

इस बीच पिंजनहेड़ी की घटना के साथ ही अन्य इलाकों में गुलदार की धमक ने नींद उड़ाकर रख दी है। चिंता का कारण ये है कि हरिद्वार में 13 माह बाद महाकुंभ होना है, जिसमें देश-दुनिया से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। ऐसे में हाथी समेत दूसरे वन्यजीवों की हरिद्वार के आबादी वाले क्षेत्रों में धमक ऐसी ही बनी रही तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसे देखते हुए अब सरकार और शासन सक्रिय हो गए हैं।

प्रमुख सचिव वन आनंदवर्धन ने सोमवार को हरिद्वार की इस समस्या के समाधान के मद्देनजर मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक समेत अन्य वनाधिकारियों के साथ ही डब्ल्यूआइआइ के वैज्ञानिकों की बैठक बुलाई है। प्रमुख सचिव वन के अनुसार इस बैठक में महाकुंभ को देखते हुए हाथी समेत दूसरे वन्यजीवों के आबादी वाले क्षेत्रों में आने से रोकने के उपायों पर मंथन किया जाएगा।

बांडीपोरा में मुठभेड़ एक आतंकी ढेर

राज्य ब्यूरो, जम्मू : उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा जिले के लवडारा गांव में रविवार को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में एक आतंकी मार गया। अभी भी एक से दो आतंकी घेराबंदी में फंसे हुए हैं और ऑपरेशन जारी है। दोनों ओर से रुक-रुक कर गोलीबारी हो रही है।

जानकारी के अनुसार, रविवार दोपहर बाद सुरक्षाबलों को सूचना मिली कि बांडीपोरा के लवाडारा गांव में दो से तीन आतंकी छिपे हुए हैं। इसके बाद सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पर पूरे क्षेत्र को घेरकर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षाबलों को अपनी ओर आते देख आतंकियों ने भागने का प्रयास करते हुए गोलाबारी शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने भी इसका जवाब दिया। दोपहर करीब तीन बजे से मुठभेड़ जारी है। अभी तक एक आतंकी मारा गया है। सेना की चिनार कोर ने आतंकी के मारे जाने की पुष्टि की है। वहीं अंधेरा होने के कारण छिपे बैठे आतंकियों के भागने की आशंका को देखते हुए सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र को घेरा हुआ है। देर शाम तक दोनों ओर से बीच-बीच में गोलीबारी जारी रही। भारतीय सेना का कहना है कि वह सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। वह दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है।

पेड़ों की कटाई का विरोध...

यह तस्वीर असम में गुवाहाटी के भरलुमुख की है, जहां पेड़ों को बचाने के लिए बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ा। रविवार को बच्चों ने बैनर व पोस्टर लेकर पेड़ों की कटाई के विरोध में मानव शृंखला बनाई। प्रेट्र

मुस्तैद

अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने सर्दी प्रबंधन रणनीति को बनाया प्रभावी, अगर आतंकी तारबंदी के पास आए तो मिलेगी गोली

सर्दी में बदले घुसपैठ के तरीकों से निटपने को तैयार सेना

विवेक सिंह, जम्मू

सर्दी शुरू हो चुकी है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के साथ नियंत्रण रेखा (एलओसी) से घुसपैठ नहीं करने से हताश आतंकियों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा (आइबी) का रुख किया है। सीमा पार की साजिशों को नाकाम करने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने आइबी पर सर्दी प्रबंधन रणनीति को प्रभावी बनाया है। इसमें जवानों की अतिरिक्त तैनाती, अतिरिक्त नाके, अत्याधुनिक तकनीक वाले उपकरणों की संख्या बढ़ाने के साथ तारबंदी के आसपास देखते ही गोली मारने के आदेश होते हैं।

आइबी पर सर्दियों की चुनौतियां : जम्मू के मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ते ही सीमांत क्षेत्रों में कोहरा छाने लगता है। दूर तक देखना संभव नहीं होता है। पाक रेंजर्स सर्दियों में सीमा प्रहरियों पर दवाब बढ़ाने के लिए सीमांत क्षेत्रों में स्नाइपरों को सक्रिय कर देते हैं। पाक रेंजर्स के साथ पाक सेना भी आतंकियों की आइबी से घुसपैठ करवाने के लिए हरकत में आ जाती है। आइबी से सटे इलाकों में पाकिस्तान की बार्डर एक्शन टीमों (बैट) हमलों का खतरा बढ़ जाता है। पाक सेना आतंकवादियों की बैट के साथ हथियार ट्रेनिंग व घुसपैठ करवाने में सहयोग देती है। ऐसे हालात में पाक रेंजर्स गोलाबारी कर घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकवादियों को कवर फायर भी देते हैं।

आतंकियों का एलओसी से आइबी की तरफ रुख : जम्म-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भारी बर्फबारी के कारण नवंबर से घुसपैठ के रास्ते बंद होने लगते हैं। आतंकी घुसपैठ करने के लिए जम्मू में आइबी के पार पाकिस्तानी इलाकों में सक्रिय हो जाते हैं। गुलाम कश्मीर में पांच सौ आतंकवादी नियंत्रण रेखा से घुसपैठ करवाने के लिए लांचिंग पैडों पर डेरा डाले थे। इन आतंकवादियों में से कइयों ने अब आइबी से सटे इलाकों का रुख कर लिया है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने अपने तेवर कड़े कर इसके स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। पाकिस्तान की ओर से अब सीमा की साफ सफाई में खलल डालने की कोशिशें की जा रही हैं। अक्टूबर के बाद से ऐसे बारह के करीब मामले हो चुके हैं यहां पाक रेंजर्स ने भारतीय क्षेत्र में साफ सफाई के अभियान में खलल डालने के लिए इक्की-दुक्की गोलियां दागी हैं। ऐसे मामलों में सीमा प्रहरी संयम बरतते हैं। सीमा पर सरकंडे आतंकवादियों के छिपने में सहायक रहते हैं। पाक रेंजर्स नहीं चाहते हैं कि सीमा पर सफाई हो। पाकिस्तान की इस मंशा को अच्छी तरह से समझने वाली सीमा सुरक्षा बल निरंतर आइबी पर साफ सफाई कर सुनिश्चित कर रही है ताकि सीमा पार दूर तक नजर रखी जा सके।

दहशतगर्दों की मौजूदगी के संकेत : सूत्रों के अनुसार आइबी के पार आतंकवादियों की मौजूदगी के पुख्ता संकेत मिलने के बाद सुरक्षा के स्तर को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान को सचेत कर दिया है कि कोहरे या सूरज ढलने के बाद अंधेरे की आड़ में कोई हथियारबंद सीमा के पास आया तो गोली मार दी जाएगी। सर्दी प्रबंधन रणनीति के तहत जम्मू संभाग के कठुआ, सांबा व जम्मू जिले में सीमा पर जवानों की तैनाती बढ़ाने के साथ अतिरिक्त नाके लगाए जा रहे हैं। सर्दियों में आइबी पर नाके इतनी दूरी पर होते हैं जिनसे सुरक्षाकर्मी धुंध, कोहरे के बावजूद एक दूसरे को देख सकें।

202 किलोमीटर आइबी : जम्मू संभाग में 202 किलोमीटर आइबी में से 192 किलोमीटर सीमा सुरक्षा बल व अखनूर में 10 किलोमीटर सेना के पास है।

आधुनिक हथियार आएंगे काम

सीमा पर आधुनिक तकनीक भी दुश्मन को मार गिराने में अब काम आएगी। सीमा पर दुश्मन अंधेरे और घने कोहरे में दुश्मन को अंधेरे में देखने में सक्षम आधुनिक नाईट विजन डिवाइस व हाई डेफिनिशन कैमरे से बच नही पाएगा। सीमा सुरक्षा बल के पास आधुनिक थर्मल इमेजर, हाई रेंज नाइट विजन और सेंसर भी है।

सीमा पर दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए पुख्ता बंदोबस्त हैं। जवान गर्मी, सर्दी की चुनौतियों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जवानों का अनुभव व तकनीकी सर्विलांस काम आएगा। सीमा पर तैनात सीमा प्रहरियों का हौसला ऊंचा है। वे दुश्मन की किसी साजिश को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

एनएस जम्वाल, आइजी सीमा सुरक्षा बल जम्मू फ्रंटियर

13 घंटे खुलने के बाद भूस्खलन से जम्मू-श्रीनगर हाईवे फिर बंद

राज्य ब्यूरो, जम्मू

करीब 13 घंटे खुलने के उपरांत रविवार दोपहर बाद जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग रामबन के पास भूस्खलन के कारण फिर बंद हो गया। इससे सैकड़ों ट्रक व यात्री वाहन हाईवे पर फंस कर रह गए हैं। रास्ते में जगह-जगह वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं।

जम्मू कश्मीर में गत गुरुवार और शुक्रवार को भारी बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर हाईवे दो दिन बंद रहा था। इसके बाद से कई जगह भूस्खलन हो रहा है। पिछले चार दिन से हाईवे कई बंद हो चुका है। रविवार तड़के तीन बजे जम्मू-श्रीनगर हाईवे यातायात के लिए खोला गया। सबसे पहले हाईवे के दोनों ओर फंसे सैकड़ों छोटे वाहनों को निकाला गया। इसके बाद जरूरी सामान से लदे ट्रकों को कश्मीर के लिए छोड़ा गया। लेकिन दोपहर बाद करीब चार बजे रामबन से करीब दो किलोमीटर पहले महार में भूस्खलन के कारण राजमार्ग पर यातायात को बंद करना पड़ा। यहां करीब सौ मीटर सड़क पर पहाड़ों से मलवा व चट्टानें गिरी हैं। इसके बाद सड़क को साफ करने के लिए काम शुरू किया गया, लेकिन देर शाम तक मलबा हटाया नहीं जा सका था। ट्रैफिक कंट्रोल रूम रामबन के अनुसार, हाईवे खुलने में अभी आठ से दस घंटे लग सकते हैं। सुबह जो वाहन छोड़े गए थे और वे जवाहर टनल को पार कर चुके हैं, लेकिन दोपहर बाद राजमार्ग बंद होने के कारण करीब 1300 छोटे बड़े वाहन फंस गए।

पहाड़ों पर फिर बर्फबारी : कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में शनिवार रात फिर हुई ताजा बर्फबारी के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ गया है।

मुगल रोड पांचवें दिन भी बंद

पुंछ और राजौरी जिलों को दक्षिण कश्मीर के साथ जोड़ने वाला मुगल रोड रविवार को लगातार पांचवें दिन भी बंद रहा। पीर की गली से शोपियां के बीच भारी बर्फबारी होने के कारण यह मार्ग बंद हो गया था। यहां भी वाहन रोके गए हैं।

71 में से 47 विधायकों ने उत्तराखंड में नहीं दिया संपत्ति का ब्योरा। ब्योरा न देने वालों में मुख्यमंत्री, दो कैबिनेट व एक राज्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हैं। नियमानुसार विधानसभा सचिवालय में विधायकों को हर साल देना होता है विवरण।

खोजा जा रहा मानव-वन्यप्राणी संघर्ष का समाधान

मनोज तिवारी, भोपाल

कार्बेट फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश स्थित कान्हा-बांधवगढ़ और बांधवगढ़-संजय दुबरी कॉरीडोर में ऐसे अनेक उपाय आजमाए हैं, जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करते दिखते हैं। वन्य प्राणियों की सुरक्षा के साथ वनवासियों को इनके संरक्षक के रूप में स्थापित करने का प्रेरक प्रयास भी इसमें शामिल है। संस्था 2009 से टाइगर रिजर्व और उससे सटे क्षेत्रों में काम कर रही है और प्रशासन की मदद भी कर रही है। वनों में संस्था के प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात हैं, जो मूलरूप से वन्यप्राणियों और मानव के बीच संभावित संघर्ष को रोकने में कारगर भूमिका निभा रहे हैं।

पर्यावरण संरक्षण

फाउंडेशन के डायरेक्टर केदार गोरे कहते हैं, मानव-वन्यप्राणी संघर्ष बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़ा है। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी यह संघर्ष चिंता का विषय है। देश में हर जगह वन्यक्षेत्रों में मानव का बढ़ता दखल हर जगह इस संघर्ष का कारण बन रहा है। यही कारण है कि वन्यप्राणी बस्तियों, शहरों और घरों तक का रुख करते देखे जा सकते हैं। इस समस्या का शीघ्र समाधान न निकाला गया तो स्थिति भयावह होगी। फूड चेन पर भीषण संकट उत्पन्न हो जाएगा, जिसका असर समूचे पर्यावरण पर पड़ेगा। कार्बेट फाउंडेशन संस्था गत 25 साल से इस काम में जुटी हुई है।

गोरे ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले सालों में संरक्षित क्षेत्रों की स्थिति सुधरी है, लेकिन वन्यक्षेत्र का दायर सीमित ही है। यह पहलू भी मानव-वन्यजीव संघर्ष का एक कारण बन रहा है। यहां बाघों के साथ ही अन्य मांसाहारी और शाकाहारी वन्यप्राणियों की संख्या बढ़ी है। इस कारण खासकर बाघ, तेंदुआ, भालूसहित अन्य मांसाहारी जानवर जंगल से बाहर आने लगे हैं। यह स्थिति ही चुनौती बनी हुई है। फाउंडेशन ने पिछले सालों में वनवासियों को जंगल में वन्यप्राणियों का महत्व समझाया और उन्हें उनसे बचाव का प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा उनके लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है। फाउंडेशन ने बांधवगढ़ में ट्राइबल म्यूजियम बनाया है, जो जल्द ही वन विभाग को सौंपा जाएगा।

कान्हा पेंच और बांधवगढ़-संजय दुबरी कॉरिडोर में पेड़ पर उपकरण लगाए जा रहे हैं।

मानव-वन्यजीव संघर्ष के समाधान के लिए इस तरह के उपाय किए जा रहे हैं।

सावधानियां बरतने की सलाह के पोस्टर लगाए गए हैं। नवदुनिया

गोरे ने बताया कि इस काम में संस्था को देश की नामी कंपनियों से सीएसआर (कार्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी) मद से फंड मुहैया कराया जाता है, जिसके बूते फाउंडेशन ने वन्यप्राणी सुरक्षा और वनवासियों की तरक्की के लिए जो काम किए हैं, कान्हा-पेंच और बांधवगढ़-संजय दुबरी टाइगर रिजर्व के कॉरीडोर पर अब इन कामों का कारगर परिणाम सामने आ रहा है। बांधवगढ़-संजय दुबरी कॉरीडोर में पांच हेक्टेयर क्षेत्र में तीन हजार से ज्यादा पौधे जम गए हैं, इससे भविष्य में बाघ को एक से दूसरे स्थान पर जाने में कठिनाई नहीं होगी। छह गांव में वाटरशेड योजना के तहत स्टॉप डैम बनाए हैं। इससे ग्रामीणों की खेती को लाभ हुआ है और उनकी वन्यक्षेत्र पर निर्भरता घटी है। ग्रामीण परिवार ईंधन के लिए लकड़ी पर निर्भर होते हैं। लकड़ी की बचत के लिए फाउंडेशन ने दो हजार परिवारों को स्मार्ट स्टोव (विशेष चूल्हा) उपलब्ध कराए हैं। क्षेत्र में संस्था की ओर से मेडिकल प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। मोबाइल मेडिकल और पैथालॉजी यूनिट है, जो गांव-गांव जाकर वनवासियों का इलाज करती है। इसके लिए संस्था प्रति रोगी 10 रुपये लेती है, लेकिन डेढ़ से दो सौ रुपये की दवाएं भी देती है। वनकर्मियों को ट्रैप कैमरे लगाने, वन्यप्राणियों के हमलों से बचने की ट्रेनिंग देता है।

गोरे बताते हैं कि जंगलों में बिजली नहीं है। वनवासी कुएं खोदते हैं। जिनमें मुंडेर न होने के कारण इनमें वन्यप्राणी गिर जाते हैं। ऐसे डेढ़ हजार कुओं की फेंसिंग कराई गई है। 22 स्थानों पर सोलर पंप लगाए गए हैं। जिनमें गर्मियों में वन्यप्राणियों के लिए पानी का इंतजाम होता है। इसका असर यह होता है कि वन्यप्राणी जंगल से बाहर नहीं निकलते। ग्रामीणों को सौर ऊर्जा से बिजली दी जाती हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रदेश के छह टाइगर रिजर्व के 250 स्कूलों में विशेष गेम दिया गया है। इसकी मदद से बच्चे जानवरों के महत्व और बचाव के बारे में सीख रहे हैं। पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण सहित टीकाकरण किया जाता है ताकि कोई बीमारी बाघ तक न पहुंचे। ग्रामीणों को सिलाई, अगरबत्ती निर्माण सहित अन्य रोजगार मूलक प्रशिक्षण दिए जाते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व के पूर्व फील्ड डायरेक्टर संजय शुक्ल बताते हैं कि फाउंडेशन वन्यप्राणियों से समाज को जोड़ने में वन विभाग की मदद कर रहा है, जिसके बूते हम वनों और वन्यजीवन की सुरक्षा-संरक्षा की ओर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोग से बचाएंगे बिस्किट और केक

वैभव शर्मा, हिसार

- एचएयू में फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के वैज्ञानिकों ने मोटे अनाज में तुलसी मिलाकर तैयार किए स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद

डायबिटीज, कैंसर और हृदय संबंधी रोगों को रोकने के लिए मोटे अनाज और तुलसी के योग से बने केक और बिस्किट मुफीद होंगे। ये केक और बिस्किट इन रोगों से लड़ेंगे। ये स्वादिष्ट भी होंगे और पौष्टिक भी। हरियाणा के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) के फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के विज्ञानियों ने इन्हें तैयार किया है।

एचएयू के विज्ञानियों ने इसके लिए उन्होंने मोटे अनाज में पांच फीसद तुलसी पाउडर का प्रयोग किया, जिसका प्रतिफल यह हुआ कि बिस्किट और केक में न्यूट्रिशन वैल्यू काफी बढ़ गई। इस रिसर्च को करने वालीं साइंटिस्ट डॉ. सरोज दहिया व सीनियर रिसर्च फैलो सुमन बताती हैं कि तुलसी मिले उत्पादों का उपयोग करने से डायबिटीज, कैंसर और हृदय संबंधी बीमारियों को रोकने में मदद मिलेगी। कुपोषण की समस्या है तो प्रतिदिन इन उत्पादों के सेवन से इस समस्या को भी रोका जा सकेगा।

एक वर्ष पहले शुरू की थी रिसर्च : डॉ. दहिया ने बताया कि एक वर्ष पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से उभरता विज्ञानी योजना के तहत इस रिसर्च को शुरू किया था जो अभी तक जारी है। इसको काफी सराहना मिली है। उद्देश्य है कि इस तरीके से उत्पाद बनाना सीखकर महिलाएं व किसान अपना कारोबार आरंभ करें। उन्होंने कहा कि काफी महिलाएं और किसान इसके लिए हमारे पास आ रहे हैं। उन्हें जल्द ही प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उद्देश्य पूरा हो सके।

जौ, ज्वार, बाजरा, चने की दाल के साथ तुलसी

डॉ. दहिया बताती हैं कि उन्होंने 60 फीसद बाजरा, 10 फीसद ज्वार व जौ, 15 फीसद चना की दाल का मिश्रण लिया। इसके साथ ही तुलसी के पत्तों को सुखाकर पाउडर तैयार कराया। मोटे अनाज के इस मिश्रण में पांच फीसद तुलसी पाउडर मिलाया गया। इसके बाद टेस्ट किया गया तो सामने आया कि सामान्य केक व बिस्किट की तुलना में तुलसी वाले उत्पादों में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ गई। इस मिश्रण से बने केक में 0.42 फीसद प्रोटीन, फैट 1.06 फीसद फैट, 0.47 फीसद फाइबर, 3.64 फीसद कैल्शियम, 0.83 फीसद आयरन पाया गया। बिस्किट में 0.36 फीसद प्रोटीन, 1.94 फीसद फैट, 0.84 फीसद फाइबर, 2.89 फीसद कैल्शियम, 0.64 फीसद आयरन मिला, जबकि सामान्य बिस्किट और केक में इन पोषक तत्वों की मात्रा काफी कम थी। इसके साथ ही तुलसी में एंटी ऑक्सीडेंट तत्व होता है जो कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है। इस मिश्रण को ओट्स, सेब, मटर जैसे प्रोडक्ट में भी आजमाया गया है। एचएयू में हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में विज्ञानियों ने विदेशी वैज्ञानिकों के समक्ष अपनी रिसर्च प्रस्तुत की।

मर्ज दूर करना है तो कुछ मीठा हो जाए

जागरण विशेष

विशाल श्रेष्ठ, कोलकाता

- कोलकाता के रवींद्र ने अभिनव सोच से मिठाइयों को दिया दवाओं का रूप
- गाजर के रसगुल्ले, औषधीय पौधों से तैयार मिठाइयों से कई बीमारियों का इलाज संभव

कहते हैं ज्यादा मिठाइयां मर्ज लेकर आती हैं, लेकिन कोलकाता के रवींद्र कुमार पाल (79) ने मिठाइयों को ही दवाओं का रूप दे दिया है। दमा, पीलिया, एसिडिटी, उदरशूल और ब्रोंकाइटिस की समस्या है तो गाजर के रसगुल्ले चख लीजिए। सर्दी-खांसी या चेचक-खसरा से पीड़ित हैं तो तुलसी की दही का सेवन कीजिए। दिल की बीमारियों के लिए अर्जुन स्पंदन नामक संदेश है। याददाश्त कमजोर है तो ब्राह्मी स्मृति आजमाएं। नींद नहीं आती तो सुसनी साउंड स्लीप खा लीजिए और शरीर में खून की कमी है तो उसके लिए कुलेखारा मुक्ति है। ये मिठाइयां अल्सर, अपच, मिर्गी, नसों में दर्द, किडनी व गॉल ब्लैडर में स्टोन, अत्यधिक रक्तस्राव और उच्च रक्तचाप में भी कारगर हैं। रवींद्र की कोलकाता में ही हिंदुस्तान स्वीट्स नाम से मिठाई की दुकान है। उनकी मिठाइयां खाकर कई लोगों को फायदा मिला है।

सबसे पहले लेकर आए गाजर के रसगुल्ले : पाल ने कहा-जब हर्बल दवाएं और सौंदर्य प्रसाधन हो सकते हैं तो हर्बल मिठाइयां क्यों नहीं? इसी सोच के साथ मैंने दो दशक पहले काम शुरू किया। ढाई वर्षों के गहन अनुसंधान के बाद हमने 2000 में सबसे पहले गाजर के रसगुल्ले तैयार किए। गाजर में कैरोटिना नामक तत्व होता है। इसमें सेहत के लिए फायदेमंद एंटी-ऑक्सीडेंट के गुण होते हैं। यह खास रसगुल्ला तैयार करने में कोलकाता के ही जादवपुर विश्वविद्यालय के फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से तकनीकी सहयोग लिया गया। इसके बाद हम एक-एक कर सुशनी साउंड स्लीप संदेश, तुलसी दही, अर्जुन स्पंदन, ब्राह्मी स्मृति, कुलेखाड़ा मुक्ति व सोयाबीन सोया रसगुल्ला लेकर आए।

मिठाइयों के साथ रवींद्र कुमार पाल। जागरण

औषधीय गुणों का रखते हैं ख्याल : रवींद्र ने आगे बताया कि इन मिठाइयों को तैयार करने में इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि इनमें प्रयुक्त होने वाले औषधीय पौधों के गुण बने रहे। इसीलिए गाजर व किसी भी औषधीय पौधे को उबाला नहीं जाता। मिठाई तैयार करने से पहले उन्हें औषधि मिश्रित जल में भिगोकर रखा जाता है, ताकि उसमें मौजूद रोग के जीवाणु मर जाएं। क्वालिटी कंट्रोल लैब में कच्चे माल की गहन जांच की जाती है। मिठाइयां तैयार हो जाने पर माइक्रो बायोलॉजी लैब उनकी एक बार फिर जांच की जाती है।

डॉक्टर भी दे रहे सेवन की सलाह : पश्चिम बंग मिष्ठान व्यवसायी समिति के अध्यक्ष रवींद्र कुमार पाल ने कहा, हमारे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं, जो अपने डॉक्टर के परामर्श पर इन मिठाइयों का नियमित रूप से सेवन कर रहे हैं और उन्हें इससे फायदा भी हो रहा है। कई देशों में भी हमारी औषधीय मिठाइयों की आपूर्ति होती है। खासकर अमेरिकी देशों में। हमारी ये मिठाइयां भारत सरकार से पेटेंट की हुई हैं। मिठाइयां बनाने में इस्तेमाल औषधीय पौधों की रामकृष्ण मिशन, नरेंद्रपुर से पूर्ति की जाती है। हमारा आइआइटी खड़गपुर से आधिकारिक तौर पर करार है। साथ ही हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी की मदद भी लेते हैं।

सात दशकों से मिठाइयों के कारोबार में : रवींद्र कुमार पाल सात दशकों से मिठाई के कारोबार में हैं। यह उनका खानदानी कारोबार है। 1947 में देश बंटवारे के बाद बांग्लादेश से उनका परिवार कोलकाता आ गया था और उन्हें यहां हिंदुस्तान स्वीट्स की शुरुआत की, जिसकी अब 11 दुकानें हैं।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

आइएएस एसोसिएशन पर सरकारी आवास का 34 लाख किराया बकाया

नईदुनिया, भोपाल : नियम-कायदे का पालन करने वाले आइएएस अफसरों की एसोसिएशन ने लंबे समय से सरकारी आवास का किराया सरकार के खजाने में जमा नहीं कराया है। लोक निर्माण विभाग ने एसोसिएशन के अध्यक्ष को 15 दिन के भीतर बकाया राशि जमा करने का नोटिस दिया है। सूचना का अधिकार कार्यकर्ता अजय दुबे ने सरकारी आवासों के किराया बकाया की जानकारी के लिए आवेदन लगाया था। इसके जवाब में मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ को आवंटित दो आवास ईएन 1/3 और 1/4 चार इमली, भोपाल (मध्य प्रदेश) पर 30 सितंबर 2019 की स्थिति में 34 लाख 56 हजार 360 रुपए का किराया बकाया है। संघ को दोनों आवास वर्ष 1999 में आवंटित किए गए थे। इन आवासों को संघ कार्यालय और गेस्ट हाउस के तौर पर संचालित करता है। संघ ने 34 लाख 56 हजार रुपए से अधिक का किराया जमा नहीं किया है। दुबे ने बताया कि यदि संघ 15 दिन में बकाया किराया जमा नहीं करता है तो फिर हम अदालत की शरण लेंगे। इस मामले में प्रतिक्रिया के लिए संघ पदाधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका।

जल ने ऐसे बदला 40 गांवों के हजारों परिवारों का जीवन

प्रेमशंकर मिश्रा, मधुबनी

- नदियों, तालाबों, कुओं और वर्षाजल को सहेज कर जल संकट से निपटने का प्रेरक सामूहिक प्रयास
- **40** वर्षों से चल रहा जल संरक्षण का काम, बिहार के मधुबनी और सुपौल के गांवों की बदली तस्वीर

महिलाओं का समय अब दूर से पानी लाने में जाया नहीं होता। किसानों को सिंचाई के लिए बारिश का मुंह नहीं ताकना पड़ता। लोग वर्षा जल का उपयोग पेयजल के रूप में कर रहे हैं। जलजनित बीमारियों से बच्चों को डायरिया नहीं होता। लोग कम बीमार पड़ते हैं। वर्षा जल और परंपरागत जलस्रोतों के बेहतर प्रबंधन से यह संभव हुआ है। बिहार के मधुबनी और सुपौल जिलों के 40 गांवों में जल संरक्षण को जारी हजारों परिवारों के सामूहिक प्रयास की यह प्रेरक गाथा पूरे देश के लिए नजीर है।

नदियों, तालाबों, कुओं और वर्षाजल को सहेज कर जल संकट से निपटने का यह प्रेरक सामूहिक प्रयास मधुबनी और सुपौल के इन गांवों में 40 साल से अनवरत चल रहा है। अब आसपास के अन्य जिलों में भी इसका विस्तार हो चुका है। देशभर के लिए यह अति प्रेरक उदाहरण है कि कैसे जल की एक-एक बूंद को सहेज कर जीवन को आसान और समृद्ध बनाया जा सकता है। कभी तालाबों, कुओं और अन्य पारंपरिक जलस्रोतों से भरपूर मधुबनी में कुप्रबंधन और अधिक दोहन के चलते जल संकट उत्पन्न हो चला था। घोघरडीहा प्रखंड के जगतपुर गांव निवासी रमेश कुमार ने इस समस्या से निपटने की ठानी और इसी क्रम में वर्ष 1978 में घोघरडीहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ अस्तित्व में आया। इसके प्रयासों ने धीरे-धीरे जागरूकता अभियान का रूप ले लिया। देखते ही देखते वह प्रयास सामूहिक प्रयास में बदल गया।

गांवों के लोगों ने पोखरों, तालाबों का संरक्षण व जीर्णोद्धार, नए का निर्माण की रणनीति अपनाई। सभी ने एक-दूसरे का साथ दिया और हौसला बढ़ाया। मधुबनी के झंझारपुर, अंधराठाढ़ी, फुलपरास, घोघरडीहा व लखनौर और सुपौल जिले के मरौना प्रखंड के करीब 40 गांवों को वर्षा जल संग्रहण तकनीक से अवगत कराया गया। मेघ पाइन अभियान की शुरुआत की गई। पानी की अशुद्धता के बारे में जागरूक किया गया। चापाकलों के पानी की जांच की गई। मटका फिल्टर बनाने के बारे में जानकारी दी गई। समुदाय केंद्रित जल योजना भी बनाई गई है। यहां जल महोत्सव भी मनाया जाता है। रमेश कुमार बताते हैं कि शुरुआत में 40 अत्यंत बाढ़ प्रभावित गांवों का चयन किया गया और सामुदायिक जल प्रबंधन योजना शुरू की गई। आज 80 गांवों में यह मुहिम चल रही है।

मधुबनी, बिहार के जहलीपट्टी गांव में जल संरक्षण के लिए बैठक करते ग्रामीण। फाइल फोटो

हर घर में नल

3700 की आबादी वाले मधुबनी के गांव जहलीपट्टी में एक दशक पहले ग्रामीण आयरनयुक्त पानी पीने को विवश थे। 1987 की बाढ़ में भुतही नदी ने सभी जलस्रोतों को बालू से पाट दिया था। इससे पेयजल की स्थिति और खराब हो गई। आज यहां सभी चार सौ परिवार वर्षाजल का संचय कर इसका पेयजल के रूप में उपयोग करते हैं। गांव में जलापूर्ति संयंत्र लगाकर प्रत्येक घर के आगे नल लगा हुआ है। गांव में जल संचय के लिए दो तालाबों का निर्माण, एक का जीर्णोद्धार, दो डबरा का निर्माण और कुएं का जीर्णोद्धार किया गया।

ऐसे सहेजते हैं पानी

जहलीपट्टी गांव की पुष्पा कुमारी बताती हैं कि बारिश के दौरान गांव में किसी खाली जगह में प्लास्टिक शीट टांग देते हैं और उसके बीच में छेद कर देते हैं और टंकियों में पानी भरते जाते हैं। इसी पानी का उपयोग पीने के लिए भी किया जाता है। टंकियों में ईंट के टुकड़े, कोयला और रेत की सतह बनाकर पानी के शुद्धिकरण (फिल्टर) की युक्ति अपनाते हैं। भूजल को भी आयरन रहित बनाने के लिए इसी युक्ति से मटका फिल्टर का भी उपयोग करते हैं।

मधुबनी के जहलीपट्टी गांव में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए लगाई गई टंकी। जागरण

घर-घर इस तरह के मटका फिल्टर के जरिये वर्षाजल का पेयजल के रूप में हो रहा उपयोग।

छह मेडिकल कॉलेजों को इंस्टीट्यूट बनाने की तैयारी

मनीष मिश्र, प्रयागराज

- पहले चरण में कानपुर मेडिकल कॉलेज होगा शामिल
- बढ़ेंगी सुविधाएं, अपनी डिग्री खुद दे सकेंगे संबंधित इंस्टीट्यूट
- सीएम ने सैद्धांतिक रूप से दी स्वीकृति, बनाया जाएगा अधिनियम

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के छह मेडिकल कॉलेजों को इंस्टीट्यूट बनाने की तैयारी कर रही है। पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कानपुर मेडिकल कॉलेज को शामिल किया गया है। इसी क्रम में पांच और मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, मेरठ, झांसी, आगरा व गोरखपुर को भी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सैद्धांतिक स्वीकृति भी दे दी है। इससे मरीजों के साथ डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को भी सहूलियत मिलेगी।

अभी मेडिकल कॉलेज अन्य संस्थानों के अधीन हैं। प्रदेश के दो मेडिकल कॉलेज राम मनोहर लोहिया संस्थान व एसजीपीजीआइ लखनऊ को ही इंस्टीट्यूट का दर्जा मिला है। अन्य मेडिकल कॉलेज दूसरे अलग-अलग संस्थानों के अधीन हैं। ऐसे में इन मेडिकल कॉलेज व उससे जुड़े अस्पतालों के संचालन में परेशानी होती है। इन मेडिकल कॉलेजों को इंस्टीट्यूट बनाने के लिए चिकित्सा विज्ञान संस्थान विधेयक बनाया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले कानपुर मेडिकल कॉलेज को इंस्टीट्यूट में तब्दील कर दिया जाएगा।

प्रतीकात्मक

इंस्टीट्यूट होने से यह फायदा

- संविदा पर प्रोफेसर व डॉक्टर लेने की व्यवस्था होगी खत्म
- यूपीपीएससी के बजाय इंस्टीट्यूट अपने स्तर से नियुक्त करेंगे डॉक्टर
- पहले के सापेक्ष बजट बढ़ेगा, संबंधित अस्पतालों में संसाधन बढ़ेंगे
- इंस्टीट्यूट अपने स्तर से मेडिकल कॉलेज व अन्य सुविधाएं बढ़ा सकेंगे
- खत्म हो जाएगी दवा की कमी, अन्य तरह के सामानों की कमी भी होगी दूर

प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों को इंस्टीट्यूट बनाने की तैयारी है। इससे मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों की व्यवस्था बेहतर होगी। 2020 में कानपुर और 2021 में अन्य पांच मेडिकल कॉलेजों को इंस्टीट्यूट बना दिया जाएगा।

-डॉ. रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ.प्र.

रहें सतर्क

रात 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू होने पर बढ़ जाती पैसे निकालने की लिमिट, इसके अलावा रात में पैसे निकालने के बाद मोबाइल पर जो मैसेज आता है, उस पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं ग्राहक

डेबिट कार्ड से रात 11 से एक बजे तक ज्यादा साइबर ठगी

हसीन शाह, गाजियाबाद

यदि आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रात 11 से एक बजे के बीच सतर्क हो जाइए, क्योंकि इस दौरान साइबर ठग सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इसकी वजह यह है कि रात 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू होने से डेबिट कार्ड से रकम निकालने की लिमिट बढ़ जाती है। इसके अलावा रात में पैसे निकलने के बाद मोबाइल पर जो मैसेज आता है, उस पर भी ग्राहक ध्यान नहीं दे पाते हैं। ज्यादातर साइबर ठग ज्यादा से ज्यादा पैसे निकालने के लिए इसे ही यही समय चुनते हैं।

साइबर ठग कार्ड क्लोनिंग करने के लिए एटीएम के होल्डर में स्कीमर व खुफिया कैमरा लगा देते हैं। कैमरा बहुत ही छोटा होता है। जब ग्राहक अपना डेबिट कार्ड एटीएम होल्डर में लगाता है तो स्कीमर में उसका डाटा स्कैन हो जाता है। एटीएम की-बोर्ड के ऊपर लगे खुफिया कैमरे में कार्ड का पिन नंबर कैद हो जाता है। इसके बाद ठग स्कीमर और कैमरा निकालकर ले जाते हैं। इसके अलावा एटीएम बूथों में डेबिट कार्ड बदलने वाले ठग सक्रिय रहते हैं। मदद करने के बहाने कार्ड बदल लेते हैं। बैंक ने डेबिट कार्ड से रकम निकालने की लिमिट निर्धारित की है। ठगों का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा रकम निकालने पर रहता है। ज्यादातर ठग दिन में पैसे नहीं निकालते। यदि वह दिन में निकालते हैं तो पीड़ित के पास पैसे निकलने का मैसेज आ जाता है और पीड़ित अपना कार्ड ब्लॉक करा देता है। इससे वह एक बार ही पैसे निकाल पाते हैं। ऐसे में साइबर ठग 12 बजने का इंतजार करते हैं। 12 बजे से कुछ मिनट पहले पैसे निकालते हैं। दूसरा दिन शुरू होने पर 12 बजे के बाद पैसे निकालने की लिमिट बढ़ जाती है और वे फिर से पैसे निकाल लेते हैं। जब सुबह पीड़ित उठता तो है उसे मैसेज देखकर ठगी का पता चलता है। इसके बाद पीड़ित अपना कार्ड ब्लॉक कराता है।

जागरूक होना ही साइबर अपराध से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। डेबिट कार्ड से ठगी करने वाले रात लगभग 12 बजे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। सावधानी बरतने पर कार्ड क्लोनिंग से बचा जा सकता है।

-जहीर खान, साइबर सेल प्रभारी

प्रतीकात्मक फोटो

बरतें सावधानियां

- उस एटीएम का इस्तेमाल करें, जहां पर सुरक्षा गार्ड तैनात हो
- डेबिट कार्ड लगाते समय होल्डर को ठीक से चेक कर लें। उसमें स्कीमर लगा हो सकता है
- कैमरे से बचने के लिए पिन डालते वक्त की-बोर्ड के ऊपर हाथ लगा लें
- कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें
- बूथ में अगर दूसरा व्यक्ति है तो उसे बूथ से बाहर भेज दें
- सुनसान स्थान पर लगे एटीएम का इस्तेमाल करने से बचें
- यदि कोई ठगी हो जाती है तो 24 घंटे के भीतर बैंक में शिकायत करें, बैंक पूरी रकम लौटाएगा
- कार्ड बदलने का शक होने पर तुरंत बैंक को फोन कर उसे ब्लॉक करा दें

उत्तरांचल के नैनी झील की सतह की होगी जांच

जागरण संवाददाता, नैनीताल

- जीपीएस लैस ईको बोट से आज से वैज्ञानिक शुरू करेंगे कार्य

सरोवर नगरी की शान नैनी झील के बेहतर संरक्षण को लेकर अत्याधुनिक तकनीक बैथीमैट्री सिस्टम का सहारा लिया जाएगा। इससे झील की सतह की जांच होगी। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के वैज्ञानिकों की टीम शनिवार से जांच कार्य शुरू कर देंगे। जांच से झील के सतह की विभिन्न जानकारियां उपलब्ध हो सकेंगी।

डीएम सविन बंसल ने बताया कि झील की सतह की जानकारी के बिना इसके संरक्षण में ठोस उपाय किए जाने संभव नही हैं, इसलिए बैथीमैट्री पद्धति प्रयोग में लाई जा रही है। इससे झील के सतह की अनेक जानकारियां उपलब्ध हो सकेंगी। वैज्ञानिकों की टीम सघन विश्लेषण करने के बाद झील के ईको सिस्टम बनाए रखने के बारे में जानकारियां जुटा पाएगी। झील की सतह की आंतरिक संरचनाओं में हुए परिवर्तन का पता चल जाएगा। इसके अलावा झील की प्रकृति की जानकारी मिलेगी। लैंड टोपोग्राफी, लेक फ्लोर व आंतरिक जलश्रोतों का पता लगाने में बैथीमैट्री सिस्टम बेहद कारगर है। रुड़की के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. वैभव गर्ग के नेतृत्व में पांच सदस्यीय टीम जीपीएस सिस्टम से लेस ईको बोट से इस कार्य को अंजाम देंगे।

नैनी झील। फाइल

पानीपत में एथनॉल प्लांट को मिली पर्यावरण मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : पर्यावरण मंत्रालय ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आइओसीएल) को हरियाणा के पानीपत जिले में एथनॉल प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है। यह दूसरी पीढ़ी का एथनॉल प्लांट 766 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि इससे किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होगी।

दुनिया और भारत की अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। लेकिन भारत आर्थिक मंदी से बहुत दूर है।
— निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री

नीलामी में स्पेक्ट्रम कीमत कम रखने पर विचार

वजह ▶ अधिक से अधिक कंपनियों को स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा लेने को प्रेरित करना लक्ष्य

टेलीकॉम कंपनियों पर बड़ा वित्तीय बोझ, ज्यादा भाव में नीलामी से रह सकती हैं दूर

नई दिल्ली, आइएएनएस : दूरसंचार विभाग (डीओटी) चालू वित्त वर्ष में प्रस्तावित स्पेक्ट्रम नीलामी में बेस प्राइस कम रखने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक यह विचार इसलिए हो रहा है ताकि टेलीकॉम कंपनियां नीलामी में हिस्सा ले सकें और उन्हें किफायती दाम में स्पेक्ट्रम मिल सके। सूत्रों का कहना है कि विभाग स्पेक्ट्रम के दाम में 35 प्रतिशत तक की कटौती के बारे में सोच रहा है।

डीओटी के एक अधिकारी ने कहा, 'हम अगले वर्ष मार्च से पहले स्पेक्ट्रम नीलामी की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक की योजना के मुताबिक यह नीलामी इसी वित्त वर्ष में होनी है। हम स्पेक्ट्रम की कीमत कम करने पर विचार कर रहे हैं। टेलीकॉम मंत्री इस वर्ष इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान कह चुके हैं कि सरकार इस वर्ष की नीलामी के लिए स्पेक्ट्रम की कीमत की समीक्षा कर रही है। हालांकि यह कटौती कितनी होगी, यह अभी तय नहीं किया जा सका है लेकिन यह 30-35 प्रतिशत तक कम हो सकती है।' सूत्रों के मुताबिक टेलीकॉम कमीशन इस महीने प्रस्तावित बैठक में स्पेक्ट्रम की बेस प्राइस घटाने के बारे में विचार करेगा। डीओटी का विचार है कि वर्तमान में टेलीकॉम कंपनियों की जिस तरह की माली हालत है, उसमें वे स्पेक्ट्रम के मौजूदा भाव पर नीलामी में हिस्सा लेने की हालत में नहीं हैं। भारत में इस वक्त टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की कीमत दुनियाभर में सबसे ज्यादा है। डीओटी ने इससे पहले भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से स्पेक्ट्रम की कीमत घटाने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा था। ट्राई ने 5-जी स्पेक्ट्रम के लिए प्रति मेगाहर्ट्ज 492 करोड़ रुपये की बेस प्राइस रखने का सुझाव दिया। इसका मतलब यह है कि 100 मेगाहर्ट्ज 5-जी स्पेक्ट्रम के लिए कंपनियों को करीब 50,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे।

गौरतलब है कि सरकार ने 4-जी के अलावा 5-जी स्पेक्ट्रम की पहली नीलामी भी चालू वित्त वर्ष में ही करने का लक्ष्य रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष 24 अक्टूबर को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) के मामले में टेलीकॉम कंपनियों की दलीलें खारिज करते हुए सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। इससे वोडाफोन आइडिया और एयरटेल पर करीब 90,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त देनदारी बन गई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कंपनियों को यह रकम अगले वर्ष 24 जनवरी तक चुका देनी है। ऐसे में अगर कंपनियां एजीआर का बकाया चुकाती हैं, तो वे नीलामी में हिस्सा लेने की हालत में नहीं होंगी।

प्रतीकात्मक

एयरटेल-टाटा विलय के खिलाफ कोर्ट जाएगा डीओटी

नई दिल्ली, आइएएनएस : दूरसंचार विभाग (डीओटी) टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड (टीटीएसएल) और एयरटेल के विलय को सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) के माध्यम से इसी महीने चुनौती देने का मन बना रहा है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने यह जानकारी दी है। टेलीकॉम विवाद निपटान अपीलीय प्राधिकरण टीडीसैट ने इस वर्ष जुलाई में दोनों कंपनियों के विलय को मंजूरी दे दी थी। अधिकारी ने कहा कि टीडीसैट के फैसले के आधार पर ही एयरटेल ने टीटीएसएल के परिचालन को समाहित कर लिया है। विभाग इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दाखिल करेगा। गौरतलब है कि एसएलपी किसी फैसले के खिलाफ कोई याचिका नहीं, बल्कि उस फैसले में अपना पक्ष सुने जाने के लिए दायर एक पिटीशन होता है। इस बीच, डीओटी ने सभी टेलीकॉम सर्किल के प्रमुखों से कहा है कि वह एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज से अलग-अलग कंपनियों की तरह व्यवहार करे। विभाग ने प्रमुखों से दोनों कंपनियों द्वारा ग्राहक अधिग्रहण प्रक्रिया और कंप्लायंस संबंधित कानूनों के पालन के मामलों को भी अलग-अलग देखने को कहा है। डीओटी ने सभी सर्किल के प्रमुखों को छह नवंबर को इस आशय का पत्र भेजा है।

एक लाख टन प्याज आयात करने की सरकार की तैयारी

- प्याज की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के हो रहे प्रयास
- दिल्ली-समेत कई स्थानों पर 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहा प्याज

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्याज की कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार एक लाख टन प्याज आयात करने की तैयारी में है। पिछले कुछ समय से प्याज की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इस समय यह दिल्ली समेत कुछ स्थानों पर 100 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर बिक रहा है। शनिवार को सचिवों की एक समिति द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक सरकारी ट्रेडिंग फर्म एमएमटीसी विदेशों से प्याज खरीदेगी, जबकि नैफेड इसे घरेलू बाजार के माध्यम से रसोई घरों तक पहुंचाएगी।

खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने इस आशय की जानकारी दी। इससे पहले पिछले सप्ताह सरकार ने यूएई और कुछ अन्य देशों से प्याज आयात करने की बात कही थी। एमएमटीसी के मुताबिक खरीद के लिए जारी पहला टेंडर 14 नवंबर और दूसरा 18 नवंबर को बंद होगा। इसमें से पहली खेप बहुत जल्द ही भारतीय पोर्ट पर पहुंच जाएगी, जबकि दूसरी खेप दिसंबर अंत तक पहुंचेगी।

प्याज आयात के इस फैसले में कहा गया है कि एमएमटीसी किसी भी देश से प्याज आयात कर सकती है। हालांकि पिछली बार जारी किए गए टेंडर पर उचित प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। सप्लाई कम होने के चलते पिछले एक महीने से अधिक समय से प्याज की कीमत में लगातार वृद्धि हुई है। देश में महाराष्ट्र और कर्नाटक प्याज के बड़े उत्पादक हैं। लेकिन इस बार अधिक बारिश के कारण यहां 30-40 परसेंट फसल बर्बाद हो गई थी।

तेजस को बढ़िया रिस्पांस 21 दिनों में कमाए 70 लाख

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस ने अपने संचालन के बाद से अक्टूबर तक 70 लाख रुपये का मुनाफा कमाया है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आइआरसीटीसी) के मालिकाना हक वाली इस ट्रेन की शुरुआत पिछले महीने की पांच तरीख को हुई थी। यह आंकड़े पांच से 28 अक्टूबर तक के हैं। ट्रेन ने इसी अवधि में टिकट बिक्री के जरिये करीब 3.70 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया है। देश में किसी ट्रेन द्वारा मुनाफा कमाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रेलवे लगातार घाटा दर्ज करता रहा है।

लखनऊ और दिल्ली के बीच चलने वाली यह ट्रेन भारतीय रेलवे की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत 50 विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन विकसित किए जाने हैं। इन पर निजी संचालकों द्वारा 150 निजी ट्रेन चलाए जाने की योजना है। आइआरसीटीसी ने बताया कि इस अवधि में तेजस के परिचालन में करीब तीन करोड़ रुपये का खर्च आया है। यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलती है। इस तरह से तेजस के संचालन में आइआरसीटीसी रोजाना करीब 14 लाख रुपये खर्च करती है, जबकि उसे यात्री किराए से 17.50 लाख रुपये की राजस्व मिलता है।

फाइल फोटो

- देश की पहली निजी ट्रेन लखनऊ और दिल्ली के बीच सप्ताह में छह दिन चलती है
- यात्रियों को दी जाती हैं कुछ विशिष्ट सुविधाएं, लेट होने पर क्षतिपूर्ति भी

गौरतलब है कि तेजस एक्सप्रेस देश में अपनी तरह की पहली निजी ट्रेन है। हालांकि इसकी संचालक आइआरसीटीसी भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी है। तेजस के यात्रियों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। इनमें विशेष खाना, 25 लाख रुपये तक का मुफ्त बीमा और लेट होने पर क्षतिपूर्ति शामिल है।

ईरान को मिला विशाल पेट्रोलियम भंडार

तेहरान, एएफपी : ईरान ने एक बड़ा तेल क्षेत्र खोज निकालने का दावा किया है। ईरान के दक्षिणी प्रांत में पाए गए इस तेल क्षेत्र में करीब 5,300 करोड़ बैरल कच्चा तेल होने का अनुमान लगाया गया है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि इस खोज के बाद उनके तेल भंडार में एक-तिहाई का इजाफा हो जाएगा। रूहानी ने सरकारी टीवी के जरिये इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद ईरान की इकोनॉमी सुचारू रूप से चल रही है।

जानकारी के मुताबिक 80 मीटर गहरा यह तेल भंडार ईरान की इराक से लगी खुजिस्तान सीमा से लेकर ओमीदिया शहर तक 200 किलोमीटर दायरे में फैला हुआ है। रूहानी ने अपने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सरकार द्वारा लोगों को दिया गया एक छोटा सा उपहार है। अमेरिका द्वारा लगातार कष्टकारी प्रतिबंध लगाने के बावजूद हम आज एक अमीर देश बन गए हैं। ईरान की ऑयल इंडस्ट्री के कर्मचारियों ने एक बड़ा तेल क्षेत्र खोज निकाला है।

इस खोज के बाद ओपेक देशों के कुल तेल भंडार में 34 परसेंट का इजाफा हो जाएगा। गौरतलब है कि ईरान तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के संस्थापक देशों में शामिल है।

- ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने सरकारी टीवी पर की घोषणा
- यहां 53 हजार करोड़ बैरल कच्चा तेल होने का अनुमान

प्रतीकात्मक

बात पते की

अगर भंडार की क्षमता ईरान की उम्मीदों के मुताबिक हुई, तो वह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन जाएगा

तेल भंडार के मामले में वह पहले से ही दुनिया का पांचवा बड़ा देश है। अगर इस तेल खोज का दावा साबित हो जाता है, तो ईरान तेल भंडार के मामले में तीसरे स्थान पर आ जाएगा। तेल के खजाने पर बैठा ईरान प्रतिबंधों के चलते अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं।

पिछले वर्ष अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में ईरान के साथ हुई परमाणु संधि से हाथ खींच लिए थे और उसपर फिर से प्रतिबंध लगा दिए थे। ईरान की इकोनॉमी पर इन प्रतिबंधों का बहुत बुरा असर हुआ है। इसके साथ ही भारत भी ईरान पर प्रतिबंधों से प्रभावित हुआ है। गौरतलब है कि भारत बड़े पैमाने पर ईरान से कच्चा तेल आयात करता रहा है।

इस दौरान दोनों देशों में कई तरह के महत्वपूर्ण समझौते भी हुए हैं। इनमें तेल खरीदने के लिए डॉलर की जगह रुपये के इस्तेमाल का समझौता भी शामिल है। हालांकि ट्रंप प्रशासन कुछ समय के लिए भारत समेत आठ देशों को ईरान से तेल खरीदने की छूट दी थी। लेकिन इस वर्ष मई में यह छूट वापस ले ली गई। इसके बाद भारत को तेल खरीदने के लिए दूसरे विक्रेता देशों को खोजना पड़ा।

म्यूचुअल फंड्स में खुदरा निवेशकों का बढ़ रहा रुझान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

म्यूचुअल फंडों में खुदरा निवेशकों की रुचि बढ़ रही है। इसकी एक प्रमुख वजह सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआइपी में मिलने वाला उच्च रिटर्न है। यही वजह है कि म्यूचुअल फंड की एसआइपी योजनाओं की कुल परिसंपत्तियां तीन लाख करोड़ रुपये को पार कर गई हैं। हालांकि बाजार में तेजी बने रहने के बावजूद अक्टूबर में म्यूचुअल फंडों में होने वाला कुल निवेश मात्र 6,015 करोड़ रुपये पर सीमित रह गया है, जो बीते पांच महीने का निचला स्तर है।

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री (एम्फी) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक खुदरा निवेशकों में एसआइपी खातों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। एम्फी का मानना है कि म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए यह सकारात्मक संकेत है। एम्फी के सीईओ एनएस वेंकटेश ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि शेयर बाजार आने वाली तिमाही में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इससे म्यूचुअल फंड में निवेश का प्रवाह और बढ़ेगा।'

एम्फी के आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष अक्टूबर में उद्योग की कुल परिसंपत्तियां (एयूएम) करीब 26.33 लाख करोड़ रुपये रही हैं। बीते वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले इसमें 18 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर इनमें एसआइपी योजनाओं में होने वाले निवेश की बात करें तो अक्टूबर में कुल 8,246 करोड़ रुपये का निवेश आया है।

लेकिन ओपन एंडेड इक्विटी योजनाओं में निवेश का प्रवाह चिंता पैदा कर रहा है। सरकार की तरफ से आर्थिक सुधारों की दिशा में उठाए गए कदमों की वजह से शेयर बाजार में चल रही तेजी के बावजूद इनमें निवेश की रफ्तार अपेक्षित नहीं है। एम्फी के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में इन योजनाओं में 6,026 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। जबकि 11 करोड़ रुपये इन योजनाओं से निवेशकों ने इसमें से निकाले। इस तरह कुल 6015 करोड़ रुपये का निवेश इन योजनाओं में आया। यह पिछले पांच महीने में ओपेन एंडेड योजनाओं में हुआ सबसे कम निवेश है।

इसके विपरीत इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड सेविंग योजनाओं में सितंबर में 6,489 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। अगस्त में 9,090 करोड़, जुलाई में 8092 करोड़, जून में 7,585 करोड़ रुपये और मई में 4,968 करोड़ रुपये मई में इन योजनाओं में निवेश किए गए।

प्रतीकात्मक

- पहली बार एसआइपी एयूएम तीन लाख करोड़ रुपये के पार
- इक्विटी में कुल निवेश अक्टूबर में पांच महीने के निचले स्तर पर

इस सप्ताह बड़े आर्थिक आंकड़ों का शेयर बाजारों पर दिखेगा असर

नई दिल्ली, प्रेट्र : इस सप्ताह बड़े आर्थिक आंकड़े भारतीय शेयर बाजारों पर अपना असर डाल सकते हैं। पिछले कुछ सप्ताह के दौरान कंपनियों के तिमाही नतीजों का शेयर बाजारों पर सीधा असर देखा गया। लेकिन अब लगभग सभी प्रमुख कंपनियों के तिमाही नतीजे जारी हो चुके हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि अयोध्या विवाद में आए फैसले का निवेशकों पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है। मंगलवार को गुरु नानक जयंती के मौके पर बाजार बंद रहेंगे।

इस सप्ताह बड़े आर्थिक आंकड़ों में औद्योगिक उत्पादन के नतीजे सोमवार को, मंहगाई दर मंगलवार और थोक मूल्यों पर आधारित मंहगाई के आंकड़े गुरुवार को जारी किए जाएंगे। निवेशक इन आंकड़ों पर नजदीक से नजर रखेंगे। इस सप्ताह कोल इंडिया लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और एनएमडीसी के तिमाही नतीजे जारी होने हैं। ट्रेडिंगबेल्स के सीनियर एनालिस्ट संतोष मीना के मुताबिक अयोध्या मामले का शेयर बाजारों पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है। शांति भंग होने की स्थिति में बाजार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते थे।

- निवेशकों को कुछ बड़े आर्थिक आंकड़ों का है इंतजार
- व्यापारिक-वार्ता को लेकर आने वाली खबरों का भी दिखेगा असर

प्रतीकात्मक

एपिक रिसर्च के सीईओ मुस्तफा नदीम ने कहा कि बाजार में इस समय उत्साह देखा जा रहा है। यह रिकॉर्ड ऊंचाई के आस-पास है। ऐसे में बड़े आर्थिक आंकड़े निवेशकों का मूड प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका और चीन में जारी ट्रेड-वार्ता पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। साथ ही रुपये का भाव और कच्चे तेल की कीमत से भी बाजार प्रभावित होंगे।

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह के दौरान बीएसई के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में 158.58 अंक का इजाफा हुआ था। हालांकि मुडीज द्वारा भारत के इकोनॉमिक आउटलुक को डाउनग्रेड करने के कारण शुक्रवार को शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई।

चार बड़ी कंपनियों के एम-कैप में गिरावट

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले सप्ताह शेयर बाजारों की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से चार का बाजार पूंजीकरण कुल 55,681.8 करोड़ रुपये गिरा। इस दौरान टीसीएस, एचयूएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आइटीसी के एम-कैप में गिरावट आई। हालांकि इस दौरान आइसीआइसीआइ बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआइ अपने एम-कैप में कुल 54,875.04 करोड़ इजाफा करने में कामयाब रहे।

टोल कंपनी के अड़ंगे से अटका मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट

श्रीशंकर शुक्ला, रायपुर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना छत्तीसगढ़ में अटक गई है। दरअसल योजना के अंतर्गत टेडेसरा से आरंग तक बनने वाले फोरलेन पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। लखौली टोल प्लाजा और धमधा टोल प्लाजा के संचालकों ने इसका विरोध किया है, क्योंकि फोरलेन बन जाने से दोनों टोल प्लाजा पर गाड़ियों की संख्या कम हो जाएगी और उनके व्यापार पर असर पड़ेगा। इसलिए दोनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) से मुआवजे की मांग है। अधिकारियों का कहना है कि पहले यह प्रोजेक्ट विभाग की प्राथमिकता में था, लेकिन अब इसे पेंडिंग में डाल दिया गया है।

वजह साफ है कि टोल प्लाजा वालों को मुआवजा देने पर प्रोजेक्ट की लागत तीन गुना बढ़ जाएगी। इतना खर्च करना एनएचएआइ के लिए संभव नहीं है। हालांकि एनएचएआइ ने दोनों टोल प्लाजा के संचालकों से मुआवजे की अनुमानित राशि की जानकारी मांगी है, लेकिन उन्होंने अभी तक जानकारी नहीं दी है।

बता दें कि टेडेसरा से रायपुर से सटे आरंग तक 92.230 किलोमीटर के फोरलेन के निर्माण की स्वीकृति करीब चार साल पहले मिली थी। फोरलेन के निर्माण में करीब 1,500 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। रायपुर से दुर्ग तक कुल 1,450 करोड़ रुपये की लागत से भू-अधिग्रहण का काम किया जाना है। एनएचएआइ के अधिकारियों ने भू-अधिग्रहण के लिए सर्वे कर लिया है। लेकिन शासकीय स्वीकृति अभी तक अधिकारियों को नहीं मिली है कि कितना पैसा किसको देना है।

- छत्तीसगढ़ में टोल कंपनियों की कमाई बचाने को अरबों का प्रोजेक्ट अधर में
- आरंग से टेडेसरा तक 92.230 किलोमीटर बननी है फोरलेन

टेडेसरा से आरंग तक बनने वाले 92.230 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना है, लेकिन आरंग से टेडेसरा के बीच आने वाले टोल नाका की वजह से दिक्कत आ रही है।
-बीएल मीना, अनुविभागीय अधिकारी, एनएच, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

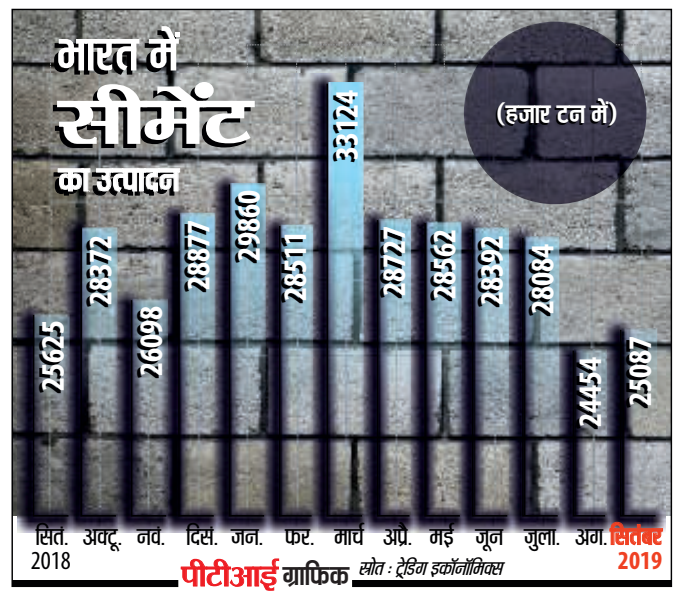

सपनों का घर खरीदने को बनाएं लक्ष्य, सुंदर घर का सपना बेचने वालों पर न जाएं

वर्षों तक लोगों की बचत और खर्च का नजदीकी निरीक्षण करने के बाद मुझे एक बात का पक्का यकीन हो गया है कि ज्यादातर बड़े फैसले वित्तीय हालत को ध्यान में रखकर नहीं लिए जाते हैं। अक्सर फैसले बचत करने वाले के मनोविज्ञान पर आधारित होते हैं। जब बात घर खरीदने की आती है, तो लोग अपनी वित्तीय स्थिति से ज्यादा दूसरी बातों पर ध्यान देते हैं। वे बाहरी चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। डेवलपर सपनों का घर देने का वादा करते हैं और लोग फंस जाते हैं।

इंसान अपने पड़ोस से प्रभावित होने वाला प्राणी है। हम दुनिया को कैसे देखते हैं, यह बहुत हद तक हमारे रहन-सहन से प्रभावित होता है। चाहे कोई झुग्गी में रहने वाला परिवार हो या शहर के किसी शानदार घर में रहने वाला कोई बड़ा बिजनेसमैन या अधिकारी तबके का व्यक्ति, यह बात सभी पर समान रूप से लागू होती है।

रियल एस्टेट डेवलपर इस तरह के इंसानी मनोविज्ञान का उपयोग भरपूर उपयोग करते हैं। वे चकाचौंध में यकीन रखने और तुरंत

धीरेंद्र कुमार, सीईओ
वैल्यू रिसर्च

बोनस

भारतीय ग्राहकों की एक खासियत यह है कि वे छोटी-छोटी खरीदारी तो खूब ठोक-बजाकर करते हैं। लेकिन जब बात बड़े वित्तीय फैसलों की आती है, तो यही ग्राहक जमीनी हकीकतों की अनदेखी कर मनोवैज्ञानिक आधार पर फैसले कर लेते हैं। सपनों का घर खरीदने के मामले में यह बात ज्यादा ही सच मालूम पड़ती है। घर खरीदते वक्त ग्राहक अक्सर झूठे प्रचार और वादों में फंसकर निवेश कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। इस तरह के खर्च का खामियाजा कई बार अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। ऐसे में लुभावने वादों में पड़ने से बेहतर है कि घर खरीदते वक्त कुछ मूलभूत बातों का ख्याल रखना चाहिए।

सपनों की दुनिया में चले जाने वाले ग्राहकों को भटकाने-भरमाने का पूरा लाभ उठाते हैं। कुछ दिनों पहले मुझे ट्विटर के जरिये एक चौंकाने वाली बात पता चली। मुंबई का एक जाना-माना डेवलपर लोगों को घर बेचने से पहले उनकी आर्थिक स्थिति को परखने का दावा कर रहा था। वह आर्थिक स्थिति के मुताबिक लोगों की पहचान करके उन्हें घर खरीदने के लिए निमंत्रण भेजता था। खैर कई वर्षों के बाद आज भी वह कांप्लेक्स खाली है। कीमतें आधी हो चुकी हैं, फिर भी घर बिके नहीं हैं। खरीदने का निमंत्रण तो आज मजाक जैसा लगता है। लेकिन उस दौर में यह कामयाब था, लोग इस निमंत्रण के झांसे में आ जाया करते थे।

आज भले ही ट्विटर जैसी जगहों पर इनका मजाक बनाया जाता हो। लेकिन उस समय डेवलपर बाकायदा अखबारों में इश्तिहार देते और डींगे हांकते कि उनकी प्रॉपर्टी सिर्फ वही लोग खरीद सकते हैं जिन्हें इसे खरीदने का निमंत्रण दिया जाएगा। जरा सोचिए कि डेवलपर्स कैसे संभावित ग्राहकों के मनोविज्ञान में सेंध लगाते थे। असल में वे लोगों की मानसिकता का फायदा उठाते थे। हर किसी के मन में यह ख्वाहिश होती है कि उसका एक शानदार घर हो। बस इसी शानदार घर का सपना दिखाकर डेवलपर लोगों को घर बेचा करते थे। वैसे अगर गौर करें तो बिक्रेता आज भी कपड़ों से लेकर स्मार्टफोन तक को बेचने में मनोविज्ञान का उपयोग कर रहे हैं।

हालांकि घर का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि यहां खर्च काफी बड़ा होता है। यह मामला किसी युवा व्यक्ति द्वारा कोई मंहगा फोन खरीदने जैसा नहीं है। अगर कोई बाहरी कारणों से प्रभावित होकर क्षमता से अधिक मंहगा फोन खरीद लेता है, तो कुछ महीनों तक उसे वित्तीय समस्या हो सकती है। इसके बाद वह इससे उबर जाएगा। लेकिन घर खरीदने के मामले में की गई गलती से बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कई बार तो इससे लोगों और परिवारों को स्थायी नुकसान हो जाता है।

घर खरीदने के मामले में तीन बेसिक नियम आज भी उतने ही कारगर हैं, जितना यह पहले होते थे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेवलपर्स कितना संकट में हैं या 2008 अथवा 2013 की तुलना में आज कीमत में कितना अंतर है। मैं पहले भी इन तीन नियमों की चर्चा कर चुका हूं। इनमें पहला नियम है कि आप सिर्फ अपने रहने के लिए घर खरीदें, जिससे कि आपको रेंट नहीं देना पड़े। इसे निवेश करने के लिए बिल्कुल भी नहीं चुनें। आपका पहला घर आपको रेंट से छुटकारा दिलाने और ईएमआइ भरने से मिलने वाली टैक्स छूट के लिए होना चाहिए।

दूसरा नियम यह है कि अपनी क्षमता से बाहर नहीं निकलें। आप किसी फैंसी घर को चाहे जितना पसंद करते हों, लेकिन एक सीमा से ज्यादा खर्च नहीं करें। आपकी ईएमआइ आपके परिवार की कुल आय के एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। घर खरीदते समय रियल स्टेट द्वारा फैलाए गए प्रचार के जाल में कतई नहीं फंसे। अपना सपनों का घर खरीदने से बचें, हो सकता है कि आप भविष्य में ज्यादा अमीर हो जाएं, तब आप इस सपने को पूरा कर सकते हैं।

तीसरा नियम यह कहता है कि घर खरीदें, वादा नहीं। मतलब आप किसी डेवलपर द्वारा किए जा रहे वादों पर भरोसा नहीं करके तकनीकी बातों का ख्याल रखें। एक तथ्य कहता है कि कीमत की वजह से लोग उतना परेशान नहीं होते, जितना निवेश करने के बाद भी घर नहीं मिलने से होते हैं। इसलिए कभी वादों पर भरोसा नहीं करें। वास्तव में सिर्फ उस घर का सौदा करना चाहिए जो मौजूद हो। किसी दूसरे के दिखाए सपने या वादों में नहीं पड़कर वास्तविक चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। इन मूल बातों को ध्यान में रखकर खरीदे गए घर के मामले में निवेशकों को निराश नहीं होना पड़ेगा।

पाक में सिख अलगाववादियों की मौजूदगी ने बढ़ाई चिंता

करतारपुर से लौटने वाले श्रद्धालुओं के साथ मिलकर देश में घुस सकते हैं आतंकी

कॉरिडोर के गलत इस्तेमाल को लेकर खुफिया एजेंसियां कर चुकी हैं आगाह

नई दिल्ली, आइएएनएस : करतारपुर कॉरिडोर खुल गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब के लिए भारतीय श्रद्धालुओं की वीजा मुक्त आवाजाही शुरू हो गई है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में सिख अलगाववादियों की मौजूदगी ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। भारत को डर है कि दरबार साहिब से मत्था टेककर लौटने वाले श्रद्धालुओं में शामिल होकर सिख अलगाववादी और आतंकी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए भारत की सीमा में घुस सकते हैं। पाकिस्तान में अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों से भी बड़ी संख्या में अलगाववादियों के आने की खुफिया जानकारी है।

खुफिया एजेंसियों ने सरकार को पाकिस्तान के गुरुद्वारों में सिख आतंकियों और अलगाववादियों की सक्रियता के प्रति आगाह भी किया है। करतारपुर गुरुद्वारा प्रबंधन समिति में पाकिस्तान द्वारा आतंकी गोपाल सिंह चावला को शामिल किए जाने से भी उसकी चाल का पता चलता है। हालांकि, भारत के विरोध के बाद चावला को हटा दिया गया था। चावला आतंकी सरगना हाफिज सईद का करीबी भी है।

गुरुनानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव पर शनिवार को करतारपुर में जुटे हजारों श्रद्धालु। रायटर

करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले पाकिस्तान ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें सिख आतंकवादी जनरैल सिंह भिंडरांवाले और उसके दो सहयोगियों के फोटो और बैनर दिखाए गए थे। कुछ भड़काऊ नारे लिखे बैनर और पोस्टर भी वीडियो में दिखाए गए थे।

कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद पाकिस्तान ने करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब के बाहर प्रदर्शनी लगाई थी। इसमें एक बम को रखा गया था, जिसके बारे में पाकिस्तान की तरफ से झूठा प्रचार किया गया कि 1971 की लड़ाई में भारतीय वायु सेना ने गुरुद्वारा को ध्वस्त करने के लिए यह बम गिराया था। पाकिस्तान की कोशिश इसके जरिए करतारपुर जाने वाले सिख श्रद्धालुओं की भावनाओं को भड़काने की थी। इसके अलावा हाल के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से पंजाब प्रांत में ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जाने की दो घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान में सक्रिय जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों और हाफिज सईद जैसे आतंकियों और सिख अलगाववादियों के बीच बैठकें भी होती हैं।

पाकिस्तान ने लरकाना में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी किया है। सरकार को लग रहा है कि पाकिस्तान सिख समुदाय के उदारता दिखाकर उन पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है और उसके जरिए पंजाब में आतंकवाद को हवा देना चाहता है।

इन तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए भारत सरकार के सामने यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पंजाब में एक बार फिर आतंकवाद को बढ़ावा देने की फिराक में है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ही खुफिया एजेंसियों ने भी इस तरह की आशंकाए जताई हैं। हालांकि, सरकारी स्तर पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान की इस नापाक चाल के बारे में उसे भी जानकारी है और उसकी हर साजिश को नाकाम करने की पूरी तैयारी है।

पाकिस्तान के वार म्यूजियम में 'अभिनंदन'

इस्लामाबाद, एएनआइ : भारत के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान के तहत पाकिस्तान ने अपने वार म्यूजियम (युद्ध से संबंधित वस्तुओं के संग्रहालय) में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान का पुतला रख दिया है। अभिनंदन इसी साल फरवरी में हमले के लिए भारत में आए पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों का पीछा करते हुए पाकिस्तान में जा घुसे थे। वहां विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी एफ-16 लड़ाकू विमान मार गिराया था, इस दौरान उनका मिग विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उन्हें पकड़ लिया गया था। बाद में भारत के तीखे तेवर देखते हुए पाकिस्तान को अभिनंदन को ससम्मान वापस करना पड़ा था।

पाकिस्तानी पत्रकार अनवर लोधी के विंग कमांडर अभिनंदन के पुतले का फोटो ट्विटर पर पोस्ट करने पर पाकिस्तान के कुचक्र से पर्दा हटा। लोधी ने पाकिस्तानी सेना की हरकत पर तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा है कि इस पुतले से निकला संदेश और बेहतर होता कि उसके हाथ में एक चाय का प्याला भी थमा दिया गया होता। फरवरी में अभिनंदन की पाकिस्तान में हिरासत के समय का जो वीडियो पाकिस्तानी सेना ने जारी किया था, उसमें उन्हें चाय पीते हुए दिखाया गया था। एक स्थान पर अभिनंदन यह कहते हुए सुनाई दिए थे- यह चाय शानदार है, धन्यवाद।

पाकिस्तान के वार म्यूजियम में विंग कमांडर अभिनंदन का पुतला एक कांच के बॉक्स में रखा हुआ है। पाकिस्तानी सेना इसे भारत पर मिली बढ़त और अपने गौरवपूर्ण कार्य के रूप में प्रदर्शित कर रही है।

पाकिस्तान की एयर फोर्स के वार म्यूजियम में रखा गया भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन का पुतला। साभार : ट्विटर

न्यूज गैलरी

ऑस्ट्रेलिया में आग फैली सिडनी पर मंडरा रहा खतरा

ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में लगी भीषण से प्रभावित लोगों से रविवार को प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भेंट की। रायटर

तारी : ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में लगी भयंकर आग कहर बरपा रही है। बीते शुक्रवार से देश में आग की घटनाओं के चलते तीन लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज्यादा घर जल कर राख हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से के जंगली इलाकों में लगी भयानक आग से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। इसकी चपेट में शहर की आबादी भी आ चुकी है। अकेले ग्लेन इंस शहर में इससे दो लोगों की मौत की खबर है। न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड प्रांतों के सौ से अधिक इलाकों में लगी यह आग अब ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहर सिडनी की ओर बढ़ रही है। अधिकारियों ने आगाह करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में सिडनी शहर बुरी तरह इसकी चपेट में आ सकता है। (एएफपी)

नेपाली पीएम से जुड़े 17 शीर्ष अधिकारियों ने दिया इस्तीफा

काठमांडू : बीमार चल रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सचिवालय से जुड़े 17 शीर्ष अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। त्यागपत्र देने वाले अधिकारियों में प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार बिष्णु रिमल, विदेश मामलों के सलाहकार राजन भट्टाराई, जनसंपर्क अधिकारी अच्युत मैनाली, पीएम की निजी सचिव इंद्रा भंडारी, मीडिया सलाहकार कुंदन आर्यल एवं सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार असगर अली प्रमुख हैं। ओली ने खुद इन अधिकारियों को त्यागपत्र सौंपने को कहा था। अधिकारियों का इस्तीफा 17 नवंबर को प्रभावी हो जाएगा। त्यागपत्र देने वाले एक अधिकारी ने कहा कि शनिवार को खुद प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा सौंपने का आदेश दिया था। (एएनआइ)

इराक में प्रदर्शन स्थल खाली कराने के दौरान सात मारे गए

बगदाद : इराक के बगदाद और बसरा में प्रदर्शन स्थलों को खाली कराने के दौरान सात लोग मारे गए। नेताओं द्वारा सरकार का साथ देने पर सहमत होने के बाद सुरक्षा बल शनिवार को प्रदर्शन स्थलों को खाली कराने में जुटे थे। सूत्रों ने बताया कि नेता रैलियां और प्रदर्शन खत्म करने पर भी सहमत हो गए हैं। एक अक्टूबर से जारी प्रदर्शनों के कारण इराक की राजधानी और इसके दक्षिणी क्षेत्र में व्यवस्था चरमरा गई है। सुबह में बगदाद के मध्य में स्थित दजला (टिगरिस) नदी पर स्थित तीन पुलों पर सुरक्षा बलों ने नियंत्रण पा लिया। (एएफपी)

थम नहीं रही हांगकांग की हिंसा

विरोध ▶ छात्र की मौत के तीन दिन बाद भी तोड़फोड़-आगजनी जारी

चीन के इस अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में लगातार 24 वें सप्ताहांत में हुई हिंसा

हांगकांग, रायटर : हांगकांग में आंदोलनकारी छात्र की मौत के बाद शुक्रवार से शुरू हुआ हिंसक आंदोलन का दौर रविवार को तीसरे दिन भी नहीं थमा। रविवार को हिंसा ने कई नए इलाकों को गिरफ्त में ले लिया। लोकतंत्र की मांग कर रहे आंदोलनकारियों ने इस दौरान शाटिन के रेलवे स्टेशन को बर्बाद कर दिया। इसी इलाके में स्थित एक बड़े रेस्टोरेंट को तोड़फोड़ से भारी नुकसान पहुंचाया गया। इस रेस्टोरेंट का मालिक चीन समर्थक कारोबारी है। चीन के इस अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में लगातार 24 वें सप्ताहांत में हिंसा हुई है। अभी तक हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति और कारोबार का नुकसान हो चुका है, जनजीवन पर भी व्यापक असर पड़ा है।

रेस्टोरेंट में घुसे आंदोलनकारियों ने वहां रखीं टेबिल पलट दीं। खाने-पीने का सामान बिखेर दिया और सजावट वाली वस्तुओं को तोड़-फोड़कर नष्ट कर दिया। ट्यून मुन इलाके में स्थित वी सिटी मॉल के बाहर भी तोड़फोड़ होने की खबर है। यहां पर तोड़फोड़ कर रहे आंदोलनकारियों से पुलिस का टकराव भी हुआ। कई लोगों के घायल होने की खबर है। सुएन वान इलाके में हुई हिंसा को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी। यहां पर आंसू गैस के गोले से नाऊ टीवी की रिपोर्टर के घायल होने की खबर है। पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि कई महत्वपूर्ण स्थानों पर हिंसक आंदोलनकारी बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए हैं। वहां से उन्हें हटाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट में भारी तोड़फोड़ और आगजनी की है। हिंसा के चलते लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है और लोग बाजार आने में डर रहे हैं। कुछ स्थानों पर स्थानीय लोगों और आंदोलनकारियों के बीच भिड़ंत होने की भी खबर है। दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में शुमार काउलून के मोंग कोक में हिंसा फैलने से पुलिस को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। संकरे रास्तों वाले घनी आबादी के इलाके में आंदोलनकारी तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव कर निकल जाते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती। इससे पहले शनिवार रात हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 22 वर्षीय छात्र की मौत का बदला लेने का आह्वान किया।

हांगकांग में रविवार को एक प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस। एपी

सरकारों से विकास के लिए नया दृष्टिकोण अपनाने की मांग

मेलबर्न, प्रेट्र : पर्यावरण सरंक्षणवादी वैज्ञानिकों ने दुनियाभर की सरकारों से मांग की है कि वे आर्थिक विकास के पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर नया दृष्टिकोण अपनाए। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों सहित अन्य वैज्ञानिकों ने कहा कि नया दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़े ताकि आर्थिक विकास से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की कुछ भरपाई हो सके।

ये बातें जर्नल 'नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन' में एक टिप्पणी के तौर पर कहीं गई हैं। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स वाटसन ने कहा, 'नए दृष्टिकोण का विचार पयार्वरण सरंक्षण अनुक्रम पर आधारित है जो जैवविविधता सरंक्षण कार्यक्रम का ढांचा इस आधार पर तैयार करेगा कि कैसे पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण में इनकी हिस्सेदारी होगी।'

शोधकर्ताओं ने आर्थिक गतिविधियों से सबसे अधिक पर्यावरण को लाभ हो यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक महत्वकांक्षी कदम उठाने की मांग की। वॉटसन ने कहा कि संरक्षण गतिविधियां इस पर आधारित होनी चाहिए कि प्राकृतिक दुनिया को संरक्षित रखने में हमारे दृष्टिकोण से कितना मेल खाता है बजाय कि प्रजातियों और पारिस्थिति को बचाने के लिए। शोधकर्ताओं ने कहा कि नीति निर्माताओं को विकास के पर्यावरण पर होने वाले असर को कम करने वाली नीति को तुरंत और गंभीरता से प्राथमिकता देनी चाहिए।

ईरान ने नया परमाणु रिएक्टर बनाने का कार्य शुरू किया

रूस के सहयोग से निर्माण लेकिन परमाणु हथियार की क्षमता अभी दूर

बुशहर, एपी : ईरान ने रविवार को बुशहर में अपने दूसरे परमाणु बिजलीघर में काम शुरू कर दिया। 2015 में अमेरिका सहित दुनिया के प्रमुख देशों के साथ हुए परमाणु समझौते के बाद ईरान ने इस बिजलीघर में काम रोक दिया था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समझौते से पीछे हट जाने और प्रतिबंध लगा देने से ईरान अब परमाणु क्षमता हासिल करने के रास्ते पर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। हालांकि परमाणु हथियार बनाने के लक्ष्य से अभी वह काफी दूर है।

ईरान ने परमाणु बिजलीघर में दूसरे रिएक्टर के लिए निर्माण का कार्य अपने तेल बिक्री पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद शुरू किया है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख अली अकबर सालेही ने कहा, समझौता हमने नहीं तोड़ा है। समझौता अमेरिका ने एकतरफा फैसले के तहत तोड़ा है। अब हम अपनी जरूरतों के मुताबिक परमाणु क्षमता विकसित कर रहे हैं। बुशहर में रूस का यूरेनियम इस्तेमाल होता है और उसकी निगरानी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कार्य करने वाली अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी करती है। ईरान ने बुशहर में यूरेनियम को 4.5 प्रतिशत तक शोधित करने का लक्ष्य रखा है जबकि अंतरराष्ट्रीय परमाणु समझौते में उसे 3.67 प्रतिशत शोधन की अनुमति मिली थी। परमाणु हथियार बनाने के लिए करीब 90 प्रतिशत शुद्ध यूरेनियम की जरूरत होती है जिससे ईरान अभी काफी दूर है।

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ईरान लंबे समय से परमाणु कार्यक्रम चलाए हुए है। इसलिए वह एक साल में ही परमाणु बम बनाने लायक शुद्ध यूरेनियम एकत्रित कर सकता है। वैसे उसने प्रमुख देशों के साथ समझौते में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण कार्यों के लिए इस्तेमाल करने का वादा किया था। तेहरान से करीब 700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बुशहर में दूसरा रिएक्टर तैयार करने के लिए काम शुरू हुआ है। यह रिएक्टर रूस के सहयोग से तैयार हो रहा है और इससे एक हजार मेगावाट बिजली पैदा होगी।

अली अकबर सालेही। फाइल

यूएई ने कही ईरान से रिश्ते सुधारने की बात: खाड़ी संकट के बीच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने ईरान के साथ संबंध सुधारने की जरूरत बताई है। कहा है कि खाड़ी के देशों को कूटनीतिक प्रयासों से ईरान से संबंध सुधारने चाहिए। यूएई के विदेश राज्य मंत्री अनवर गारगेश की ओर से यह बयान अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच आया है।

रक्षा खर्च पर नाटो प्रमुख से मिलेंगे ट्रंप

वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (नाटो) के प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग (फाइल फोटो)। रायटर

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (नाटो) के प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग से 14 नवंबर को मुलाकात करेंगे। ह्वाइट हाउस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, दोनों के बीच नाटो के बढ़ते रक्षा खर्च और उसके अधिक न्याय संगत बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप और जेंस आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर भी बातचीत करेंगे। इसी दिन नाटो प्रमुख अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो से भी मुलाकात करेंगे।

ट्रंप और नाटो प्रमुख के बीच यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है, जब गठबंधन के सदस्य देशों के बीच गंभीर तनाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति नाटो के सदस्य देशों की खुलकर आलोचना करने से भी नहीं हिचक रहे हैं। कुछ दिन पूर्व उन्होंने जर्मनी की आलोचना करते हुए कहा था कि कुछ देश अपनी अर्थव्यवस्था का दो फीसद भी रक्षा पर खर्च नहीं कर रहे हैं। सीरिया में तुर्की के हमले और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी गठबंधन में मतभेद हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी रक्षा खर्च में कटौती को लेकर नाटो की आलोचना कर चुके हैं।

अमेरिका लौटना चाहती है इस्लामिक स्टेट आतंकी की पत्नी

वाशिंगटन, एफपी : सीरिया में तीन आइएस आतंकियों से शादी करने वाली होदा मुथाना अमेरिका लौटना चाहती है। इसके लिए उसने ट्रंप प्रशासन से फिर गुहार लगाई है। अमेरिका में पैदा हुई होदा ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) में शामिल होने पर खेद प्रकट करते हुए घर वापसी की इजाजत मांगी है। वह अपने दो साल के बेटे के साथ उत्तर पूर्व सीरिया स्थित अल-रोज शरणार्थी शिविर में रह रही है।

अमेरिकी सरकार ने महिला की अपील को ठुकराते हुए कहा है कि वह हमारे देश की नागरिक नहीं है। होदा ने अमेरिका लौटने के लिए कोर्ट में केस दर्ज करवाया है। वह अमेरिकी पासपोर्ट पर सीरिया पहुंची थी।

उत्तर पूर्वी सीरिया के अल-रोज शरणार्थी कैम्प में विदेशी मीडिया को दिए साक्षात्कार में होदा ने कहा, 'मुझे आइएस का साथ देने पर खेद है।'

अमेरिका का कहना है कि होदा यमन के एक राजनयिक की बेटी है, जिसका जन्म अमेरिका में हुआ। यहां जन्म लेने के कारण विदेशी राजनयिक के बच्चे को नागरिकता नहीं मिलती है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो उसे पहले ही आतंकी करार दे चुके हैं।

शाही यात्रा पर निकले जापान के सम्राट

जापान के 126 वें सम्राट नारुहितो और महारानी मसाको की पहली बार शाही यात्रा निकाली गई। राजधानी टोक्यो में मोटरसाइकिल सवारों का दस्ता सबसे आगे चल रहा था। सम्राट खुली जीप में सवार होकर लोगों को अभिवादन कर रहे थे। करीब पांच किलोमीटर की इस शाही यात्रा का दीदार करने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। शाही जोड़े की करीब आधे घंटे की परेड को देखने के लिए रात से ही भीड़ जुटने लगी थी। यह परेड 22 अक्टूबर को होनी थी लेकिन हाल में आए तूफान हेगिबिस के कारण हुई तबाही की वजह से इसे टाल दिया गया था। वर्ष 1993 में विवाह के बाद शाही युगल की यह पहली परेड है। नारुहितो ने इस वर्ष मई में अपने पिता के बाद आधिकारिक तौर पर शाही गद्दी ग्रहण की है। उनका राज्याभिषेक समारोह पिछले महीने आयोजित किया गया था। राजनयिक परिवार में जन्मी और हार्वर्ड से शिक्षा प्राप्त करने वाली मसाको ने शाही परिवार में शादी करने के लिए अपना राजनयिक करियर छोड़ दिया था। एपी

ब्रिटिश चुनाव में भी कश्मीर बन रहा महत्वपूर्ण मुद्दा

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन में हो रहे आम चुनाव में कश्मीर भी अहम मुद्दा बनता जा रहा है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर संसद में विपक्षी दल लेबर पार्टी ने भारत विरोधी प्रस्ताव रखा था। अब यही प्रस्ताव उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। भारतीय समुदाय आपसी मेल-मिलाप और सोशल मीडिया पर लेबर पार्टी के खिलाफ अभियान चला रहा है। उसके खिलाफ वोट डालने की अपील कर रहा है।

लेबर पार्टी के खिलाफ अभियान तो कई दिन पहले शुरू हो चुका है लेकिन जैसे-जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे-वैसे यह अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। पार्टी को हो रहे नुकसान को थामने की कोशिश में भारतीय मूल के लेबर पार्टी के सांसद वीरेंद्र शर्मा ने कहा, हम ब्रिटेन को बांटने की कोशिश करके अच्छा नहीं कर रहे। कश्मीर का मसला कश्मीरियों के लिए है। यह मसला भारत के संविधान और नियमों के तहत सुलझना चाहिए। इसलिए हमें ब्रिटेन और उसकी समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए। शर्मा एलिंग साउथहॉल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट 2007 से लेबर पार्टी के पास है।

दिग्गज टेक कंपनियों ने रणनीति बनाई

चुनाव में गलत सूचनाओं और सनसनीखेज बातों को रोकने के लिए तकनीक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां तैयारी में जुट गई हैं। कंपनियों ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग न होने देने के लिए संकल्प जताया है। फेसबुक ने वार रूम बनाकर चुनाव से जुड़ी सूचनाओं को सही रूप में प्रस्तुत करने की रूपरेखा बनाई है। वह गलत सूचनाओं को रोकने के साथ ही उन पर स्पष्टीकरण देने की भी व्यवस्था बना रहा है। जबकि ट्विटर ने राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। गूगल यूट्यूब पर चुनाव पर डाले जाने वाले वीडियो पर नजर रखेगा। गड़बड़ी मिलने पर वे वीडियो डिलीट कर दिए जाएंगे।

कैटेलोनिया संकट के बीच स्पेन में मतदान किसी को बहुमत नहीं मिलने का अनुमान

मैड्रिड, एएफपी : कैटेलोनिया के अलगाववादी नेताओं को सजा के बाद उपजे तनाव के बीच स्पेन में रविवार को वोट डाले गए। देश में पिछले कुछ सालों में यह चौथा आम चुनाव है। अप्रैल में हुए चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की सोशलिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी लेकिन संसद में बहुमत नहीं जुटा सकी थी। मैड्रिड में मतदान के बाद सांचेज ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भागीदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को सक्षम बनाने के लिए स्थिरता जरूरी है।

ओपिनियन पोल के अनुसार, दक्षिणपंथी वॉक्स पार्टी अपना जनाधार बढ़ा सकती है। पिछले चुनाव में उसे 24 सीटें मिली थीं। हालांकि यह चुनाव भी गतिरोध को दूर नहीं कर सकेगा। स्पेन की 350 सीटों वाली संसद में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलने की संभावना नहीं है। ओपिनियन पोल का मानना है कि सोशलिस्ट पार्टी एक बार फिर देश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है लेकिन उनकी सीटें 123 से घट सकती हैं। पिछले चुनाव में रिकॉर्ड 76 फीसदी मतदान हुआ था, जिसने सांचेज की पार्टी को फायदा पहुंचाया था।

स्पेन में चुनाव ऐसे वक्त पर हो रहा है जब कैटेलोनिया को लेकर देश बंटा हुआ नजर आ रहा है। एक महीने से भी कम वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट ने नौ कैटेलोनिया अलगाववादियों को जेल में डाल दिया था। उन पर 2017 में स्पेन से अलग होने की असफल कोशिश में शामिल होने का आरोप था। जिसके बाद भड़की हिंसा में करीब 600 लोग घायल हो गए थे।

स्पेन में रविवार को मतदान करतीं एक युवती। देश में पिछले कुछ सालों में यह चौथा आम चुनाव है। स्पेन में यह चुनाव ऐसे वक्त पर हो रहा है जब कैटोलोनिया को लेकर देश बंटा हुआ नजर आ रहा है। एएफपी

अफगानिस्तान में मतगणना रोकने के पक्ष में अब्दुल्ला

राष्ट्रपति चुनाव परिणाम आने में देरी की है संभावना

काबुल, एएफपी : अफगानिस्तान के चीफ एग्जिक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने राष्ट्रपति चुनाव की पुनर्मतगणना रोकने की मांग की है। अपने चुनाव पर्यवेक्षण टीम को एकतरफा हटाते हुए उन्होंने कहा है कि वह मतगणना में धांधली कर घोषित किए जाने वाले नतीजों को स्वीकार नहीं करेंगे। देश में 28 सितंबर को हुए चुनाव के बाद इस घटनाक्रम से अनिश्चितता पैदा हो गई है और परिणाम घोषित होने में देरी हो सकती है। निवर्तमान राष्ट्रपति अशरफ गनी को चुनौती देने वाले दो प्रत्याशियों ने रविवार को कहा कि वह पुनर्मतगणना में पहले से ही नियोजित संदिग्ध मतों को शामिल किए जाने का समर्थन नहीं करेंगे।

इन चुनावों में मतदान फीसद काफी कम रहा जो कि एक रिकार्ड है। अब्दुल्ला ने काबुल में एक रैली में कहा, 'पुनर्मतगणना रोकनी चाहिए। हम धोखेबाजों से प्रक्रिया को बचाना चाहते हैं। धांधलीपूर्ण चुनाव को स्वीकार नहीं किया जाए। चुनाव नतीजे हमारे लोगों के स्पष्ट वोटों पर आधारित होने चाहिए।' अब्दुल्ला को पिछले दो राष्ट्रपति चुनावों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब्दुल्ला ने पुनर्मतगणना की प्रक्रिया से अपनी टीम को एकतरफा तरीके से हटा लिया है। उन्होंने चुनाव नतीजों की घोषणा से पहले यह कदम उठाया है। अब्दुल्ला ने कहा कि यदि उनकी टीम के पर्यवेक्षक अफगानिस्तान के 'स्वतंत्र चुनाव आयोग' (आइईसी) द्वारा पुनर्मतगणना के दौरान उपस्थित नहीं रहते हैं तो चुनाव नतीजों की कोई वैधता नहीं रहेगी।

राष्ट्रपति अशरफ गनी के नेतृत्व वाली देश की सरकार में अब्दुल्ला एक साझेदार हैं। इस चुनाव में गनी उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं। गनी ने पुनर्मतगणना प्रक्रिया से अब तक अपने पर्यवेक्षकों को नहीं हटाया है लेकिन अन्य उम्मीदवारों ने पुनर्मतगणना प्रक्रिया से परेशानी जाहिर की है। मतगणना में धांधली और तकनीकी मुद्दों के लेकर नतीजों की घोषणा बार-बार टाली गई।

टी-20

www.jagran.com

दैनिक जागरण

दांव पर साख

सोमवार 11 नवंबर 2019

चाहर के कहर से भारत ने जीती टी-20 सीरीज

तीसरे मैच में बांग्लादेश को 30 रन से हराया, दीपक ने हैट्रिक सहित चटकाए छह विकेट, अय्यर ने जड़ा टी-20 करियर का पहला अर्धशतक

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: श्रेयस अय्यर (62) और केएल राहुल (52) की अनुभवी पारियों के बाद अपने अनुभवहीन गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी-20 में 30 रनों से जीत दर्ज कर सीरीज 2-1 से जीत ली। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में रविवार को खेले गए टी-20 मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट पर 174 रन बनाए थे। जवाब में दीपक चाहर के छह और शिवम दुबे के तीन विकेट की बदौलत बांग्लादेश को 19.2 ओवर में 144 रनों पर समेटकर तीन मैचों की टी-20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। चाहर ने इस मैच में हैट्रिक लेकर सभी को चौंका दिया।

स्विंग के सौदागर दीपक का कमाल: 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश के शुरुआती क्रम को स्विंग के नए सौदागर दीपक चाहर ने नेस्तोनाबूत कर दिया। चाहर ने शुरुआती तीन ओवर के अंदर ही लिटन दास (09) और सौम्य सरकार (00) के विकेट निकालकर मेहमान टीम को मुश्किल में डाल दिया। इसके बाद मुहम्मद मिथुन (27) और मुहम्मद नईम (81) की जोड़ी खतरनाक दिख होती दिखी। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 98 रनों की साझेदारी करके बांग्लादेश की मैच में वापसी करा दी। इस साझेदारी को तोड़ने में दीपक ही काम आए और उन्होंने मिथुन को चलता करके मेहमान टीम को चौथा तीसरा झटका दिया। दीपक यहीं नहीं रुकने वाले थे। धौनी की सेना के युवा शागिर्द दीपक ने अंतिम ओवरों में अमिनुल इस्लाम (09), शैफुल इस्लाम (04) और मुस्तफिजुर रहमान (01) के विकेट निकालकर अपने छह विकेट पूरे कर लिए। दीपक ने मात्र सात रन देकर छह विकेट पूरे किए।

दुबे का कमाल: मेजबान टीम दिल्ली की हार को भुली नहीं थी, जहां अनुभवी बल्लेबाज मुश्फिकुर रहीम (00) ने कमाल की बल्लेबाजी करके मैच जिताया था, लेकिन नागपुर में युवा गेंदबाज दुबे ने उन्हें पहली ही गेंद पर पवेलियन भेजकर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय विकेट लिया। इसके बाद अपने अगले ही ओवर में दुबे ने खतरनाक दिख रहे बल्लेबाज नईम और अफिफ हुसैन को आउट करके बांग्लादेश की जीत की उम्मीदें खत्म कर दी। वहीं युजवेंद्रा सिंह चहल ने भी अपनी फ्लिपर पर महमूदुल्लाह (08) को बोल्ड करके बांग्लादेश को सातवां झटका दिया। यहां से बांग्लादेश की वापसी लगभग मुश्किल थी और पूरी टीम 144 रन पर ढेर हो गई।

रोहित हुए फ्लॉप: इससे पहले, बांग्लादेश के कप्तान महमूदुल्लाह ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। पिछले मैच में आतिशी पारी खेलने वाले रोहित शर्मा (02) से एक बार फिर नागपुर के दर्शकों को ऐसी ही पारी की उम्मीद थी। इससे पहले की रोहित ऐसा कुछ दोबारा कर पाते पारी के दूसरे ओवर में ही शैफुल इस्लाम ने उन्हें बोल्ड करके चलता कर दिया। रोहित के जल्द आउट होने पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों में जबरदस्त खुशी थी, क्योंकि उनकी इस विकेट के साथ भारत के खिलाफ पहली टी-20 सीरीज जीतने की उम्मीदें भी बढ़ गई थी।

राहुल ने कराई वापसी: अब पूरा दारोमदार शिखर धवन (19) और राहुल पर था। धवन को दिल्ली और राजकोट में खेले गए पहले दो टी-20 मुकाबलों में धीमी बल्लेबाजी के लिए आलोचना झेलनी पड़ी थी। इस बार भी दिल्ली के बल्लेबाज धवन रनों की गति को नहीं सुधार सके। धवन 16 गेंद में सिर्फ 19 रन बना सके और शैफुल की गेंद पर सीमा पार भेजने के चक्कर में कैच आउट हो गए। दूसरी ओर राहुल, विराट कोहली की अनुपस्थिति में नंबर तीन के स्थान पर भरोसेमंद बल्लेबाजी करते दिखे। हालांकि राहुल अपनी पारी में कोई छक्का नहीं लगा सके, लेकिन 35 गेंद में 52 रनों की उनकी पारी ने भारतीय टीम को मैच में वापसी करा दी। अल अमीन हुसैन ने जिस वक्त राहुल को पवेलियन भेजा उस वक्त टीम का स्कोर 94 रन था।

पंत का क्या करें: अब टीम प्रबंधन समेत पूरी टीम के जहन में यह सवाल घर कर गया है कि आखिर रिषभ पंत (06) का क्या किया जाए। टेस्ट में तो पंत को बैंच पर बैठा दिया गया है, लेकिन टी-20 में उनके आक्रामक खेल को देखते हुए एक बार फिर इस सीरीज में उन्हें संजू सैमसन पर तरजीह दी गई। नतीजा एक बार फिर यही रहा कि वह दबाव में खुद को संभाल नहीं सके। टीम के लिए जिस वक्त दूसरे छोर पर अय्यर रनों की बरसात कर रहे थे। उस वक्त पंत गैरजिम्मेदाराना शॉट खेलकर बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए।

श्रेयस ने पक्की की टीम में जगह: रविवार के मुकाबले में जिस खिलाड़ी ने बल्लेबाजी में छाप छोड़ी, वह अय्यर ही थे। अय्यर ने अपने घरेलू क्रिकेट के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए खूब रन बटोरे। अफिफ हुसैन के पहले ओवर में उन्होंने लगातार तीन छक्के जड़कर यह साबित भी कर दिया कि आगामी टी-20 विश्व कप में वह टीम के लिए सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनने जा रहे हैं। अय्यर ने मात्र 33 गेंद में तीन चौके और पांच छक्कों की मदद से 62 रनों की शानदार पारी खेली और टीम के स्कोर को 150 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। यह उनके टी-20 करियर का पहला अर्धशतक भी रहा। हालांकि अय्यर सौम्य सरकार की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पवेलियन लौट गए।

स्कोर बोर्ड

टॉस : बांग्लादेश (गेंदबाजी)

भारत — **174/5** (20 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
रोहित शर्मा बो. शैफुल	02	06	00	00
धवन का. महमूदुल्लाह बो. शैफुल	19	16	04	00
केएल राहुल का. दास बो. अल अमीन	52	35	07	00
श्रेयस अय्यर का. दास बो. सौम्य	62	33	03	05
रिषभ पंत बो. सौम्य	06	09	00	00
मनीष पांडे नाबाद	22	13	03	00
शिवम दुबे नाबाद	09	08	00	00

अतिरिक्त : (वा-2) 2

कुल : 20 ओवर में पांच विकेट पर 174 रन

विकेट पतन : 1-3 (रोहित, 1.3), 2-35 (धवन, 5.2), 3-94 (राहुल, 12.1), 4-139 (पंत, 16.1), 5-144 (अय्यर, 16.5)

गेंदबाजी :
अल अमीन हुसैन 4-0-22-1
शैफुल इस्लाम 4-1-32-2
मुस्तफिजुर 4-0-42-0
अमिनुल इस्लाम 3-0-29-0
सौम्य सरकार 4-0-29-2
अफिफ हुसैन 1-0-20-0

बांग्लादेश — **144** (19.2 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
लिटन दास का. सुंदर बो. चाहर	09	08	02	00
मुहम्मद नईम बो. दुबे	81	48	10	02
सौम्य सरकार का. दुबे बो. चाहर	00	01	00	00
मुहम्मद मिथुन का. राहुल बो. चाहर	27	29	02	01
मुश्फिकुर रहीम बो. दुबे	00	01	00	00
महमूदुल्लाह बो. चहल	08	10	00	00
अफिफ हुसैन का. एवं बो. दुबे	00	01	00	00
अनिमुल इस्लाम बो. चाहर	09	09	01	00
शैफुल इस्लाम का. राहुल बो. चाहर	04	06	00	00
मुस्तफिजुर का. अय्यर बो. चाहर	01	03	00	00
अल अमीन हुसैन नाबाद	00	00	00	00

अतिरिक्त : (लेबा-3, वा-2) 5, **कुल :** 19.2 ओवर में 144 रनों पर सभी आउट,

विकेट पतन : 1-12 (लिटन, 2.4), 2-12 (सौम्य, 2.5), 3-110 (मिथुन, 12.6), 4-110 (रहीम, 13.1), 5-126 (नईम, 15.3), 6-126 (अफिफ, 15.4), 7-130 (महमूदुल्लाह, 16.5), 8-135 (शैफुल, 17.6), 9-144 (रहमान, 19.1)

गेंदबाजी :
खलील अहमद 4-0-27-0
वाशिंगटन सुंदर 4-0-34-0
दीपक चाहर 3.2-0-7-6
चहल 4-0-43-1
शिवम दुबे 4-0-30-3

चहल ने पूरे किए 50 विकेट

लेग स्पिनर युजवेंद्र सिंह चहल ने बांग्लादेशी कप्तान महमूदुल्लाह का विकेट लेते ही अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 50वां विकेट पूरा कर लिया। उन्होंने 34 मैचों में यह कारनामा किया। जब सीरीज शुरू हुई थी तो वह चार विकेट दूर थे, लेकिन दिल्ली और राजकोट में तीन विकेट झटकने के बाद उन्हें इस कारनामे को पाने के लिए एक विकेट की दरकार थी। चहल से पहले जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन ही भारत के लिए यह मुकाम हासिल कर सके हैं। चहल ने 2016 से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण किया था और 2019 विश्व कप तक वह टीम की मजबूत कड़ी बने रहे।

सोम्य सरकार का विकेट लेने के बाद दीपक चाहर ● एएनआइ

15 वर्षीय शेफाली ने सचिन का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

- वर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाली भारत की सबसे युवा खिलाड़ी बनीं
- तेंदुलकर ने अपना पहला अर्धशतक 16 साल व 214 दिन की उम्र में लगाया था

ग्रोस आइलेट, प्रेट्र : 15 वर्षीय शेफाली वर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाली भारत की सबसे युवा खिलाड़ी बन गईं और उन्होंने दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

शेफाली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 49 गेंद में 73 रन की पारी खेली, जिससे भारतीय टीम ने शनिवार देर रात को 84 रन से जीत हासिल की। भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। अपना पांचवां टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रही शेफाली ने अपनी पारी के दौरान छह चौके और चार छक्के जड़े। शेफाली ने यह उपलब्धि 15 साल और 285 दिन की उम्र में हासिल की। इस तरह उन्होंने दिग्गज क्रिकेटर तेंदुलकर को पीछे छोड़ा, जिन्होंने अपना पहला टेस्ट अर्धशतक 16 साल और 214 दिन की उम्र में बनाया था। हरियाणा की इस युवा क्रिकेटर ने पिछले महीने सूरत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने करियर के दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 46 रन की पारी खेली थी।

वेस्टइंडीज के खिलाफ 73 रनों की पारी खेलने वाली युवा बल्लेबाज शेफाली। फाइल फोटो, एएफपी

शेफाली ने स्मृति मंधाना (67) के साथ पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 143 रन की साझेदारी की जिससे भारत ने डेरेन सैमी राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट पर 185 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके बाद भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को नौ विकेट पर 101 रन ही बनाने दिए और जीत हासिल की। तेज गेंदबाज शिखा पांडे, राधा यादव और पूनम यादव ने क्रमश : दो-दो विकेट चटकाए।

मंधाना ने अपनी 46 गेंद की पारी में 11 चौके लगाए जिससे भारत ने 10 ओवर में बिना विकेट गंवाए 102 रन बना लिए थे। इन दोनों ने भारत के लिए टी-20 में किसी भी विकेट के लिए सर्वोच्च साझेदारी का रिकॉर्ड भी बनाया। इन दोनों ने 2013 में थिरुष कामिनी और पूनम राउत के बांग्लादेश के खिलाफ 130 रन की साझेदारी के रिकॉर्ड को पछाड़ा।

शेफाली के 16वें ओवर में आउट होने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 13 गेंद में 21 रन बनाए जबकि वेदा कृष्णमूर्ति ने सात गेंद में 15 रन बनाकर भारत को चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने में मदद की। मेजबान टीम के लिए शकीरा सेलमान और अनीसा मुहम्मद ने दो-दो विकेट हासिल किए। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम के लिए कोई बड़ी साझेदारी नहीं बनी जिसमें केवल शर्मेन कैंपबेल ही 34 गेंद में 33 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं। वेस्टइंडीज ने 14.1 ओवर तक 86 रन पर छह विकेट खो दिए थे।

दिग्गज लियोन मेसी की हैट्रिक ने बार्सिलोना को शीर्ष पर पहुंचाया

मैड्रिड, एएफपी : स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में बार्सिलोना ने सेल्टा विगो को 4-1 से हराकर अंक तालिका में फिर से शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया जहां लियोन मेसी ने फ्री किक पर दो शानदार गोल करते हुए हैट्रिक लगाई। इस जीत से बार्सिलोना ने अपने मैनेजर ईर्नेस्टो वाल्वर्डे पर से दबाव कम किया।

मेसी ने पहले हाफ के 23वें मिनट में पेनाल्टी किक के जरिये बार्सिलोना को शुरुआती बढ़त दिलाई, लेकिन हाफ टाइम से थोड़ी देर पहले सेल्टा विगो के लुकास ओलाजा ने एक बेहतरीन फ्री किक गोल के जरिये अपनी टीम को बराबरी पर ला खड़ा किया। हालांकि पहले हाफ के इंजुरी टाइम में बार्सिलोना को एक फ्री किक मिली जिसे मेसी ने सेल्टा विगो के गोलकीपर रुबेन बलैंको की बायीं ओर से गोल पोस्ट में पहुंचाकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ के तीसरे मिनट में भी एक बार फिर बार्सिलोना को फ्री किक मिली और एक बार फिर मेसी ने उसी तरीके से गेंद को गोल में पहुंचाया और अपनी हैट्रिक मुकम्मल की। मुकाबला समाप्त होने से पांच मिनट पहले सर्जियो बास्किट्स ने भी गोल करके बार्सिलोना की 4-1 की आसान जीत में अपना योगदान दिया।

32 वर्षीय मेसी ने अपने ला लीगा करियर की 34वीं हैट्रिक पूरी की और इस मामले में क्रिस्टियारो रोनाल्डो की बराबरी कर ली। मेसी ने इस सत्र के सात मुकाबलों में अपना नौवां गोल दागा और बार्सिलोना के लिए अपने कुल गोल की संख्या 612 पहुंचा दी। पिछली बार मेसी ही वह खिलाड़ी थे जिसने 2012 में सेट पीसेस के जरिये हैट्रिक पूरी की थी और अब उन्होंने सात साल बाद अपने उस प्रदर्शन को दोहराया। इस मुकाबले के आखिरी कुछ मिनटों में लुइस सुआरेज भी मैदान पर उतरे जो चोटिल चल रहे थे।

रीयल की धमाकेदार जीत : ला लीगा के एक अन्य अहम मुकाबले में रीयल मैड्रिड ने ईबर को 4-0 से हरा दिया जहां विजेता टीम के लिए करीम बेंजमा ने दो गोल दागे और रीयल के लिए अपने कुल गोल की संख्या 157 पहुंचा दी। बेंजमा के अलावा सर्जियो रामोस और फेड वाल्वर्डे ने भी स्कोर किए। इस जीत के बावजूद रीयल को अंक तालिका में दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। बार्सिलोना और रीयल के 25-25 अंक हैं लेकिन बेहतर गोल औसत के आधार पर बार्सिलोना शीर्ष पर पहुंच गया।

बायर्न के हाथों हारा डोर्टमंड

म्यूनिख, एएफपी : जर्मन फुटबॉल लीग बुंडिशलीगा में बायर्न म्यूनिख ने बोरुसिया डोर्टमंड को 4-0 से करारी शिकस्त दी। इस दौरान बायर्न के स्टार रॉबर्टो लेवांदोवोस्की ने अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए दो गोल दागे। उनके अलावा सर्जी गेनाब्री और मैट्स हुमेल्स ने भी स्कोर किए। इस सत्र में लेवांदोवोस्की ने बुंडिशलीगा और चैंपियंस लीग के सभी मुकाबलों में गोल किए हैं और अपने कुल गोल की संख्या 23 पहुंचा दी है।

इंटर मिलान की रोचक जीत

मिलान, एएफपी : निकोलो बारेला के शानदार गोल के दम पर इटालियन लीग सीरी-ए में इंटर मिलान ने वेरोना पर 2-1 की रोचक जीत दर्ज की। वेरोना के वेलेरियो वेरो और इंटर के मैटियस वेनो के गोल के दम पर निर्धारित समय से सात मिनट पहले तक दोनों टीमें बराबरी पर चल रही थीं लेकिन बारेला ने गोल करते हुए इंटर को रोचक जीत दिला दी। एक अन्य अहम मुकाबले में नापोली को गेनोआ से गोलरहित (0-0) ड्रॉ के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं ब्रेसिया को 4-0 से हराकर टोरिनो की टीम जीत की राह पर लौटी।

गोल की हैट्रिक पूरी करने के बाद जश्न मनाते मेसी। एएफपी

सचिन तेंदुलकर को ही आदर्श मानती हैं रोहतक की शेफाली

- लाहली में सचिन को खेलते देखकर मिली थी प्रेरणा
- अपनी लाडो के शानदार प्रदर्शन पर माता-पिता गौरवान्वित

जागरण संवाददाता, रोहतक :

शेफाली वर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जब अपने आदर्श खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा तो खुशी से उसके माता-पिता के आंसू छलक आए। छलकते भी क्यों न? उनका सपना था बेटी देश के लिए खेले और बेटी देश के लिए तो खेल ही रही है, उसने अपने आदर्श और क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक बनाने वाली भारतीय बनीं शेफाली के पिता संजीव वर्मा और मां प्रवीन ने बताया कि शेफाली शुरू से ही सचिन को आदर्श मानती हैं। संजीव ने बताया कि सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने की सूचना उनको फोन पर मिली। उसके बाद उन्होंने बेटी की फोटो वाला एलबम देखा और यादों को ताजा किया। शेफाली की मां प्रवीन ने जानकारी दी कि रोहतक के लाहली स्थित चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम में अपना अंतिम रणजी मैच रहे सचिन को शेफाली ने बल्लेबाजी करते देखा था। उसके बाद ही उसने सचिन के खेल से प्रेरणा लेकर क्रिकेट खेलना शुरू किया था। तभी से वह सचिन को आदर्श मानकर क्रिकेट में आगे बढ़ती जा रही हैं।

शुरुआत में गली क्रिकेट

दिलचस्प है कि पांच साल पहले शेफाली के पिता जब गली में क्रिकेट खेलते थे तो उनको देख शेफाली भी पहुंच जाती थी। पिता भी बेटी की भावनाओं को देख उसे साथ में खेलने का मौका देने लगे। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद बेटी उनसे अच्छा खेलने लगी। शेफाली की उम्र उस समय करीब 10 साल थी और वह पांचवीं कक्षा में पढ़ती थी। तीन साल पहले शेफाली ने रोहतक की रामनारायण क्रिकेट अकादमी में अभ्यास शुरू किया। वहां कोच अमन कुमार ने उसके खेल को निखारा। उसके बाद वह टूर्नामेंटों में छाने लगी।

इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जीतेंगे टी-20 विश्व कप : वॉन

नई दिल्ली, एएनआइ : इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का मानना है कि अगले वर्ष ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप को इंग्लैंड या मेजबान ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतेगी। वॉन ने ट्विटर पर लिखा कि ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड टी-20 विश्व कप जीतेगी। यह मेरी सबसे पहले की गई भविष्यवाणी है। ऑस्ट्रेलिया ने 2019 में कोई भी टी-20 मुकाबला नहीं गंवाया है। टीम ने आठ मुकाबले खेले हैं और सात में जीत दर्ज की है। वहीं इंग्लैंड ने भी न्यूजीलैंड को पांच मैचों की टी-20 सीरीज में हराया है। बता दें कि टी-20 विश्व कप अगले वर्ष ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक खेला जाएगा।

एमएसएल से हटे चोटिल डुमिनी

केप टाउन, एएनआइ : पार्ल रॉक के खिलाड़ी जेपी डुमिनी ने चोट की वजह से मजांसी सुपर लीग (एमएसएल) से अपना नाम वापस ले लिया है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि डुमिनी चोट से जूझ रहे हैं। 35 वर्षीय डुमिनी पिछले वर्ष भी हाथ में चोट के कारण यह टूर्नामेंट नहीं जीत पाए थे। टीम के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने कहा कि डुमिनी के अनुभव को टीम मिस करेगी। उन्होंने कहा कि टीम में डुमिनी का अहम योगदान होता है। उनका अनुभव याद आएगा। खास तौर से युवा लड़कों के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी टीम टूर्नामेंट में जवाबी हमला करेगी। इस बार हमारी बल्लेबाजी काफी अच्छी है।

तीन पाक खिलाड़ियों ने दी टी-10 को तवज्जो

कराची, प्रेट्र : पाकिस्तान के तीन खिलाड़ियों ने प्रथम श्रेणी टीम के साथ खेलने की जगह टी-10 लीग में खेलने को तवज्जो दी। ऐसे में एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच चल रही समस्या उजागर हो गई। तेज गेंदबाज हैरिस राउफ और बल्लेबाज मिर्जा अहसान बैग, सोहेल अख्तर ने अबु धाबी में टी-10 लीग में खेलने का फैसला कर लिया है, जबकि खिलाड़ियों को बोर्ड की ओर से अभी तक टूर्नामेंट में खेलने के लिए एनओसी नहीं मिली है। एक सूत्र ने बताया कि तीनों खिलाड़ियों ने अपनी टीमों को बता दिया है कि वह कायदे आजम ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे।

क्रिकेट डायरी

ऑस्ट्रेलिया को हरा फ्रांस ने जीता फेड कप

टेनिस डायरी

फेड कप फाइनल में 2-3 से हारी मेजबान टीम, डबल्स जोड़ी ने फ्रांस को 16 वर्षों बाद बनाया चैंपियन

पर्थ, एएफपी : क्रिस्टिना मलादेनोविक और कैरोलिना ग्रासिया की महिला जोड़ी ने फ्रांस को 2003 के बाद पहली बार फेड कप टेनिस टूर्नामेंट का खिताब दिलाया। इन दोनों ने निर्णायक डब्लस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में 3-2 से हराकर फ्रांस को चैंपियन बनाया।

पर्थ एरीना में दो दिवसीय फेड कप फाइनल में रविवार को मलादेनोविक और ग्रासिया की जोड़ी ने विश्व की नंबर एक खिलाड़ी एश्ले बार्टी और सामंथा स्टोसुर की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को 6-4, 6-3 से हराया और घरेलू टीम को 45 वर्षों बाद फेड कप जीतने का ख्वाब तोड़ दिया। यह फ्रांस का कुल तीसरा और 16 साल बाद पहला फेड कप खिताब है। पिछली बार 2003 में फ्रांस ने अमेरिका को हराकर खिताब जीता था। सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम 45 वर्षों बाद फेड कप में खिताबी जीत की उम्मीद से खेल रही थी जो अब तक नौ फाइनल्स हार चुकी है।

रविवार को खेले गए पहले सिंगल्स मुकाबले में फ्रांस की मलादेनोविक ने बार्टी को 2-6, 6-4, 7-6 से हराकर चौंका दिया। हालांकि एल्जा टॉमजानोविक ने फ्रांस की पॉलने पारमेंटियर को 6-4, 7-5 से हराकर एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को बराबरी पर ला खड़ा किया, लेकिन रिकॉर्ड घरेलू दर्शकों के बीच ऑस्ट्रेलिया को निर्णायक डबल्स मुकाबले में शिकस्त झेलनी पड़ी। मौजूदा प्रारूप में आखिरी बार फेड कप का आयोजन किया गया और अब अगले साल से छह दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में 12 देश हिस्सा लेंगे। ऐसे में अगले वर्ष होने वाले टूर्नामेंट में सभी 12 देशों की टीमों के लिए नई चुनौतियां होंगी।

फेड कप जीतने के बाद ट्रॉफी के साथ फ्रांस की टीम। एएफपी

इटली के जानिक सिनर बने चैंपियन

मिलान, एएफपी : इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर ने घरेलू सरजमीं पर शीर्ष वरीय ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डि मिनॉर पर सीधे सेट में जीत दर्ज कर नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स की ट्रॉफी अपने नाम की। 18 वर्षीय सिनर ने एक घंटे से ज्यादा समय तक चले मुकाबले में दुनिया के 18वीं रैंकिंग के खिलाड़ी डि मिनॉर को 4-2, 4-1, 4-2 से पराजित किया। डि मिनॉर पिछले साल फाइनल में स्टीफानोस सितसिपास से हार गए थे। 2017 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट में 21 साल के कम उम्र के शीर्ष आठ खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और सभी खिलाड़ियों में जीत के लिए कड़ी जद्दोजहद देखने को मिलती है।

प्रजनेश और नागल पुणे चैलेंजर में करेंगे घरेलू टीम की अगुआई

पुणे, प्रेट्र : प्रजनेश गुणेश्वरन फॉर्म में चल रहे सुमित नागल के साथ सोमवार से शुरू होने वाले केपीआईटी-एमएसएलटीए टेनिस चैलेंजर में भारतीय चुनौती की अगुआई करेंगे जिसमें मेजबान देश के 21 सिंगल्स खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भारत इस सत्र में चेन्नई ओपन के बाद दूसरे एटीपी चैलेंजर की मेजबानी कर रहा है। पिछले साल एटीपी चैलेंजर सर्किट में किए गए आमूलचूल बदलाव के बाद ड्रॉ में खिलाड़ियों की संख्या बढ़ गई है जिससे 19 भारतीय सिंगल्स मुख्य ड्रॉ में खेल रहे हैं जबकि दो और क्वालीफाइंग से शामिल हो जाएंगे।

20 से ज्यादा खिलाड़ियों का सिंगल्स मुख्य ड्रॉ में होना भी किसी भी मेजबान देश के लिए रिकॉर्ड है। विश्व रैंकिंग में 94 नंबर पर काबिज प्रजनेश के पिता का शनिवार को निधन हो गया था, लेकिन इस खिलाड़ी ने टूर्नामेंट में खेलने का फैसला किया है। प्रजनेश इसमें शीर्ष वरीय होंगे। उन्होंने कहा, 'मैं खेल रहा हूं। मेरे पिता मुझे खेलते हुए देखना चाहेंगे। मैं उनकी इच्छा का सम्मान करूंगा। यह सत्र का अंतिम टूर्नामेंट है और मैं इसका समापन करूंगा।' उनके साथ युवा नागल से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी जो इस सत्र में शानदार फॉर्म में हैं। 129 रैंकिंग के नागल को क्वार्टर फाइनल में एक और शीर्ष भारतीय रामकुमार रामनाथन से भिड़ना पड़ सकता है। दोनों को पहले दौर में बाई मिली है और दोनों भारतीयों को क्वार्टर फाइनल से पहले दो मैच खेलने हैं।

कोहली जैसा बनना चाहती हैं वार्नर की बेटी

सिडनी, प्रेट्र : भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के प्रशंसकों की लिस्ट में एक खास नाम शामिल हो गया है। भारत के बच्चे तो विराट बनना ही चाहते हैं अब एक क्रिकेटर की बेटी ने खुद को विराट कोहली बताया है।

वह बेटी ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर की बेटी इंडी रे हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बल्लेबाजी करते वक्त खुद को विराट कोहली बताती दिख रही हैं। रोचक बात यह है कि यह वीडियो खुद उनके क्रिकेटर पिता वार्नर ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शेयर किया है। इस वीडियो में वार्नर की बेटी उनके साथ क्रिकेट खेलती दिख रही हैं और उनसे कह रही हैं कि आइ एम विराट कोहली। इस वीडियो को सबसे पहले वार्नर की पत्नी कैंडिस ने ट्विटर पर पोस्ट किया और बेटी को पिता के जैसा बताते हुए बेस्ट कैप्शन की मांग की। हालांकि कुछ ही देर बाद वार्नर ने इसे दोबार पोस्ट किया और लिखा, मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूं। वह विराट कोहली बनना चाहती है। उन्होंने वीडियो को विराट को भी टैग किया। यही नहीं, वार्नर की गेंद पर उनकी बेटी ने अच्छा शॉट भी लगाया।

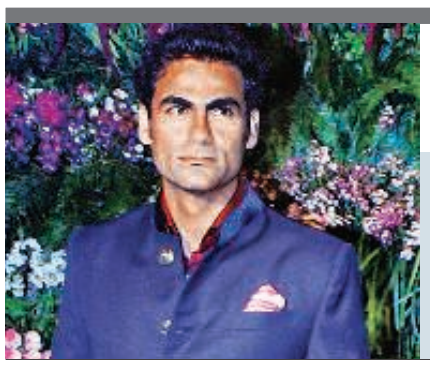

भारत का विचार किसी भी विचारधारा से बड़ा : कैफ

नई दिल्ली, आइएएनएस : पूर्व भारतीय क्रिकेटर मुहम्मद कैफ ने विवादित रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भारत की संकल्पना (विचार) किसी भी विचारधारा से बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अयोध्या विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने विवादित जमीन राम मंदिर के लिए हिंदुओं को और मुसलमानों के लिए पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया।

मेरे लिए टी-20 सीरीज में रन बनाना अच्छा था। मैंने कुछ टी-10 क्रिकेट खेले हैं, इसलिए मुझे पता था कि कहां रन बनाने हैं। – इयोन मोर्गन, कप्तान इंग्लैंड टीम

न्यूज गैलरी

कपूर प्लेऑफ में पहुंचकर जीत से चूके

चाचोएंगसाओ (थाइलैंड) : भारतीय गोल्फर शिव कपूर नौ होल में शानदार प्रदर्शन करते हुए संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंचने के बाद थाइलैंड ओपन में प्लेऑफ के बाद संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने आखिरी नौ होल में पांच बर्डी, एक ईगल व एक बोगी की जिससे 11 अंडर के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गए। तीसरे दौर के बाद संयुक्त रूप से 11वें स्थान पर रहे कपूर ने चौथे दौर में 65 का कार्ड खेला। वह जॉन काटलिन व थाइलैंड के पावित तांगकामोलप्रसेर्ट के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर आ गए। विजेता का फैसला प्लेऑफ से हुआ जिसमें काटलिन तीन शॉट में होल में गेंद डालने में सफल रहे। बाकी खिलाड़ियों ने इसके लिए चार शॉट लिए। शनिवार को संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहे एसएसपी चौरसिया ने एक ओवर 72 का कार्ड खेला जिससे 275 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से छठे स्थान पर खिसक गए। (प्रेट्र)

रांची में दोस्तों के संग मस्ती करते दिखे धौनी

रांची : क्रिकेट से दूर चल रहे पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धौनी इस समय अपने गृह नगर रांची में दोस्तों के साथ समय गुजार रहे हैं। धौनी शनिवार को फॉर्म हाउस कैलाशपती में अपने बचपन के दोस्त सीमांत लोहानी के जन्मदिन पर उनका बर्थडे मनाते दिखे। इस अवसर पर धौनी के सभी पुराने दोस्त एकसाथ इकट्ठे हुए। भारत इसी महीने बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डेंस में अपना पहला दिन-रात प्रारूप का टेस्ट मैच खेलेगा। इस मैच में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी कॉमेंट्री करते हुए देखे जा सकते हैं। भारत को बांग्लादेश के खिलाफ 22 से 26 नवंबर के बीच यह टेस्ट मैच खेलना है। (आइएएनएस)

विलियम्स को आइएसएल हीरो ऑफ द मंथ का अवॉर्ड

नई दिल्ली : हीरो इंडियन सुपर लीग (आइएसएल) के छठे सत्र में एटीके के लिए खेल रहे स्टार खिलाड़ी डेविड विलियम्स को अक्टूबर में शानदार प्रदर्शन करने के लिए आइएसएल हीरो ऑफ द मंथ का अवॉर्ड दिया गया है। विलियम्स ने इस पुरस्कार को जीतने के लिए केरला ब्लास्टर्स के बार्थोलोमेव ओग्बेचे, दो बार के गोल्डन बूट विजेता एफसी गोवा के फेरान कोरोमिनास, जमशेदपुर के सर्गियो कास्टेल और मुंबई सिटी एफसी के अमरिंदर सिंह को पछाड़ा। (आइएएनएस)

इंग्लैंड को मिली सुपर ओवर में शानदार जीत

टी-20 ▶ सीरीज के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड पर रोमांचक जीत दर्ज कर सीरीज पर जमाया कब्जा

फिर ताजा हुआ वनडे विश्व कप फाइनल का यादगार मुकाबला

ऑकलैंड, एपी : लॉर्ड्स के मैदान पर 14 जुलाई का दिन कौन भूल सकता है, जब क्रिकेट को चाहने वाले करोड़ों प्रशंसकों को इतिहास का सबसे रोमांचक वनडे मुकाबला देखने को मिला था। विश्व कप फाइनल के बाद एक बार फिर रविवार को ऑकलैंड के मैदान पर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के बीच कुछ ऐसा ही मुकाबला दोहराया गया, लेकिन इस बार यह वनडे नहीं टी-20 मुकाबला था। जहां इंग्लैंड ने सुपर ओवर की रोमांचक जीत से न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज 3-2 से अपने नाम की।

तेज बारिश के कारण मैच 11-11 ओवर का हो गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने पांच विकेट पर 146 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके बाद इंग्लैंड की टीम ने सात विकेट पर 146 रन बनाए, जिससे दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो गया। इसके बाद सुपर ओवर में इंग्लैंड ने खिताबी जीत दर्ज की।

याद आया विश्व कप फाइनल : फिर सुपर ओवर खेला गया, जिसमें जॉनी बेयरस्टो और कप्तान इयोन मोर्गन ने इंग्लैंड के लिए 17 रन बनाए। यह ओवर न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउथी ने फेंका। वहीं न्यूजीलैंड के लिए मार्टिन गुप्टिल, टिम सेफर्ट और कोलिन डि ग्रैंडहोम ने एक ओवर में केवल आठ रन बनाए और टीम मैच गंवा बैठी। इस मैच ने विश्व कप फाइनल की याद ताजा कर दी, जो दोनों टीमों के बीच जून में खेला गया था जिसमें इंग्लैंड ने 50 ओवर के बाद स्कोर बराबर होने से खेले गए एक ओवर के एलिमिनेटर में भी बराबरी के बाद बाउंड्री की गिनती से ट्रॉफी जीती थी।

न्यूजीलैंड को हराने के बाद खिताबी जीत दर्ज करने के बाद ट्रॉफी के साथ इंग्लैंड की टीम। एएफपी

बेयरस्टो की अच्छी पारी : बेयरस्टो 18 गेंद में 47 रन की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच रहे, जिनकी बदौलत इंग्लैंड ने 11 ओवर में स्कोर बराबर किया और सुपर ओवर में भी उनका योगदान अहम रहा। इंग्लैंड ने बारिश के कारण देर से शुरू हुए मैच में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी का न्योता दिया। गुप्टिल ने 20 गेंद में 50 रन बनाकर घरेलू टीम को प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया।

ऐसे हुआ मैच टाई : दो ओवर में न्यूजीलैंड ने बिना विकेट गंवाए 37 रन बना लिए थे जिसके बाद टीम केवल 7.3 ओवर में 100 रन तक पहुंच गई थी। वहीं इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, जिसमें उसने टॉम बैंटन और जेम्स विंस के विकेट पहली सात गेंद में ही गंवा दिए थे। बेयरस्टो की पारी ने उसे मैच में वापसी कराई और फिर अंतिम ओवर में उसे जीतने के लिए 16 रन की जरूरत थी। जेम्स नीशाम की गेंद पर जॉर्डन ने महत्वपूर्ण छक्का जड़ा, फिर अंतिम गेंद में चौका जड़ा जिससे स्कोर बराबर हो गया और मैच एक ओवर एलिमिनेटर तक पहुंच गया। यहां से इंग्लैंड ने जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम कर ली।

2000 रन टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बनाने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बने इयोन मोर्गन। उन्होंने यह कारनामा 86 टी-20 मुकाबले खेलकर किया। इस दौरान उन्होंने 11 अर्धशतक लगाए

ऐसा रहा सुपर ओवर

इस बार हालांकि इंग्लैंड ने सुपर ओवर में नतीजा अपने पक्ष में किया। बेयरस्टो और मोर्गन ने छक्के जड़कर न्यूजीलैंड को जीत के लिए 18 रन का लक्ष्य दिया जो एक ओवर के लिहाज से मुश्किल ही था। न्यूजीलैंड ने विकेटकीपर टिम सेफर्ट को सुपर ओवर की पहली गेंद खेलने के लिए चुना और क्रिस जॉर्डन के ओवर में उन्होंने दो रन लिए और फिर चौका लगाया। अगली गेंद पर कोई रन नहीं बना, जिसके बाद वह मोर्गन को शानदार कैच देकर आउट हो गए। अब न्यूजीलैंड को अंतिम दो गेंद में 10 रन की दरकार थी जिस पर गुप्टिल केवल एक ही रन बना सके और टीम मैच हार गई।

एएफसी अंडर-19 में अफगानिस्तान की टीम से हारा भारत

अल खोबार (सऊदी अरब), प्रेट्र : 2020 एएफसी अंडर-19 चैंपियनशिप क्वालीफायर में रविवार को भारतीय फुटबॉल टीम का अभियान अफगानिस्तान के खिलाफ 0-3 से हार के साथ खत्म हुआ।

अफगानिस्तान की टीम ने मैच के पहले हाफ में ही तीन गोल करके भारतीय टीम पर बड़ी बढ़त हासिल कर ली। हालांकि भारतीय टीम ने वापसी की हर संभव कोशिश की लेकिन वह अफगानिस्तान के डिफेंस में सेंध नहीं लगा सकी। टीम ने दूसरे हाफ में गोल करने के कुछ मौके बनाए लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। दो मौकों पर गेंद गोल पोस्ट से टकराकर बाहर निकल गई। इस हार के साथ ही टूर्नामेंट में भारत का सफर लगातार तीन हार के साथ खत्म हुआ। अफगानिस्तान ने खेल के दूसरे मिनट में ही कप्तान अहमद रमाकि के गोल से बढ़त हासिल कर ली। इसके दो मिनट बाद मिडफील्डर अहमद नौशाद ने गोल करके इस बढ़त को दोगुना कर दिया।

कोच फ्लॉयड पिंटो की भारतीय टीम ने इसके बाद मैच में वापसी के लिए आक्रमक रुख अपनाया जिसका टीम को फायदा मिलता हुआ भी दिखा। मैच के 22वें मिनट में विक्रम प्रताप संधू ने शानदार किक लगाई जिसे अफगानिस्तान के गोलकीपर ने गेंद को हाथ लगाकर गोल पोस्ट से दूर कर दिया। इसके बाद मैच के 29वें मिनट में खातम डेल ने अफगानिस्तान के लिए तीसरा गोल कर भारतीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इससे पहले भारतीय टीम को सऊदी अरब ने 4-0 से हराया था। अफगानिस्तान से हार के बाद भारत की मुश्किल बढ़ गई हैं।

अंगद, मेराज व ऐश्वर्य को ओलंपिक कोटे

दोहा, प्रेट्र : अंगद वीर सिंह बाजवा और मेराज अहमद ने रविवार को यहां 14वीं एशियाई चैंपियनशिप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में क्रमश : पहले और दूसरे स्थान पर रहते हुए देश के लिए दो और ओलंपिक कोटे हासिल किए।

इन निशानेबाजों के पदक से टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय निशानेबाजों ने अब तक रिकॉर्ड 15 कोटे हासिल कर लिए। यहां लुसैन निशानेबाजी परिसर में दोनों खिलाड़ी 56 अंक के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर थे जिसके बाद विजेता का फैसला शूटऑफ से हुआ। अंगद ने शूटऑफ में मेराज को 6-5 से पछाड़ा। ओलंपिक कोटा के मामले में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत के 11 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया था जबकि रियो ओलंपिक 2016 में 12 भारतीय निशानेबाज उतरे थे। रविवार को ही भारत ने तीन ओलंपिक कोटे हासिल किए।

अंगद और मेराज से पहले निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने भी देश के लिए रिकॉर्ड 13वां कोटा हासिल किया था। 18 वर्षीय तोमर ने आठ पुरुषों के फाइनल में 449.1 अंक बनाकर तीसरा स्थान हासिल किया। कोरिया के किम जोंगयुन (459.9) ने स्वर्ण ओर चीन के झोंगहाओ झाओ (459.1) ने रजत पदक जीता। इस भारतीय निशानेबाज ने 120 शॉट के क्वालीफाइंग में 1168 अंक बनाकर फाइनल्स में जगह सुरक्षित की थी।

मध्य प्रदेश के खरगौन के रहने वाले तोमर ने जर्मनी के सुहल में आइएसएसएफ जूनियर विश्व कप में राइफल थ्री पोजीशन में जूनियर वर्ग में विश्व रिकॉर्ड बनाया था। टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के क्रम को जारी रखते हुए मनु भाकर एवं अभिषेक वर्मा की जोड़ी ने सौरभ चौधरी एवं यशस्विनि सिंह देशवाल की जोड़ी को 10 मीटर एयर पिस्टल मिस्क्ड टीम स्पर्धा में 16-10 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

नोजोमी ओकुहारा को हराकर यू फेई बनीं चैंपियन

पेइचिंग, प्रेट्र : विश्व नंबर तीन चीन की चेन यू फेई ने दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर रविवार को चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। तीसरी वरीयता प्राप्त यू फेई ने महिला सिंगल्स के फाइनल में ओकुहारा को 9-21, 21-12, 21-18 से हराकर खिताब अपने नाम किया। चीनी खिलाड़ी ने एक घंटे 22 मिनट तक चले मुकाबले में चौथी वरीयता प्राप्त ओकुहारा को मात दी। चीनी खिलाड़ी की जापानी खिलाड़ी के खिलाफ यह लगातार तीसरी जीत है।

यू फेई ने इस जीत के साथ ही ओकुहारा के खिलाफ अपना करियर रिकॉर्ड 4-4 का कर लिया है। फेई ने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी ओकुहारा को हराया था। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी को शनिवार को यहां चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के मार्कस फर्नाल्डी गिडियोन और केविन संजय सुकामुल्जो की तीन बार की चैम्पियन जोड़ी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।

- चीन ओपन के फाइनल में 9-21, 21-12, 21-18 से दी करारी शिकस्त
- जापानी खिलाड़ी के खिलाफ फेई ने दर्ज की लगातार तीसरी जीत

इस जोड़ी की हार के साथ ही बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर सुपर 750 प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती भी समाप्त हो गई थी। सात्विक एवं चिराग की जोड़ी को शीर्ष वरीयता प्राप्त और विश्व की नंबर एक इंडोनेशियाई जोड़ी से 16-21, 20-22 से हार मिली। विश्व रैंकिंग में नौवें पायदान पर काबिज भारतीय जोड़ी की मार्कस और केविन की जोड़ी के खिलाफ यह लगातार 8वीं हार है जिसमें पिछले महीने फ्रेंच ओपन के फाइनल में मिली शिकस्त भी शामिल है। इस साल अगस्त में थाइलैंड ओपन का खिताब जीतने वाले सात्विक और चिराग की जोड़ी को इंडोनेशिया की जोड़ी ने इस साल तीसरी बार हराया है। टूर्नामेंट में भारत के अन्य खिलाड़ी पहले ही बाहर हो गए थे।

विविध

जूता घोटाले में कोर्ट ने नहीं स्वीकारी केंसलेशन रिपोर्ट

रमेश सिंगटा, शिमला

पुलिस महकमे से जुड़े नौ साल पुराना जूता घोटाला फिर सुर्खियों में आ गया है। मामले की जांच में जुटी विजिलेंस ने इसे रद करने के लिए स्टेटस रिपोर्ट (केंसलेशन रिपोर्ट) कोर्ट में दाखिल की थी लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया है।

सूत्रों के अनुसार शिमला की कोर्ट विजिलेंस की इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने अब 15 नवंबर को विजिलेंस से पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। इससे जेल के मौजूदा डीजी सोमेश गोयल, पूर्व डीजीपी डीएस मन्हास व पूर्व डीआइजी एचपीएस वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विजिलेंस की जांच में प्रोसीजर लैप्स पाए जाने की पुष्टि हुई है। शिमला के एक कोर्ट में 17 सितंबर को सौंपी गई इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। इसे स्वीकार न करने पीछे गोयल व वर्मा के खिलाफ कार्रवाई किसी निष्कर्ष पर न पहुंचना बताया जा रहा है।

जूता घोटाले में विजिलेंस जांच में इन तीनों के खिलाफ आरोप लगे थे। उस समय मिन्हास प्रदेश के डीजीपी, गोयल एडीजीपी मुख्यालय और वर्मा डीआइजी प्रशासन के पद पर कार्यरत थे। तीनों अफसरों के खिलाफ आरोप तैयार कर 26 दिसंबर 2013 को सरकार के पास भेजा गया था। छह मई 2017 को प्रधान सचिव विजिलेंस ने सूचित किया गया कि इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए मामला प्रशासनिक सचिव के हवाले किया जाए। 31 मार्च 2017 को प्रशासनिक सचिव ने सोमेश गोयल के खिलाफ चार्जशीट ड्रॉप कर दी। मन्हास के खिलाफ विभागीय इन्क्वायरी करने की अनुमति 18 फरवरी 2015 को मांगी गई। लेकिन 13 जुलाई 2015 को गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वर्मा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए 23 अप्रैल 2014 को गृह मंत्रालय को पत्र भेजा, लेकिन अभी तक इस बारे में स्वीकृति नहीं दी है।

क्या था मामला

पुलिस विभाग में वर्ष 2010 में एक करोड़ से अधिक के जूतों की खरीद की गई। लेकिन आवंटन के बाद ही कुछ ही समय में जूते फट गए थे। पुलिस कल्याण संघ ने इस मामले को सरकार से उठाया था। यह मुद्दा राज्य विधानसभा में भी प्रमुखता से उठा था। विजिलेंस ने सात जून 2013 को दर्ज की थी। जिन अफसरों पर आरोप लगे वे डीआइजी से लेकर डीजी रैंक के थे। जबकि जांच का जिम्मा डीएसपी रैंक के अधिकारी को दिया गया था। इससे भी जांच पर कई सवाल खड़े हुए थे।

योग व संयमित खानपान से कैंसर पर पाया जा सकता है काबू

चंद्रशेखर वर्मा, ग्रेटर नोएडा

कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की मुख्य वजह पर्यावरण, प्रदूषण व खानपान है। बीमारियां खानपान के जरिये ही शरीर में जाती हैं। कुल मामलों में यह पाया गया है कि लगभग 20 फीसद कैंसर खेत में प्रयोग किए जाने वाले हानिकारक रसायनों से होता है। योग से कैंसर को खत्म करने को लेकर काफी शोध हो रहे हैं। योग के जरिये कैंसर पर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए संयमित जीवन बेहद जरूरी है। रोजाना योग के साथ ही जीवन में जैविक खानपान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इंडिया एक्सपो मार्ट में चल रहे आयुर्योग एक्सपो में भाग लेने पहुंचे योगा इन डेली लाइफ ग्लोबल साइंटिफिक सिस्टम के संस्थापक स्वामी महेश्वरानन्द पुरी ने दैनिक जागरण से बातचीत में ये बातें कही हैं।

उन्होंने बताया कि योग में कई शोध हो रहे हैं, जिससे लोग निरोगी रह सकें। यह मानव जाति के लिए बहुत जरूरी है। भारत की संस्कृति काफी महान है। यहां जीवन जीने की पद्धति योग से ही प्राप्त हुई है। सबसे पहला योग भगवान शिव ने किया था। दुख की बात है कि विश्व को रास्ता दिखाने वाला देश आज प्रदूषण की चपेट में है। अधिक पढ़े-लिखे लोगों ने विकास के लिए भारत की संस्कृति को संकट में ला दिया।

स्वामी महेश्वरानन्द पुरी। जागरण

स्वामी ज्ञानेश्वर। जागरण

औषधीय पौधे समाप्ति की कगार पर है। इससे आयुर्वेद की दवाइयां भी नहीं बन पा रही हैं। योग के जरिये प्रयास हो रहा है कि इंसान को निरोगी काया दी जा सकें।

स्वामी ने बताया कि कैंसर लोगों के खानपान में है। इंसान पैदा होता है तो स्वस्थ होता है, लेकिन जीवनशैली बीमार बनाती है। खेती करते समय रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जमीन खराब हो रही है तो यहां उगने वाली खाद्य सामग्री कैसे स्वास्थ्यवर्धक हो सकती है। जैविक खेती पर ध्यान देना होगा तभी कैंसर से बचा जा सकता है। योग से कैंसर

योग का अभ्यास काफी कठिन है। केवल कुछ दिन योग करने से बीमारी को काबू करने में मदद नहीं मिलती है। किसी भी बीमारी को दबाने के लिए योग लगातार एक से दो घंटे किया जाना चाहिए। बीमारी काबू में आने के बाद भी इसका अभ्यास करना नहीं छोड़ना है, तब जाकर फायदा मिलता है।

– स्वामी ज्ञानेश्वर

जैसी बीमारियां पूरी तरह से ठीक तो नहीं होतीं, लेकिन इसके जरिये बीमारी को दबा सकते हैं, जिससे लंबा जीवन जीने में मदद मिलती है।

बेटे के जिम ट्रेनर दोस्त ने कंफेशन नोट में जुर्म स्वीकारा

फरीदाबाद हत्याकांड

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद

सेक्टर-7ए में शुक्रवार रात दंपती (रेडियोलॉजिस्ट प्रवीन मेहंदीरत्ता, उनकी पत्नी भारती) व उनके बेटी-दामाद (प्रियंका, सौरभ कटारिया) की चाकू से गला रेतकर हत्या मामले में पुलिस ने हत्यारे की पहचान का दावा किया है। एसीपी क्राइम अनिल कुमार के मुताबिक उनके पास पर्याप्त तथ्य हैं कि दंपती के बेटे दर्पण के जिम ट्रेनर दोस्त मुकेश ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। 30 वर्षीय मुकेश डबुआ कॉलोनी के पास न्यू राजीव कॉलोनी में परिवार संग रहता है। सेक्टर-7ए में दंपती के घर के पास जिम में वह करीब सात साल से ट्रेनर की नौकरी कर रहा था। यहीं उसकी दर्पण से दोस्ती हुई। पुलिस के मुताबिक मुकेश का दंपती के घर आना-जाना भी था।

क्राइम ब्रांच की टीमों ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच के बाद रात में ही चार संदिग्ध चिह्नित किए थे। मुकेश भी उनमें से एक था। पुलिस ने रात में सभी संदिग्धों को फोन कर सुबह पूछताछ के लिए थाने पहुंचने का निर्देश दिया था। सुबह मुकेश को छोड़कर बाकी तीन लोग पूछताछ के लिए पहुंच गए। सुबह पुलिस मुकेश के घर तक पहुंच पाती, इससे पहले ही उसका भाई लाला कंफेशन नोट लेकर डबुआ थाने पहुंच गया। लाला ने पुलिस को बताया कि मुकेश यह नोट छोड़कर घर से गया है। नोट में चारों हत्या करने की बात कबूल की है। साथ ही लिखा है कि वह आत्महत्या कर सकता है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुट गईं। पुलिस ने उसके घर के बाहर से स्कूटी, उसका जिम बैग, स्कूटी की चाबी बरामद की है। सभी पर खून के निशान हैं। उसके परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आरोपित के गिरफ्तार होने पर ही सारी बातें साफ होंगी।

शुक्रवार शाम घर से हत्या की साजिश रच निकला था मुकेश

हरेंद्र नागर, फरीदाबाद : पुलिस लगभग मान चुकी है कि न्यू राजीव कॉलोनी निवासी जिम ट्रेनर मुकेश ने शुक्रवार रात सेक्टर-7ए में मेहंदीरत्ता दंपती, उनकी बेटी व दामाद की हत्या की। अगर पुलिस की थ्योरी को सही मानें तो यह हत्याकांड बेहद सोच-समझकर किया गया है। मुकेश शुक्रवार शाम साजिश रचकर घर से निकला था। मुकेश के परिजनों ने बताया है कि शुक्रवार रात उसने देर से घर आने की बात कही थी। वजह पूछने पर उसने बताया कि एक दोस्त की शादी में जाना है। उसने शादी का निमंत्रण कार्ड भी दिखाया था। इससे साफ है कि उसने पहले ही साजिश रच ली थी और वह घर से तैयारी के साथ निकला। मुकेश अन्य दिनों में जिम से रात 10 बजे तक घर आ जाता था। मगर शुक्रवार को वह 12 बजे घर आया। परिजनों के मुताबिक उन्होंने अगले दिन मुकेश के व्यवहार में किसी तरह का बदलाव महसूस नहीं किया। शनिवार रात करीब 11 बजे मुकेश ने भाभी कमलेश से पेन मांगा था। अनुमान है कि उसी पेन से रात में उसने कंफेशन नोट लिखा और सुबह फरार हो गया।

दुर्घटनाग्रस्त होने से बची अन्त्योदय एक्सप्रेस

जासं, मुरादाबाद

- पहिए के ऊपर लगी प्लेट टूटी, नजीबाबाद के पास बोगी को ट्रेन से हटाया

अन्त्योदय एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बच गई। आखिर में बिजनौर में नजीबाबाद के पास बोगी को काट कर हटाया गया, जबकि बरेली में ही बोगी में खराबी का पता चल गया था। दरभंगा से जालंधर जाने वाली अन्त्योदय एक्सप्रेस में शनिवार रात 1.57 पीछे के कोच में तेज आवाज आने पर बरेली में ट्रेन को रोका गया। तकनीकी टीम ने जांच की तो पाया कि पीछे की बोगी के पहियों के ऊपर लगी प्लेट निकल रही है। टीम ने कोच को काट कर अलग करने के बजाय अस्थायी मरम्मत कर ट्रेन चला दी। ट्रेन के चलने के थोड़ी देर बाद फिर से बोगी में तेज आवाज आने लगी। गार्ड की सूचना पर मुरादाबाद में तकनीकी टीम ने कोच की जांच की। यहां भी कोच को काटकर हटाने के बजाय अस्थायी मरम्मत कर रात 3.45 बजे ट्रेन को चला दिया गया। चकराजमल स्टेशन पहुंचने से पहले कोच ज्यादा तेजी से हिलने लगा। नजीबाबाद से तकनीकी कर्मियों को चकराजमल स्टेशन भेजा गया। तकनीकी टीम ने परीक्षण किया तो पहिया के ऊपर लगी प्लेट आगे निकल गयी थी। थोड़ी दूर ट्रेन और चलती तो बोगी पटरी से नीचे उतर जाती क्योंकि पहिये की ट्राली भी टूट जाती।

बरेली से संचालित फेसबुक ग्रुप में 300 पाकिस्तानी

हिमांशु मिश्र, बरेली : अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश के लोगों ने जिस तरह से एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की उससे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बेचैन हो गया है। फैसले पर अमन पसंद भारतीय मुसलमानों की सकारात्मक राय पाकिस्तानियों को रास नहीं आई। अब वह देश का माहौल खराब करने के लिए भारतीय मुस्लिम युवाओं को भड़काने की नापाक कोशिश में जुट गया है। जरिया फेसबुक को बनाया है। बरेली में ऐसे चार फेसबुक ग्रुप का पता चला है, जिनमें 300 से अधिक पाकिस्तानी सक्रिय हैं। एक फेसबुक ग्रुप तो पाकिस्तान के अली शाह नाम के शख्स ने खुद विवादित ढांचे के नाम पर तैयार किया। जिसमें बरेली, अलीगढ़, अयोध्या, हैदराबाद, दिल्ली व लखनऊ सहित देशभर के 1900 से ज्यादा मुस्लिम युवाओं को जोड़ लिया है। ग्रुप में तमाम विवादित पोस्ट भी किए गए हैं।

इकलाख हत्याकांड के आरोपित पर जानलेवा हमला

जागरण संवाददाता, नोएडा

- पीड़ित के पिता की शिकायत पर गांव के तीन लोगों पर मुकदमा

जारचा कोतवाली क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव में इकलाख हत्याकांड के आरोपित युवक पर रविवार को गांव के कुछ युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक को स्वजन ने दादरी के अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल युवक के पिता ने गांव के तीन युवकों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

जारचा कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार राजपूत ने बताया कि बिसाहड़ा गांव निवासी संजय राणा का बेटा विशाल राणा इकलाख हत्याकांड का आरोपित है। वह जमानत पर बाहर है। विशाल राणा रविवार को बाइक पर दादरी से गांव लौट रहा था। वह बिसाहड़ा फाटक के पास पहुंचा, तो घात लगाए तीन लोगों ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोगों को आता देख आरोपित फरार हो गए। लोगों ने विशाल के स्वजनों को घटना की जानकारी दी। स्वजनों ने उसे दादरी के निजी अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

ग्रामीणों ने बताया कि विशाल का शनिवार शाम आरोपित युवकों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। गांव के लोगों ने विवाद शांत करा दिया था। कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार राजपूत का कहना है कि पीड़ित के पिता की शिकायत पर गांव के विकास, डिग्गी व गौरव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।

मौसम विशेष

कश्मीर घाटी में मौसम ठंडा बना रहेगा। जम्मू क्षेत्र में शुष्क मौसम के साथ दिन आरामदायक रहेगा। पर्वतीय स्थानों पर हल्की बर्फबारी संभव है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब व दिल्ली में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी। आंशिक बादलों के साथ दिन हल्का गर्म रहेगा।

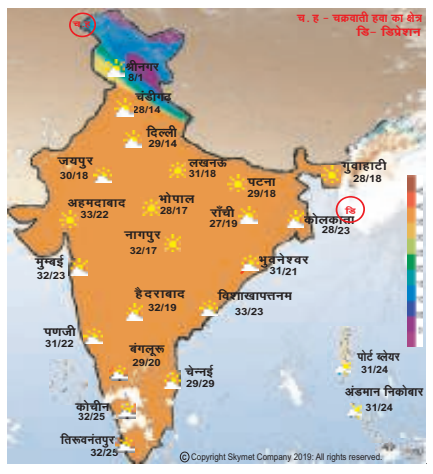

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	33/23/आंबा	अहमदाबाद	32/19/आंबा
कोलकाता	29/22/रसा	बड़ोदा	32/18/रसा
चेन्नई	34/25/आंबा	नागपुर	32/17/ए
हैदराबाद	32/20/रसा	इन्दौर	28/19/आंबा
बंगलूरु	30/20/आंबा	रांची	29/19/आंबा
त्रिवेन्द्रम	33/24/रसा	पटना	31/20/आंबा
गुवाहाटी	28/21/रसा	जमशेदपुर	29/19/ए
जगटोक	15/05/आंबा	पुणे	30/20/आंबा

भारत में लगी पहली अंतरराष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी

1977 में आज ही नई दिल्ली में पहली बार अंतरराष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी शुरू की गई थी। इसमें दुनिया के विभिन्न टिकटों का प्रदर्शन हुआ। भारत का पहला डाक टिकट 21 नवंबर 1947 को जारी हुआ। इस पर भारतीय ध्वज का चित्र और जय हिंद लिखा हुआ है।

आइंस्टीन और उनके सहयोगी को मिला रेफ्रिजरेटर का पेटेंट

1930 में आज ही महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन और उनके पूर्व छात्र लियो जिलार्ड को संयुक्त रूप से रेफ्रिजरेटर का पेटेंट मिला। स्थिर ऊष्मा और दाब से संचालित होने वाले इस उपकरण का पेटेंट अमेरिका में कराया गया। इलेक्ट्रोलक्स कंपनी ने इसके उत्पादन का अधिकार खरीदा।

शिक्षा की बुनियाद मजबूत करने वाले अबुल कलाम आजाद

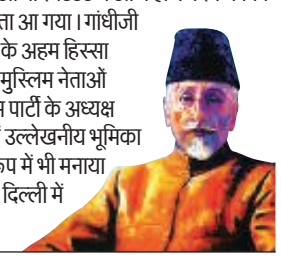

देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद 1888 में आज ही के दिन मक्का में पैदा हुए थे। 1890 में उनका परिवार कोलकाता आ गया। गांधीजी के विचारों से प्रभावित हुए और उनके आंदोलनों के अहम हिस्सा बने। वे अलग राष्ट्र के सिद्धांत का विरोध करने वाले प्रमुख मुस्लिम नेताओं में से एक थे। 1923 में सबसे कम आयु में (35 वर्ष) कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। आइआइटी, आइआइएम और यूजीसी की स्थापना में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। तभी उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1992 में भारत रत्न मिला। 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में आखिरी सांस ली।

इधर-उधर की

कब्र में लेटकर तनाव खात्मे का फार्मूला

एम्सटर्डम, एजेंसी : यह किसी शोध से निकला फंडा नहीं, बल्कि नीदरलैंड्स के निजमेजेन शहर की राडबाउड यूनिवर्सिटी अपने छात्रों को परीक्षा के तनाव से मुक्त करने के लिए यह तरीका अपना रही है। इस फार्मूले के बारे में जो भी सुन रहा है, बिना चकित हुए नहीं रह पा रहा, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन इस कदम को लेकर बहुत गंभीर है। इस असामान्य तरीके के तहत वह अपने छात्रों को कब्र में लिटाकर प्राणायाम करवाता है। इससे परीक्षा संबंधी तनाव दूर होने के दावे किए जा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय का यह कार्यक्रम काफी लोकप्रिय हो चुका है। इसके इच्छुक छात्रों के लिए प्रतीक्षा सूची काफी लंबी हो चुकी है। कब्र में प्राणायाम और योग के लिए कंबल और चटाई की व्यवस्था है। इसे तीस मिनट से तीन घंटे के लिए बुक किया जा सकता है।

...ऐसे होता है बर्फ के कणों का निर्माण

बर्लिन, प्रेट्र : सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी भी होने लगी है। लेकिन ये बर्फबारी होती कैसे है? आकाश में तेज हवाओं और गरजते बादलों के बीच बर्फ कैसे बनती है? एक नए अध्ययन में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है।

शोधकर्ताओं का दावा है कि इस अध्ययन के जरिये हमें बारिश और बर्फबारी की प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। इस अध्ययन में जर्मनी के लीबनिज इंस्टीट्यूट फॉर ट्रोपोस्फेरिक रिसर्च (टीआरओपीओएस) के शोधकर्ता भी शामिल थे। शोधकर्ताओं ने कहा, 'बादलों में इस प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना पृथ्वी के मध्य अक्षांशों में कोई वर्षा नहीं होगी, जिसमें दक्षिणी भारत के भी कुछ हिस्से शामिल हैं।

यह अध्ययन एपीजे क्लाइमेट एंड एटमॉस्फियरिक साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसमें कहा गया है, 'गर्म हवाएं सर्द हवाओं के मुकाबले कम संघनित होती हैं। ये ऊर्ध्वाधर हवाओं की गति को बढ़ाने का काम करती हैं और जिन बादलों में वाष्प, ठंडे पानी की बूंदें मौजूद होती हैं उनमें बर्फ के निर्माण में सहायता करती हैं।

शोधकर्ताओं ने कहा, 'एरोसोल कणों, हवा की गति, और बादलों में अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण बादलों में बर्फ बनने की प्रक्रिया को अलग-अलग कर अध्ययन करना मुश्किल है।'

- जर्मनी के लीबनिज इंस्टीट्यूट फॉर ट्रोपोस्फेरिक रिसर्च के शोधकर्ताओं ने किया अध्ययन
- कहा-गर्म हवाएं भी हैं बर्फबारी के लिए जिम्मेदार

यह शोध जर्नल एपीजे क्लाइमेट एंड एटमॉस्फियरिक साइंस में प्रकाशित हुआ है।

रडार और लेजर तकनीक का किया उपयोग : इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने रडार और लेजर तकनीक का उपयोग करते हुए लगभग 2 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर बड़े बादल क्षेत्रों का आकलन किया। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि अशांत और गजरते बादल सीधे बर्फ के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन बादलों में मौजूद वाष्प और पानी के कण बर्फ के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं।

जल चक्र का हिस्सा है बर्फबारी : आम तौर पर यह प्रक्रिया जल चक्र के रूप में जानी जाती है। इसमें सूरज की गर्मी से नदियों, तालाबों, झीलों और समुद्र का पानी वाष्प बनकर आसमान में पहुंच जाता है। जब कई वाष्प के कण संघनित होते हैं यानी इकट्ठे हो जाते हैं तो वे बादल का रूप ले लेते हैं। जब ये बादल आपस में टकराते हैं, तो बारिश होने लगती है। लेकिन जब यही बादल वातावरण में अधिक ऊपर चले जाते हैं तो वहां का तापमान बहुत कम हो जाता है और वातावरण बहुत ठंडा हो जाता है। बादल का तापमान बहुत कम हो जाने पर इनमें मौजूद वाष्प कण छोटे बर्फ के कणों में बदल जाते हैं। जब हवा इन बर्फ के कणों का वजन सहन नहीं कर पाती तो ये नीचे की ओर गिरने लगते हैं। इस दौरान एक-दूसरे से टकरा कर जुड़ने से इनका आकार बड़ा होने लगता है। रूई जैसे ये कण जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो हम उसे बर्फबारी कहते हैं।

अब चीनी से बढ़ाई जा सकेगी आंखों की रोशनी

विक्सन सिक्रोड़िया, कानपुर

स्पेक्ट्रम

अध्ययन

- राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने खोजी चीनी में विटामिन ए मिलाने की तकनीक
- अब मल्टीविटामिन युक्त चीनी तैयार करने पर भी चल रहा परीक्षण

चीनी खाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी... सुनकर थोड़ी हैरानी होगी लेकिन यह सच है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआइ) ने को-क्रिस्टलाइजेशन तकनीक से ऐसी चीनी तैयार की है जो मिठास देने के साथ आंखों का भी ध्यान रखेगी। प्राथमिक परीक्षण में विटामिन ए मिलाने का प्रयोग सफल रहा है। अब मल्टीविटामिन युक्त चीनी तैयार की जा रही है।

अभी तक चीनी बनाने के दौरान शीरे का स्प्रे करके विटामिन ए की मात्रा मिलाई जाती है लेकिन विटामिन की यह मात्रा कुछ समय तक ही रहती है। अब एनएसआइ ने को-क्रिस्टलाइजेशन तकनीक से चीनी में विटामिन मिलाने का जो तरीका ईजाद किया है, उससे साल भर व उससे अधिक समय तक चीनी में इसकी मात्रा को शामिल रखा जा सकेगा।

एनएसआइ निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने बताया कि चीनी में सुक्रोज, लैक्टोज व फ्रक्टोज पाया जाता है। इसमें विटामिन ए मिलाने की जो प्रक्रिया अभी अपनाई जाती है वह बहुत अधिक कारगर नहीं है। ऐसी चीनी में विटामिन की मात्रा कुछ समय में खत्म हो जाती है लेकिन को-क्रिस्टलाइजेशन तकनीक से उसे लंबे समय तक बरकरार रखा जा सकेगा। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिससे चीनी में विटामिन को उसका एक अंश बनाकर मिलाया जा सकता है। इस प्रकार की चीनी की मांग लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका व अफ्रीका जैसे देशों में बहुत है। मानक के अनुसार चीनी में 15 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए मिलाकर परीक्षण किया गया है। इसी तरह विटामिन सी, बी कांप्लेक्स व आयरन समेत चीनी में मल्टीविटामिन मिलाने पर परीक्षण चल रहा है। प्रो.नरेंद्र मोहन ने बताया कि खपत के बाद बची चीनी को विटामिन युक्त करके उसका निर्यात किया जा सकता है। पिछले वर्ष चीनी का उत्पादन 332 लाख टन हुआ था जबकि इस वर्ष 280 लाख टन होने का अनुमान है। इसके सापेक्ष खपत 260 लाख टन है। इस तरह बची 20 लाख टन चीनी को विटामिन युक्त करके निर्यात किया जा सकता है।

प्रतीकात्मक

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से 3डी में बदली जा सकेंगी 2डी इमेज

तकनीक ▸ वैज्ञानिकों ने खोजा तरीका, माइक्रोस्कोपी की क्षमताओं में होगा विस्तार

शरीर के भीतरी हिस्सों में होने वाली बीमारियों का भी हो सकेगा प्रभावी इलाज

सैन फ्रांसिस्को, आइएएनएस : आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) के जरिये अब 2डी इमेज को 3डी में बदली जा सकेंगी। वैज्ञानिकों ने शरीर के भीतर की गतिविधियों और रोगों की सटीक पहचान के लिए इस तकनीक को महत्वपूर्ण बताया है। लॉस एंजिलिस स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं की टीम ने डीप लर्निंग तकनीक का उपयोग करते हुए एक ऐसी तकनीक तैयार की है, जो प्रतिदीप्ति (फ्लोरेंस) माइक्रोस्कोपी की क्षमताओं को और विस्तार दे सकती है। इसके जरिये वैज्ञानिकों उन कोशिकाओं को ठीक करने में मदद मिलेगी जो विशेष प्रकाश डाले जाने पर चमकती हैं।

दरअसल, शरीर के भीतर कोशिकाओं में होने वाले बदलावों के कारण गंभीर बीमारियां पनपने का खतरा रहता है क्योंकि कई बार रासायनिक प्रक्रियाओं के चलते कोशिकाएं अव्यवस्थित तरीके से बढ़ने लगती हैं। इनके इलाज के लिए माइक्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। इस प्रक्रिया में शरीर के भीतर माइक्रोस्कोप डालकर रोग की पहचान की जाती है। इसमें लगे कैमरे के जरिये डॉक्टर अंदर की सारी गतिविधियों का आकलन करते हैं और बीमारी की परख करने के बाद उसका इलाज करते हैं। लेकिन कई बार कोशिकाओं में होने वाली अनियंत्रित वृद्धि और बदलाव माइक्रोस्कोप में लगे 2 डी कैमरे पकड़ में नहीं आते क्योंकि ये कैमरे अपने सामने की सतह की इमेज का ही परीक्षण कर पाते हैं।

प्रतीकात्मक

शोधकर्ताओं का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर माइक्रोस्कोप में लगे कैमरे को 3डी बनाया जा सकता है, जिससे माइक्रोस्कोप के शरीर के भीतर पहुंचते ही यह 3डी इमेज बनाना शुरू कर देता है। उन्होंने कहा कि इसका फायदा है यह होगा कि आंतों की हर एंगल से जांच की जा सकेगी और ऐसी संभावनाएं कम हो जाएंगी कि बीमारी या कोशिकाओं में होने वाले अनियंत्रित बदलावों को पहचाना ना जा सके। नेचर मैथर्ड नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में यह भी बताया कि 'डीप-जेड' नामक फ्रेमवर्क में ऐसी क्षमताएं हैं जो इमेजों की कमियों को दुरुस्त कर सकता है। साथ ही माइक्रोस्कोप से 2डी इमेज कर उन्हें 3 डी में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक के जरिये माइक्रोस्कोपी के जरिये इलाज को और प्रभावी बनाया जा सकता है। इस अध्ययन के वरिष्ठ लेखक आयडोगन ओजकन ने कहा, 'यह एक बहुत ही शक्तिशाली विधि है। यह प्रकाश की मौजूदगी में हानिकारक तत्वों को आसानी से पहचान सकती है।'

बैक्टीरिया का खात्मा करेगा यह वायरस

बोस्टन, प्रेट्र : हमारे शरीर में कई तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनमें से कुछ स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं तो कुछ शरीर को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इन्हीं विशेष प्रकार के जीवाणुओं (बैक्टीरिया) को मारने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई विधि विकसित की है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अब वाइरस की मदद से बैड बैक्टीरिया का खात्मा किया जा सकता है। साथ ही इससे एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बढ़ते खतरे को दूर करने में मदद मिल सकती है।

दरअसल, कई बार बीमारियों से बचने के लिए खाई जाने वाली दवाएं असर नहीं करतीं। इसका मुख्य कारण यही होता है कि हमारे शरीर के भीतर पाए जाने वाले बैक्टीरिया एंटीबायोटिक प्रतिरोधी हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि नई विधि से ऐसे बैक्टीरिया को मार कर बीमारियों से बचा जा सकता है।

सेल नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक बैक्टीरिया-संक्रमित वायरस, जिसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, में कोशिकाओं में पाये जाने वाले प्रोटीन की मदद से कुछ हेरफेर कर ई-कोली नामक बैक्टीरिया को मारा जा सकता है। 'ई-कोली' ऐसे बैक्टीरिया का उपभेद है, जो आतों में पाया जाता है और शरीर को नुकसान पहुंचाता है। शोध के मुताबिक, इस तरीके से बीमारियों से लड़ने के नए तरीके खोजे जा सकते हैं।

'हाइड लाइक काउंट्स' का अमेरिका में भी परीक्षण करेगा इंस्टाग्राम

सैन फ्रांसिस्को,आइएएनएस : फेसबुक के स्वामित्व वाली फोटो मैसेजिंग एप इंस्टाग्राम अमेरिका में कुछ यूजर्स के साथ 'हाइड लाइक काउंट्स' टेस्ट शुरू करने को लेकर तैयार है। उम्मीद है कि इस सप्ताह यह परीक्षण शुरू हो जाएगा।

द वर्ज के अनुसार, सैन फ्रांसिस्को में एक आयोजित एक कार्यक्रम में इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसेरी ने यह घोषणा की। सोशल मीडिया के प्रभावशाली नेटवर्क में से एक इंस्टा ने पहले कहा था कि इस पहल का उद्देश्य उन यूजर्स के दबाव को कम करना है, जो अपनी पोस्ट और प्रभाव की पहुंच को लेकर चिंतित रहते हैं। मोसेरी ने बीते अप्रैल माह में कहा था कि हम चाहते हैं कि लोग इस बारे में कम चिंतित हों कि उनके इंस्टाग्राम पर कितने लाइक हैं और साथ ही वे अपने चाहने वाले लोगों के साथ जुड़कर अधिक समय बिताएं। कनाडा, आयरलैंड, इटली, जापान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इंस्टाग्राम 'हाइड लाइक कॉउंट्स' का परीक्षण चला रहा है। इसके अतिरिक्त फेसबुक भी ऑस्ट्रेलिया में 'हाइड लाइक कॉउंट्स' टेस्ट चला रहा है। सोशल मीडिया प्लेफॉर्म के एक प्रवक्ता ने कहा, 'बहरहाल हम सीमित क्षेत्रों में ही इसका परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार किया जा सकता है।'

शोध अनुसंधान

डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों को हो सकता है गठिया

डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों को गठिया (आर्थराइटिस) रोग होने का ज्यादा खतरा रहता है। एक हालिया शोध में यह बात उजागर हुई है। करीब एक हजार बच्चों में से एक में क्रॉनिक आर्थराइटिस की संभावना होती है। यह बीमारी बच्चों को किसी भी उम्र में प्रभावित कर सकती है। हालांकि जन्म के बाद छह महीनों तक इसकी संभावना काफी ही कम होती है। डाउन सिंड्रोम और आर्थराइटिस से पीड़ित बच्चों की पहचान शुरुआत में नहीं हो पाती है। इस कारण उनका उपचार देर में शुरू हो पाता है। पीड़ितों के ज्वाइंट्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और उपचार के दौरान विकलांग होने का भी खतरा होता है। यह ऐसी अवस्था है, जिसमें बच्चे में माता-पिता से एक अतिरिक्त 21वां क्रोमोसोम आ जाता है। इस कारण ऐसे बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास धीमा को जाता है। -एएनआइ

एआइ बता देगा कहां और कब गिरेगी बिजली

अभी तक आसमानी बिजली गिरने का सही-सही पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल काम रहा है। लेकिन शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) का इस्तेमाल कर अब इसे भी आसान बना दिया है। स्विट्जरलैंड स्थित शोध संस्थान ईपीएफएल के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी एआइ प्रणाली विकसित की है, जो 30 किलोमीटर के दायरे में गिरने वाली आसमानी बिजली के बारे में पहले ही बता देगी, वह भी आधा घंटा पहले। मौसम संबंधी डाटा के आधार पर नई एआइ प्रणाली बिजली गिरने की किसी भी संभावना का सटीक अनुमान लगा सकती है। शोध के दौरान वज्रपात पर किया गया पूर्वानुमान 80 फीसद सटीक पाया गया। इस अध्ययन को क्लाइमेट एंड एटमोसफेरिक साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। -एएनआइ

जापान में अग्नि महोत्सव

16 वी शताब्दी के पारंपरिक तैमत्सु आकाशी फायर फेस्टिवल पर उत्तरपूर्वी जापान के फुकुशिमा प्रांत के सुकागावा में बड़ी-बड़ी मशाल जलाकर जश्न मनाया जाता है। इस समारोह के दौरान करीब 10 मीटर ऊंची और तीन टन वजनी 22 मशालें जलाई गईं। यह महोत्सव 420 साल पहले इस क्षेत्र में युद्ध के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले समुराई (योद्धा) और आम लोगों की आत्मा की शांति के लिए मनाया जाता है। एएफपी

नौसैनिकों की याद में मनाया वार्षिकोत्सव

कंबोडिया की राजधानी फ्नोम पेंह में इन दिनों देश के लोग अपने नौसैनिक योद्धाओं की याद में वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। तीन दिवसीय इस समारोह में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। रविवार को आयोजित बोट रेस में भी देश भर से आए कई प्रतिभागियों ने भाग लिया। बता दें कि देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली यह नगरी टोंले साप एवं मेकांग नदी के तट पर स्थित है। एपी

स्क्रीन शॉट

व्यक्तिगत सवालों के जवाब देना होता है मुश्किल : नेहा धूपिया

सात सवाल

अभिनेत्री नेहा धूपिया अपनी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में संतुलन साध कर चल रही हैं। वह अपने शो 'नो फिल्टर नेहा' के चौथे सीजन में एक बार फिर सेलिब्रिटी के कई अनसुने पहलुओं से पर्दा उठा रही हैं। नेहा ने शो और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें साझा कीं:

● शो में आप सितारों की व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़े सवाल पूछती हैं। आप अपने इंटरव्यू में व्यक्तिगत जिंदगी को कितना साझा करती हैं?

खुद मेरे लिए व्यक्तिगत सवालों के जवाब देना मुश्किल होता है। कभी-कभी जब मैं अपने सवालों को सुनती हूं तो मुझे लगता है कि मेरा मेहमान इन सवालों का जवाब कैसे देगा? मैं अपने मेहमानों को ऐसे सवालों से बचाने की कोशिश करती हूं। इतना जरूर है कि मेरे मेहमान सवालों के जवाब मुझसे कहीं बेहतर तरीके से देते हैं। सच कहूं तो मुझे अपनी व्यक्तिगत जिंदगी मीडिया में साझा करना नहीं पसंद है।

● क्या आपको लगता है कि खुद एक एक्टर होने के नाते दूसरे एक्टर आपके सवालों का जवाब सहजता से देते हैं?

एक्टर होने के नाते ज्यादातर एक्टर मेरे दोस्त हैं। इस शो के बाहर भी मेरे उनसे अच्छे संबंध हैं। उन्हें पता है कि अगर शो में कुछ गलत होगा तो उनके बचाव के लिए मैं यहां हूं। मुझे लगता है कि दोस्ती होने के कारण दूसरे एक्टर मेरे साथ अपनी जिंदगी के किस्से सहजता से साझा कर पाते हैं। इसके साथ ही शो पर आने वाले एक्टर्स को मेरे ऊपर भरोसा होता है।

● शो में आपका पसंदीदा एपिसोड कौन-सा है?

पहले सीजन का पहला एपिसोड मेरा पसंदीदा एपिसोड है। उसको करण जौहर के साथ रिकॉर्ड किया था। वह अब तक हमारे शो में तीन बार आ चुके हैं। हमारे बीच अच्छी दोस्ती है। लिहाजा वे तीनों एपिसोड मेरे दिल के काफी करीब हैं।

● यह आपके शो का चौथा सीजन है। क्या आपने कभी शो को वीडियो चैट में बदलने के बारे में नहीं सोचा?

हमारे बीच इसको लेकर चर्चा होती है। पर हर साल हम इस योजना को अगले साल के लिए टाल देते हैं। हमें यह डर भी लगता है कि एक अच्छे शो से छेड़छाड़ करके वीडियो शो बनाएं और कहीं ऑडियो-वीडियो के बीच वह फंस न जाए। दूसरी चीजें करने से कहीं ज्यादा बेहतर अपने जंगल का राजा बने रहना है। वैसे भी सोशल मीडिया पर शो के छोटे-छोटे वीडियो साझा किए जाते हैं।

● एक साल बाद आप फिर से काम पर लौट आई हैं। दूसरी पारी में किस तरह की फिल्मों को आप प्राथमिकता देंगी?

फिल्म 'तुम्हारी सुलु' के लिए मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद मैंने किरदार की लंबाई नहीं उसका प्रभाव देखते हुए काम करना शुरू किया है।

● कभी-कभी बच्चों से भी हमें कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। बेटी मेहर आपको किस तरह की प्रेरणा देती है?

मेहर के आने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। उसको देखकर मुझे अपना काम सही समय पर और सही तरीके से करने की प्रेरणा मिलती है। जो भी प्रस्ताव मेरे पास आते हैं मैं उनको पेशेवर तरीके से वक्त पर खत्म करने की कोशिश करती हूं, जिससे मैं घर लौटकर अपनी बच्ची संग ज्यादा वक्त गुजार पाऊं।

● पति अंगद बेदी और आप के बीच काम को लेकर किस तरह की चर्चा होती है?

शादी से पहले हमारे बीच काम को लेकर दोस्तों की तरह चर्चा होती थी। शादी के बाद भी उसी तरह की चर्चा होती है। हम दोनों एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते हैं। बेटी के लिए हम दोनों को समय निकालना पड़ता है। इस काम में हम दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। मुझे अंगद की सारी फिल्में पसंद हैं खासकर 'पिंक'।

-दीपेश पांडे

चिंताजनक

गाय-भैंस में भी हो रहा कैंसर, उबालकर पीयें दूध

लुवास ने सैकड़ों जानवरों का अल्ट्रासाउंड किया तो सामने आई हकीकत, अब तक वैज्ञानिक मानते थे कि घोड़ी में ही पाए जाते हैं कैंसर के लक्षण

वैभव शर्मा, हिसार

अगर आप यह सोच रहे हैं कि तंबाकू का सेवन करने से ही आपको कैंसर हो सकता है तो आप गलत हैं। दूध पीने से भी यह बीमारी हो सकती है। यह बात हम नहीं लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार (लुवास) की रिपोर्ट कहती है। लुवास ने हाल ही में अपने यहां इलाज के लिए आने वाले जानवरों की अल्ट्रासाउंड से एक डाटाबेस तैयार किया है, जिसमें सामने आया कि भैंस या गाय में कैंसर के मामले कम नहीं है। वैज्ञानिक अब तक मानते थे कि घोड़ियों में ही कैंसर पाया जाता है। मगर पिछले कुछ समय में दुधारू पशुओं में भी कैंसर फैलाने वाले कारक देखे जा रहे हैं।

पशु विज्ञानी बताते हैं कि अगर इन दुधारू पशुओं का दूध बिना उबाले पिया तो कैंसर आपको भी हो सकता है। हालांकि भारत में खास बात है कि यहां लोग दो से तीन बार दूध उबाल कर पीते हैं। इससे दूध में मौजूद कैंसर फैलाने वाले तत्व समाप्त हो जाते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि दूध पीने से पहले उसे दो से तीन बार धीमी आंच में जरूर उबालना चाहिए।

रहें सतर्क

- पोखरों और तालाबों का प्रदूषित पानी पीने से बढ़ती है समस्या
- वैज्ञानिकों ने कहा-दूध पीने से पहले दो-तीन बार धीमी आंच में जरूर उबालें

गर्भाशय में कैंसर के मामले आ रहे सामने : लुवास के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में पशु वैज्ञानिक डॉ. आरके चंदोलिया बताते हैं कि हमारे पास जो भी पशु आए, उनकी जांच में हमने पाया कि इनमें कई गाय-भैंसें ऐसी थी जिनमें गर्भाशय के कैंसर के लक्षणों को देखा गया। अगर समय पर पता चल जाता है कि उनके गर्भाशय को निकालकर ही उपचार किया जाता है। हमारे संस्थान में कई जानवरों का इलाज भी किया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड की सुविधा से यह संभव हो सकता है।

ऐसे फैल रहा कैंसर : पशुओं को जो चारा दिया जा रहा है, उनमें रासायनिक दवाओं के प्रयोग होता है। फसलों में रासायनिक दवाओं के प्रयोग के बाद बारिश के पानी में यह दवाएं मिल जाती हैं। इसके बाद किसी जलाशय से पशु जब पानी पी लेते हैं तो उनमें कैंसर की पूरी-पूरी संभावना रहती है। पशु वैज्ञानिक डॉ. चंदोलिया बताते हैं कि पशु विज्ञान में विदेशों में काफी काम हो चुका है, भारत में अब इस पर काम में तेजी आई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्यों की तर्ज पर पशुओं की हर बीमारी का इलाज किया जा सके।

बीमारियों से घिरे रहते हैं आवारा पशु : डॉक्टर चंदोलिया ने कहा कि हमारे पास लाए जाने वाले ज्यादातर जानवर पालतू होते हैं। इनमें कैंसर के लक्षण मिलना आश्चर्य की बात तो जरूर है पर असंभव नहीं है। दूसरी ओर जो जानवर आवारा सड़कों में घूमते रहते हैं वे भी कई गंभीर बीमारियों के शिकार रहते हैं।

अगले साल फिल्म में गाना गाना चाहती हूं : तारा सुतारिया

फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से अपने फिल्मी करियर का आगाज करने वाली तारा सुतारिया अब 'मरजावां' में नजर आएंगी। इसके अलावा, वह मिलन लूथरिया निर्देशित फिल्म में भी काम कर रही हैं। उसमें वह सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी के अपोजिट नजर आएंगी। अहान की यह डेब्यू फिल्म होगी। यह सुपरहिट तेलुगु फिल्म आरएक्स 100 का रीमेक होगी। तारा अभिनय के साथ गायन में भी पारंगत हैं। उन्होंने वेस्टर्न, सेमी क्लासिकल और जैज गाने की ट्रेनिंग ली है। वह अभिनय के साथ गायकी को भी आगे ले जाना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि वह अभिनय के साथ गायन पर भी फोकस कर पाएंगी। तारा के मुताबिक वह संगीत से बेहद लगाव रखती हैं। उन्हें अगले साल फिल्म में गाना गाना है या फिर अपना सिंगल निकालने की कोशिश करेंगी। उन्हें वेस्टर्न क्लासिकल संगीत बहुत पसंद है। वह कहती हैं, 'मैं बचपन से उसे परफॉर्म कर रही हूं। लिहाजा भविष्य में जरूर वेस्टर्न क्लासिकल में कुछ करना चाहूंगी।'